रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

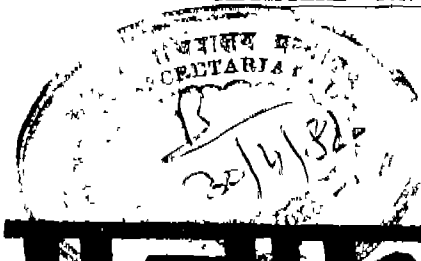

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1982/फाल्गुन 29, 1903
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1982/PHALGUNA 29, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1982

का०आ० 1152—नौटरीज, नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कल्याण कुमार भादुरी, अधिवक्ता, 5, सीधिया हाउस, कनाट सरकस, नई दिल्ली ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सम्पूर्ण भारत में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्राकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(17)/82-न्या०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 3rd March, 1982

S.O. 1152.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Kalyan Kumar Bhaduri, Advocate, 5, Scindia House, Connaught Circus, New Delhi for appointment as a Notary to practise throughout the Union of India.

2 Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(17)/82-Judl.]

का०आ० 1153—नौटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नानक प्रसाद श्रीवास्तवा, अधिवक्ता, सीतापुर, उ० प्र० ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(65)/81-न्या०]

S.O. 1153.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Nanak Prasad Srivastava, Advocate, Sitapur, U.P. for appointment as a Notary to practise in Sitapur District of U.P.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(65)/81-Judl.]

का०आ० 1154.—नौटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के० बाला कृष्णा अधिवक्ता, नं० 4, 3 क्रास रोड, 4 ब्लाक के०पी० डब्ल्यू० एक्सटेंशन, बंगलौर-560020 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे बंगलौर शहर और जिले में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

7. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(72)/81 न्या०]

के० सी० डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 1154.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri K. Balakrishna, Advocate, No. 4, 3rd Cross Road, 4th Block, K.P.W. Extn., Bangalore-560020 for appointment as a Notary to practise in District and City of Bangalore.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(72)|81-Judl.]

K. C. D. GANGWANI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1982

का०आ० 1155.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. जनगणना कार्य निदेशालय, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110052
2. जनगणना कार्य निदेशालयक, बिहार पटना-800001.
3. जनगणना कार्य निदेशालय, मध्य प्रदेश भोपाल-462002.
4. जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा, चण्डीगढ़-160022
6. जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान-जयपुर-3020026
7. जनगणना कार्य निदेशालय, पंजाब, चण्डीगढ़-160026
8. जनगणना कार्य निदेशालय, चण्डीगढ़-160026
9. जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171004
10. जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात, अहमदाबाद-380006
11. जनगणना कार्य निदेशालय, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर-744101
12. जनगणना कार्य निदेशालय, महाराष्ट्र, बम्बई-400038
13. जनगणना कार्य निदेशालय, केरल, त्रिवेन्द्रम-695003
14. जनगणना कार्य निदेशालय, लक्षद्वीप अरनाकुलम, कोचीन-16

[सं० 12017/1/82-हिन्दी]

अशोक कुमार वर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th March, 1982

S.O. 1155.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Home Affairs, the staff whereof they have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Directorate of Census Operations, Old Secretariat Delhi-110054.
2. Directorate of Census Operations, Bihar, Patna-800001.
3. Directorate of Census Operations, Madhya Pradesh, Bhopal-462002.
4. Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow.
5. Directorate of Census Operations, Haryana, Chandigarh-160022.
6. Directorate of Census Operations, Rajasthan, Jaipur-302004.
7. Directorate of Census Operations, Punjab, Chandigarh-160026.
8. Directorate of Census Operations, Chandigarh-160026.
9. Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh, Simla-171004.
10. Directorate of Census Operations, Gujarat, Ahmedabad-380006.
11. Directorate of Census Operations, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair-744101.
12. Directorate of Census Operations, Maharashtra, Bombay-400038.
13. Directorate of Census Operations, Kerala, Trivandrum-695003.
14. Directorate of Census, Operations, Lakshadweep, Ernakulam, Cochin-16.

[No. 12017|1|82-Hindi]

A. K. VARMA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1981

आयकर

का०आ० 1156.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (III) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या 4008 (फा०सं० 398/8/81 आ०क०स०फ०) का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री आर०आर० हेमराजानी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री आर०आर० हेमराजानी द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[संख्या 4260/फा.सं. 398/8/81-आ०क०ब०]

आर० सी० हांडा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th October, 1981

INCOME-TAX

S.O. 1156.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 4008 (F. No. 398|8|81-ITCC) dated 3-6-81, the Central Government hereby authorises Shri R. R. Hemrajani, being a gazetted Officer of the

Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri R. R. Hemrajani takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4260/F. No. 398/8/81-ITB]
R. C. HANDA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1982

आय-कर

का०आ० 1157.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मुस्लिम अनाथालय समिति" को निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4418/फा० सं० 197/234/80 आ० क(ए1)]

New Delhi, the 20th January, 1982

INCOME-TAX

S.O. 1157.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Muslim Orghanage Committee" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 4418/F. No. 197/234/80-IT(AI)]

का०आ० 1158.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 34) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मालंकर मारथोमा सीरियन चर्च, मालाबार" को निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4419/फा० सं० 197/99/80-आ० क(ए1)]

S.O. 1158.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Malankara Mar Thoma Syrian Church of Malabar" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 4419/F. No. 197/99/80-IT(AI)]

का०आ० 1159.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी देवस्थानम्, कादिरी को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4420/फा० सं० 197/1/81-आ० क(ए1)]

S.O. 1159.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Lakshmi Narasimhaswamy Devasthanam, Kadiri" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1983-84.

[No. 4420/F. No. 197/1/81-IT(AI)]

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1982

का०आ० 1160.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का43) की धारा 10 की उपधारा(23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री रंगम श्रीमद अंदमान पेरिआश्रमन् श्रीरंगम को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4465/फा० सं० 197/138/81 आ० क(ए1)]

New Delhi, the 12th February, 1982

S.O. 1160.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Srirangam Srimad Andavan Periashraman, Srirangam" for the purpose of the said section for and from the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4465/F. No. 197/138/81-IT(AI)]

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1982

का०आ० 1161.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "श्री तिरु पुराइक्कल भगवती मंदिर, वडाकंथारा को निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4469/फा० सं० 197/166/80 आ० क(ए1)]

New Delhi, the 16th February, 1982

S.O. 1161.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Thirupuraikkal Bhagavathy Temple, Vadakkanthara" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1975-76 to 1982-83.

[No. 4469/F. No. 197/166/80-IT(AI)]

का०आ० 1162.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री गुरु सिंह सभा (रजिस्टर्ड) मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4472/फा० सं० 197/87/81 आ० क(ए1)]

S.O. 1162.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Guru Singh Sabha (Regd.), Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1981-82.

[No. 4472/F. No. 197/87/81-IT(AI)]

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1982

का०आ० 1163.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्टूडेंट क्रिस्चियन मूवमेंट आफ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, बंगलौर" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1979-80 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4476/फा० सं० 197/53/78 आ० क(ए1)]

New Delhi, the 19th February, 1982

S.O. 1163.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Student Christian Movement of India Trust Association, Bangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1977-78 to 1979-80.

[No. 4476/F. No. 197/53/78-IT(AI)]

का०आ० 1164.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "सोसायटी आफ दि सिस्टर्स आफ दि डिवाइन सेवियर" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4479/फा० सं० 197/167/80 आ० क (ए1)]
मिलाप जैन, अवर सचिव

S.O 1164—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Sisters of the Divine Saviour" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1977-78 to 1981-82.

[No 4479/F No. 197/167/80-IT(A1)]
MILAP JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1982

आय-कर

का०आ० 1165—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है, अर्थात्

(1) यह कि जैन विश्व भारती इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का उपयोग अनन्यरूप से सामाजिक विज्ञान/सामाजिक दर्शन में अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए करेगा ।

(2) यह कि संस्थान इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(3) यह कि उक्त संस्थान वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित विवरण परिषद् को नियमित रूप से भेजेगा जिसमें इस छूट के अधीन संगृहीत निधि और उसके उपयोग की रीति भी वर्णित की जाएगी ।

संस्था

जैन विश्व भारती, राजस्थान

यह अधिसूचना इसको जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगी और तीन वर्ष के लिए विधिमान्य है ।

[सं० 4436/फा० सं० 203/95/81-आई टी ए-II]

New Delhi, the 25th January, 1982

INCOME-TAX

S O. 1165—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 subject to the following conditions :—

(1) That the funds collected by the Jain Vishwa Bharati under this exemption shall be utilised exclusively for promotion of research in Social Sciences/Social Philosophy.

(2) That the Institute shall maintain separate accounts of the funds so collected by them under this exemption

(3) That the Institute shall send to the Council Annual Report and audited statement of accounts regularly showing the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilised.

INSTITUTION

Jain Vishwa Bharati, Rajasthan.

This notification takes effect from the date of issue of this notification and is valid for a period of three years.

[No. 4436/F. No. 203/95/81-ITA. II]

का०आ० 1166—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् —

(i) यह कि संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

(iii) उक्त संस्थान लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

दी इंस्टीट्यूट आफ जेनेटिक्स होस्पीटल फार जेनेटिक डिसीजेज, हैदराबाद ।

यह अधिसूचना 1-10-1981 से 30-9-1984 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4437/फा० सं० 203/164/81-आई० टी० ए०-II]

S O. 1166—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Institute" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Institute will maintain a separate account of the sums received by it for medical Research.

(ii) That the Institute will furnish annual return of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Institute will furnish an annual audited statement of accounts to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concened Income-tax Commissioner

INSTITUTION

The Institute of Genetics Hospital for Genetic Diseases, Hyderabad.

The notification is effective for a period of three years from 1-10-1981 to 30-9-1984.

[No. 4437/F. No. 203/164/81-ITA.II]

का०आ० 1167.—राजस्व विभाग यह अधिसूचित करता है कि आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के अधीन, अधिसूचना सं० 77/10/50/62 आई० टी० ए० I तारीख 15-11-1962 द्वारा दिया गया अनुमोदन मंजूरी तारीख 14 दिसम्बर, 1984 तक विधिमान्य है।

[सं० 4438/फा० सं० 203/5/82-आई० टी० ए०-II]

S.O. 1167.—Department of Revenue hereby notifies that the approval granted u/s 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, to the Economic and Scientific Research Foundation vide Notification No. 77/10/50/62-ITA. I, dated 15-11-1962 is valid upto 14th of December, 1984.

[No. 4438/F. No. 203/5/82-ITA. II]

का०आ० 1168.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 3017/203/80/79-आई० ए० टी० II, तारीख 21-9-81 के अनुक्रम में सर्व-साधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र इस छूट के अधीन राशियों का उपयोग केवल सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए ही किया जाएगा ।

(ii) यह कि केंद्र इस छूट के अधीन प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(iii) यह कि केन्द्र लेखाओं का वार्षिक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (विहित प्राधिकारी) को और संबद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगा जिसमें इस छूट के अधीन संगृहीत निधि और उसके उपयोग की रीति भी दर्शित की जाएगी ।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(iii) के अधीन प्राप्त दोनों में से उपयोग न की गई राशियों की धारा 13(1)(ब) में विहित रीति में विनिधान, जिसके अंतर्गत सरकारी बचत प्रमाण पत्र विनियोग अनुसूचित बैंक में जमा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान पब्लिक सैक्टर कंपनियों में जमा डाकघर और सरकारी कंपनियों में जमा भी है, किया जाएगा ।

संस्था

उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद ।

यह अधिसूचना 1-4-1982 से 31-3-1985 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4439/फा० सं० 203/202/81-आई० टी० ए० II]

S.O. 1168.—In continuation of this Office Notification No. 3017/203/80-79-ITA. II, dated 21-9-81 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 subject to the following conditions :—

(i) That the funds collected by the Consumer Education and Research Centre, under this exemption shall be utilized exclusively for promotion of research in Social Sciences.

(ii) That the Centre shall maintain a separate accounts of the funds collected by them under the exemption.

(iii) That the Centre shall send annual statement of accounts and Annual Report to the ICSSR (Prescribed Authority) as well as to the concerned Commissioner of Income-tax, showing the funds collected by them under the exemption and the manner in which the funds were utilized.

(iv) Any unutilized funds, out of the donations received under section 35(1)(iii) of the Income-tax Act, 1961, will be invested in the manner prescribed in Section 13(1)(d) which includes investment in Govt. Saving Certificates, deposits in Scheduled Bank, investment in U.T.I., deposits with the Public Sector Companies, deposits in Post Office and Govt. Companies etc.

INSTITUTION

The Consumer Education and Research Centre, Ahmedabad.

This notification is effective for a period of three years from 1-4-1982 to 31-3-1985.

[No. 4439/F. No. 203/202/81-ITA. II]

का०आ० 1169—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2-क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है ।

1. वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम	फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरियम एफ० एसपी० उडुम परिस्थिति विज्ञान, मिट्टी में अरहर के मुरझाने के कारणात्मक जीव का अध्ययन ।
2. प्रायोजक	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग पी० ओ० 7003, नई दिल्ली-110062 ।
3. प्रायोजन-स्थल	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी-741235 ।
4 प्राक्कलित व्यय	29,100 रु० (उन्तीस हजार एक सौ रुपए) ।
5. अनुसंधान परियोजना की अवधि	1 नवम्बर, 1981 से 3 वर्ष ।

2. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी भूतपूर्व बिन विभाग की अधिसूचना सं० 878 तारीख 18-4-1975 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के अधीन अनुमोदित है ।

[सं० 4440/फा० सं० 203/100/81-आई० टी० ए०-II]

S.O. 1169:—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 by Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

1. Name of the Scientific Research Project	Studies on Ecology of Fusarium Oxysporum F. Sp. Udum, the Casual Organism of Wilt of Pigeon Pea, in Soil.
2. Sponsored (a) by	Hindustan Lever Limited, Express Building, Bahadur Shah Zafar Marg, P. O. 7003, New Delhi-110002.

3. Sponsored (b) at	Bidhan Chandra Krishi Viswa-Vidyalaya, Kalyani-741235.
4. Estimated expenditure	Rs. 29,100/- (Rupees Twenty nine thousand & one hundred only).
5. Duration of Research Project.	3 years with effect from 1st Nov., 1981.

2. Bidhan Chandra Krishi Viswa Vidyalaya, Kalyani stands approved urs. 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide late Finance Department Notification No. 878 dated 18-4-75.

[No. 4440/F. No. 203/100/81-ITA. II]

का०आ० 1170.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2443 (फा० सं० 203/75/78-आई० टी० ए०-II, तारीख 29-7-1978 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था का आयकर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) सोसाइटी इस छूट के अधीन प्राप्त राशियों का उपयोग केवल सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रगति के लिए ही करेगी ।

(ii) यह कि संस्थान प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(iii) उक्त संस्थान वार्षिक रिपोर्ट और इस छूट के अधीन एकत्रित राशियों और जिस रीति में इन राशियों का उपयोग किया गया है उसको दर्शाने वाला लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को नियमित रूप से भेजेगा ।

संस्था

कर्वे इंस्टीट्यूट आफ सोसल सर्विस, पूणे

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1984 तक प्रभावी है।

[सं० 4441/फा० सं० 203/59/81-आई० टी० ए०-II]

S.O. 1170.—In conunuation of this Department's notification No. 2443 (F. No. 203/75/78-ITA-II, dated 29-7-1978 it is hereby notified for General information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) That such funds collected by the society under this exemption shall be utilised exclusively for promotion of research in social sciences.

(ii) That the Institute shall maintain separate accounts of the funds collected by them under this exemption.

(iii) That the Institute shall send to the Council Annual Report and audited statement of accounts regularly showing the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilized.

INSTITUTION

Karve Institute of Social Service, Poone.

This notification is effective from 1st April, 1981 to 31st March, 1984.

[No. 4441/F. No. 203/59/81-ITA-II]

का०आ० 1171.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधार (2-क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

1. वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम	"तेलों का इपाक्सीकरण" ।
2. प्रायोजक का नाम	नेशनल परआक्साइड लि० नेविले हाउस, जे० एन० हेरेडिया मार्ग, बलार्ड एस्टेट, बम्बई-400038 ।
3. क्रियान्वयन प्रयोगशाला	बम्बई विश्व विद्यालय रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई ।
4. आरम्भ होने की प्रस्तावित तारीख	अक्तूबर, 1981 ।
5. समाप्त होने की प्रत्याशित तारीख	मार्च, 1982 ।
6. प्राक्कलित व्यय	24,955 रु० ।

2. बम्बई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई भूतपूर्व बिल विभाग की अधिसूचना सं० 34 तारीख 23-11-1946 द्वारा आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2)(xiii) के अधीन अनुमोदित है ।

[सं० 4442/फा० सं० 203/205/81-आई०टी०ए०-II]

S.O. 1171.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 by Department of Science & Technology, New Delhi.

1. Name of the Scientific Research Project.	"Expoxidation of Oils".
2. Name of the Sponsorer	National Peroxide Ltd., Neville House, J. N. Heredia Marg Ballard Estate, Bombay-400038.
3. Implementing Laboratory	University of Bombay, Deptt. of Chemical Technology, Bombay.
4. Proposed date of commencement.	October, 1981.
5. Anticipated date of completion.	March, 1982.
6. Estimated outlay	Rs. 24,955.

2. The University of Bombay, Deptt. of Technology, Bombay stands approved u/s. 10(2)(xiii) of the Income-tax Act, 1922 vide late Finance Department S. O. No. 34, dated 23-11-1946.

[No. 4442/F. No. 203/205/81-ITA. II]

का०आ० 1172.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि सेंट जोसेफ कालिज, तिरुचिरापल्ली प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) उक्त कालिज प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई, तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) उक्त कालिज लेखाओं का वार्षिक विवरण को प्रति वर्ष आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

सेंट जोसेफ कालिज, तिरूचिरापल्ली ।

यह अधिसूचना 11-12-1981 से 10-12-1984 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4443/फा० सं० 203/190/81-आई० टी० ए०-II]

S.O. 1172.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the St. Joseph's College, Tiruchirapalli, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than Agricultural|Animal husbandry|Fisheries and medicines;

(ii) That the said college will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said college will submit the Annual return and Statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax, every year.

INSTITUTION

St. Joseph College, Tiruchirapalli.

This notification is effective for a period of three years from 11-12-1981 to 10-12-1984.

[No. 4443/F. No. 203/190/81-ITA. II]

का० आ० 1173.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 1830 (फा० सं० 203/168/76 आई०टी०ए०II) तारीख 20-6-1977 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि केंद्र, इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का उपयोग अनन्य रूप से सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए करेगा ।

(ii) यह कि केंद्र इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(iii) यह कि केंद्र नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को भेजेगा जिसमें इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों और उसके उपयोग की रीति भी दर्शित की जाएगी ।

संस्था

विकास अध्ययन और क्रियाकलाप केंद्र, पूर्ण ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1983 तक प्रभावी है ।

[सं० 4444/फा० सं० 203/66/81-आई०टी०ए०-II]

S.O. 1173.—In continuation of this Department's notification No. 1830 (F.No. 203|168|76-ITA.II) dated 20-6-1977 it is hereby notified for information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) That such funds collected by the Centre under this exemption shall be utilized exclusively for promotion research in Social Sciences.

(ii) That the Centre shall maintain separate accounts of the funds collected by them under this exemption.

(iii) That the Centre shall send to the Council Annual Report and audited statement of accounts regularly showing the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilized.

INSTITUTION

Centre for Development Studies & Activities, Poona.

This notification is effective from 1st April, 1980 to 31st March, 1983.

[No. 4444/F. No. 203/66/81-ITA. II]

का० आ० 1174.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम, चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

(iii) यह कि उक्त संगम लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

बर्न्स एसोशिएशन आफ इंडिया, मुम्बई ।

यह अधिसूचना 18-9-1981 से 17-9-1983 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4445/फा०सं 203/165/81-आईटीए II]

S.O. 1174.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific reserach activities to the Council by 31 May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish a copy of the annual audited statement of accounts to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Burns Association of India, Bombay

The notification is effective for a perlod of two years from 18-9-1981 to 17-9-1983.

[No. 4445/F. No. 203/165/81-ITA. II]

का०आ० 1175.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम, चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किए जाए।

(iii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद को प्रतिवर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

पर्यावरण और पोषण विषयक स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 8-12-1981 से 7-12-1984 तक 3 वर्ष वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4446/फा० सं० 203/17/81-आईटीए II]

S.O. 1175.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific research association" in the field of medical research, subject to the following conditions :—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Association will furnish annual return of its scientific research activities to the council by 31st May, each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish a copy of the annual audited statement of accounts to the Council by 31st May each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Environmental & Nutritional Health Research Organisation, New Delhi.

This notification is effective for a period of 3 years from 8-12-1981 to 7-12-1984.

[No. 4446/F. No. 203/17/81-ITA-II]

का०आ० 1176.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि जयसी अनुसंधान फाउंडेशन, नई दिल्ली प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त फाउंडेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

(iii) यह कि उक्त फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरण और लेखाओं का विवरण की प्रति आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

जयसी अनुसंधान फाउंडेशन, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 11-12-81 से 10-12-84 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4447/फा०सं० 203/34/81-आईटीए II]
पी० सक्सेना, उप सचिव

S.O. 1176.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Jaycee Research Foundation, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than Agricultural/Animal husbandry/Fisheries and medicines;

(ii) That the said Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Foundation will submit the Annual return and Statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax for every year.

INSTITUTION

Jaycee Research Foundation, New Delhi

This notification is effective for a perlod of three years from 11-12-81 to 10-12-1984.

[No. 4447/F. No. 203/34/81-ITA. II]
P. SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1982

का०आ० 1177.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड को, मात्र पांच लाख बासठ हजार पांच सौ रुपए के उस समेकित स्टाम्प शुल्क को अदा करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा ऋण-पत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बन्ध पत्रों पर लगाने वाले स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य है।

[सं० 7/82 स्टाम्प-फा०सं० 33/35/81-वि०क०]
भगवान दास, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th March, 1982

STAMPS

S.O. 1177.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the East India Hotels Limited to pay consolidated stamp duty of five lakhs sixtytwo thousand five hundred rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures to be issued by the said company

[No 7/81-Stamps-F No 33/35/81-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1982

का०आ० 1178—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 119 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 147 के अधीन पुन निर्धारण या पुन संगणना करने वाला आयकर अधिकारी

(1) यदि कर से प्रभार्य आय पर जो सुसगत वर्ष मे निर्धारण से छूट गई है, कर दो सौ पचास रुपए से कम है तो सुसगत निर्धारण वर्ष के अत से चार वर्ष के भीतर, और

(2) यदि कर से प्रभार्य आय पर जो सुसगत वर्ष मे निर्धारण से छूट गई है कर पाच सौ रुपये से कम है तो सुसगत निर्धारण वर्ष के अत से चार वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष के अवसान के पूर्व

उक्त अधिनियम की धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण —इस आदेश मे "सुसगत निर्धारण वर्ष" का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 147 से 153 मे उसका है।

2 यह आदेश 15 फरवरी, 1982 को प्रवृत्त होगा।

[फा०स० 289/135/80-आयकर (अन्वेषण)]

आर० एच० भट्ट, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

New Delhi, the 11th February, 1982

S.O. 1178—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 119 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Income-tax Officer, making the reassessment or recomputation under section 147 of the said Act, shall not issue a notice under section 148 of the said Act—

(i) within four years from the end of the relevant assessment year, if the tax on income chargeable to tax which has escaped assessment for the relevant assessment year, amounts to less than rupees two hundred and fifty, and

(ii) after the expiry of four years but before the expiry of eight years from the end of the relevant assessment year, if the tax on income chargeable to tax which has escaped assessment for the relevant assessment year, amounts to less than rupees five hundred

Explanation —In this order, "relevant assessment year" shall have the same meaning assigned to it in sections 147 to 153 of the said Act

2 This order shall come into force on the 15th day of February, 1982.

[F No 289/135/80-IT(Inv)]

R H BHATT, Under Secy

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1982

का० आ० 1179—भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 के अधीन भारतीय निर्यात आयात बैंक के निदेशक मण्डल का गठन किया जाना है

अत अब उक्त अधिनियम के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार फरवरी, 1982 से भारतीय निर्यात आयात बैंक निदेशक मण्डल का एतद्द्वारा गठन करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) के अनुसरण मे भारतीय निर्यात आयात बैंक के निदेशको के रूप मे नामित करती है।

1 श्री एस०एम० घोष, सचिव, औद्योगिक विकास, उद्योग मंत्रालय, नयी दिल्ली

2 श्री आबिद हुसैन सचिव वाणिज्य मत्रालय, नयी दिल्ली

3 श्री सी० वेंकटरामन अपर सचिव, वाणिज्य मत्रालय, नयी दिल्ली

4 श्री आर० के० कौल, अपर सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मत्रालय, नयी दिल्ली

5 डा० बिमल एन० जालान, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मत्रालय, नयी दिल्ली

[सं० 2(2)/81 इएक्सआईएम]

एन० बालसुब्रह्मण्यन, उप सचिव

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(Banking Division)

New Delhi, the 27th February, 1982

S.O 1179—Whereas a Board of Directors of the Export-Import Bank of India is to be constituted under section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);

Now, therefore, in pursuance of the said Act, the Central Government hereby constitutes the Board of Directors of the Export-Import Bank of India with effect from February 24, 1982 and nominates the following persons as Directors of the Export Import Bank of India in pursuance of sub-clause (i) of clause (e) of sub section (1) of Section 6 of the Act

1 Shri S M Ghosh, Secretary, Industrial Development Ministry of Industry, New Delhi

2 Shri Abid Hussain, Secretary Ministry of Commerce, New Delhi

3 Shri C Venkataraman, Additional Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi

4 Shri R K Kaul, Additional Secretary, Banking Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi

5 Dr Bimal N Jalan, Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi

[No 2(2)/81-EXIM]

N BALASUBRAMANIAN, Dy Secy

नई दिल्ली 6 मार्च 1982

का०आ० 1180—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (1) के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक मडल की सिफारिश पर, उक्त

निगम द्वारा 29 मार्च, 1982 को जारी किए जाने वाले और 29 मार्च, 1997 को परिपक्व होने वाले बांडो पर दी जाने वाली ब्याज की दर, एतद्द्वारा 7-1/4 (सवा सात प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[सं० 2(27)आईएफ० 1/81]

के०पी० पाण्डियन अवर सचिव

New Delhi, the 6th March, 1982

S.O. 1180.—In pursuance of sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government on the recommendation of the Board of Diretcors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 7-1|4 per cent (seven and one fourth per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 29th March, 1982 and maturing on 29th March, 1997.

[No. 2(27)IF I/81]

K P. PANDIAN, Under Secy.

समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क

अधिसूचना सं० 24/81

इन्दौर, 4 मार्च, 1982

का०आ० 1181.—श्री सी० आर० राजवैद्य, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' मध्यप्रदेश इन्दौर निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनाक 31-12-81 के अपरान्ह से शासकीय सेवा से निवृत्त हो गये है।

[प० स० II(3) 9-गोप/81/1261]

(Central Excise Collectorate, Madhya Pradesh)

NOTIFICATION No 24/81

Indore, the 4th March, 1982

S.O. 1181.—Shri C. R. Rajvaidya, Superintendent, Central Excise Group 'B' of Madhya Pradesh Collectorate, Indore, having attained the age of superannuation, has retired from Government service in the afternoon of 31-12-81

[C. No. II (3)9-Con/81/1261]

अधिसूचना सं० 25/81

का०आ० 1182.—अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" के पद पर पदोन्नत होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (च० श्रे०) ने उनके नाम के आगे दर्शाई तिथियों को, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री		
1	निरजन सिह	अधीक्षक (निवारक) कें०उ० शुल्क मुख्यालय इन्दौर	29-12-81 (पूर्वान्ह)
2	के०एम० जोसेफ	अधीक्षक के०उ०शुल्क, रेंज-1 देवास	31-12-81 (पूर्वान्ह)

[प०स० II(3) 9-गोप 81/1264]

एस० के० धर, समाहर्ता

NOTIFICATION NO 25/81

S.O. 1182:—Consequent upon their promotion as Superintendent, Central Excise, Group 'B', the following Inspectors of Central Excise (S. G.), have assumed their charge as Superintendent of Central Excise, Group 'B' with effect from the dates as shown against their names:—

Sl. No.	Name of the officer	Place of Posting	Date of assumption of charge
1.	S/Shri Niranjan Singh	Superintendient (Prev) C. Ex. Hqrs. Office Indore.	29-12-81 (F.N.)
2.	S/Shri K. M. Joseph	Superintendent, C. Ex Range I, Dewas.	31-12-81 (F.N.)

[C. No. II(3)9-Con/81/1264]

S. K. DHAR, Controller.

MINISTRY OF COMMERCE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th March, 1982

S.O. 1183.—In the order of the Govt. of India in the Ministry of Commerce S.O. No. 557 dated 6-2-1982 published in the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 13th February, 1982 at page Nos. 556-557.

For,
C. B Kukreti, Joint Secretary

Read
C B. Kukreti, Joint Director

[No 3(11)/76-EI&EP]

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1982

का० आ० 1184.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा यह द्योतन करने के प्रयोजन के लिए खारे पत्थर की चमकदार पाइप और फिटिंग्स के सबध में भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव करती है कि जहा खारे पत्थर की चमकदार पाइप और फिटिंग्स पर ऐसे चिन्ह लगाए जाते है या चिपकाए जाते है, वे उक्त अधिनियम के अधीन उस पर लागू होने वाले मानक विनिर्देशो के अनुरूप समझे जाएंगे।

अत: केन्द्रीय सरकार ने उन्हे निर्यात (क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है।

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त उप-नियम के अनुसरण मे उक्त प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

2 यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे मे कोई आक्षेप या सुझाव भेजने का इच्छुक कोई व्यक्ति, उन्हे इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण अभिकरण, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' 14/1 बी० एजरा स्ट्रीट (8वीं मंजिल) कलकत्ता-700001 को भेज सकता है।

3 इस अधिसूचना मे "खारे पत्थर की चमकदार पाइप और फिटिंग्स" मे (क) रासायनिक रूप से प्रतिरोधी खारे पत्थर के चमकदार पाइप और फिटिंग्स और (ख) सामान्य जल निकास के उद्देश्य के लिए खारे पत्थर के चमकदार पाइप और फिटिंग्स, दोनो अभिप्रेत है। पाइप और

फिटिंग्स की आन्तरिक और बाह्य सतह जो जोड़ने के उपरान्त अनावृत्त रह जाती है चमकदार होगी । जोड़ने के बाद आवृत्त भाग चमकदार भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं । चमक जलाने की प्रक्रिया के दौरान पाइप और फिटिंग्स की सतह पर साधारण नमक के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

[सं० संख्या 6(13)/80-नि०नि० तथा नि०उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 20th March, 1982

S.O. 1184.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), proposes to recognise the Indian Standards Institution Certification mark in relation to Salt glazed stoneware pipes and fittings for the purpose of denoting that where salt glazed stoneware pipes and fittings are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable there to under the said Act;

And whereas the Central Government forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within fortyfive days of the publication of this notification in the Official Gazette to Export Inspection Agency, 'World Trade Centre', 14|1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

3. In this notification "Salt Glazed Stoneware Pipes and Fittings" shall mean both (a) chemically resistant salt glazed stoneware pipes and fittings and (b) normal drainage purpose salt glazed stoneware pipes and fittings. The interior and the exterior surfaces of the pipes and fittings which remain exposed after jointing shall be glazed The portions which remain covered after jointing may or may not be glazed The glazing shall be obtained by the action of the fumes of volatized common salt on the material of the pipes and fittings during the process of burning.

[F. No. 61(13)/80-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एंव निर्यात का कार्यालय)

अहमदाबाद, 14 अप्रैल, 1981

विषय : सर्वश्री एम० एम० खंबातवाला, अहमदाबाद के नाम में जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1826461, दिनांक 1-10-80 को रद्द करना ।

का० आ० 1185.—सर्वश्री, एम० एम० खंबातवाला, सिटी मिल कंपाउंड, कंकरिया रोड, अहमदाबाद को आयात नीति पुस्तक, 1981 के परिशिष्ट 5 के अनुसार अनुमेय मदों के आयात के लिए 1,57,774/- रुपये का आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1826461, दिनांक 1-10-80 प्रदान किया गया था ।

उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाए बिना और उपयोग में लाए बिना ही खो गया/अस्थानस्थ हो गया है । अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने नोटरी, अहमदाबाद के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एस/1826461, दिनांक 1-10-80 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि उक्त लाइसेंस की (केवल सीमा शुल्क प्रयोजन) अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जाए ।

एतद्द्वारा लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है ।

टी० टी० ला, संयुक्त मुख्य नियंत्रक

विषय:– मूल लाइसेंस सं० पी/एस/1826461 दिनांक 1-10-80 के बदले में लाईसेंस सं० डी०-2466867 दिनांक 15-4-81 की अनुलिपि प्रति जारी करना ।

आपको यह सूचित किया जाता है कि 157774/-रुपए के लिए लाईसेंस सं० पी/एस/1826461 दिनांक 1-10-80 की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रति सर्वश्री एम० एम० खम्बातवाला, अहमदाबाद को जारी की गई है । यह अनुरोध है कि यदि सीमा शुल्क प्रति (विवरण नीचे दिया गया है) प्रस्तुत की जाए तो इसे वैध नहीं समझा जाना चाहिए और यह कि यदि उपर्युक्त लाईसेंस की मूल प्रति पहले ही इस पत्तन पर प्रस्तुत की गई हो या उसका उपयोग किया गया हो तो उसकी सूचना तत्काल ही इस कार्यालय को दी जानी चाहिए ।

ला० सं० और दिनांक	जारीकर्ता	मद	लाईसेंस अवधि	वैधता	क्षेत्र	प्रयुक्त मूल्य	शेष मूल्य
पी/एस/1826461 दिनांक 1-10-80	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात अहमदाबाद	अप्रैल-मार्च 81 की नीति पुस्तक के परिशिष्ट 5 की अनुमेय मद	अप्रैल-मार्च 1981	12 महीने	सामान्य मुद्रा क्षेत्र	कुछ नहीं	1,57,774/- रुपए

[एफ० स० 445/ई यू/13610/ए एम-80/एस एस आई]

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports

Ahmedabad, the 14th April, 1981

Sub :—Cancellation of import licence No. P/S/1826461 dt. 1-10-80 to M/s. M. M. Khambhatwala, Ahmedabad.

S. O. 1185 :—M/s. M. M. Khambhatwala, City Mills Compound, Kankaria Road, Ahmedabad has been granted Import licence No. P/S/1826461 dt. 1-10-80 for Rs. 157774/- (Rs. One Lac Fifty Seven Thousand Seven Hundered Seventy Four Only) for import of Permissible Items as per Appx. 5 of Am. 81 policy book.

They have applied for issue of duplicate copy of custom purpose copy of above said licence on the ground that the original copy of the said licence has been lost/misplaced without having been registered with customs authority & utilised at all.

In support of their claim they have filed an affidavit duly sworn before Notary, Ahmedabad.

I am satisfied that custom purpose copy of licence No. P/S/1826461 dt. 1-10-80, has been lost/misplaced & direct that the duplicate copy of said licence (C.C.P. Only), be issued to applicant.

The original copy of licence CCP is here by cancelled.

T. T. LA, Jt. Chief Controller

Sub:— Issue of duplicate copy of licence No. D. 2468867-dt 15-4-81 in liew of original licence No. P/S/1826461 dt. 1-10-80.

This is to inform you that the duplicate customs copy of licence No. P/S/1826461 dt. 1-10-80 for Rs. 157774/-has been issued to M/s. M. M. Khambhatwala, Ahmedabad. It is requested that custom copy (particulars given below) should not be treated as valid if produced & that information should be sent to this office immediately if the original copy of above said licence has already been presented utilised at this port.

Lic. No. & Dt.	Issued by	Item	Licensing Period	Valid for
P/S/1826461 dt. 1-10-80	JCCI&E, Ahmedabad	P. items of Appx. 5 of AM. 81 P.B.	AM. 81	12 Months

Area	Value utilised	Value
GCA	Nil	Rs. 157774/-

[F. No. 445/EU/13610/AM. 81/SSI]

अहमदाबाद, 12 अगस्त, 1981

विषय :—सर्वश्री इंगरसॉल—रेंड (इंडिया) लि०, अहमदाबाद को प्रदत्त आयात लाइसेंस सं० पी/डी/1826850, दिनांक 12-12-1980 को रद्द करना।

का०आ० 1186 :—सर्वश्री इंगरसॉल—रेंड (इंडिया) लि०, जी आई डी सी एस्टेट, पोस्ट नरोदा, जिला अहमदाबाद को अप्रैल-मार्च 1981 की नीति-पुस्तक के परिशिष्ट–5 के अनुसार अनुमेय मदों के आयात के लिए 5,00,000 रु० (केवल पांच लाख रुपए) का आयात लाइसेंस सं० पी/डी/1826850/सी/एक्सएक्स/77/ए/80, दिनांक 12-12-80 प्रदान किया गया है।

उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति बंबई सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराने और आंशिक रूप से 74493 रु० तक उपयोग में लाने के पश्चात् खो गई है।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने बंबई के सहायक पंजीयक/महानगरीय जिलाधीश न्यायालय के सम्मुख विधिवत् सांख्यांकित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/डी/1826850 दिनांक 12-12-80 की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की केवल अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जाए।

लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

टी० टी० ला०, संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

विषय :—मूल लाइसेंस सं० पी/डी/1826850, दिनांक 12-12-80 के बदले में लाइसेंस सं० डी० 2466875, दिनांक 21-8-1981 की अनुलिपि प्रति जारी करना।

आपको यह सूचित किया जाता है कि सर्वश्री इंगरसॉल-रेंड (इंडिया) लि०, अहमदाबाद को 500000 रु० के लाइसेंस सं० पी/डी/826850 दिनांक 12-12-80 की अनुलिपि प्रति जारी की गई है। यह अनुरोध है कि सीमाशुल्क नियंत्रण प्रति (जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है) प्रस्तुत करने पर वैध न समझी जाए और यदि यह इस पत्तन पर प्रस्तुत की जाए/प्रयोग में लाई जाए तो उसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

लाइसेंस सं० एवं दिनांक	जारी कर्ता	मदें	लाइसेंस अवधि	अवधि जिसके लिए वैध है।
पी/डी/ 1826860 दिनांक 12-12-80	सं०मु०नि०आ०नि०, अहमदाबाद	अप्रैल,मार्च 81 की नीति-पुस्तक के परिशिष्ट-5 के अनुसार अनुमेय मदें	अप्रैल-मार्च 81	26-11-80 तक

क्षेत्र	प्रयुक्त मूल्य	शेष मूल्य
सामान्य मुद्रा क्षेत्र	74493 रु०	425307 रु०

[मि० सं० 369/ईयू/11535/अप्रैल-मार्च 81]
बी० बी० मेनन, नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Ahmedabad, the 12th August, 1981

Sub:— Cancellation of Import licence No. P/D/1826850 dt. 12-12-80 to M/s. Ingersoll-Rand (India) Ltd., Ahmedabad.

S. O. 1186 :—M/s. Ingersoll-Rand (India) Ltd., GIDC Estate, West Naroda. Dist. Ahmedabad has been granted import licence No. P/D/1826850/C/XX/77/A/80 dt. 12-12-80 for Rs. 5,00000/- (Rupees Five Lacs only) for import of Permissible items as per Appx. 5 of AM. 81 P.B.

They have applied for issue of duplicate customs purpose copy of the above said licence on the ground that the original customs purpose copy of the said licence has been lost after having been registered with the Bombay Customs authority and Utilised partly i.e. Rs. 74493/-.

In support of their claim they have filed an affidavit duly sworn before Asstt. Registrar Metropolitan Magistrates Court Bombay.

I am satisfied that Customs Purpose copy of licence No. P/D/1826850 dt. 12-12-80 has been lost/misplaced and direct that the duplicate copy customs purpose copy only, of the said licence be issued to applicant.

The original Custom purposes copy of licence is hereby Cancelled.

T. T. LA, Jt. Chief Controller
Imports & Exports.

Sub.:—Issue of duplicate copy of licence No. D 2466875 dt. 21-8-1981, in lieu of original licence No. P/D/1826850 dt. 12-12-80.

This is to inform you that the duplicate Custom copy of licence No. P/D/1826850 dt. 12-12-80 for Rs. 5,00000/- has been issued to M/s. Ingersoll Rand (India) Ltd., Ahmedabad. It is requested that Customs Control copy (Particulars given below) should not be treated as valid if produced and that information should be sent to this office presented/utilised at this port.

Lic. No. & Date.	Issued by	Item	Licensing Period	Valid for
P/D/1826850 Dt. 12-12-80	JCCI&E Ahmedabad	Permissible Items as per Appx. 5 of AM. 81. P.B.	AM. 81	UPTO 26-11-80

Area	Value utilised	Value Balance
GCA	Rs. 74493/-	Rs. 425307/-

[F. No. 369/EU/11535/AM. 81]
V. B. MENON, Controller,
Imports and Exports
For Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय)

आदेश

मद्रास, 26 दिसम्बर, 1981

का०आ० 1187.—सर्वश्री सेन्चुरि फलावर मिल्स लिमिटेड, इंडियन चेम्बर बिल्डिंग्स, पो० बा० नम्बर 1674, मद्रास-600001 को 1981-82 की अवधि के लिए रुपये 4,20,000 तक चिल्ड कास्ट आइरन के बिना दस संख्या डबल रोलर मिल्स साइज 1000 × 250 एम एम, टाइप जीएम 420 का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-सीजी-2078750-सी-एक्सएक्स-81-एम-81 दिनांक 30-10-81 जारी किया गया था। उपर्युक्त लाइसेंस असावधानी से जारी किया गया था।

केन्द्रीय सरकार को यह बात स्पष्ट हो जाने के कारण, कि उपर्युक्त लाइसेंस असावधानी से जारी किया गया है, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के यथा संशोधित धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत उस लाइसेंस को रद्द करने के लिए प्रस्ताव किया गया।

इस कार्यालय के पावती पंजीकृत द्वारा भेजे गये पत्र संख्या ऐटीसी-सीजी-डीजीटीडी-99 एएम 81-एयु-2 दिनांक 30-11-81 के द्वारा फर्म को यह बताया गया कि वे उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे किसी भी वचन बद्धता में बंधे बिना उसे 31-11-81 की तिथि में सात दिनों के भीतर वापस भेजें।

इस कार्यालय के पत्र के प्रत्युत्तर में फर्म ने अपने पत्र संख्या सीएफएम-एएमपी-सीएपीटी-1-81 दिनांक 1-12-81 में यह लिखा था कि उन्होंने पहले ही उपर्युक्त लाइसेंस के दर्शाये गये माल के संभरण के लिए 12-11-81 को करार का पुष्टिकरण कर चुका है, अतः वे लाइसेंस को वापस नहीं कर सकते।

फर्म ने लाइसेंस को वापस न भेजा। अतः आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के यथा संशोधित धारा 6(1)(ए) के अनुसार कार्रवाई करने धारा 10 के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या ऐटीसी-सी-जी-डीजीटीडी-99-एम-81-एयु-2 दिनांक 9-12-81 के द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस को रद्द करने के लिए फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फर्म को कारण बताओ नोटिस की अपना उत्तर भेजने के लिए दस दिनों का अवकाश भी दिया गया था। उनको 21-12-81 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी अवसर दिया गया था।

कारण बताओ नोटिस का उत्तर फर्म ने अपने पत्र संख्या सीएफएम-ऐएमपी-सीएपीटी-1-81 दिनांक 12-12-81 में दिया है और, उनके प्रतिनिधि 21-12-81 को अधोहस्ताक्षरी के सामने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ।

अपने बचाव में फर्म ने यह तर्क किया है कि निम्नलिखित आधारों के कारण, लाइसेंस असावधानी से जारी नहीं किया गया है कि कार्यालय ने आवेदन पत्र की जांच के लिए कम से कम दस मास लेकर आवेदन पत्र की जांच बहुत सावधानी से की है और उनके यथापेक्षित आठ श्रेणियों की मशीनरी और उपस्कर के प्रतिस्थापना के स्थान पर एक ही मद्दे के लिए यानी डबल रोलर मिल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हुए लाइसेंस जारी करने में लाइसेंस प्राधिकारी की ओर से कोई असावधानता नहीं हुई है।

अधोहस्ताक्षरी फर्म के तर्कों को बहुत सावधान से जांच करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा है कि उनके तर्क में इसलिए कोई विषय नहीं है कि वर्तमान फलावर मिल्स के लिए सिर्फ रोलर्स के आयात के लिए ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है और अन्य मदों के लिए नहीं।

अतः लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंस असावधानता से जारी किया गया है।

इसलिए आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 के अभी तक यथा संशोधित धारा 9(1)(ए) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं रुपये 4,20,000 का लाइसेंस संख्या पी-सीजी-2078750-सी-एक्सएक्स 81 एम-81 दिनांक 30-10-81 की सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति और मुद्रा विनिमय प्रति दोनों को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[ऐ टीसी-सीजी-डीजीटीडी-99-एएम-81-एयु-2]
एम० नरसिंहन, उप मुख्य नियंत्रक
आयात तथा निर्यात

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Madras, the 26th December, 1981

S.O. 1187.—M/s. Century Flour Mills Ltd., Indian Chamber Buildings, P.B. No. 1674, Madras-600001, were issued an import licence No P|CG|2078750|C|XX|81|M|81 dated 30-10-81 for Rs. 4,20,000 for the import of 10 Nos. Double Roller Mills—size 1000 x 250 MM, Type GM 420 without chilled cost Iron Rolls, for the year 1981-82. The said licence was issued through inadvertence.

2. It was therefore proposed to cancel it under clause 9(i)(a) of the Imports (Control) Order 1955 as amended from time to time as the Central Govt. was satisfied that the said licence was issued through inadvertence.

3. The firm was therefore, asked to return the said licence within 7 days from 30-11-81 without entering into any commitment vide letter No. ITC|CG|DGTD|99|AM|81|AU. II dated 30-11-81, sent by Registered Post A|D. The letter was duly received by the firm.

4. In reply to this letter, the firm, in their letter No. CFM|IMP|CAPT|1|81 dated 1-12-81, have stated that as they had entered into confirmed contact on 12-11-81 for the supply of the goods covered by the said licence, they could not return the licence.

5. As the firm have not returned the said licence, a show cause Notice was issued to the firm vide No. ITC|CG|DGTD|99|AM81|AU. II dated 9-12-81, under Clause 10 for action under Clause 9(i)(a) of Imports (Control) Order 1955, as amended, for cancellation of the said licence. The firm was given 10 days time for filing their reply. They were also given a date for personal hearing viz. 21-12-81.

6. The firm have furnished their reply to the Show Cause Notice vide their letter No. CFM|IMP|CAPT|1|81 dated 12-12-81 and their Representative also appeared before the undersigned for a Personal Hearing on 21-12-81.

7. The firm in their defence, have argued that the licence had not been issued inadvertently by this office on the ground that this office had taken not less than Ten months for scrutinising the application and that the application has been scrutinised very carefully and that, of the eight categories of machinery|equipment required by them as Replacement, the licence has been issued only for one item viz., Double Roller Mill and that in view of the circumstances stated above there is no inadvertence involved in the issue of the licence, on the part of the licensing authority. The undersigned has carefully examined the contention of the firm

and has come to the conclusion that there is no substance in the argument as licences for existing flour mills can be issued only for the import of Rollers and not for any other item and therefore, the licence had been issued by the licensing authority inadvertently.

8. Therefore, in exercise of the powers conferred on me under Clause 9(i)(a) of the Imports (Control) Order 1955 date 7-12-55 as amended upto date the said licence No. P|CG|2078750|C|XX|81|M|81 date 30-10-81 (both Exchange Control and Customs purposes copies) for Rs. 4,20,000 is hereby cancelled.

[Endt. No. ITC|CG|DGTD|99|AM|81|AU|II]
S. NARSIMHAN, Dy. Chief Controller
Imports and Exports

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1982

का०आ० 1188.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए टैक्सटाइल उद्योग के लिए एक विकास परिषद स्थापित करती है।

उक्त विकास परिषद में अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:—

अध्यक्ष :

1. सचिव, (टैक्सटाइल), टैक्सटाइल विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

सदस्य

2. विकास आयुक्त, हथकरघा, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (टैक्सटाइल) टैक्सटाइल विभाग, वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली।
4. सलाहकार, योजना आयोग योजना भवन, नई दिल्ली
5. वस्त्र आयुक्त, पोस्ट बैग सं० 11500 मुम्बई-400020
6. सलाहकार (शैल रसायनिक) पैट्रोलियम विभाग, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. प्रबन्ध निदेशक, एन टी सी सूर्य किरण बिल्डिंग, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
8. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. अध्यक्ष, इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन (आई सी एम एफ) टैक्सटाइल सेंटर, 34, पी डी मिलो रोड, मुम्बई 400009
10. प्रधान, इंडियन वूलेन मिल्स फैडरेशन (आई डब्ल्यू एम एफ) चर्चगेट, चैम्बर्स 5, मैरीन लाइन्स, मुम्बई-400020
11. अध्यक्ष, फैडरेशन आफ इंडिया आर्ट सिल्क वीविंग, इंडस्ट्री (एफ आई ए एस डब्ल्यू आई), रेशम भवन, वीर नारीमन रोड, मुम्बई-400020
12. प्रधान, टैक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, 53 मित्तल चैम्बर्स, छठी मंजिल, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021
13. निम्नलिखित टैक्सटाइल अनुसंधान संघों (रिसर्च एसोसिएशनों) में से किसी एक का निदेशक,
    (क) अहमदाबाद टैक्सटाइल उद्योग अनुसंधान संघ, अ०टे०उ०अ०सं०, पालटेक्निक डा०घ० अहमदाबाद, 380015
    (ख) मुम्बई टैक्सटाइल अनुसंधान संघ (मु०टे०अ०सं०) लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाट कोपर (पश्चिम) मुम्बई 400086
    (ग) दक्षिण भारत टैक्सटाइल अनुसंधान संघ, (द०भा०टे०अ०सं०), कोयम्बटूर, हर ई पत्र, डा०घ० कोयम्बटूर-641014
    (घ) उत्तरी भारत टैक्सटाइल अनुसंधान संघ (उ०भा० टे० अ०सं० पोस्ट बाक्स सं० 123, गाजियाबाद
    (ङ) सिल्क और आर्ट सिल्क मिल अनुसंधान संघ (सि०आ०सि०मि०आ०सं०), डा० एनी बेसेन्ट रोड, वार्ली, मुम्बई-400025
    (च) ऊन अनुसंधान संघ (ऊ०अ०सं०) अकबर कैम्प रोड, डाकघर सैन्डोज बाग, कोलशेट रोड, थाने-4000607, महाराष्ट्र
    (छ) कृत्रिम टैक्सटाइल अनुसंधान संघ (कृ०टे०अ०सं०) रेशम भवन, लाल दरवाजा, सूरत-395003, गुजरात
    (उक्त अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व वार्षिक, आधार पर बारी बारी से किया जाएगा)
14. प्रधान आल इंडिया फैडरेशन आफ को आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, 14, मुर्जाबान रोड, तीसरी मंजिल, मुम्बई-400001
15. महासचिव, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आई एन टी यू सी), 1, बी, मोलाना, आजाद रोड, नई दिल्ली

या

महासचिव, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए आई टी यू सी), 24, कैनिंग लेन, नई दिल्ली

16. विकास आयुक्त, हथकरघा, नई दिल्ली, उक्त परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में

17. संयुक्त सचिव (टैक्सटाइल), जो वाणिज्य मंत्रालय के टैक्सटाइल विभाग में समन्वय कार्य का भारसाधक हो, उक्त विकास परिषद् के सचिव के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

[फा० सं० 8(8)/80-सीडीएन]
एम. एल. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 1982

S.O. 1188.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 the Central Government hereby establishes for a period of two years with effect from the date of issue of this order, a Development Council for Textile Industry.

The said Development Council shall consists of the following chairman and members, namely :—

Chairman :

1. Secretary (Textile),
Department of Textiles,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

Members :

2. Development Commissioner for Handlooms,
New Delhi.

3. Joint Secretary (Textiles),
Department of Textiles,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

4. Adviser, in the Planning Commission,
Yojna Bhavan,
New Delhi.

5. The Textile Commisssioner,
Post Bag No. 11500,
Bombay-400020.

6. Adviser (Petrochemicals),
Department of Petroleum,
Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers,
New Delhi.

7. The Managing Director,
NTC, Surya Kiran Building,
19 Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi.

8. Joint Secretary,
Department of Agriculture,
Ministry of Agriculture,
New Delhi.

9. Chairman,
Indian Cotton Mills' Federation (ICMF)
Textile Centre,
34, P. O. Mellow Road,
Bombay-400009.

10. President,
Indian Woolfen Mills Federation (IWMF),
Churchgate Chambers,
5, New Marine Lines,
Bombay-400020.

11. Chairman,
Federation of India Art Silk Weaving Industry (FIASWI),
Resham Bhavan,
78 Veer Nariman Road,
Bombay-400020.

12. President,
Textile Machinery Manufacturers' Association,
53, Mittal Chambers, 5th Floor,
Nariman Point,
Bombay-400021.

13. Director of any of the following Textile Research Association, namely :—

(a) Ahmedabad Textile Industry's Research Association, ATIRA, Polytechnic P. O. Ahmedabad-380015.

(b) Bombay Textile Research Association (BTRA),
Lal Bahadur Shastri Marg,
Ghatkopar (West), Bombay-400006.

(c) South India Textile Research Association (SITRA),
Coimbatore Aerodrome,
P.O. Coimbatore-641014.

(a) Northern India Textile Research Association (NITRA), Post Box No. 123, Ghaziabad.

(e) Silk and Art Silk Mills Research Association (SASMIRA),
Dr. Annie Besent Road,
Worli, Bombay-400025.

(f) Wool Research Association (WRA),
Akbar Camp Road, P. O. Sandoz Baugh,
Colshet Road, Thane-400607,
Maharashtra.

(g) Man-made Textile Research Association (MANTRA),
Resham Bhavan, Lal Darvaza,
Surat—Gujarat-395003.

(The above research bodies will be represented by turn on a yearly basis).

14. President,
All India Federation of Cooperative Spinning Mills.
14, Murzanan Road, 2nd Floor,
Bombay-400001.

15. General Secretary,
Indian National Trade Union Congress (INTUC).
1 B, Maulana Azad Road,
New Delhi.
Or
General Secretary,
All India Trade Union Congress (AITUC),
24 Canning Lane, New Delhi.

(Those bodies will be represented by turn on a yearly basis).

16. Development Commissioner for Handlooms,
New Delhi.
as the Vice-Chairman of the said Council.

17. Joint Secretary (Textiles) in-charge of coordination work in the Department of Textiles, Ministry of Commerce shall discharge the functions of the Secretary to the said Development Council.

[F. No. 8(8)/80-CDN]
M. L. GUPTA, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1982

का०आ० 1189.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 2763 तारीख 10/10/1981 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने

उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और अत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, अत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद-द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाए दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड तलोजा तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—महाराष्ट्र— जिला—रायगड तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर		क्षेत्र	
			स्क्वे. मीटर्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नवघर	44	4	24	00
		5	28	00
	45	4	36	00
		5	34	00
		6	06	00
	70	3	41	00
		4	37	00
	71	—	08	00
	68	1	16	00
		2	24	00
		3	40	00
		4 ए	32	00
		4 बी०	24	00
	67	1	12	00
		2	24	00
		3	01	00
		4	38	00
		6	01	00
	66	2	36	00
		3	20	00
	65	1	40	00
		2	30	00
	79	1	04	00
	57	1	18	00
		3	10	00
		4	10	00
		5	10	00
		6	14	00
		7	07	00
	58	1	02	00
	59	2	02	00
		3	24	00
		5	02	00
		6	28	00
		4	10	00
	99	1	16	00
		2	24	00
	56	1	12	00
	98	1	14	00
		2	16	00
		3	08	00
		5	07	00
		7	22	00
		8	16	00

[सं० 12016/42/81-प्रो]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 1st March, 1982

S.O. 1189.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Feltilizers (Department of Petroleum) S. O. No. 2763 dated 10-10-1981 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in Deepak Fertilizers and Petrochemical Corporation Ltd., free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Panvel

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters	
1	2	3	4	5
Navghar	44	4	24	00
		5	28	00
	45	4	36	00
		5	34	00
		6	06	00

1	2	3	4	5
Nayghar—*Contd.*		70	3	41.00
			4	37.00
		71	—	08.00
		68	1	16.00
			2	24.00
			3	40.00
			4A	32.00
			4 B	24.00
		67	1	12.00
			2	24.00
			3	01.00
			4	38.00
			6	01.00
		66	2	36 00
			3	20.00
		65	1	40.00
			2	30.00
		79	1	04.00
		57	1	18.00
			3	10.00
			4	10.00
			5	10.00
			6	14.00
			7	07.00
		58	1	02 00
		59	2	02.00
			3	24.00
			5	02.00
			6	28.00
			4	10.00
		99	1	16.00
			2	24.00
		56	1	12.00
		98	1	14.00
			2	16.00
			3	08.00
			5	07.00
			7	22.00
			8	16.00

[No. 12016/42/81— Prod.]

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1982

का० आ० 1190.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत (सरकार पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2779 तारीख 10-10-1981 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

उराण टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—महाराष्ट्र	जिला—रायगढ़		ताल्लुका—पनवेल	
गांव	सर्वेक्षण नम्बर		क्षेत्र	
			स्क्वे.	मीटर्स
आसुडगांव	नाला	—	28	. 00
	97 पी० टी०	—	198	. 00
	96 पी० टी०	—	66	. 00
	53 पी० टी०	—	240	. 00
	51 पी० टी०	—	92	. 00
	50 पी० टी०	—	20	. 00
	42	5 पी०टी	76	. 00
	सड़क	—	376	. 00

[सं० 12016/50/81-प्रो०]

टी० एन० परमेश्वरन, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 1982

S.O. 1190.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S. O. No. 2779 dated 10-10-1981 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the puprpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in Deepak Fertilizers and Petrochemical Corporation Ltd., free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Panvel

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Asudgaon	Nala	—	28.00
	97 pt.	—	198.00
	96 pt.	—	66.00
	53 pt.	—	240.00
	51 pt.	—	92.00
	50 pt.	—	20.00
	42	5 pt.	76.00
	Road	—	376.00

[No. 12016/50/81—Prod.]

T.N.Parameswaram, under secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली 17 फरवरी, 1982

का० आ०.1191—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 7 नवम्बर, 1980 पृष्ठ 3599-3605 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3068 तारीख 19 अक्टूबर, 1981 में:—

पृष्ठ 3599 पर

1. पैरा 3 में (ख) "239.37 में एकड़". के स्थान पर "239.27 एकड़" पढ़ें।
2. अनुसूची "क" में "रेखांक सं० सी-1(ई) /III/डी० आर० /181/181" के स्थान पर "रेखांक सं० सी-1(ई)/III/डी० आर० /181/181 तारीख 1-1-1981" पढ़ें।

पृष्ठ 3600 पर

ग्राम पौड़ी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक "506" के स्थान पर "406" पढ़ें।

पृष्ठ 3601 पर

1. ग्राम बिझरी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक "78 से 84" के स्थान पर "70 से 84" और "447 (भाग)" के स्थान पर "447" पढ़ें।
2. सीमा वर्णन —ङ—$ङ_1$ —$ङ_2$—$ङ_3$ $ङ_4$—$ङ_5$—च रेखा में, "ग्राम धुरेना, कलमुंडा, मानगांव" के स्थान पर "ग्राम धुरेना, कसमुंडा, मुंड, मानगांव" और "कच्छानाकी" के स्थान पर "कुच्छेना" पढ़ें।

पृष्ठ 3602 पर

अनुसूची "ख" में 1 सारणी में "गेवड़ा" के स्थान पर "गेवरा" पढ़ें।

2. "ग्राम गेवड़ा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक" के स्थान पर "ग्राम गेवरा में अर्जित किए गए संख्यांक" पढ़ें।

[सं० 19(67)/81-सी० एल०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th February, 1982

S.O. 1191.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3068 dated the 19th October, 1981, published at pages 3602 to 3605 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 7th November, 1981;

at page 3603—

1. In the Schedule 'A', against serial number 1 below the column Halka No., for "45" read "54".
2. In the Schedule 'A', against serial No. 4, below the column village, for 'Dipke' read 'Dipka'.
3. Under the heading Plot numbers acquired in village Dipka, for '491 (P)' read '591 (P)'.
4. In the heading plot numbers acquired in village Jeingatpur, for Jeingatpur read "Jhingatpur".
5. Under the heading Plot numbers acquired in village Mangaon, for plot number '193/3' read '190/3'..
6. Under the heading plot numbers acquired in village Binjhri, for plot '157(P), to 165' read '157 to 165'.

at page 3604—

1. Under the heading Boundry Description in line 'H-I' for 'dated 7-7-1978' read 'dated 3-7-1978'.
2. In Schedule 'B', under the heading Plot numbers acquired in village Georc, for '1164 to 1181' read '1164 to 1181'.

at page 3605—

1. Under the heading Boundary Description, in line L-I, for 'meets at point I-I' read 'meets at points II
2. Under the heading Boundry Description, for 'LI—I' read 'II—I'.

[No. 19/67/81-CL]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1982

का०आ० 1192.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii), तारीख, 9 मई, 1981 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1406 तारीख 6 मार्च, 1981 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 3650.00 एकड़ (लगभग) या 1477.10 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :—

(क) इससे संलग्न अनुसूची "क" में वर्णित उप-ब्लाक I/क में 45.00 एकड़ (लगभग) या 18.21 हैक्टर (लगभग), उप-ब्लाक I/ख में 5.00 एकड़ (लगभग) या 2.02 हैक्टर (लगभग), उप-ब्लाक II/क में 472.00 एकड़ (लगभग) या 191.00 हैक्टर (लगभग) उप-ब्लाक III/क में 605.00 एकड़ (लगभग) या 244.82 हैक्टर (लगभग), उप-ब्लाक IV में 430.00 एकड़ (लगभग) या 174.01 हैक्टर (लगभग) उप-ब्लाक V में 40.00

एकड़ (लगभग) या 16 19 हैक्टर (लगभग) और उप-ब्लाक ग में 1985 00 एकड़ (लगभग) या 803 29 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि, और

(ख) इससे संलग्न अनुसूची "ख" में वर्णित उप-ब्लाक 2/ख में 8000 एकड़ (लगभग) या 3 24 हैक्टर (लगभग) 20 00 एकड़ (लगभग) या 8 09 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान और करने, उनकी खुदाई करने और उन्हें तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने और उन्हें ले जाने के निधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण

(1) इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त, गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कालफील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण-2

कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है —

अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति -

8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी सक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।

टिप्पण 3 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

कर्गली विस्तार

उपब्लाक—1, 2, 3, 4, 5 और 6

पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र

जिला—हजारी बाग और गिरीडीह (बिहार)

रेखांक सं० राजस्व/61/81

तारीख 20-6-81

(जिसमें अर्जित किए जाने वाली भूमि वर्णित की उप-ब्लाक 1/क सभी अधिकार गई है)

क्र० सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	बेरमो	नवाडीह (बेरमो)	18	गिरडीह	25 00	भाग
1	2	3	4	5	6	7
2	जिरीडीह	नवाडीह (बेरमो)	19	गिरिडीह	20 00	भाग
		कुल क्षेत्र 45 00 एकड़ (लगभग) या 18 21 हैक्टर (लगभग)				

बेरमो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक —

216 (भाग), 217 से 220, 221 (भाग), 222 (भाग), 223 224 (भाग) 225, 226 227 (भाग), 228 (भाग) और 230 (भाग)

जिरीडीह ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

21 (भाग), 22 (भाग), 23, 24, 25, 26 (भाग), 27 (भाग), 252 (भाग), 256 (भाग), 257 से 265,266 (भाग), 268 (भाग), 269 (भाग), 278 (भाग), 279, 280 (भाग), 281 (भाग), 283 (भाग), 284, 285, 286, 287 (भाग), 288 (भाग), 289, 290 (भाग), 327 (भाग), 655 (भाग), 656 (भाग), 657, 658 (भाग), 672 (भाग), 674 (भाग), 675, 676, 677 (भाग), 693(भाग), 694, 695 (भाग), 697 (भाग), 698 (भाग), 699 (भाग), 700 (भाग), 701 (भाग), 705 और 721 (भाग)

सीमा वर्णन —

क-ख रेखा बेरमो ग्राम में प्लाट संख्यांक 221 से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग-घ-ङ रेखाएं बेरमो ग्राम में प्लाट संख्यांक 221 और 216 से होकर जिरीडीह ग्राम में प्लाट संख्यांक 26, 21, 22, 26, 27, 26, 256, 252, 266, 269, 268, 327, 280, 278, 281, 283, 290, 693, 700, 677, 672, 658, 655 से होकर जाती हैं (जो वर्तमान रेल अर्जित सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च रेखा जरीडीह ग्राम के प्लाट संख्यांक 656 और 721 से होकर जाती है (जो बोकारो कोयला क्षेत्र के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-क रेखा जरीडीह ग्राम के प्लाट संख्यांक 720 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ होती हुई प्लाट संख्यांक 672, 674, 701, 699, 698, 697, 695, 290, 288, 287 से होती हुई फिर बेरमो ग्राम के प्लाट संख्यांक 228, 227, 230, 224, 222, 230 और 221 से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित कारो ब्लाक के उप-ब्लाक क के साथ सम्मिलित सीमा है) और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

उप-ब्लाक 1/ख सभी अधिकारी

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	बेरमो	नवडीह (बेरमो)	18	गिरीडीह	1.90	भाग
2.	जरीडीह	,,	19	,,	3.90	,,

कुल क्षेत्र 5.00 एकड़ (लगभग)
या 2.02 हैक्टर (लगभग)

बेरमो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :—
208 (भाग), 209, 210 (भाग) और 211 (भाग)

जरीडीह ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक
1 से 4, 8 (भाग), 9 (भाग), 10, 11, 12 (भाग), 13 (भाग), और 26 (भाग)

सीमा वर्णन :

छ-ज रेखा कुमार नदी के भागतः दक्षिणी किनारे के साथ-साथ जाती है और बिंदु-ज पर मिलती हैं।

ज-झ-ञ रेखाएं जिरीडीह ग्राम के प्लाट संख्यांक 6 की भागतः उत्तरी सीमा के साथ-साथ होती हुई प्लाट संख्यांक 8, 9, 12 और 13 से होकर जाती है (जो वर्तमान रेल अर्जित सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिंदु "ञ" पर मिलती है।

ञ-छ रेखा जिरीडीह ग्राम के प्लाट संख्यांक 13 और 26 से होकर बेरमो ग्राम के प्लाट संख्यांक 210, 211 और 208 से होकर जाती है (जो वर्तमान रेल सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और आरम्भिक बिन्दु "छ" पर मिलती है।

उप-ब्लाक 11/क सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र एकड़	टिप्पणियां
1.	फुसरो	नवडीह (बेरमो)	67	गिरीडीह	324.50	भाग
2.	ढोरी	,,	68	,,	147.50	भाग

कुल क्षेत्र 472.00 एकड़ (लगभग)
या 191.00 हैक्टर (लगभग)

फुसरो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :
61 (भाग), 67 से 74-75 (भाग), 76 (भाग), 77 से 80, 81 (भाग) 82 (भाग), 83 (भाग), 419 (भाग), 422 (भाग), 425 (भाग), 426 (भाग), 427, 428 (भाग), 429 (भाग), 431 (भाग) 433 (भाग), 434 से 445, 446 (भाग), 447, 448, 449, 450 (भाग), 453 (भाग), 454 से 464, 465 (भाग), 466 (भाग), 467 (भाग), 468 (भाग), 473 (भाग), 477 (भाग) 478 से 483, 484 (भाग), 485 (भाग), 487 (भाग), 488, 489 (भाग), 555, 556 (भाग), 557 (भाग), 558 (भाग), 559, 560, 561 (भाग), 562 से 574, 575 (भाग), 576 (भाग), 577 से 580, 581 (भाग), 582 से 594, 603 (भाग), 604, 605, 610 (भाग), 612, 613, 614 (भाग) 615, 644 (भाग), 645, 646 (भाग), 648 से 668, 669 (भाग), 670 (भाग), 671 (भाग), 704 (भाग), 705 से 724, 725 (भाग), 726 (भाग), 727 (भाग) 728 (भाग), 760 से 790, 792 से 798, 811 (भाग), 812 (भाग), 813.

ढोरी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक।
353 (भाग) और 940 (भाग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा फुसरो ग्राम में प्लाट संख्यांक 82, 61, 811, 610, 811, 610, 811, 644, 811, 644, 646, 811, 646, 811, 812, 671, 669, 704, 726, 727, 725, 728 और 812 [से होकर जाती है (जो चल कर ब्लाक विस्तार (उप-ब्लाक 11) की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है] और बिंदु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा फुसरो और ढोरी ग्राम की दामोदर नदी के भागतः बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिंदु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 1349 और प्लाट संख्यांक 1312 की भागतः पश्चिमी सीमा से होकर प्लाट संख्यांक 1319 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्यांक 1318 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ और प्लाट संख्यांक 940 और 1308 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ होकर तथा प्लाट संख्यांक 940 और 353 से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित ढोरी ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिंदु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 353 से होकर जाती है (जो ढोरी कोयला क्षेत्र की भागतः सतही अधिकार सीमा बनाती है) और बिंदु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च रेखा फुसरो और ढोरी ग्राम की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो ढोरी कोयला क्षेत्र की भागतः सतही अधिकार सीमा बनाती है) और बिंदु "च" पर मिलती है।

च-क रेखा फुसरो ग्राम के प्लाट संख्यांक 561, 556, 561, 557, 435, 556, 446, 489, 487, 485, 473, 484, 477, 465, 466, 467, 468, 453, 450, 446, 433, 431, 428, 429, 426, 419, 422, 425, 83, 75, 76, 83, 81 और 82 से होकर जाती है (जो करगली कोयला क्षेत्र की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और आरंभिक बिंदु "क" पर मिलती है।

उप-ब्लाक 11/ख, खनन अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र एकड़	टिप्पणियां
1	ढोरी	नवडीह (बेरमो)	68	गिरीडीह	8.00	भाग

कुल क्षेत्र 8.00 एकड़ (लगभग)
या 3.24 हैक्टर (लगभग)

ढोरी ग्राम मे अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :
352 (भाग) और 353 (भाग)

सीमा वर्णन :

ध-ङ रेखा फुसरो और ढोरी ग्राम की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो उप-ब्लाक 11/क के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) जो बिंदु "ङ" पर मिलती है।

ङ-ष रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 353 से होकर जाती है (जो उप-ब्लाक 11/क के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिंदु "ष" पर मिलती है।

ष-छ रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 353 से होकर प्लाट संख्यांक 352 की भागतः पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित ढोरी ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिंदु "छ" पर मिलती है।

छ-क रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 352 और 353 मे होकर जाती है (जो कर्गाली कोयला क्षेत्र की भागत सम्मिलित सीमा बनाती है) और प्रारंभिक बिंदु "क" पर मिलती है।

उप-ब्लाक III/क सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना स०	जिला	क्षेत्र एकड	टिप्पणियां
1	ढोरी	नवाडीह (बेरमो)	68	गिरीडीह	605 00	भाग
		कुल क्षेत्र	605 00 एकड़ (लगभग)			
		या	241 82 हेक्टर (लगभग)			

ढोरी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सख्याक

353 (भाग), 672 (भाग), 699 (भाग), 700 (भाग), 701 (भाग), 702, 703 (भाग), 704 से 709, 710 (भाग), 711, 712 (भाग), 714 (भाग), 715 (भाग), 716, 717 (भाग), 729 (भाग), 762 (भाग), 765 (भाग) 766 (भाग), 767 (भाग) 769 (भाग), 792 (भाग), 793 (भाग), 794 (भाग), 795 796 (भाग) 798 (भाग), 799, 800 से 834, 836 838 से 855, 856 (भाग), 857 (भाग), 858 (भाग), 859 से 877, 878 (भाग), 879 (भाग), 880 (भाग), 881 882 (भाग), 885 (भाग), 888 (भाग) 889 से 931, 940 (भाग), 941 से 1280, 1288 से 1299, 1301, 1322 से 1343, 1391 से 2024, 2025 (भाग), 2026 (भाग), 2027 (भाग), 2028 (भाग), 2096 (भाग), 2204 (भाग), 2206 (भाग), 2207 (भाग), 2208 से 2211 2215 (भाग), 2216 से 2255, 2256 (भाग), 2257 (भाग), 2258 से 2281, 2285 (भाग), 2288 से 2290, 2291 (भाग), 2292 से 2304 2305 (भाग), 2306 से 2308, 2309 (भाग), 2310 (भाग), 2313 (भाग), 2333 (भाग), 2381 (भाग), 2382 (भाग), 2383 (भाग), 2384 (भाग), 2406 से 2408 2409 (भाग), 2410 से 2414, 2415 (भाग), 2416 (भाग), 2417, 2418 (भाग), 2420 (भाग), 2498 (भाग), 2499, 2500, 2501 (भाग), 2502 (भाग), 2503 (भाग), 2504 (भाग), 2505 (भाग), 2506 से 2508, 2508 (भाग), 2510, 2511 (भाग), 2521 (भाग), 3189 (भाग), 3190 (भाग), 3191 से 3206, 3208 (भाग), 3209, 3210 (भाग), 3211 से 3227, 3229, 3233, 3235 3236 3237, 3238, 3239, 3240, 3241 और 3245

सीमा वर्णन

क-ख रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 353 940 और प्लाट सख्याक 940, 1321, 1308 1302, 1300, 1304, 1287, 1288, 1282 और 1281 की उत्तरी सीमा प्लाट सख्याक 1300, 1304, 1287 1286, 1285, 1284, 1283 और 1281 की पश्चिमी सीमा से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित ढोरी ब्लाक की भागत सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ख" पर मिलती है

ख--ग रेखा ढोरी ग्राम की दामोदर नदी के भागत बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग पर मिलती है।

ग--घ रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 3189 3208 3189, 3210 3189 3190 3189, 2333, 2285, 2291, 2313, 2309 2305, 2310, 2381, 2382 2383, 2384 प्लाट सख्याक 2406 की उत्तरी सीमा से होकर प्लाट सख्याक 2499, 2415, 2416, 2420, 2418, 2257, 2256, 2498, 2501, 2502 2503, 2504, 2505, 2509, 2511, 2215, 2521, 2207, 2206, 2204, 2096, 2215, 2026, 2075 2027, 2028, 2027, 672, 701, 700, 699 700, 703, 710, 712, 714, 715, 717, 729, 792, 793, 794, 796, 798, 769, 767, 762, 766, 765, 857, 856, 858, 878, 879 880, 882 885, 888 और 353 से होकर जाती है (जो ढोरी कोयला क्षेत्र के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "घ पर मिलती है।

घ ड च-छ-क रेखाएं ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 353 से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क पर मिलती है।

उप-ब्लाक III/ख--खनन अधिकार

क्रम स०	ग्राम	थाना	थाना स०	जिला	क्षेत्र एकड	टिप्पणियां
1	ढोरी	नवाडीह (बेरमो)	68	गिरिडीह	20 00	भाग

कुल क्षेत्र --20 00 एकड (लगभग)
या 8 09 हेक्टर (लगभग)

ढोरी ग्राम मे अर्जित किए जाने वाले प्लाट सख्याक --353 (भाग) 457 (भाग), 458 (भाग), 460 (भाग), 582 से 586, 587 (भाग)।

सीमा वर्णन

ज-क रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 353 मे होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित ढोरी ब्लाक की भागत सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "क पर मिलती है।

क-छ च-ड रेखाएं ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 353 से होकर जाती है और बिन्दु "ड पर मिलती है।

ड-झ रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 353 587, 353, 458 457, 458, 460 और 353 से होकर जाती है (जो ढोरी कोयला क्षेत्र के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "झ पर मिलती है।

झ--ज रेखा ढोरी ग्राम के प्लाट सख्याक 353 से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "ज' पर मिलता है।

उप-ब्लाक सभी अधिकार

क्रम स०	ग्राम	थाना	थाना स०	जिला	क्षेत्र एकड	टिप्पणियां
1	चलकरी	पेटरवार	46	गिरिडीह	9 50	भाग
2	झुमरी	,,	48	,,	420 50	,,

कुल क्षेत्र -- 430 00 एकड़ (लगभग)
या 174 01 हेक्टर (लगभग)

चलकरी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

1573 (भाग), 2555, 2556 (भाग), और 4172 (भाग),

झुझको ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

1(भाग), 2(भा), 3 से 15, 16(भाग), 20(भाग), 21(भाग), 22 से 28, 29 (भाग), 30 (भाग), 48 (भाग), 49 से 56, 57 (भाग), 58, 59, 60 (भाग), 61 से 91, 92 (भाग), 93 से 104, 105 (भाग), 106 (भाग), 107 (भाग), 108 (भाग), 115 (भाग), 116 से 148, 149 (भाग) 150, 151, 152, 153 (भाग), 154 (भाग), 155 से 158, 159 (भाग)' 160 (भाग), 162 (भाग), 163 से 167, 168 (भाग), 172 (भाग), 173 (भाग), 174 (भाग), 175 (भाग), 176 से 251 252 (भाग), 253 (भाग), 255 (भाग), 257 (भाग), 260 (भाग) 261 से 295, 296 (भाग) 297 (भाग), 320 (भाग), 321 से 369, 370 (भाग), 424 (भाग), 430(भाग), 431 (भाग) 436 (भाग) 437 438 (भाग) 439 (भाग) 440 (भाग), 441 से 449, 451 (भाग), 452, 453, 454 (भाग), 459 (भाग) 466 (भाग), 467, 468(भाग), 469 से 524, 525 (भाग)' 533(भाग), 534(भाग), 535(भाग), 536(भाग), 537 से 566, 567 (भाग), 568' 569, 570, 571 (भाग), 573(भाग), 580(भाग), 581 से 589, 590 (भाग), 591, 592, 593(भाग), 594 से 602, 603(भाग), 604(भाग), 605(भाग), 606 से 609, 617 (भाग), 618 (भाग), 662(भाग), 663(भाग), 1160 (भाग), 1161(भाग), 1162(भाग), 1163(भाग), 1164(भाग) और 1168 (भाग) ।

सीमा वर्णन

क—ख	रेखा चलकरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 4172 और 1573 से होती हुई झुझको ग्राम के प्लाट संख्यांक 1, 21, 16, 21, 20, 21, 29, 30, 149, 60, 57, 48, 1160, 92 1168, 105, 106 107 और 108 से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।
ख—ग	रेखा झुझको ग्राम के प्लाट संख्यांक 115, 253 252, 255, 260, 257, 297, 296, 320 1164, 1163, 603, 604, 617, 605, 618, 593, 590, 580, 573, 571, 567, 662 और 663 से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।
ग—घ	रेखा झुझको ग्राम के प्लाट संख्यांक 663, 533, 534 535, 536, 525' 466, 468, 1162, 454, 459, 454, 451 और 454 से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित अगवाली ब्लाक की भागत सम्मिलित सीमा बनाती है] और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।
घ—ङ	रेखा दामोदर नदी के भागत वाए किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।
ङ—क	रेखा झुझको ग्राम के प्लाट संख्यांक 440, 439, 438, 439 436, 431, 1161, 830, 1161, 424, 370, 1160, 172, 173, 174, 175, 168, 162, 168, 160 159, 160, 154, 153, 2 और 1 से होती हुई फिर चलकरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 1573 4172 1573 4172 2956 और 4172 से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित चलकरी ब्लाक विस्तार की भागत सम्मिलित सीमा बनाती है] और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

उप-ब्लाक 5 सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र एकड	टिप्पणियां
1	अगवाली	पेटरवार	51	गिरीडीह	40 00	भाग

कुल क्षेत्र—40 00 एकड़ (लगभग)
या 16 19 हैक्टर (लगभग)

अगवाली ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 169(भाग), 170(भाग) 171 से 174, 175(भाग)- 182 (भाग), 184(भाग), 185 से 191, 192(भाग), 194(भाग), 195, 196 (भाग) 197, 198(भाग), 199, 200(भाग), 202(भाग), 204, 254(भाग), 255(भाग), 256(भाग), 257, 258, 259, 260 (भाग), 261 से 282 283(भाग), 284(भाग), 285(भाग), 288 (भाग), 289(भाग) 290, 291, 292(भाग), 303(भाग), 307(भाग), 309(भाग), 376(भाग), 379(भाग), 380(भाग), 383(भाग), 384 से 393, 394(भाग) और 395(भाग),

सीमा वर्णन

क—ख	रेखा अगवाली ग्राम के प्लाट संख्यांक 170 169 184, 175, 184 182, 192, 194 से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित अगवाली ब्लाक की भागत सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ख" पर मिलती है
ख—ग	रेखा अगवाली ग्राम के प्लाट संख्यांक 204, 202, 196, 198, 200, 254, 255, 356, 309 307, 260, 307, 283, 284, 303, 285, 288, 289, 292 379 376, 380, 383, 394 और 395 से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।
ग—घ—क	रेखाए खजो नदी के भागत वाए किनारे के साथ-साथ जाती है, (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित नदीगर्भ की भागत सम्मिलित सीमा बनाती है) और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

उप-ब्लाक VI सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र एकड	टिप्पणियां
1	खेरो	पेटरवार	50	गिरीडीह	400 35	भाग
2	पिछरी	"	49	"	1584 65	"

कुल क्षेत्रफल 1985 00 एकड़ (लगभग)
या 803 20 हैक्टर (लगभग)

खेरो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

2, 3, 4 (भाग), 5, 6, 7 (भाग), 8 से 16, 17 (भाग), 18 (भाग), 20 (भाग), 26 (भाग), 45 (भाग) 46, 47 (भाग), 48 से 256, 257, (भाग), 258 (भाग), 259, 260 (भाग) 261 (भाग), 263 (भाग) 265 (भाग), 286(भाग), 289 (भाग), 291, 293 (भाग), 294 (भाग), 295 (भाग), 300 (भाग), 301 से 305, 306 (भाग), 307 से 327, 328 (भाग) 329 (भाग), 330 (भाग), 347 (भाग), 348, 349 (भाग), 350 (भाग), 351 से 380, 381 (भाग), 383(भाग), 463 (भाग), 540 (भाग), 541, 542 (भाग), 543 (भाग), 544, 545, 546 (भाग), 550 (भाग)

551 से 577, 578 (भाग), 579 से 584, 585 (भाग), 586 से 596, 597 (भाग), 598 (भाग), 605 और 607

पिछरी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

2, 6, 8 से 496, 497 (भाग), 498 से 530, 531 (भाग), 532 (भाग), 554 (भाग), 571 (भाग), 572, 573 574 (भाग) 575, 576, 577 (भाग), 587 (भाग), 588 से 615, 616 (भाग), 617 (भाग), 618 (भाग), 619 (भाग), 620 (भाग), 621 (भाग), 623 (भाग), 624, 625 (भाग), 626 से 838, 839 (भाग), 840 (भाग), 841 (भाग), 842 (भाग), 843, (भाग), 844 से 847, 848 (भाग). 849 से 949, 950 (भाग), 951, 952 (भाग), 955 (भाग), 956 (भाग), 957, 958, 959 (भाग), 961 (भाग), 962 से 967, 968 (भाग), 969 (भाग), 971 (भाग), 972 (भाग), 973 (भाग), 974 (भाग), 1158 (भाग), 1160 (भाग), 1164 (भाग), 1165 (भाग), 1166 से 1170, 1171 (भाग), 1177 (भाग), 1178, 1179 (भाग), 1185 (भाग), 1186 (भाग), 1187 (भाग), 1188 (भाग) 1434 (भाग), 1443, 1444 (भाग), 1445, 1446, 1447 (भाग), 1448 से 1489, 1490 (भाग), 1491, 1492, 1493, 1494 (भाग), 1495 (भाग), 1496 (भाग), 1497 (भाग), 1498 (भाग), 1499 (भाग), 1500, 1501, 1502 (भाग), 1504 (भाग), 1513 (भाग), 1719 (भाग), 1720 से 1727, 1728 (भाग), 1729, 1730 (भाग), 1731 से 1733, 1734 (भाग), 1739 (भाग), 1754 (भाग), 1755 (भाग), 1756, 1757 (भाग), 1758 (भाग), 1759 (भाग), 1790 (भाग), 1791 (भाग), 1807 (भाग), 3304 (भाग), 3310 (भाग), 3311 (भाग), 3312 (भाग), 3313 (भाग), 3315 से 3327, 3328 (भाग), 3329, 3330 (भाग), 3331 (भाग), 3332 (भाग), 3333 (भाग), 3340 (भाग), 3553 (भाग), 3556 (भाग), 3559 (भाग), 3560 (भाग), 3561 से 3574, 3575 (भाग), 3576, 3577, 3578 (भाग), 3579 (भाग), 3580 से 3586, 3587 (भाग), 3588, 3589, 3590, 3591, 3592 (भाग), 3594 (भाग), 3595 (भाग), 3596 (भाग), 3598 (भाग), 3606 (भाग), 3665 (भाग), 3666, 3667, 3668, 3670 (भाग), 3672 (भाग), 3678 (भाग), 3687 (भाग), 3688 (भाग), 3689 (भाग), 3690, 3691, 3692, 3693 (भाग), 3694 से 3703, 3704 (भाग), 3705 से 3709, 3710 (भाग), 3711 (भाग), 3717 (भाग), 3718 (भाग), 3719 (भाग), 3720 से 3742, 3743 (भाग), 3744 (भाग), 3645 (भाग), 3746 से 3754, 3755 (भाग), 3756 से 3764, 3765 (भाग), 3766 (भाग), 3769, 3914 (भाग), 3915 (भाग), 3929 (भाग), 3930 (भाग), 3931 (भाग), 3932 (भाग), 3940 (भाग), 3941 (भाग), 3947 (भाग), 4266, 4267, 4268, 4280 (भाग), 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4318, 4321, 4322, 4323 और 4324

सीमा वर्णन :—

क-ख-ग रेखाएं पिछरी ग्राम की खंजो नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ होती हुई फिर खेरो ग्राम की खंजो नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग-घ-ङ रेखाएं खेरो ग्राम के प्लाट संख्यांक 26, 4, 7, 17, 18, 20, 17, 45, 47, 258, 263, 260, 261, 258 257, 265, 289, 293, 306, 286, 294, 295, 306, 300, 328, 329, 330, 350, 349, 347, 381, 543, 383, 463 और 540 से होकर जाती हैं और बिन्दु "क" पर मिलती हैं ।

ङ-च रेखा खेरो ग्राम के प्लाट संख्यांक 340, 542, 546 550, 585, 578, 585, 598, और 597 से होती हुई फिर पिछरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 3947, 3940, 3932, 3931, 3930, 3929, 3914, 3925, 3765, 3766 से होकर जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है ।

च-छ-ज-झ रेखाएं पिछरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 3766, 3310, 3766, 3311, 3313, 3312, 3766, 3304, 3328, 3330, 3233, 3332, 3333, 3331, 3340, 3560, 3575, 3553, 3559, 3575, 3556, 3598, 3606, 3594, 3596, 3595, 3594, 3592, 3587, 3579, 3578, 3755, 3745, 3755, 3744, 3743, 3672, 3665, 3672, 3670, 3672, 3678, 3693, 3688 और 3687 से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है ।

झ-ञ-ट-ठ-ड-ढ रेखाएं पिछरी ग्राम के प्लाट संख्यांक 3687, 3688, 3689, 3710, 3704, 3710, 3711, 3710, 3718, 3710, 3717, 973, 974, 972, 971, 968, 969, 3719, 961, 959, 956, 955, 952, 950, 1160, 1158, 1160, 848, 848, 842, 841, 840, 839, 1160, 1164, 1165, 1171, 1177, 1179, 1185, 1186, 1187, 1188, 623, 625, 621, 620, 618, 610, 617, 616, 587, 1160, 577, 574, 571, 554, 531, 532, 497, 1444, 1447, 4270, 1434, 1490, 1434, 1728, 1730, 1734, 1939 1754, 1755, 1757, 1791, 1759, 1807, 1790, 1739, 1758, 1719, 1513, 1494, 1595, 1496, 1497, 1498, 1499, 1502 और 1504 से होकर जाती है और बिन्दु "ढ" पर मिलती है ।

ढ-क रेखा पिछरी ग्राम की दामोदर नदी के भागतः दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19/110/81-सी०एल०]

स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 1982

S.O. 1192.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S. O. 1406, dated the 6th March, 1981 and published in the Gazette of India, Part-II—Section 3, sub-section (ii), dated the 9th May, 1981, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 3650.00 acres ,approximately or 1477.10 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the part of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire —

(a) the land measuring 45.00 acres (approximately) or 18.21 hectares (approximately) in sub-block I/A, 5.00 acres (approximately) or 2.02 hectares (approximately) in sub-block I/B, 472.00 acres (approximately) or 191.00 hectares (approximately) in sub-blocks II/A, 605.00 acres (approximately) or 244.82 hectares (approximately) in sub-block III/A, 430.00 acres (approximately) or 174.01 hectares (approximately) in sub-block IV, 40.00 acres (approximately) or 16.19 hectares (approximately) in sub-block V, and 1985.00 acres (approximately) or 803.29 hectares (approximately) in sub-block II/B and 20.00 schedule 'A' appended hereto; and

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the land measuring 8.00 acres (approximately) or 3.24 hectares (approximately) in sub-block II|B and 20.00 acres (approximately) or 8.09 hectares (approximately) described in schedule 'B' appended hereto;

Note 1 : The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows :-

Objection to acquisition :—

"8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation :—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objection an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the said Act.

SCHEDULE

Kargali Extension
Sub-block I, II, III, IV, V & VI
East Bokaro Coalfield
District Hazaribagh and Giridih (Bihar)

Drg. No. Rev/61/81
Dated 20-6-81
(Showing lands to be acquired).

Sub-Block-I/A All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area in acres	Remark
1.	Bermo	Nawadih (Bermo)	18	Giridih	25.00	part
2.	Jaridih	-do-	19	-do-	20.00	-do-
		Total area :—45.00 acres (approximately) or :—18.21 hectares (approximately)				

Plot numbers to be acquired in village Bermo:—216 (part), 217 to 220, 221 (part), 222 (part), 223, 224 (part) 225, 226, 227 (part), 228 (part) & 230 (part).

Plot numbers to be acquired in village Jaridih:—21 (part), 22 (part), 23, 24, 25, 26 (part), 27 (part), 252 (part), 255 (part), 57 to 265, 266 (part), 268 (part), 269 (part), 278 (part), 279, 280 (part), 281 (part), 283 (part), 284, 285, 286, 287 (part), 288 (part), 289, 290 (part), 327 (part), 655 (part), 656 (part), 657, 658 (part), 672 (part), 673, 674 (part), 675, 676, 677 (part), 693 (part), 694, 695 (part), 697 (part), 698 (part), 699 (part), 700 (part), 701 (part), 705 and 721 (part).

Boundary description:—

A-B lines passes through plot number 221 in village Bermo and meets at point 'B'.

B-C-D-E lines pass through plot numbers 221 and 216 in village Bermo through plot numbers 26, 21,22, 26,27, 26, 256, 252, 266, 269, 268, 327, 280, 278, 281, 283, 290, 693, 700, 677, 672, 658, 655 of village Jaridih (which forms common boundary with the existing Railway acquired boundary) and meets at point 'E'.

E-F line passes through plot numbers 656 and 721 of village Jaridih (which forms common boundary with Bokaro Colliery) and meets at point 'F'.

F-A line passes along the southern boundary of plot number 720 through plot numbers 672, 674, 701, 699, 698, 697, 695, 290, 288, 287, of village Jaridih, then through plot numbers 228, 227, 230, 224, 222, 230 and 221 (which forms part common boundary with sub-block A of Karo Block acquired u/s 9(1) of the Coal Act of village Bermo and meets at starting point 'A'.

Sub-Block-I/B All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area in acres	Remark
1.	Bermo	Nawadih (Bermo)	18	Giridih	1.90	Part
2.	Jaridih	-do-	19	-do-	3.10	-do-
		Total Area:—5.00 acres (approximately) or 2.02 hectares (approximately)				

Plot numbers to be acquired in village Bermo:—208 (part), 209, 210 (part) and 211 (part).

Plot numbers to be acquired in village Jaridih:—1 to 4, 8(part), 9 (part), 10, 11, 12 (part), 13 (part) & 26 (part).

Boundary description:—

G-H line passes along the part of left bank of Kunar River and meets at point 'H'.

H-I-J lines pass along part of northern boundary of plot number 6 through plot numbers 8, 9, 12 and 13 of village Jaridih (which forms common boundary with the existing Railway acquired boundary) and meets at point 'J'.

J-G line passes through plot numbers 13 and 26 of village Jaridih through plot numbers 210, 211 and 208 of village Berm (which forms common boundary with the existing Railway boundary) and meets at starting point 'G'.

Sub-Block II/A All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area in acres	Remarks
1.	Phusro	Nawadih (Bermo)	67	Giridih	324.50	Part
2.	Dhorhi	-do-	68	-do-	147.50	-do-
		Total area:—472.00 acres (approximately) or 191.00 hectares (approximately)				

Plot numbers to be cquired in village Phusro:—

61 (part), 67 to 74, 75 (part), 76 (part), 77 to 80, 81 (part), 82 (part), 83 (part), 419 (part), 422 (part), 425 (part), 426 (part), 427, 428 (part), 429 (part), 431 (part), 433 (part), 434 to 445, 446 (part), 447, 448, 449, 450 (part), 453 (part), 454 to 464, 465 (part), 466 (part), 467 (part), 468 (part), 473 (part), 477 (part), 478 to 483, 484 (part), 485 (part), 487 (part), 488, 489 (part), 555, 556 (part), 557 (part), 558 (part), 559, 560, 561 (part), 562 to 574, 575 (part), 576 (part), 577 to 580, 581, (part), 582 to 594, 603 (part), 604, 605, 610 (part), 612, 613, 614 (part), 615, 644 (part), 645, 646 (part), 648 to 668, 669 (part), 670 (part), 671 (part), 704 (part), 705 to 724 725 (part), 726 (part), 727 (part), 728 (part), 760 to 790, 792 to 798, 811 (part), 812 (part), and 813.

Plot numbers to be acquired in village Dhorhi:—
353 (part) and 940 (part).

Boundary description:—

A-B line passes through plot numbers 82, 61, 811, 603, 811, 610, 811, 644, 811, 644, 646, 811, 646, 811, 812, 671, 669, 704, 726, 727, 725, 728 and 812 of village Phusro (which forms part common boundary of Chalkari Block Extn. (sub-block-II) and meets at point 'B'.

B-C line passes along the part of left bank of Damodar River of village Phusro and Dhori and meets at point 'C'.

C-B line passes through plot number 1349 and part western boundary of plot number 1312 along the southern boundary of plot number 1319 along the northern boundary of plot number 1318 and along common boundary of plot number 940 and 1303 and through plot numbers 940 and 353 of village Dhorhi (which forms part common boundary of Dhorhi Block acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'D'.

D-E line passes through plot number 353 of village Dhorhi (which forms part surface rights boundary of Dhorhi Colly.) and meets at point 'E'.

E-F line passes along the part of common boundary of village Phusro & Dhorhi (which forms part surface rights boundary of Dhorhi Colliery) and meets at point 'F'.

F-A line passes through plot numbers 561, 556, 561, 557, 556, 446, 489, 487, 485, 473, 484, 477, 465, 466, 467, 468, 453, 450, 446, 433, 431, 428, 429, 426, 419, 422, 425, 83, 75, 76, 83, 81 & 82 of village phusro (which forms part common boundary with Kargali Colly.) and meets at starting plont 'A'.

Sub-Block-II/B Mining Rights

Sl No.	Village	Thana	Thana number	District	Area in acres	Remarks
1.	Dhorhi	Nawadih (Bermo)	68	Giridih	8.00	part

Total area:—8.00 acres (approximately)
or 3.24 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Dhorhi :—352 (part) & 353 (part).

Boundary description:—

F-E line passes along the part of common boundary of village Phusro & Dhorhi and (forms common boundary with sub-block II/A) and meets at point 'E'.

E-D line passes through plot number 353 of village Dhorhi (which forms common boundary of with sub-block II/A) and meets at point 'D'.

D-G line passes through plot number 353 along part eastern boundary of plot number 352 of village Dhorhi (which forms part common boundary of Dhorhi Block acquired u/s 9 (1) of the Coal Act) and meets at point 'G'.

G-F line passes at through plot numbers 352 and 353 of village Dhorhi (which forms part common boundary of Kargali Colly.) and meets at starting point 'A'.

Sub-Block-III/A All Rights

Sl No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area in acres	Remarks
1.	Dhorhi	Nawadih (Bermo)	68	Giridih	605.00	part

Total Area:—605.00 acres (approximately)
or 244.82 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Dhorhi:—353 (part), 672 (part), 699 (part), 700 (part), 701 (part), 702, 703 (part), 704 to 709, 710 (part), 711, 712 (part), 714 (part), 715 (part), 716, 717 (part), 729 (part), 762 (part), 765 (part), 766 (part), 767 (part), 769 (part), 792 (part), 793 (part), 794 (part), 795, 796 (part), 798 (part), 799, 800 to 834, 836, 838 to 855, 856 (part), 857 (part), 858 (part), 859 to 877, 898 (part), 879 (part), 880 (part), 881, 882 (part), 885 (part), 888 (part), 889 to 931, 940 (part), 941 to 1280, 1288 to 1299, 1301, 1322 to 1343, 1391 to 2024, 2025 (part), 2026 (part), 2027 (part), 2028 (part), 2096 (part), 2204 (part), 2206 (part), 2207 (part), 2208 to 2214, 2215 (part), 2216 to 2255, 2256 (part), 2257 (part), 2258 to 2284, 2285 (part), 2288 to 2290, 2291 (part), 2292 to 2304, 2305 (part), 2306 to 2308, 2309 (part), 2310 (part), 2313 (part), 2333 (part), 2381 (part), 2382 (part), 2383 (part), 2384 (part), 2406 to 2408, 2409 (part), 2410 to 2414, 2415 (part), 2416 (part), 2417, 2418 (part), 2420 (part), 2498 (part), 2499, 2500, 2501 (part), 2502 (part), 2503 (part), 2504 (part), 2505 (part), 2506 to 2508, 2509 (part), 2510, 2511 (part), 2521 (part), 3189 (part), 3190 (part), 3191 to 3206, 3208 (part), 3209, 3210 (part), 3211 to 3227, 3229, 3232, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241 and 3245.

Boundary Description:—

A-B line passes through plot numbers 353, 940 and northern boundary of plot numbers 940, 1321, 1308, 1302, 1300, 1304, 1287, 1283, 1282 and 1281, western boundary of plot numbers 1300, 1304, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283 and 1281 of village Dhorhi (which forms part common boundary of Dhorhi Block acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'B'.

B-C line passes along the part of left bank of Damodar River of village Dhorhi and meets at point 'C'.

C-D line passes through plot numbers 3189, 3208, 3189, 3210, 3189, 3190, 3189, 2333, 2285, 2291, 2313, 2309, 2305, 2310, 2381, 2382, 2383, 2384 northern boundary of plot number 2406 through plot numbers 2409, 2415, 2416, 2420, 2418, 2257, 2256, 2498, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2511, 2215, 2521, 2207, 2206, 2204, 2096, 2215, 2026, 2075, 2027, 2028, 2027, 672, 701, 700, 699, 700, 703, 710, 712, 714, 715, 717, 729, 792, 793, 794, 796, 798, 769, 767, 762, 766, 765, 857, 856, 858, 878, 879, 880, 882, 885, 888 and 353 of village Dhorhi (which forms common boundary with Dhorhi Colly.) and meets at point 'D'.

D-E-F-G-A lines pass through plot number 353 of village Dhorhi and meets at starting point 'A'.

Sub-Block-III/B Mining Rights

Serial No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area in acres	Remarks
1.	Dhorhi	Nawadih (Bermo)	68	Giridih	20.00	part
		Total area:—20.00 acres (approximately) or 8.09 hectares (approximately)				

Plot numbers to be acquired in village Dhorhi:—353 (part), 457 (part), 458 (part), 460 (part), 582 to 586, 587 (part).

Boundary description:—

H-A line passes through plot number 353 of village Dhorhi (which forms part common boundary of Dhorhi block acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'A'.

A-G-F-E lines pass through plot number 353 of village Dhorhi and meets at point 'E'.

E-I line passes through plot numbers 353, 587, 353, 458, 457, 458, 460 and 353 of village Dhorhi (which forms common boundary with Dhorhi Colly.) and meets at point 'I'.

I-H line passes through plot number 353 of village Dhorhi and meets at starting point 'H'.

Sub-Block-IV All Rights

Serial No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area in acres	Remarks
1.	Chalkari	Petarbar	46	Giridih	9.50	part
2.	Jhujhko	-do-	48	-do-	420.50	-do-
		Total area:—430.00 acres (approximately) or 174.01 hectares (approximately)				

Plot numbers to be acquired in village Chalkari:—1573 (part), 2555, 2556 (part) and 4172 (part).

Plot numbers to be acquired in village Jhujhko:—1 (part), 2 (part), 3 to 15, 16 (part), 20 (part), 21 (part), 22 to 28, 29 (part) 30 (part), 48 (part), 49 to 56, 57 (part), 58, 59, 60 (part), 61 to 91, 92 (part), 93 to 104, 105 (part), 106 (part), 107 (part) 108 (part), 115 (part), 116 to 148, 149 (part), 150, 151, 152, 153 (part), 154 (part), 155 to 158, 159 (part), 160 (part), 162 (part), 163 to 167, 168 (part), 172 (part), 173 (part), 174 (part), 175 (part), 176 to 251, 252 (part), 253 (part), 255 (part) 257 (part), 260 (part), 261 to 295, 296 (part), 297 (part), 320 (part), 321 to 369, 370 (part), 424 (part), 430 (part) 431 (part), 436 (part), 437, 438 (part), 439 (part), 440 (part), 441 to 449, 451 (part), 452, 453, 454 (part), 459 (part), 466 (part), 467, 468 (part), 469 to 524, 525 (part), 533 (part), 534 (part), 535 (part), 536 (part), 537 to 566, 567 (part), 568, 569, 570, 571 (part), 573 (part), 580 (part), 581 to 589, 590 (part), 591, 592, 593 (part), 594 to 602, 603 (part), 604 (part), 605 (part), 606 to 609, 617 (part), 618 (part), 662 (part), 663 (part), 1160 (part), 1161 (part), 1162 (part), 1163 (part), 1164 (part) and 1168 (part).

Boundary description :—

A–B line passes through plot numbers 4172 & 1573 of village Chalkari, through plot numbers 1, 21, 16, 21, 20, 1, 20, 30, 149, 60, 57, 48, 1160, 92, 1168, 105, 106, 107 & 108 of village Jhujhko and meets at point 'B'.

B–C line passes through plot numbers 115, 253, 252, 255, 260, 257, 297, 296, 320, 1164, 1163, 603, 604, 605, 617, 618, 593, 590, 580, 573, 571, 567, 662 and 663 of village Jhujhko and meets at point 'C'.

C–D line passes through plot numbers 663, 533, 534, 535, 536, 525, 466, 468, 1162, 454, 459, 454, 451 and 454 of village Jhujhko (which forms part common boundary of Angwali Block acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'D'.

D–E line passes along the part right bank of Damodar River and meets at point 'E'.

E–A line passes through plot numbers 440, 439, 438, 439, 436, 431, 1161, 430, 1161, 424, 370, 1160, 172, 173, 174, 175, 168, 162, 168, 160, 159, 160, 154, 153, 2 and 1 of village Jhujhko, then through plot numbers 1573, 4172, 1573, 4172, 2556 and 4172 of village Chalkari (which forms part common boundary of Chalkari Block Extn. acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at starting point 'A'.

Sub-Block-V All Rights

S. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area in acres	Remarks
1.	Angwali	Petarbar	51	Giridih	40.00	part
		Total area :— 40.00 acres (approximately) or 16.19 hectares (approximately)				

Plot numbers to be acquired in village Angwali :—169 (part), 170 (part), 171 to 174, 175 (part), 182 (part), 184 (part), 185 to 191, 192 (part), 194 (part), 195, 196 (part), 197, 198 (part), 199, 200 (part), 202 (part), 204, 254 (part), 255 (part), 256 (part), 257, 258, 259, 260 (part), 261 to 282, 283 (part), 284 (part), 285 (part), 288 (part), 289 (part), 290, 291, 292 (part), 303 (part), 307 (part), 309 (part), 376 (part), 379 (part), 380 (part), 383 (part), 384 to 393, 394 (part), and 395 (part).

Boundary description :—

A–B line passes through plot numbers 170, 169, 184, 175, 184, 182, 192, 194 of village Angwali (which forms part common boundary of Angwali Block acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'B'.

B–C line passes through plot numbers 204, 202, 196, 198, 200, 254, 255, 256, 309, 307, 260, 307, 283, 284, 303, 285, 288, 289, 292, 379, 376, 380, 383, 394 and 395 of village Angwali and meets at point 'C'.

C–D–A lines pass along the part of left bank of River Khanjo (which forms part of common boundary of River Bed acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at starting point 'A'.

Sub-Block-VI All Rights :

S. No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area in acres	Remarks
1.	Khero	Petarbar	50	Giridih	400.35	part.
2.	Pichhri	-do-	49	-do-	1583.65	-do-
		Total area :— 1985.00 acres (approximately) or 803.29 hectares (approximately)				

Plot numbers to be acquired in village Khero : –1, 2, 3, 4 (part), 5, 6, 7 (part), 8 to 16, 17 (part), 18 (part), 20 (part), 26 (part), 45 (part), 46, 47 (part), 48 to 256, 257 (part), 258 (part), 259, 260 (part), 261 (part), 263 (part), 265 (part), 286 (part), 289 (part), 291, 293 (part), 294 (part), 295 (part), 300 (part), 301 to 305, 306 (part), 307 to 327, 328 (part), 329 (part), 330 (part), 347 (part), 348, 349 (part), 350 (part), 351 to 380, 381 (part), 383 (part), 463 (part), 540 (part), 541, 542 (part), 543 (part), 544, 545, 546 (part), 550 (part), 551 to 577, 578 (part), 579 to 584, (part), 586 to 596, 597 (part), 598 (part), 605 & 607.

Plot numbers to be acquired in village Pichhri :—2 to 6,8 to 496, 497 (part), 498 to 530, 531 (part), 532 (part), 554 (part), 571 (part), 572, 573, 574 (part), 575, 576, 577 (part), 587 (part), 588 to 615, 616 (part), 617 (part), 618 (part), 619 (part), 620 (part), 621 (part), 623 (part), 624, 625 (part), 626 to 838, 839 (part), 840 (part), 841 (part), 842 (part), 843 (part), 844 to 847, 848 (part), 849 to 949, 950 (part), 951, 952 (part), 955 (part), 956 (part), 957, 958, 959 (part) 961 (part), 962 to 967, 968 (part), 969 (part), 971 (part), 972 (part), 973 (part), 974 (part), 1158 (part), 1160 (part), 1164 (part), 1165 (part), 1166 to 1170, 1171 (part), 1177 (part), 1178, 1179 (part), 1185 (part), 1186 (part), 1187 (part), 1188 (part), 1434 (part), 1443, 1444 (part), 1445, 1446, 1447 (part), 1448 to 1489, 1490 (part), 1491, 1492, 1493, 1494 (part), 1495 (part), 1496 (part), 1497 (part), 1498 (part), 1499 (part), 1500, 1501, 1502 (part), 1504 (part), 1513 (part), 1719 (part), 1720 to 1727, 1728 (part), 1729, 1730, (part), 1731 to 1733, 1734 (part), 1739 (part), 1754 (part), 1755 (part), 1756, 1757 (part), 1758 (part), 1759 (part), 1790 (part) 1791 (part), 1807 (part), 3304 (part), 3310 (part), 3311 (part), 3312 (part), 3313 (part), 3315 to 3327, 3328 (part), 3329, 3330 (part), 3331 (part), 3332 (part), 3333 (part), 3340 (part), 3553 (part), 3556 (part), 3559 (part), 3560 (part), 3561 to 3574, 3575 (part), 3576, 3577, 3578 (part), 3579 (part), 3580 to 3586, 3587 (part), 3588, 3589, 3590, 3591, 3592 (part), 3594 (part), 3595 (part), 3596 (part), 3598 (part), 3606 (part), 3665 (part), 3666, 3667, 3668, 3670 (part), 3672 (part), 3678 (part), 3687 (part), 3688 (part), 3689 (part), 3690, 3691, 3692, 3693 (part), 3694 to 3703, 3704 (part), 3705 to 3709, 3710 (part), 3711, (part), 3717 (part), 3718 (part), 3719 (part), 3720 to 3742, 3743 (part), 3744 (part), 3745 (part), 3746 to 3754, 3755 (part), 3756 to 3764, 3765 (part), 3766 (part), 3769, 3914 (part), 3915 (part), 3929 (part), 3930 (part), 3931 (part), 3932 (part), 3940 (part), 3941 (part), 3947 (part), 4266, 4267, 4268, 4270 (part), 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4318, 4321, 4322, 4323, and 4324.

Boundary description :—

A–B–C	lines pass along the right back of River Khanjo of village Pichhri, then along the part right bank of River Khanjo of village Khero and meets at point 'C'.
C–D–E	lines pass through plot numbers 26, 4, 7, 17, 18, 20, 17, 45, 47, 258, 263, 260, 261 258, 257, 265, 289, 293, 306, 286, 294, 295, 306, 300, 328, 329, 330, 350, 349, 347, 381, 543, 383, 463 and 540 of village Khero and meets at point 'E'.
E–F	line passes through plot numbers 540, 542, 546, 550, 585, 578, 585, 598 and 597 of village Khero then through plot numbers 3947, 3940, 3982, 3931, 3930, 3929, 3932, 3914, 3915, 3765, 3766 of village Pichhri and meets at point 'F'.
F–G–H–I	lines pass through plot numbers 3766, 3310, 3766, 3311, 3313, 3312, 3766, 3304, 3328, 3330, 3333, 3332, 3333, 3331, 3340, 3560, 3575, 3553, 3559, 3575, 3556, 3598, 3606, 3594, 3596, 3595, 3594, 3592, 3587, 3579, 3578, 3755, 3745, 3755, 3744, 3743, 3672, 3665, 3672, 3670, 3672, 3678, 3693, 3688 and 3687 of village Pichhri and meets at point 'I'.
I–J–K–L–M–N	lines pass through plot numbers 3687, 3688, 3689, 3710, 3704, 3710, 3711, 3710, 3718, 3710, 3717, 973, 974, 972, 971, 968, 969, 3719, 961, 959, 956, 955, 952, 950, 1160, 1158, 1160, 848, 843, 842, 841, 840, 839, 1160, 1164, 1165, 1171, 1177, 1179, 1185, 1186, 1187, 1188, 623, 625, 621, 620, 618, 610, 617, 616, 587, 1160, 577, 574, 571, 554, 531, 532, 497, 1444, 1447, 4270, 1434, 1490, 1434, 1723, 1730, 1734, 1739, 1754, 1755, 1757, 1791, 1759, 1807, 1790, 1759, 1758, 1719, 1513, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1502, and 1504 of village Pichhri and meets at point 'N'.
N–A	line passes along the part right back of River Damodar of village Pichhri and meets at starting point 'A'.

[No. 19/110-81-CL]
SWARAN SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च 1982

का०आ० 1193.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में इंदौर विश्वविद्यालय ने डा० पी० एल० टंडन, डीन, महात्मा गांधी मेमोरियल कालेज, इंदौर को 29 दिसम्बर, 1981 से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय के 9 जनवरी, 1960 के एस० ओ० संख्या 138 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"33. डा० पी०एल० टंडन, एम०एस०
डीन,
महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज,
इंदौर।"

[संख्या वी० 11013/7/81-एम०ई० (पी०)]
प्रकाश चन्द्र जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 2nd March, 1982

S.O. 1193.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. P. L. Tandon, Dean, Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore, has been elected by the Indore University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 29th December, 1981;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S. O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 33 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted namely :—

'33. Dr. P. L. Tandon,
Dean,
Mahatma Gandhi Memorial Medical College,
INDORE."

[No. V. 11013/7/81-M.E. (Policy)]
P. C. JAIN, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1982

का० आ० 1194.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कम्पनी, इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कम्पनी लिमिटेड, पो० मरार, जिला हजारीबाग को, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[संख्या ई०-11011/4/81-हिन्दी]
विनेश चन्द्र बाजपेयी, निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 26th February, 1982

S.O. 1194.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies India Firebricks and Insulation Company Limited, P.O. Marar, Distt. Hazaribagh of Bharat Refractories Limited, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[E-11011/4/81-Hindi]
D. C. BAJPAI, Director

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 5 मार्च 1982

(पुरातत्व)

का० आ० 1195.—केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 18 जुलाई, 1981 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 1953 तारीख 30 जून, 1981 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त प्राचीन स्थल का राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त अधिसूचना की एक प्रति उक्त प्राचीन स्थल के पास सहजदृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 21 अगस्त, 1981 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सम्यक्तः विचार कर लिया है;

अतः केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त प्राचीन स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	सम्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले सर्वेक्षण प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	कालाहांडी	नरला	असुरगढ़	असुरगढ़ किले का प्राचीन स्थल, जो सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 207, 208 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 और 210/511 में अन्तर्विष्ट है।	सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 और 210/511.

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणी
7	8	9	10
41.22 एकड़	उत्तर :– सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 206,203,201, और 276 पूर्व : –सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 276 दक्षिण –सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 519, 270 और 269. पश्चिम.– सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 260, 256, 257, 520 और 205	सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 207, 212, 213, 229, 233, और 254, सरकार के स्वामित्व में हैं और शेष प्लाट संख्यांक प्राइवेट स्वामित्व में है।	

[सं० 2/8/73-स्मा०]

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 5th March, 1982

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 1195.—Whereas by the notification of the Government of India in the Department of Culture No. S. O. 1953 dated the 30th June, 1981 published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 10th July, 1981, the Central Government gave two months notice of its intention to declare the said ancient site, specified in the Schedule to the said notification, to be of national importance, and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient site as required in sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas, the Gazette copies of the said notification were made available to the public on the 21st August, 1981;

And whereas, the objection received from the public has been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeology Sites and Remains Act, 1958, the Central Government hereby declares the said ancient sites specified in the Schedule below to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of site	Revenue plot number included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Orissa	Kala-handi	Narla	Asurgarh	Ancient site of Asurgarh Fort comprising in survey plot Nos. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 and 210/511	Survey plot Nos. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 and 210/511	41.22 Acres	North:—Survey plot Nos. 206, 203, 201 nad 276 East:—Survey plot No. 276 South:—Survey plot Nos. 519, 270 and 269 West:—Survey plot Nos. 260, 256, 257, 520 and 205	Survey plot Nos. 207, 212 213, 229, 233 and 254 are Government owned and remaining plot number are unders private ownership	

[No. 2/8/73-M]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1982

(पुरातत्व)

का० आ० 1196.—केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 दिसम्बर, 1981 में प्रकाशित, भारत सरकार के संस्कृति विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 3472, तारीख 7 दिसम्बर, 1981 द्वारा, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) में यथापेक्षित उक्त अधिसूचना की एक प्रति को उक्त प्राचीन स्थल के पास सहज दृश्य स्थान पर चिपका दिया गया था ;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 फरवरी 1982 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

अतः केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले सर्वेक्षण प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
केरल	पालघाट	ओट्टापलम	पट्टाम्बी	सपार्श्विक क्षेत्र सहित, नेल्लिसगलम् स्थित शिव मंदिर, जो सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/1 में और भागत सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/2 और 68/3 में समाविष्ट है जैसा नीचे उद्धृत स्थल योजना में दर्शित है।	सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/1 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/2 तथा 68/3 का भाग जैसा नीचे उद्धृत स्थल योजना में दर्शित है।

क्षेत्र	सीमाएं		स्वामित्व	टिप्पणी
7	8		9	10
0 83 एकड़	उत्तर	सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/3 का अवशेष भाग।	क्रम सं० 68/1, कैथली मंदिर, क्रम सं० 68/2, कैथली देवास्वम के अधीन पट्टाधृत भूमि का भाग। क्रम सं० 68/3 कैथली देवास्वम के भूमि का भाग	शिवमंदिर में उपासना की जाती है। संरक्षित सीमाओं के भीतर कोई आधुनिक संरचना नहीं है।
	पूर्व	सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/2 का अवशेष भाग (बैलगाड़ी का ट्रेक)		
	दक्षिण	सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/2 का अवशेष भाग (बैलगाड़ी का ट्रेक)		
	पश्चिम	सर्वेक्षण प्लाट सं० 68/3 का अवशेष भाग।		

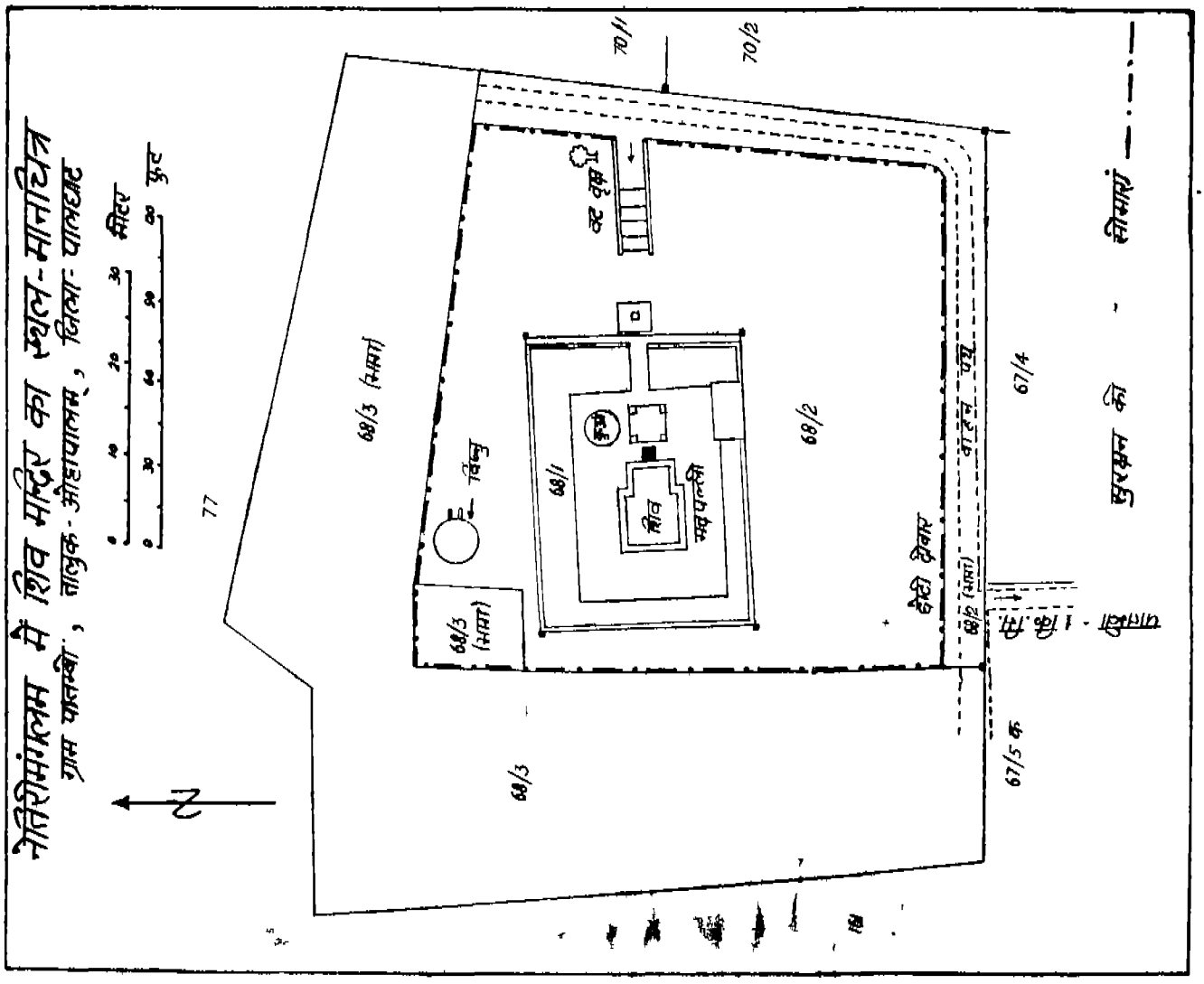

[सं० 2/36/76 स्मा०]

डा० (श्रीमती) देवला मित्र, महानिदेशक
और पदेन संयुक्त सचिव

New Delhi, the 6th March, 1981

(ARCHEOLOGY)

S.O. 1196.—Whereas by the notification of the Government of India in the Department of Culture S. O. No. 3472 dated the 7th December, 1981, published in Part II, Section 3; sub-section (ii) of the Gazette of India dated 26th December, 1981, the Central Government gave two months notice of its intention to declare the said ancient monument, specified in the Schedule to the said notification, to be of national importance, and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument as required in sub-section (i) of section 4 of the Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas no objection has been received from the public now;

And whereas, the gazette copies of the said notification were made available to the public on the 3rd February, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the Schedule below to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of Monument	Revenue plot number included under protection	Area	Boundries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kerala	Palghat	Ottapa-lam	Pattambi	Siva temple at Netrimangalam together with adjacent area comprised in Survey plot Nos. 68/1 and part of Survey plot Nos. 68/2 and 68/3 as shown in the site plan reproduced below.	Survey Plot No. 68/1 and part of Survey Plot Nos. 68/2 and 68/3 as shown in the site plan reproduced below.	0.83 acre	North:—Remaining portion of Survey Plot No. 68/3. East:—Remaining portion of Survey Plot No. 68/2 (Cart Track). South:—Remaining portion of Survey Plot No. 68/2 (Cart Track). West:—Remaining portion of Survey Plot No. 68/3.	S.No. 68/1 : Kaithali temple S. No. 68/2: Part Patta land under Kaithali Devaswom. S. No. 68/3 : Part patta land under Kaithali Devaswom	Siva temple under worship. No modern structures in the protected limits.

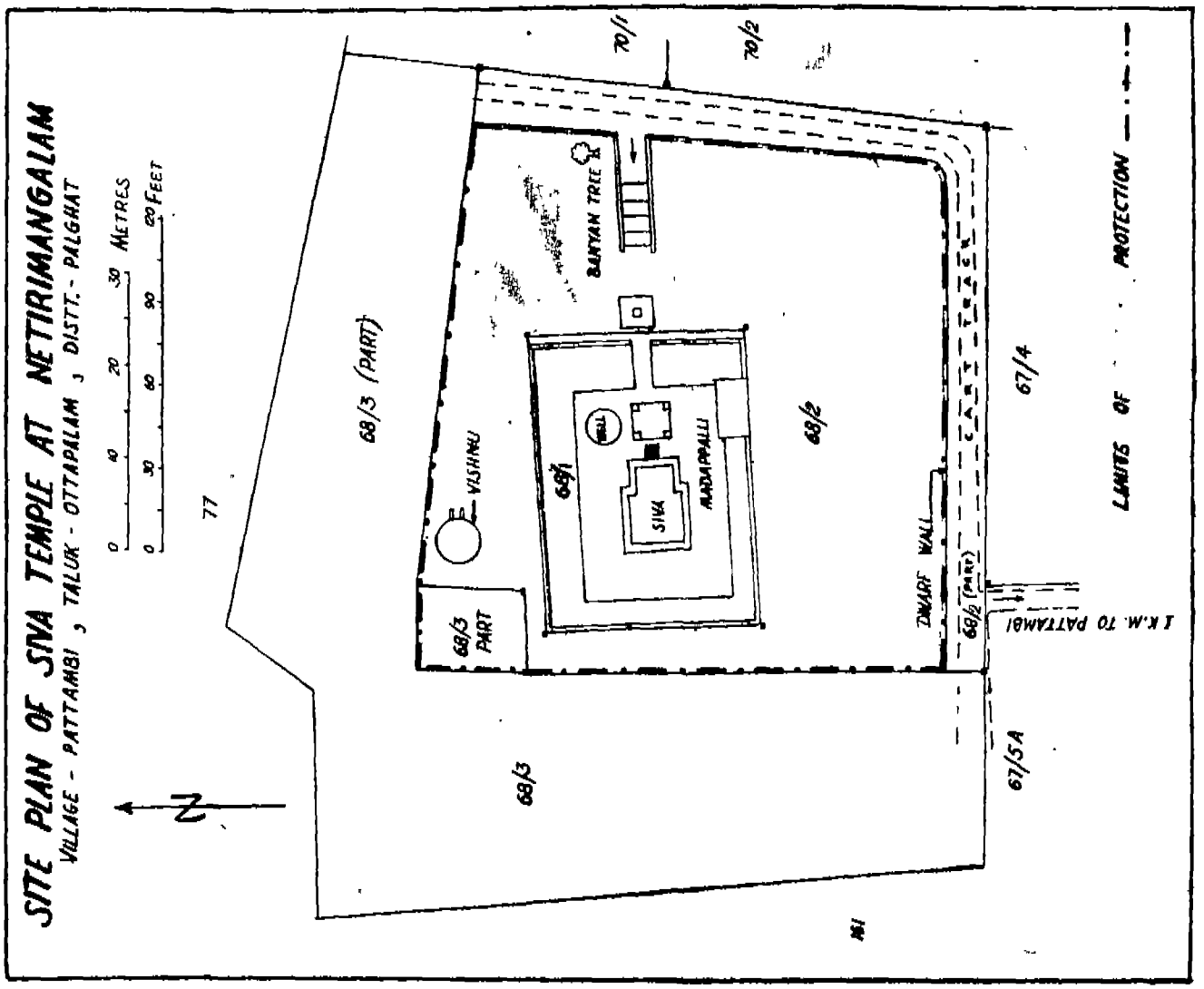

[No. 2/36/76-M]

D. MITRA, Director General and Ex-officio Joint Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1982

का०आ० 1197—नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित समुद्री व्यापार अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नौवहन विकास निधि समिति के अवर कार्यकारी निदेशक श्री अनिल वैश को, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त समिति का सदस्य नियुक्त करती है ।

[सं० एस डब्ल्यू/एम एस डी (24)/79-एमडी]
यादवेन्द्र दत्त बनकटा, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 8th March, 1982

S.O. 1197.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rule 3 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri Anil Vaish, Additional Executive Director, Shipping Development Fund Committee, as a member of the said Committee with effect from the date of the publication of this Notification in the official Gazette.

[No. SW/MSD(24)/79-MD]
Y. D. BANKATA, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1982

का०आ० 1198—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के संयुक्त सचिव श्री एन० आर० होता को, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से पुनर्वास विभाग में मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में, तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

2. इससे दिनांक 29-12-1979 की अधिसूचना सं० 1(21)/विशेष सैल/78-एस एस-2 का अधिक्रमण किया जाता है।]

[सं० 1(1)/विशेष सैल/82-एस एस 2-(क)]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 27th Februarv, 1981

S.O. 1198.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri N. R. Hota, Joint Secretary in the Department of Rehabilitation as Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Chief Settlement Commissioner by or under the said Act with immediate effect.

2. This supersedes Notification No. 1(21)/Spl. Cell/78-SS. II., dated the 29th December, 1979.

[No. 1(1)/Spl. Cell/82-SS. II.(A)]

का०आ० 1199—निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संयुक्त सचिव श्री एन० आर० होता को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत महाभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से निष्क्रांत संपत्तियों के महाभिरक्षक के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

2. इससे दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना सं० 1(21)/विशेष सैल/78-एस एस-2 का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1(1)/विशेष सैल/82-एस०एस०-2(ख)]
एन० एम० वाधवानी, अवर सचिव

S.O. 1199.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government appoints Shri N. R. Hota, Joint Secretary in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) as the Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing functions assigned to such Custodian General by or under the said Act with immediate effect.

2. This supersedes Notification No. 1(21)/Spl. Cell/78-SS.II, dated the 29th December, 1979.

[No. 1(1)/Spl. Cell/82-SS. II.(B)]
N. M. WADHWANI, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1982

का०आ० 1200—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने लाडवा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-5/82-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi, the 6th March, 1982

S.O. 1200.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960 the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-4-1982, as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Ladwa Telephone Exchange N. W. Circle.

[No. 5-5/82-PHB]

का०आ० 1201—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने हुसूर/सिपकोट टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-82 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/81-पी एच बी]

S.O. 1201.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-4-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Hosur and Sipcot Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/81-PHB]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1982

का० आ० 1202.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8-3-1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पोल्लापुडि टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-82 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/81 पी एच बी]

New Delhi, the 8th March, 1982

S.O. 1202.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-4-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Pollapudi Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/81-PHB]

का०आ० 1203—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कोथूर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/82-पी एच बी]

आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

S.O. 1203—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-4-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kovur Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/82-PHB]

R. C. KATARIA, Asst. Director General (PHB)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1982

का०आ० 1204—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 17 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना सं० का० आ० 2645 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में :—

(i) क्रम संख्या 5 में, कालम (1) के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"अपर मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार, अलीपुरदुआर जंकशन और लमडिंग।"

(ii) क्रम संख्या 8 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा अर्थात् :—

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी स्थानों की कोटियां तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
"मण्डल रेल प्रबंधक और अपर मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, बैंगलोर मंडल	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं की अन्तर्गत स्थित दक्षिण रेलवे के नियंत्रण में परिसर।"

[फाईल सं० 69/डब्ल्यू 2/एल ई/13]

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड

1412 GI/81—5

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 3rd March, 1982

S.O.1204.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. S.O. 2645 dated 17th September, 1980 namely :—

1. In the Table annexed to the said notification,—

(i) in serial No. 5 for the entries under column (1) the following shall be substituted namely :—

"Additional Divisional Railway Managers, North-east Frontier Railway, Katihar Alipurduar Junction and Lumding".

(ii) after serial No. 8 and the entries relating thereto, the following shall be added namely :—

Designation of the officers	Categories of the Public Premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
"Divisional Railway Manager and Additional Divisional Railway Manager, Southern Railway, Bangalore Division.	Premises under the control of the Southern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction".

[File No. 69/W2/LE/13]

HIMMAT SINGH, Secy., Railway Board

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1982

का०आ० 1205.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ग की उपधारा (2) के अधीन श्री हरनाम सिंह ने पंजाब सिंध बैंक के विरुद्ध श्रम न्यायालय लखनऊ में एक आवेदन फाइल किया, जिसे 1964 का मामला सं० 20 के रूप में रजिस्टर किया गया,

और उक्त श्रम न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन 8 मई, 1965 को रद्द कर दिया गया,

और श्री हरनाम सिंह द्वारा फाइल की गई विशेष अपील 1970 का सं० 275 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपील को मंजूर कर लिया और आदेश दिया कि अभ्यर्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ग (2) के अधीन मामले को विधि के अनुसार उठा सकता है जोकि उनके आदेश के फलस्वरूप श्रम न्यायालय (केन्द्रीय) लखनऊ के समक्ष लम्बित होगा; और

और श्रम न्यायालय (केन्द्रीय) लखनऊ अस्तित्व में नहीं रह गया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक श्रम न्यायालय का गठन करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री हरिहर शरण होंगे जिनका मुख्यालय लखनऊ में होगा और जो उपर निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उक्त आवेदन पर गए सिरे से विचार करेंगे।

[सं० एल-12025/13/80-डी II (ए)

ORDERS

New Delhi, the 16th January, 1982

S.O. 1205.—Whereas an application under sub-section (2) of section 33C of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) was filed by Shri Harnam Singh against the Punjab Sind Bank Limited in the Labour Court, Lucknow, which was registered as case No. 20 of 1964;

And whereas the said application was dismissed by the said Labour Court on the 8th May, 1965;

And whereas the High Court of Judicature at Allahabad in Special Appeal No. 275 of 1970 filed by Shri Harnam Singh allowed the appeal and ordered that the applicant would be free to agitate the matter in accordance with law in proceedings under section 33C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), which would, in consequence of their Order become pending before the Labour Court (Central) Lucknow;

And whereas the Labour Court (Central), Lucknow, has ceased to exist;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes a Labour Court of which Shri Harihar Sharan shall be the Presiding Officer with headquarters at Lucknow for fresh consideration of the said application in accordances with the Order of the High Court referred to above.

[No. L-12025/13/80-DII(A)]

नई दिल्ली, 29 जनवरी 1982

का०आ० 1206—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुदर्शनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए निदेशित करती है ।

अनुसूची

"क्या भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास के प्रबन्धतंत्र को अपने पत्र तारीख 15-6-78 द्वारा चेंगम शाखा के संदेश वाहक श्री पी० जय पासन को सेवोन्मुक्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल 12012/327/81 डी-II-ए]

एन० के० वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th January, 1982

S.O. 1206.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exits between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers coferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribual of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India, Madras in discharging from service of Shri P. Jayapalan, Messenger Chengam Br. under their letter dated 15-6-78 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-12012/327/81-D.IIA]

N. K. VERMA, Desk Officer

New Delhi, the 26th February, 1982

S.O. 1207.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Madras L. H. O., Madras-1, and their workman, which was received by the Central Government on the 22-2-1982.

BEFORE THIRU T. SUDARSANAM DANIEL, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU

(Constituted by the Government of India)
Monday, the 8th day of February, 1982

Industrial Disptue No. 61 of 1981

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of State Bank of India, Madras-1).

BETWEEN

The workmen represented by—

The General Secretary,
State Bank Employees Union,
36/37, Angappa Naicken Street, Madras-600001.

AND

The Chief General Manager,

State Bank of India, Madras L. H. O.

21, Rajaji Street, Madras-600001.

REFERENCE :

Order No. L-12012/209/80-D. II.A, dated 30th July, 1981 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, 30th day of December, 1981 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru K. Chandru for Thiruvalargal Row and Reddy and K. Chandru, Advocate for the workmen and of Thiruvalargal T. S Gopalan and P. Raghunathan, Advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This is an Industrial Dispute between the workmen and the Management of State Bank of India, Madras-1 referred to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in Order No. L-12012/209/80-D. II.A, dated 30th July, 1981 of the Ministry of Labour, in respect of the following issue :

"Whether the action of the Management of State Bank of India, Madras in terminating the services of Shri A. Perumal, Ex-Watchman with effect from 21-5-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Facts leading upto this dispute are as follows : The Management is the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Madras-1, Tamil Nadu. The reference made by the Government of India, Ministry of

Labour to this Tribunal for adjudication relates to the action of the Management of State Bank of India, Madras terminating the services of Thiru A. Perumal, Ex-watchman with effect from 21-5-1979. The cause of Thiru A Perumal is being espoused by State Bank Employees Union, 36/37, Angappa Naicken Street, Madras-600001, Tamil Nadu. The workman concerned in this dispute Thiru A. Perumal was serving in the Indian Army as a driver for about 15 years. He was discharged from the Army on 4-4-1978 and he got himself registered with Ex-Servicemen Welfare, D.S.S. and A Board The workman was appointed as a substitute watchman in the Management's Branch at Guindy on 9-5-1978 and he was working in that Branch upto 22-12-1978. Ex. W-1 is the certificate issued by the Management-Bank, Guindy office date 22-1-1979 to the effect that the concerned workman had worked as a substitute watchman of the Bank for an aggregate period of 180 days from 9-5-1978 to 22-12-1978. Thereafter he was employed at the Adyar Branch of the Management for three days, namely 13th, 14th and 15th January, 1979. Subsequently he was employed by the Management at the Local Head Office from 17-1-1979 till 21-5-1979. The services of the concerned workman were terminated at the close of duty hours on 21-5-1979. It is common ground that at the time of termination the concerned workman was neither given any notice nor any compensation was offered to him.

3 In order to appreciate the claim put forward by the concerned workman Thiru A. Perumal in the first place it will be pertinent to ascertain the total service put in by the workman under the Management Bank. I have already referred to the employment certificate Ex. W-1 issued by the Management-Bank on 22-1-1979 to the effect that Thiru A. Perumal had worked as Watchman of Guindy Branch for a period of 180 days from 9-5-1978 to 22-12-1978. Even according to the Management as seen from the end of paragraph (2) of the counter statement filed that the Bank had given directions to its Branches that no branch office should employ a temporary employee as watchman for more than 180 days and restrict the scope of temporary watchman to less than 180 days. Then again the concerned workman had worked for three days on 13th, 14th and 15th January, 1979 at Adyar Branch of the Management Bank. Lastly the concerned workman was also employed by the Management-Bank at their Local Head Office from 17-1-1979 till 21-5-1979. Therefore it is obvious that the workman has put in 279 days of service as a watchman between 9-5 1978 to 21-5-1979. These two documents Exs. W-1 and W-2 would justify the claim made by the Union in paragraph 4(a) of the claim statement that the workman concerned has put in 279 days in a period of one year starting from 9-5-1978. The record of service of the concerned worman had been adverted to by the Management in paragraph (4) and (5) of the counter statement filed by them. One would search in vain in these two paragraphs that the Management challenged the claim of the workman that he had worked for 279 days from 9-5-1978 upto 21-5-79. A perusal of these two paragraphs of the Management would only indicate that the Management was anxious to impress that the services of the concerned workman was only temporary and intermittent in nature. But there is no specific denial that the workman had put in 279 days of service in a period of one year starting from 9-5-1978. This position is also made clear that by the General Manager (Planning) under Ex M-7 dated 1-3-1980 that the employee Thiru A. Perumal has completed over 240 days of temporary service in a continuous period of 12 months and becoming eligible for protection as per the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947. At the time of termination of the workman concerned, the workman had not been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment nor has the workman been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice, nor has the workman been paid, at the time of retranchment, compensation. Under paragraph 522(4) of the Sastri Award termination of the services of a temporary employee could be done only after giving 14 days notice and the same has not been done in the case of present workman concerned Thiru A. Perumal Therefore it is pretty clear that the workman's service had not been terminated in accordance with Secion 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 and as such in view of the following decisions of the Supreme Court commencing with 1976—I—I.L.J. page 478 (State Bank of India Vs. N. Sundramoney), 1980—II—L.L.J. page 72 (Santosh Gupta va. State Bank of India), 1981—I—L.L.J. page 386 (Surendra Kumar Verma Vs. Central Government Industrial Tribunal, New Delhi) and 1981—II—L.L.J. Page 70 (Mohan Lal vs. Bharat Electronics Limited), the termination of the workman Thiru A. Perumal must be held to be null and void and he must be held to be entitled to reinstatement with full benefits.

4. The defence put forward by the Management-Bank is two fold. (1) Thiru A. Perumal was employed by three different establishments for three different periods and therefore there is no scope to treat all of them as one and the same or to treat them as continuous employment under one employer. (2) Even if the workman is held to have put in more than 240 days of service in a year the various periods have to be separtely treated and cannot be consolidated as one period. The State Bank of India has been constituted pursuant to the provisions of the State Bank of India Act, 1955. The Bank is divided into 12 circles and one such circle is the Madras Circle. Madras Circle in turn has about 700 branches and the total number of employees employed in the branches would in the region of 15,000. The short question is whether on these materials each branch of the Bank can be considered to be a separate establishment by itself. Although this plea has been taken in paragraph (2) and (3) of the counter statement filed by the Management, no serious argument was addressed on this aspect. However, there are certain features which cannot be challanged. As far as the subordinate staff is concerned the Bank has laid down the number of subordinate staff for each of the branches and the Manager of the branch in consultation with and approval of the Personnel Department of the Local Head Office and the Regional Office of the Bank recruits the subordinate staff from among the candidates sponsored by the Employment Exchange. The Bank has given directions to its branches/administrative offices should employ a temporary employee as watchman for more than 180 days, etc. Even on these contentions of this Management, it is not difficult to hold that State Bank of India, Madras Circle is one establishment. As a matter of fact, even in the order of reference made by the Government of India, Ministry of Labour, the Central Government is of opinion that an Industrial Dispute exists between employers in relation to the Management of State Bank of India and their workmen and copy of this reference has been marked to the Chief General Manager, State Bank of India, Madras L.H.O., 21, Rajaji Street Madras-600001. The counter statement has also been filed by the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Madras-600001. Under these circumstances, the services put in by the concerned workman Thiru A. Perumal respectively at Guindy, Adyar and Local Head Office of the Management-Bank are not distinct and different employment, but one of continuous one. It should also be remembered that only for the purpose of Section 250 of the Industrial Disputes Act, 1947, an "establishment" has been defined. But under Section 25F the word "employer" alone is used. With regard to the second point, learned councel for the Management however strongly contended that the three different periods of service of the concerned workman ought to be treated separately and not been taked on. Support for this position is also sought to be had that when the employment at Adyar Branch of the Management-Bank came to an end. the Bank had settled all the accounts of the workman concerned. Granting it to be so it yet remains to be considered whether on this account the three periods of service put in by the workman concerned should be treated separately in law. Learned councel for the Union Thiru Chandru points out that the decision of the Supreme Court reported in 1976—I—L.L.J. page 478 (State Bank of India vs. N. Sundaramoney) should set at rest the contentions now put forward by the Management no doubt all the details of the facts are not obtained in the decision of the Supreme Court, but the facts are evident from the decision of our High Court reported in 1973—II—L.L.J page 551 (N Sundaramony vs. The State Bank of India, Kuzhithurai Branch). On reading these two citations, it can be found that Thiru N. Sundaramony was appointed for specific periods for more than 19 times during the relevant period and yet the Supreme Court has taken the entire service into consideration for reckoning continuous service Further more, under Section 25B(1) of the Industrial Disputes Act, 1947, "a workman shall be said to be is continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,

including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike, which is not illegal, or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman." It is never the case of the Management that cessation of work to the concerned workman Thiru A. Perumal was due to any fault on the part of the workman Thiru A. Perumal himself. Under these circumstances, there is no merit in either of the contentions raised by the Management and therefore, it follows that the termination of the workman's service was not in accordance with Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 and the termination is null and void and he would be entitled to reinstatement with all benefits.

5. In paragraph (11) of the counter statement filed by the Management it is stated that in any event the concerned workman is not entitled in law and does not deserve the relief of reinstatement in view of his false declaration and therefore the Bank cannot repose confidence in the workman concerned. Even at the outset, it must be pointed out that the learned counsel for Union Thiru Chandru states that even assuming that there was a declaration given by the workman, the same cannot be put against him to deny the benefits conferred under Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 and such a document will have to be ignored by virtue of Section 25J(2) of the Industrial Disputes Act, 1947. That leads me to the consideration of the points (2) whether a declaration as such was given by the concerned workman Thiru A. Perumal as claimed by the Management and (ii) if so whether such a declaration was false. According to the Management before appointing a temporary watchman, the aspirant has to give a declaration that he was not employed as a temporary watchman in any of the branches or offices of the Management-Bank. No specific circular in this direction has been placed by the Management-Bank requiring the candidate to give a declaration that he was not an employee as a temporary watchman in any of the branches of the Management-Bank before. The case of the Management-Bank as can be gathered from the counter statement filed is that prior to his appointment under Local Head Office the concerned workman Thiru A. Perumal has given a declaration in writing on 10-1-1979. Thiru A. Perumal was terminated with effect from 22-5-1979. Immediately thereafter, the Petitioner-Union took up the case of Thiru A. Perumal with the Management for his reinstatement. Since the Union could not succeed they took up the matter to the Regional Labour Commissioner (Central), Madras by their letter dated 5-6-1979. The Management has submitted their remarks before the Conciliation Officer on 11-8-1979—vide Ex. W-3. In Ex. W-3, there is no whisper that the workman had given any false declaration as such with the Management-Bank. As a matter of fact, from paragraph (3) of Ex. W-3 it can be noted that the case of the Management was that Thiru A. Perumal was not employed after 22-12-1978. There is no mention about the workman employed under the Adyar Branch on 13th, 14th and 15th January 1979 or at the Local Head Office from 17-1-1979 upto 21-5-1979. But in the conciliation failure report Ex. W-4 it can be seen that the Management's case was that Thiru A. Perumal gave a false declaration to the Bank on 10-1-1979. A copy of declaration said to have been given by the workman on 10-1-1979 was produced before the Conciliation Officer. In these circumstances, it is apparent that this case of the workman giving a false declaration has been advanced by the Management only subsequent to the remarks of the Management given under Ex. W-3 before the Conciliation Officer.

6. Now what happened to the declaration said to have been given by the workman on 10-1-1979. The evidence on this aspct is nothing but serappy and the Management had to comman all its forces to substantiate a plea take up by them. Here again, the case of the Management has to be distinctly borne in mind, in that, the workman was given a separate engagement and not in continuation of his previous engagement in Guindy and Adyar branches acting as separate employers—vide middle of paragraph (6) of counter statement of the Management. Therefore this stated declaration on 10-1-1979 related only to the temporary appointment of the workman concerned in the Local Head Office. It has been elicited from the workman W.W. 1 that when he first entered the services of the Bank at Adyar he had given declaration that he was not previously employed by any of the branches of the Management-Bank. Admittedly the workman was employed at the Adyar Branch of the Management-Bank on 13th, 14th and 15th January, 1979 and according to the Management, the Guindy and Adyar Branches are separate employers. Therefore when the workman is engaged in the Adyar Branch which is said to be separate employer, certainly the Bank would have obtained a declaration from the workman that he was not employed in any other Braches of the Management earlier. That is not the case of the Management and no declaration as such relating to Adyar Branch is forthcoming or is said to be in existence. Therefore it lends support to the view that only at the first engagement by the Bank, a declaration is obtained from the employee that he was not worked in any branches of the Management-Bank prior to that, because the subsequent employment by the Bank would be on the basis of the employee's work in other branches. Therefore in as much as no declaration is even thought of from the workman for Adyar Branch which is said to be separate employer, it is highly improbable a declaration would have been obtained from the workman with regard to his employment in the Local Head Office from 17-1-1979. In this context, I may also refer to the evidence of M.W. 1, the Assistant Security Officer who has stated in cross-examination that as an Assistant Liaison Officer his jurisdiction was limited to Nungambakkam Complex and Parry but not C.C.M's house at Adyar. He also makes it clear he is not empowered to send casual watchmen to any of the branch of the Management-Bank as such Therefore his admissions clearly point out that the Management had not insisted declaration from the workman prior to his engagement at the Adyar Branch on 13th, 14th and 15 January, 1979 and so the Management wants to deprive if possible the relief of reinstatement by putting forward a false plea as such with regard to a stated declaration relating to the workman's employment under the Local Head Office. It is manifest that this case of declaration given by the workman on 10-1-1979 is thought of by the Management only after 1-3-1980. Under Ex. M-7 the General Manager (Planning) has pointed out that the employee concerned Thiru A. Perumal has completed 240 days of temporary service in a continuous period of 12 months and becoming eligible for protection as per the provisions of the Industrial Disputes Act. Therefore the concerned Officer Thiru Captain Valentine Jesudas (MW. 1) who had acted as Assistant Security Officer at Madras Local Head Office had been asked to explain under Ex. M-7. This Officer has also been examined as M.W. 1. A persual of his evidence would amply demonstrate that in order to safeguard his position he must have put forward a case of declaration being given by Thiru A. Perumal on 10-1-1979. In cross-examination, he has admitted that his Regional Chief Manager at Madurai called for explanation in writing. But he would have the Tribunal to believe that he submitted his explanation only in person and not in writing. This is also given a lie circumstantial by unimpeachable documents Exs M.8 and M|9 Ex. M-9 is dated 28-3-1980 while Ex. M-8 is dated 9-6-1980. M.W. 1 has been asked to give his explanation by proceedings dated 1-3-1980. In both Exs. M-8 and M-9, it is clearly stated that M. W. 1 has given explanation in writing and the same is forwarded. M.W. 2 is Asslstant Law Officer of the Local Head Office of the State Bank of India, Madras. Both M.W. 1 and M. W. 2 would assert that there was no written explanation given by M.W. 1. A. Perumal of the deposition of M.W. 1 and M.W. 2 would convince any one that neither the one nor the other has any regard for truth whatsoever. The demeanour of these witnesses in the box did not at all impress me that they are telling the truth. Even Ex. M-10 which is said to be a copy of a declaration given by W.W.1 has not been verified by officer. It is not even worth that paper on which it is typed and presented before this Tribunal. In the light of confliction testimony of M.W. 1, M.W. 2 and the documents placed by the Management, the hard reality appears to be that in the written explanation given by M. W. 1 there was absolutely no shiper about the declaration said to have been given by Thiru A Perumal and for that reason the Management has designedly refrained from producing before the Tribunal the written explanation offered by M W. 1 and forward to the Head Office. Even a copy of the same has not been placed before this Tribunal. Learned counsel for the Union Thiru Chandru points out that

in the light of the admission of M.W. 2 and the Management's remarks to the Labour Commissioner under Ex. W-3 must be held to be false or suppresso facto and suggestio falsi and he also points out that even M. W. 2 would say that the document Ex M 8 is a false document. The note under Ex. M-11 is admittedly put up by M. W. 2 and is dated 29-3-1980 and refers to CRM 1339/16/7 addressed to General Manager (Personnel) but Ex M-9 has the same reference number but dated 26-3-1980 and found to be addressed to General Manager (Operations). Thiru Chandru also points out that M. W. 1's statement that he took the declaration form from Madras to Madurai has to be rejected in toto. On an analysis of the entire materials oral and documentary, it is perfectly clear that the case of declaration given by W.W. 1 on 10-1-1979 is false and has been put up only to resist the the claim of the concerned workman Thiru A. Perumal. In this regard, it must be remembered that the concerned workman Thiru A. Perumal has served as driver in the Indian Army for 15 years and he was discharged from Army only on 4-4-1978 and he got himself registered with the Ex-Servicemen Welfare, D.S.S and A Board. It is most unfortunate that the Management, a public sector agency has thought fit to drive an ex-serviceman from pillar to post. Therefore it was that the learned counsel for Union Thiru Chandru furnishes to this Tribunal with an extract from the report appeared in Indian Express, Madras dated 11-12-1981 said to an extracts from the judgement of the Madras High Court. It runs as follows :

> "The Respondents had miserably let down a man who had defended the nation and whose services had been recognised. If Ex-servicemen and war widows are to be treated in this niggardly fashian fashion it would certainly effect the interests of the nation when energetic and braven an would be needed to defend it."

Under these circumstances, the Management has miserably failed to substantiate their claim that in any event reinstatement of the workman should not be ordered But in the light of the latest decisions of the Supreme Court the normal rule is to order reinstatement with full benefits. Under these circumstances I have little hesitation to find that the action of the Management in terminating the services of the workman Thiru A. Perumal is unjustified and that the workman is entitled to be reinstated with full back wages and other insidental benefits.

7. In the result, an Award is passed holding that the action of the Management in terminating the services of Thiru A Perumal is unjustified and he is entitled to be reinstated with full back wages and other incidental benefits. I direct the Management-Bank to pay a cost of Rs 500 to the Petitioner-Union and bear their own costs.

Dated this 8th day of February, 1982.

T. SUDARSANAM DANIEL, Presiding Officer

WITNESSES EXAMINED

For workman :—

W W. 1 : Thiru A. Perumal

For Management :—

M.W. 1 : Capt. Valentine Jesudoss.

M.W. 2 : Thiru R Krishnamacharv. Assistant Law Officer

For workman :

W. 1/22-1-79 : Employment certificate issued to W.W. 1 by the Bank.

W 2/5-6-79 : Letter from the Union to the Regional Labour Commissioner (Central), Madras for taking up the conciliation.

W. 3/11-8-79 : Statement of remarks submitted by the Bank
W. 4/16-8-80 : Conciliation failure report.

For Management :

M 1/29-3-77 : Staff circular 24 regarding appointment of substitute/Temporary watchman.
(True copy).

M. 2/9-5-78 : Application of W.W. 1 for appointment to the post of watchman.

M 3/9-5-78 : Letter from the Bank to W.W. 1 regarding appointment.

M 4/11-5-78 : Letter of W.W. 1 certifying that he did not work as temporary employee in any of the branches of the Bank except the Guindy Branch.

M 15—7 . Register showing the particulars of temporary engagement of Watchmen in Guindy Branch and particulars of payment.

M. 6/ — : Attendance register of the Guindy Branch of the Bank from 3-7-78 to 30-9-79.

M 7/1-3-80 :Letter from the General Manager (Planning) of the Bank to the Chief Regional Manager of the Bank, Madurai requiring to call for detailed advice from M. W. 1 about the appointment of W W. 1.

M 8/9-6-80 : Letter from the personnel Officer of the Bank at Madurai to Thiru P. A. Devendradas forwarding Ex. M. 9.

M 9/28-3-80 : Letter from the Regional Office of the Bank, Madurai to Local Head Office of the Bank, Madras forwarding explanation of M. W. 1.

M. 10/10-1-79 : Declaration form of W.W. 1.

M. 11/29-5—:Office note put up by M W. 2 to the Personnel Manager of the Bank.

T. SUDARSANAM DANIEL, Presiding Officer
[No. L-12012/209/80-D.II(A)]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1982

का०आ० 1208—बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त निधि के कार्यकलापों का लेखा-जोखा तथा उस वर्ष के लेखो का विवरण दिया गया है।

सामान्य

बीडी प्रतिष्ठानो मे सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से नियोजित व्यक्तियो के कल्याण को बढावा देने के उपायो के संबंध में वित्तीय सहायता देने के लिए बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि गठित की गई है।

बीडी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1975 के अधीन बनाए गए नियम 15 फरवरी, 1976 को लागू हुए। बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बनाए गए नियम 7 अक्तूबर, 1978 से लागू हुए।

बीडी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 56) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने बीडी के निर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए गोदाम से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर प्रति किलो 25 पैसे की दर निर्धारित की थी, जिस पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क लगाया जाना था और एकत्र किया जाना था।

वित्त अधिनियम, 1979 के अनुसार अनिर्मित तम्बाकू पर उत्पाद-शुल्क लगाने से छूट दी गई और गोदामों को लाइसेंस देना समाप्त किया गया। अतः बीडी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन एकत्र किए जाने वाले उपकर को पहली मार्च, 1979 से समाप्त कर दिया गया है। पहले से शुरु किए गए वर्तमान कल्याण उपायों को जारी रखने तथा बीड़ी श्रमिको के लिए और कल्याण उपायों की व्यवस्था करने के लिए निधि को वित्तीय सहायता देने की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण के अधीन कार्यकलापों को वित्तीय सहायता पिछले वर्षों में एकत्र की गई राशि में दी जाती है।

प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसे राज्यों को जहां देश के बीड़ी श्रमिक संकेन्द्रित हैं, पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए कल्याण आयुक्तों, उप कल्याण आयुक्तों और सहायक कल्याण आयुक्तों के पद सृजित किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

क्रमांक अधिकारी का नाम	राज्यों के नाम
1. कल्याण आयुक्त भुवनेश्वर	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी राज्य
2. कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा	राजस्थान और गुजरात
3. कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद	बिहार और उत्तर प्रदेश
4. कल्याण आयुक्त, बंगलौर	कर्नाटक आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल
5. कल्याण आयुक्त, जबलपुर	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

चिकित्सा सुविधाएं

चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है और आलोच्य अवधि के दौरान निम्नानुसार 14 औषधालयों की मंजूरी दी गई है :—

पश्चिम बंगाल	कूच बिहार में 1, परगना, नादिया, मिदनापुर में 2।
मध्य प्रदेश—	सतना और वारासियोनी में दो औषधालय
उत्तर प्रदेश— और	मिर्जापुर और मुगलसराय में 2 औषधालय। गया (बिहार), बंगलौर (कर्नाटक), त्रिची (तमिलनाडु), कांडाट्टी (केरल), बेवर (राजस्थान) तथा अहमदाबाद (गुजरात) में एक-एक।

उपर्युक्त 14 औषधालयों के अलावा, 55 औषधालय तथा मैसूर में एक दस पलंगों वाले अस्पताल तथा निगिसिया में एक मोबाइल क्लीनिक कार्य करती रही। आलोच्य वर्ष की रिपोर्ट के दौरान अर्थात् 1980-81 में बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने में 53,29,210.30 रुपये खर्च किए गए हैं।

शिक्षा .

विभिन्न क्षेत्रों में बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को 23,25,295.50 रुपये की राशि छात्रवृत्तियों के रूप में दी गई।

आवास .

बीड़ी कर्मकारों को आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत बीड़ी श्रमिकों को 79,380 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

1980-81 का लेखा विवरण

(क) अथ शेष	4,15,37,362.00 रुपये
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्तियां	90,270.00 रुपये
(ग) वर्ष के दौरान व्यय	91,96,210.00 रुपये
(घ) अंत शेष	3,24,31,422.00 रुपये

(ङ) नोट :—वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट में, उस वर्ष के अन्त शेष को 4,29,01,691.00 रुपये दिखाया गया है। बाद में लेखों के मिलान के परिणामस्वरूप सही अन्तशेष 4,15,37,362.00 हो गया। इसे वर्ष 1980-81 के लिए अथशेष माना गया है।

[फाइल संख्या एस०/23011/2/81-एम० 5]

New Delhi, the 6th February 1982

S.O. 1208. In pursuance of Section 10 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby publishes the following report giving an account of its activities financed under the said Act during the financial year 1980-81 together with a statement of accounts for that year.

General :

The Beedi Workers Welfare Fund has been constituted under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 and the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for the financing of measures to promote the welfare of persons engaged in beedi establishments, directly or through any agency.

The Rules framed under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 came into force with effect from 15th day of February 1977. The Rules under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 were brought into force with effect from 7th October, 1978.

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), the Central Government had fixed the rate of 25 paise per kilogram of tobacco issued to any person from a warehouse for any purpose in connection with the manufacture of beedi, as the rate at which the duty of excise was to be levied and collected by way of cess.

According to Finance Act, 1979, unmanufactured tobacco was exempted from the levy of excise duty and licensing of warehouses was discontinued. The cess which was being collected under Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 has therefore to be discontinued with effect from 1st March, 1979. In order to continue the existing welfare measures already introduced and also to provide more welfare measures to beedi workers, alternative arrangement for financing the Fund are under consideration.

The activities under the Beedi Workers Welfare were financed out of the collections made in the previous years.

For administrative convenience, the States having concentration of beedi workers in the country, have been grouped into five regions and for implementing the various activities, posts of Welfare Commissioners, Deputy Welfare Commissioners and Assistant Welfare Commissioners have been created. The jurisdiction of various regions is as under :—

Sl. No	Name of the Officer	Name of the States
1.	Welfare Commissioner, Bhubanesawar	Orissa, West Bengal and Eastern States
2.	Welfare Commissioner Bhilwara	Rajasthan and Gujarat
3.	Welfare Commissioner Allahabad	Bihar and Uttar Pradesh
4.	Welfare Commissioner Bangalore	Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala.
5.	Welfare Commissioner Jabalpur.	Madhya Pradesh and Maharashtra.

Medical facilities :

Medical care has been given priority and during the period under report 14 dispensaries as under were sanctioned :

West Bengal :	4 dispensaries at Cooch-Bihar, 24 Parganas, Nadia and Midanapur.
Madhya Pradesh:	2 dispensaries at Satna and Warasioni
Uttar Pradesh: and	2 dispensaries at Mirzapur and Mughalsarai one dispensary each at Gaya (Bihar), Bangalore (Karnataka), Trichy (T. N.) Kondatti (Kerala), Bewar (Rajasthan) and Ahmedabad (Gujarat).

Besides the above 14 dispensaries, 55 dispensaries, one ten-bedded hospital at Mysore and Chest Clinic at Nipani also continued to function. During the year under report, viz. 1980-81 an amount of Rs. 53, 29, 210.30 has been spent in providing medical care facilities to beedi workers and members of their family.

Education

An amount of Rs. 23,25,295.50 was paid as scholarship to the children of beedi workers in different regions.

Housing

For providing housing facilities to beedi workers Rs. 79,381 was given as subsidy to beedi workers under Build Your Own House Scheme.

Statement of account for 1980-81

	Rs.
(a) Opening Balance	4,15,37,362.00*
(b) Receipts during the year	90,270.00
(c) Expenditure during the year	91,96,210.00
(d) Closing Balance	3,24,31,422.00

*Note—In the Annual Report for the year 1979-80, the closing balance for that year was shown as Rs. 4,29,01,691.00. Consequent on a subsequent reconciliation of accounts the correct closing balance was arrived at Rs. 4,15,37,362.00. This has been adopted as the opening balance for the year 1980-81.

[No. S/23011/2/81-M.V.]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1982

का॰आ॰ 1209.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 और नियम 16 के उपनियम (2) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए केन्द्रीय समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे और उक्त समिति का मुख्यालय निर्धारित करती है, अर्थात् :—

1. श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार — अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, इलाहाबाद — उपाध्यक्ष
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर — सदस्य-पदेन
4. श्री खान घफरान जैदी, विधायक — सदस्य
5. श्री पीर मोहम्मद अन्सारी, भागीदार, हिन्दी स्वार बीड़ी वर्क्स, डायेरा शाह अजमल, इलाहाबाद
6. श्री रामकिशन, भागीदार रामकिशन दयाराम एण्ड कम्पनी

(5–6) — नियोजक प्रतिनिधि

7. श्री इकबाल हुसैन, अध्यक्ष, बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, 73, बक्शी बाजार, इलाहाबाद — सदस्य
8. श्री अब्दुल कादिर मसूदी, सेक्रेटरी, बीड़ी मजदूर यूनियन, फर्रूखाबाद — सदस्य

(7–8) — कर्मचारी प्रतिनिधि

9. कुमारी आलिया जुबेरी, अबूसेही, फैजाबाद — महिला प्रतिनिधि

[संख्या यू/23018/6/81-एम (5)]

एच॰ पी॰ दास, अवर सचिव

New Delhi, the 6 March, 1982

S. O. 1209.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976) read with sub-rule (2) of rule 3 and rule 16 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Uttar Pradesh consisting of the following members and fixes the headquarters of the said Committee namely :—

(1) Labour Minister, Government of Uttar Pradesh —Chairman
(2) Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Allahabad —Vice-Chairman
(3) Labour Commissioner, Uttar Pradesh, Kanpur —Member exofficio
(4) Shri Khan Ghafran Zaidi, Member of Legislative Assembly —Member
(5) Shri Pir Mohamed Ansari, Partner, Hindi Swar Bidi Works, Dayera Shah Ajmal, Allahabad — Member
(6) Shri Ram Kishan, Partner, Ram Kishan Dayaram & Co., Gurshi ganj, Farrukhabad — Member

(5)–(6) Employers' Representatives

(7) Shri Iqbal Hussain, President, Bidi Udyog Karamchari Union, 73-Baxi Bazar, Allahabad —Member
(8) Shri Abdul Qadir Masoodi, Secretary, Bidi Mazdoor Union, Farrukhabad — Member

(7)–(8) Employees' Representatives

(9) Miss Alia Zuberi, Abuseshi, Faizabad — Women Representative

[No. U/23018/6/81—M.V.]

H. P. DAS, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1982

का॰ आ॰ 1210.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 298 तारीख 31 दिसम्बर, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, असम राज्य के लिए एक प्रादेशिक समिति की स्थापना करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. सचिव, श्रम विभाग, असम सरकार, दिसपुर

सदस्य

2. उप सचिव, असम सरकार, वित्त विभाग, दिसपुर
3. श्रम आयुक्त, असम सरकार, दिसपुर

(2–3) — राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति।

4. श्री डी॰ पी॰ मनपुरिया, प्रबन्धक, मैसर्स बेनियर मिल्स लिमिटेड, असम प्लाईवुड मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, तिनसुकिया (असम)
5. श्री पी॰ बी॰ बक्शी, चीफ एग्जीक्यूटिव, स्टीलवर्थ लिमिटेड, तिनसुकिया-786125 (असम) (दि आल इंडिया मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन)
6. श्री आर॰ बी॰ रूगरा, असम मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, गवर्नमेंट प्रेस के पीछे कान्नी मैदान, गौहाटी-781007।

(4–6) — राज्य में नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि

7. श्री ए० सी० सइकिया, महामंत्री, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, असम शाखा, उलुबारी, गोहाटी-781007।	राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि।
8. श्री प्रबीन गोस्वामी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आफिस डाकखाना-जोरहाट (असम)।	
9. श्री देवानन्द बोरा, विधायक, सचिव, हिन्द मजदूर सभा (असम) द्वारा—जनता पार्टी, सिलपुकुरी गोहाटी-781003।	

[सं० वी-20012/16/78-भ० नि०-2]

New Delhi, the 9th February, 1982

S.O. 1210.—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 298 dated the 31st December, 1976, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Assam consisting of the following persons namely:

Chairman

1. Secretary to the Government of Assam, Labour Department, Dispur.

Members

2. Deputy Secretary to the Government of Assam, Finance Department, Dispur.	Two persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.
3. Labour Commissioner, Government of Assam, Dispur.	
4. Shri D.P. Manpuria, Manager, Messrs Veneer Mills Private Limited, Assam Plywood Manufacturers' Association Tinsukia (Assam).	Three representatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the organisations of employers in the State.
5. Shri B.P. Bakshi, Chief Executive, Steelworth Limited, Tinsukia-78125 (Assam) (The All India Manufacturers' Organisation).	
6. Shri R.B. Roongta, Assam Manufacturers' Association, Behind Government Press, Banunimaidan, Gauhati-781007.	
7. Shri A.C. Saikia, General Secretary, Indian National Trade Union Congress, Assam Branch, Ulubari, Gauhati-781007. (Assam).	Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the organisations of employees in the State.
8. Shri Probin Goswami, Indian National Trade Union Congress Office, P.O. JORHAT (Assam).	

9. Shri Devanand Bora, MLA., Secretary, Hind Mazdoor Sabha (Assam), C/o Janata Party, Silpukuri, Gauhati-781003.

[No.V. 20012/16/78-PF.II]

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1982

का०आ० 1211.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम० डी० पाल, निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और श्री आर० एन० सोनी, निदेशक, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 236 तारीख 16 दिसम्बर, 1975 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 4 और 6 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(4) "श्री आर० एन० सोनी, निदेशक, उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।"

(6) "श्री एम० डी० पाल, निदेशक वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।"

[सं० वी० 20012/1/75-पी०एफ-II]
पी० सिन्हा, उप सचिव

New Delhi, the 3rd March, 1982

S.O. 1211.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri M. D. Pal, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and Shri R. N. Soni, Director, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, as members of the Central Board of Trustees and makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Labour No S.O. 236, dated the 16th December, 1975. namely :—

In the said Notification for the entries against Serial Numbers 4 and 6, the following entries shall respectively be substituted, namely :

(4) "Shri R. N Soni, Director, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Government of India, New Delhi."

(6) "Shri M. D. Pal, Director, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India, New Delhi."

[No. V-20012|1|75-PF-II]
P. SINHA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1982

का०आ० 1212.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड. के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री सुवर्णनम डेनियल, होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड मनवालकुरिचि के नियोजकों के ठेकेदारों के द्वारा नियोजित सारे ठेकेदार मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा के समाप्त होने पर सीधे कामगार के रूप में रखना चाहिए ? यदि हां, तो इसके लिए क्या मापदंड होना चाहिए ? और साथ ही मानवालकु

मिनरल कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्टर सोसाइटी और अन्य ठेकेदारों द्वारा पहले नियोजित कितने कामगारों को सीधे कामगारों के रूप में र[illegible] चाहिए ?

जब कि ठेकेदारी प्रथा के समाप्त होने पर नियोजक अतिरिक्त कामगारों को नियोजित करना चाहते हैं, तो क्या 1969 में छंटनी किये गये कम्पनी के कामगारों की औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(एच) के तहत नियोजन में प्राथमिकता की माग न्यायोचित हैं ?

[एल 43012/1/81 डी 3(बी)]
शशि भूषण, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1982

S.O. 1212.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Indian Rare Earths Ltd. Manavalakurichi and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T .Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

"Whether the employer of M|s. Indian Rare Earths Ltd., Manavalakurichi should absorb the contract labour employed through contractors under them as direct employees on abolition of the contract system and it so what should be the criteria for such absorption and what should be the number required to be so recruited from those previously employed through Manavalakurichi Mineral Cooperative Labour Contract Society and other contractors ?

Whether the workmen of the Company retrenched in the year 1969 are justified in demanding preferece in employment as per Section 25H of the Industrial Disputes Act while the employers propose to take into their employment additional workmen on abolition of the contract system".

[No. L-43012(1)/81-D. III(B)]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

New Delhi, the 4th March, 1982

S.O. 1213.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore in the industrial dispute between the employers in relation to the management of R. Raman, Contractor, C/o Branch Manager, B. R. H. Mines and Dalmia International, Hospet and their workman, which was received by the Central Government on 26th February, 1982.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 20th day of February, 1982

Complaint No. 1 of 1980 in Central Reference No. 1/74

L. Muniswamy, workman
c/o M. Ismail, Vice President,
Dalmia Mine Employees' Union,
Hospet, Complaint.

-Vs-

R. Raman, Contrator,
c/o Branch Manager,
B.R.H. Mines of Dalmia International
Hospet. Opposite Party :

APPEARANCES :

For the Complainant—Sri K. Subba Rao, Advocate Bangalore.

For the Opposite Party—None present.

AWARD

This is a complaint under Section 33-A of the Industrial Disputes Act. It is alleged in the annexure to the complaint that the complainant was chargesheeted for misconduct of theft, fraud or dishonesty in connection with employers' business or property and an enquiry was held and he was finally dismissed from service with effect from 2nd June, 1974. According to the complainant, the enquiry was not conducted in accordance with the principles of natural justice. He has added that at the time of dismissal a reference in Central Reference No. 1/74 was pending before this Tribunal and he was concerned in the said proceedings.

2. This complaint dated 2nd August. 1974 was filed on 10th October, 1980 It would appear that a similar complaint was filed on 5th August. 1974 and the same was ordered to be filed on 2nd January, 1975 as no process fee was paid. In this complaint when notice was taken to the opponent it was returned saying that he is dead Several opportunities were given to the complainant to take steps in the matter and finally on 1st February, 1982 he filed two applications one to implead the management of B.R.H. Iron Ore Mines of Dalmia International and another to implead M. Raj Kumar, contractor alleging that he is the son who is now managing the contract taken by his father M Raman is his successor.

3. When the proceedings in the Central Reference No 1/74 were checked to find out as to whether the complainant was the worker concerned in the said dispute it was notice that the said dispute referred to this Tribunal for decision was to adjudicate as to whether the action taken by the Opponent in terminating the services of four of his employees was justified The said reference was referred on 23rd January, 1974. When the learned pleader for the complainant was asked as to how the said complainant is connected with the dispute that was pending adjudication before this Tribunal he contends that the complainant as well as the other workmen whose dismissal was under adjudication in the previous reference were all dismissed on account of their trade union activities and as the union has sponsored the cause of the other dismissed servants the present complainant who is also the member of the union is the person directly concerned in the dispute.

4. It has been observed in the commentary below, Section 33 at page 1419 in the book of Law of Industrial Disputes by O. P. Malhotra, Third Edition Vol. I that in the absence of any averment and proof that the workman is connected with the pending dispute, even on the broad construction of the expression of "a workman concerned in such dispute", the Tribunal cannot come to the conclusion that the workman is concerned in the pending dispute and, therefore, could claim the protection of Section 33 of the Act. From the papers in the Central Reference No. 1/74 it can be made out that none of the workmen concerned in that dispute had taken a stand that they were dismissed on account of their union activities. The charges against them were of cases of misconduct during the working hours. The charges were found to have been established and they were dismissed from service. The Industrial Tribunal have also held that the dismissal was justified. In the complaint, apart from adding a sentence "I am concerned in the above proceedings" there is no specific detail as to how the complainant is concerned with it. He has not alleged that he was a member of any union and was instrumental in raising the previous dispute. From his own allegations it can be made out that he was charge-sheeted for misconduct of theft, fraud or dishonesty in connection with employers business or property. It is nowhere alleged that his dismissal was on account of any trade union activities or for having joined any union along with

others. It has been observed in the commentary at page 1416 in the above book by relying on a decision of Rajasthan High Court that But where the dispute is raised or sponsored by the union on behalf of an individual workman relating to an incident concerning the act of that workman individually, it cannot be said that every member of such union will be a workman "concerned" in the disptue.

5. It has been observed at page 1418 in the above book that the nature of the dispute should be such as would ordinarily affect the interests of the rest of the workmen or in which the principle applicable to the workmen in general is involved or when it could be said that it was a collective dispute on behalf of the workmen in general. The dispute in Central Reference No. 1/74 which was relating to the dismissal of four of the employees for acts of misconduct on their part cannot be said to be the one in which the present complainant who had been dismissed on independent charge of misconduct is concerned. The complainant is not the workman who would gain or loose anything by any decision in the previous reference and hence it cannot be said that the present complainant is concerned with the previous dispute.

6. Hence I hold that the complaint has failed to establish that the Opponent has contravened the provisions of Section 33 of the Industrial Disputes Act and consequently I hold that the present complaint is not maintainable and is liable to be dismissed in limine. Award is passed accordingly. No costs.

V. H. UPADHYAYA, Presiding Officer

[No. 633/82-D.III.B]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

New Delhi, the 2nd March, 1982

S.O. 1214.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. I, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jharia-Golukdih Area No. IX of Messrs Bharat Coking Coal Limited, At and Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st March, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 15 of 1981

PARTIES:

Employers in relation to the management of Jharia-Golukdih Area No. IX of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., At and Post Office Jharia, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri G. Prasad, Advocate.
For the Workmen—Shri B. Lall, Advocate.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, dated the 23rd February, 1982

AWARD

By Order No. L-20012/210/80-D.III(A), dated the 6th April, 1981 the Central Government being of opinion that an industrial dispute existed between the employers in relation to the management of Jharia-Golukdih Area No. IX of Messrs Bharat Coking Coal Ltd. At and Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the schedule to the order, referred the same for adjudication to this Tribunal.

The schedule attached to the order reads thus.

"Whether the demand of the workmen that Sarvashri Nathuni Prasad of Golukdih Colliery, Surajdeo Yadav of Ghanudih Colliery, Ashok Kumar Mukherjee of Kujama Colliery and Puran Lall Jaitwa of Ghanudih Colliery of Bastacolla Area (Area No. IX) of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, should be promoted with effect from the date of their passing the examination of Electrical Supervisor's Certificate of Competency is justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. After notice to the parties they have filed their respective written statements and rejoinders.

The case of the union as made out in its pleading is as follows. S/Shri Nathuni Prasad, Surajdeo Yadav, Ashok Kumar Mukherjee and Puran Lall Jaitwa working in different collieries in Area No. IX of M/s. B.C.C.L. passed the Electrical Supervisorship Examination with effect from 13-3-78, 8-11-78, 9-11-78 and 8-11-78 respectively. While the management promoted the other workmen in Areas other than Area No. IX where the concerned workmen were working automatically to the posts of Asstt. Foremen from the dates of their passing the Electrical Supervisorship Examination, the said management promoted the concerned workmen in Area No. IX with effect from 12-9-79 even though they had passed the aforesaid examination previously as mentioned above. This action of the management in promoting the concerned workmen with effect from 12-9-78 has not only affected them financially but also their seniority has been affected in relation to their counterparts in other areas. Therefore, the action of the management so far as the concerned workmen are concerned is discriminatory. M/s. Bharat Coking Coal Limited although maintains uniformity in wage structure service conditions and promotion policy in respect of their workmen working in different areas still they in respect of the concerned workmen have not followed the same. It is very much necessary to maintain uniformity as stated earlier because workmen under the management are transferable from one area to another. The management of Area No. X of the company automatically promoted different electricians working in that area to the post of Asstt. Foreman from the very dates when they passed Electrical Supervisorship Examination. This is evident from the letter of the General Manager of Area No. X dated 10-5-79. The act of the management in not promoting the workmen concerned from the dates they passed Electrical Supervisorship Examination gave rise to discontentment and so they made a demand before the concerned authorities to give them promotion to the posts of Asstt. Foreman with effect from the dates they passed Electrical Supervisorship Examination. That demand not having been conceded the present dispute has been raised. On these allegations the union prays that the demand of the concerned workmen to be promoted with effect from the dates when they passed the Electrical Supervisorship Examination be declared to be justified, that they be treated as Electrical Supervisors from the dates of their passing the examination and that they be paid their wages and other benefits accordingly.

The case of the management may be briefly stated thus. The Area Office not being a mine the Central Government cannot be the appropriate government in respect of the workmen working in the said office and therefore the reference is bad in law. About 1600 workmen are employed in Golukdih Colliery, about 2900 workmen are employed in Ghanudih colliery and about 1050 workmen are employed in Kujama Colliery. The dispute not having been supported by a substantial number of workmen empolyed in all these three collieries the sponsoring union cannot claim to represent the workmen in the case. Neither the concerned workmen nor the sponsoring union having made a demand on the employers regarding the present dispute, the dispute cannot be said to be an industrial dispute. It not being a condition of employment that the concerned workmen would be promoted with effect from the dates of their passing Electrical Supervisorship Examination the demand is wholly unjustified. Promotion to a higher post is purely a managerial function and the Tribunal has no jurisdiction to direct promotion of the concerned workmen as claimed. The condition precedent for promotion not having been satisfied by the workmen they cannot claim promotion from the dates of their passing the examination. Promotion to the post of Asstt. Foreman are made on the basis of selection on merit after electricians qualify themselves in the aforesaid examination. This promotion also is made on the recommendation of the D.P.C. on area basis and not

company-wise. In that view the workmen cannot make a grievance in the present case that their seniority would be affected as they have not been promoted on the dates they have passed the examination. The employees cannot claim promotion as a matter of right simply because they qualify themselves for the promotion by passing an examination. It is not at all correct to say that promotion to the post of an Asstt. Foreman from that of an electrician is automatic on the latter's passing the examination. As there was no vacancy in the cadre of Asstt. Foreman the promotion of the concerned workmen could not be made on the dates they passed the examination as claimed. Each area of B.C.C.L. is a separate unit and is an individual establishment. Seniority of workmen in one area cannot be compared with the seniority of workmen in another area. The reference being a post dated one has become infructuous as the concerned workmen have already been promoted with effect from 12-9-79 long before the demand. A Tribunal cannot give retrospective effect to its award for a period prior to the date of the demand. The management in these circumstances claims that the demand of workmen be held not to be justified and if he held that they are not entitled to any relief.

3. In course of hearing the union has examined one witness, namely, WW-1 who is no other than one of the four concerned workmen. He deposes not only on behalf of himself but also on behalf of the three other concerned workmen as follows. He became electrician in 1976. On 9-11-78 he passed Electrical Supervisors Certificate of Competency Examination. Nathuni Prasad passed the said examination in March or April 1978. Surajdeo Yadav and Puran Lall Jaitwa passed the examination on 8-11-78. After passing the examination all the four concerned workmen started working as Asstt. Foreman and even though they worked as such they were not designated as Asstt. Foremen till 12-9-79. For the period prior to 12-9-79 during which they worked as Asstt. Foremen they were not paid wages admissible to them as such. It is only with effect from 12-9-79 they have been paid wages of an Asstt. Foreman. All of the concerned workmen belong to Area No. IX. An Asstt. Foreman of one area can be transferred to another area. One Bindeswari Nisad of Area No. X was promoted to the post of Asstt. Foreman from the date of his passing examination. The said workman passed the examination a day or two after WW-1 passed the examination. This is all what is stated by WW-1. In course of cross-examination the witness asserts that the claim of the concerned workmen is that they should have been automatically promoted the moment they passed the examination. He is constrained to admit his ignorance as to whether the promotion in Technical Gr. 'C' from amongst the workmen is done areawise. The witness further admits that promotion is made only when there is vacancy and selection by D.P.C. While admitting this he also says that so far as promotion to the post of Asstt. Foreman is concerned an electrician is promoted to the said post as soon as he passes the examination. Regarding his knowledge about promotion of one Bindeswari in Area No. X the witness has no personal knowledge and says that he only heard about it. He is unable to say that if there is a provision in the Standing Orders for transfer of a workman from one colliery to another according to exegency of situation. He denies the suggestion that the concerned workmen were promoted on recommendation of D.P.C. made on 25-9-79. According to him there was no D.P.C. selection so far as the concerned workmen were concerned. He further admits that the four concerned workmen were served with copies of the orders Ext M-5 promoting them to the post of Asstt. Foreman. The witness also admits that after passing the qualifying examination all the four concerned workmen even though they were working as Asstt. Foremen they were mentioned in the Attendance Register as Electricians only. He has admitted Exts. M-6 to M-9 to be the orders under which the four workmen were released from posts of electricians on being promoted to the posts of Asstt. Foreman. He also proves Ext. M-10 the joining report of one of the concerned workmen, namely, Surajdeo Yadav. The witness for the management MW-1 says that for the last six months he has been working in the office of Area No. IX. He says that prior to that he was working as Executive Engineer of Dobari Colliery included in Area No. IX and that Surajdeo Yadav one of the concerned workmen was working under him in that colliery. The witness denies the fact that Surajdeo was assigned the duties of an Asstt. Foreman before he was promoted. With regard to the three other concerned workmen he also deposes to the same effect. According to the witness there is no rule in the company to promote an electrician to the post of Asstt. Foreman from the date the former passes the examination. In course of cross-examination the witness admits that the requisite qualification for promotion of an electrician to a post of an Asstt. Foreman is passing the Electric Supervisor Certificate Examination. The witness also denies the suggestion that when the four concerned workmen after passing the examination demanded promotion to posts of Electrical Supervisor the company created posts of Asstt. Foreman Tech. Gr. 'C' to meet their demand. The witness also pleads his ignorance as to whether office of Area No. IX recommended to the head office that the four concerned workmen having passed qualifying examination should be promoted to the posts of Asstt. Foreman in the same manner in which electricians have been promoted in Area No. X. The witness also denies the existence of any policy adopted by the company to promote all the workmen passing Electrical Supervisor Certificate Examination to posts of Asstt. Foremen from the date of their passing. He also pleads his ignorance as to whether any workman in Area No. X has been promoted to the post of Asstt. Foreman from the date of his passing examination. Besides the aforesaid oral evidence as many as 11 documents have been relied upon by the management and they have been marked as Exts. M-1 to M-11 for the company whereas only one document marked Ext. W-1 has been relied upon by the union.

Mr. B. Lal learned counsel for the union argues that originally there was no post known as the post of Asstt. Foreman in the company. An Electrician after passing the Electrical Supervisor Certificate Examination of competency was entitled to be promoted to the post of an Electrical Supervisor. But in course of time as a good number of electricians passed the qualifying examination and their promotion to the next higher grade was not possible immediately after their passing the examination there was a demand by the electricians for creation of another promotional avenue for them before they were promoted to the grade of an Electrical Supervisor. The management of the company realised the difficulties of the electricians passing the examination and the justification of their demand. Therefore the management adopted a policy that as soon as an electrician would pass qualifying examination he would be promoted to the post of Asstt. Electrical Foreman from the date of his passing the examination. This post of Asstt. Electrical Foreman is in between the post of an electrician and the post of a supervisor. According to this policy Mr. Lal submits that management promoted in Area No. X electricians who passed the examination to posts of Asstt. Foreman with effect from the dates they passed the examination. But this policy was not given effect to so far as Area No. IX was concerned where the four concerned workmen while working as electricians passed the qualifying examination on different dates in the year 1978. This act of the management according to Mr. Lal is discriminatory and there is no justification for this. For this contention Mr. Lal relies upon Ext. W-1 which shows that the workmen named therein who were working as electricians in Area No. X have been promoted to posts of Asstt. Foreman with effect from the date of their passing the examination. Against this contention of Mr. Lal, Mr. G. Prasad learned counsel for the management argues that no such policy was ever adopted by the company according to which an electrician from the date of his passing the examination is to be promoted to the post of Asstt. Foreman. Promotion according to Mr. Prasad to the post of Asstt. Foreman is made according to recommendations of the D.P.C. in an area and this promotion is made areawise only. He, however, concedes that before an electrician is considered to be promotion to the post of an Asstt. Foreman he has to pass the examination. His contention is that by passing the examination an electrician qualifies himself for promotion only and his actual promotion depends upon the selection of D.P.C. in the area and upon vacancy in the promotional post. He vehemently challenges the contention of Mr. Lal that promotion is automatic. Mr. Lal in course of his argument at one time wanted to say that the real demand of the concerned workmen in the present case is not for promotion but is only for upgradation of the posts which they were holding on their passing the examination. Such a case as argued by Mr. Lal cannot be accepted at this stage in asmuchas according to the language used in the order of reference the claim of the workmen is not for upgradation of posts which they were holding before but for promotion to posts of Asstt. Foreman So far as the policy alleged to have been adopted by the company regarding automatic promotion of an electrician to the post of an Asstt. Foreman from the date of his passing the qualifying examination as per contention of Mr. Lal, there

is absolutely no evidence. A suggestion regarding the policy made to the management's witness MW-1 has been denied. That being so it is not possible to accept the case regarding the policy as contended by Mr. Lal on solitary evidence of one of the concerned workmen WW-1 without any corroboration. Mr. Lal, however, in this connection relies upon management's document Ext. M-11 which is a copy of letter of Dy. Personnel Manager to the Area Manager of Area No. IX. This letter refers to area office letter dated 8/9th August, 1979 regarding placement of persons passing Electrical Supervisor Certificate of competency examination. The letter also refers to another circular dated 8/9th November, 1978 issued on the subject of placement of holders of Electrical Supervisor Certificate. In this letter the Dy. Chief Personnel Manager has written to the General Manager of the Area that the posts of workmen holding Electrical Supervisor Certificate should be upgraded to posts of Asstt. Foreman through D.P.C. in relaxation to the cadre scheme. Probably on the basis of this letter Mr. Lal as noticed earlier was contending that the present dispute is not a case of promotion but is a case for upgradation. But in view of the language used in the order of reference I have rejected the contention of Mr. Lal and my conclusion is further fortified by looking to the pleading of the parties in which parties have all along taken their stand that the dispute relates to case of promotion. The letter Ext. M-11 while saying that the posts held by electricians who hold Electrical Supervisor Certificate should be upgraded has clearly mentioned that it must be done through D.P.C. It really the Dy. Chief Personnel Manager in his letter Ext. M-11 meant that the posts held by electricians after they pass the qualifying examination should be upgraded he could not have said that the upgradation should be made through D.P.C. The very fact that the Dy. Chief Personnel General Manager says that the upgradation should be made through D.P.C. clearly shows that what the Dy. Chief Personnel Manager meant by using the word "upgradation" was "promotion". Therefore I am of the view that even though the Dy. Chief Personnel Manager has used the word "upgradation" in the letter Ext. M-11 he really means "promotion through D.P.C.". Promotion as has been rightly contended by Mr. Prasad from one post of a higher post is not a matter of right for a workman. In the present case both parties concede that passing of the examination only qualifies an electrician for promotion to the post of an Asstt. Foreman. According to Mr. Lal one who passes the examination has to be made automatically an Asstt. Foreman whereas according to Mr. Prasad that is not so and promotion to the post of Asstt Foreman has to be made through a selection by D.P.C. from amongst electricians who have passed the qualifying examination. This contention of Mr. Prasad is not only supported by Ext. M-11 referred to above but also by Ext. M-5 letter dated 13-10-79 of the management promoting the four concerned workmen. Ext. M-5 clearly shows that four concerned workmen have been promoted to the post of Asstt. Foreman (Elec.) Tech Grade 'C' on initial basic pay of Rs. 572 p.m. as per NCWA-II in accordance with the recommendation of the members of Area D.P.C. This letter mentions serially the names of the four concerned workmen and clearly indicates the new places of posting on promotion as Asstt. Foremen for each of the four workmen. According to this letter the workmen have been advised to report to their duty before their respective Sundts/Managers. This letter further says that the employees concerned will remain on probation for one year in Tech. Gr. 'C' from the date of their reporting for duty. According to this document promotion will be effective from 12-9-79. Ext. M-6 is office order under which Surajdeo Yadav one of the concerned workmen has been allowed to resume duty at the place of his posting as Asstt. Foreman. Ext. M-9 is the office order directing Nathuni Prasad to join the promotional post. Ext. M-10 is the joining report of Suraideo Yadav. Ext. M-7 is an Office Order of Manager, Dobari Colliery saying that Surajdeo Yadav one of the concerned workmen has been promoted to the post of Asstt. Foreman as per Ext. M-5. All these documents discussed above only go to show that even if an electrician passes an examination he does not get automatic promotion to the post of Asstt. Foreman he is only promoted on the recommendation of the D.P.C. held in an area. The above documents also show that there was a meeting of D.P.C. which considered the case of promotion of four concerned workmen and recommended their promotion. Promotion therefore is not automatic as claimed by the union. Ext. W-1 on which much reliance has been placed also prima facie does not show that the workman named therein have been promoted to the posts of Asstt. Foreman automatically with effect from the dates they have passed the qualifying examination. I have already said that the union has signally failed to show that the management has adopted a policy that promotion of an electrician to the post of Asstt. Foreman will be automatic on his passing the qualifying examination. Nothing has been shown to me as pleaded by the union and as argued by Mr. Lal that in order to make available a promotional avenue for an electrician passing the qualifying test the management adopted a policy as said by the union. On the other hand the documents relied upon by the management clearly go to show that promotion of an electrician on his passing the qualifying examination is still made on the selection of a D.P.C. areawise. Mr. Lal in support of his contention that the management in order to afford early promotion avenue for electricians passing the qualifying examination created posts of Asstt. Electrical Foreman just below the post of Supervisors and dapoted a policy that an electrician passing the test would automatically be promoted to the post of Asstt. Electrical Foreman relies upon an endorsement made in Ext. M-10 joining report of one of the concerned workmen, namely, Surajdeo Jadav at the time he joined the post of Asstt. Foreman on promotion. In the aforesaid endorsement the concerned Engineer has made a quarry if Surajdeo Yadav would be authorised to work as electrical supervisor. According to Mr. Lal the endorsement shows that an electrician on passing the test automatically becomes an Asstt. Electrical Foreman and is able to discharge the duties of a supervisor. I do not understand how the aforesaid endorsement supports Mr. Lal's contention. It may be mentioned here that under Wage Board's recommendations of 1967 electrical staff have been classified into three grades, namely, 'A', 'B' and 'C' and as per the recommendation there is no post of a supervisor. It is only under rule 131 of Indian Electricity rules 1956 there has to be an electrician who is to be appointed as supervisor. This rule is mandatory. Therefore even if Wage Board's recommendation adopted by management does not recognise a supervisor, the management in compliance with the above rule 131 has to appoint an electrician as a supervisor. So when Surajdeo Yadav joined the post of Asstt. Electrical Foreman on promotion the Engineer made a querry if he would discharge the function of a supervisor. This does not help Mr. Lal's contention in any way. Such being the position I do not find any merit in the demand of the union in the case and hold that the demand of the union in the case that the concerned workmen in Area No. IX should be promoted with effect from the dates of their passing the examination of Electrical Supervisor Certificate of competency is not justified and they are not entitled to any relief. It may be mentioned here that as a matter of fact all the concerned workmen have been promoted by the management after selection by D.P.C. in the area by Ext. M-5 with effect from 12-9-79. It has also been noticed that in pursuance to this order the concerned workmen have joined the promotional posts by filing joining reports. This would go to show that at the time they submitted their joining reports they accepted the order of the management Ext. M-5 showing that on the recommendation of the D.P.C. they have been promoted. Having thus accepted this position they cannot now go back and claim promotion with retrospective effect from the dates they passed the examination. The other points of law raised by the management in its pleading have not been pressed before me at the time of hearing and so this case is disposed of on the footing that those points have not been pressed. The reference is answered accordingly. There will be no order for cost.

B. K. RAY, Presiding Officer

[No. L-20012(210)/80-D.III(A)]

New Delhi, the 5th March, 1982

S.O. 1215.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Security Headquarters, Post Office Jealgora, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd March, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

Reference No. 43 of 1981

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES: Employers in relation to the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Security Headquarters, Post Office: Jealgora, District Dhanbad and their workman.

APPEARANCES:

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.
On behalf of the workman—Shri B. K. Lath, Advocate.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 24th February, 1982

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947, The Central Government by its order No. L/20012/92/81-D.III (A) dated 24th June, 1981 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Security Headquarters, Post Office Jealgora, District Dhanbad in stopping from service Shri Bansidhar Gararia Night Guard of Lodna colliery with effect from the 5th July, 1979 is justified? If not to what relief is the said workman entitled?"

2. The concerned workman, Shri Bansidhar Gararia was admittedly a night guard in Lodna colliery of M/s Bharat Coking Coal Ltd. His case is that he was stopped from service w.e.f 5th July, 1979. In his written statement plea is that he was illegally transferred vide office order No. BCCL/C/S/76G-89-554 dated 22-3-76. He was further released vide letter No. L/Supdt./Release order dated 30-3-79. His further case is that vide letter No. BCCL/CS/76/G-89/689 dated 31-3-79 his transfer order was kept in abeyance. According to him he has all along been reporting for duty but he has not been paid wages since 22nd March, 1976. He was further told on 5-7-79 by the DIG, Security Chief that he should consider himself to be discharged. In the instant case his prayer is that the stoppage of work since 6-7-79 is illegal, unwarranted arbitrary and unjustified. His further prayer is that he should be ordered to be reinstated with full back wages.

3. The clear case of the management is that the concerned workman was found old infirm and limping and complained of severe pain in his leg. If was noticed that he was unable to perform his duties. He was therefore ordered to appear before the medical board for examination. The medical board examined on 4-5-76 and found him medically unfit to perform his duties as night guard. As a result of the medical examination the concerned workman was retired by letter dated 8-6-76 which was duly received by him on 14th June, 1976. Thereafter the concerned workman did not make any protest against the order of retirement. The management denied that at any time the concerned workman approached the DIG, Security Chief to present his case. According to the management he approached the Asstt. Labour Commissioner (C); Dhanbad alleging that he was stopped from duty on 5-7-79. The management thus have prayed that the case of the concerned workman should be dismissed.

4. In order to substantiate their case the management examined three witnesses and proved two documents. The document, Ext. M-1 shows that the concerned workman Shri Bansidhar Gararia was examined on 4-5-76. He gave out the age as 50 years but by appearance his age was estimated to be 60 years. In column No. 8 it was found that he had artherits with limping gait. This report, Ext. M-1 was proved by Dr. A. M. Kundu who was one of the members of the medical board. The report was recorded by Dr. S. R. Dutta who was the Chairman of the medical board. In his evidence he has also said that the concerned workman had Osteo artheritis on the right knee with limping gait. In his opinion he could not work efficiently as night guard. MW-2 Shri S. K. Banerjee had identified the concerned workman before the medical board. His evidence is that the concerned workman put his LTI on the report in his presence. MW-3 has been working since 1971 as head clerk in Lodna colliery. He knows the concerned workman. He has proved the office copy of the letter dated 8/10-6-76 issued to the concerned workman under the signature of Shri A. K. Saha, Superintendent of collieries. He has further said that the concerned workman received the original letter of superannuation (Ext. M2) and put his LTI on the office copy. Now, Ext.M2 shows that on the basis of the medical report the concerned workman was found to have completed the age of 60 years and was therefore superannuated. He was directed to be paid one month salary in lieu of notice of retirement. He was further directed to hand over the quarter and to collect his dues.

5. On behalf of the concerned workman no oral evidence was adduced. Even Shri B. K. Lath, Advocate who appeared for him was not available to cross-examine the last witness, MW-3. He did not produce any witness nor was present for argument. The argument from the side of the management was heard.

6. It appears that as far back as in May, 1976 this concerned workman was medically examined and found to be medically unfit to perform his duties on account of artheritis in his right knee and his limping gait. He was further found to be 60 years of age. Although there is no enough material in Ext.M1 the medical report to come to a definite conclusion with regard to his age, it is apparent that the concerned workman cound not work as night guard with the desease he was suffering. Ext.M2 will show that he was superannuated and he was also given one month's pay in absence of any prior notice of retirement. It will appear that from the side of the management Ext.M2 was issued as an order of retirement on medical ground and in lieu of notice he was given one month's pay. This action justifies the retirement of the concerned workman though may be prematurely. It is clear that no fault could be found in the action of the management in the steps taken to retire the concerned workman.

7. It will appear that in the written statement no such plea has been taken to criticise the action of the management in his premature retirement. In fact the concerned workman does not talk about his retirement at all. He talks about the transfer and cancellation of the transfer in 1979. There appears to be no basis for the same and this has been denied be the management. It is clear that the management could not have permitted him to work after the order of retirement served on him on 14-5-76.

8. Thus having considered all aspects of the case, I hold that the action of the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Security Headquarters, Post office Jealgora, District Dhanbad in stopping from service Shri Bansidhar Gararia night guard of Lodna colliery with effect from the 5th July, 1979 is justified. Consequently the concerned workman is entitled to no relief.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012/92/81-D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 2nd March, 1982

S.O. 1216.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kunustoria Colliery of M|s Eastern Coalfields Ltd., PO Topsi, Disstt. Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-3-1982.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 13|81

PRESENT:

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Kunustoria Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd, P.O. Topsi, Dist. Burdwan.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. Das, Advocate.

For the Workman—Shri C. S. Mukherjee, Advocate

INDUSTRY : Coal.

STATE: West Bengal.

Dated, the 24th February, 1982

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers confered on them u|s 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(60)|80-D.IV(B) dated April, 1981.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kunustoria Colliery of Eastern Coalfields Ltd., in placing the workman Shri B. K. Lala in Grade II from 16-10-74 to 18-9-75 and in Technical Grade 'C' from 19-9-75 to 31-12-78 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The case of the workman is that he was originally appointed at Lachipur Colliery in 1958 and was subsequently transferred to Kunustoria Colliery in 1962 where he was designated as Time Keeper but he was actually performing the job of a Loading Supervisor. After nationalisation such anomalies including the present one were regularised and he was re-designated as Loading Supervisor with effect from 16-10-1974 but he was not given Grade I which the only grade applicable to the post. The concerned workman made representation before the management but meanwhile on 19-9-1975 he was promoted to the post of Despatch Superintendent, but this time also he was not given legitimate grade i.e. Technical Grade B. A dispute was raised and during conciliation proceeding the management wanted some time to rectify the mistake but the concerned workman was put in, Technical Grade B only with effect from 1-1-79 though he should have been given Technical Grade B from 19-9-1975. As the conciliation failed hence this reference.

3. The prayer of the concerned workman is that he should have been given Grade I from 16-10-1974 to 18-9-75 and Technical Grade B from 19-9-1975 to 31-12-1978 with consequential relief.

4. The defence of the management is that the concerned workman Sri B. Ke. Lala was previously serving as a Despatch Clerk Grade II in Kunustoria Colliery and he was given provisional promotion to work as Loading|Despatch Supervisor in Grade I in the colliery with effect from 16-10-74 as per order of the General Manager dated 6-10-1974. It is submitted that while granting provisional promotion it was clearly mentioned that the ultimate promotion of the concerned workman to the post would be decided by the Departmental Promotion Committee (D.P.C.) along with other eligible employees and it was also clearly mentioned that the said provisional promotion would not create any claim for his regular promotion to the said post and pending such regularisation he would be entitled to difference of wages payable for the higher post. It is stated that from 16-10-1974 to 18-9-75 the concerned workman got the pay of Grade I though substantially he was in Grade II and it was a provisional promotion.

5. It is also stated that the post of Despatch Superintendent is not a Wage Board post and as such the management decided to place such promotees in Technical Grade C of the Wage Board who were in Grade II and in Technical Grade B who were in Grade I and as the concerned workman at the material time was in substantial Grade II he was placed in Technical Grade C from 19-9-1975 and subsequently he was promoted to Technical Grade B from 1-1-1979. It is submitted that on the ground of provisional promotion the concerned workman is claiming Technical Grade B which is not justified.

6. The point for consideration is as to whether the action of the management of Kunustoria colliery of Eastern Coalfields Ltd., in placing the concerned workman in Grade II from 16-10-1974 to 18-9-1975 and in Technical Grade C from 19-9-1975 to 31-12-1978 is justified. If not, to what relief is the concerned workman entitled.

7. In support of his case the concerned workman has examined himself and has also filed certain documents marked Exts. W-1 to W-9. These documents indicate the work which the concerned workman was performing during the relevant period.

8. On behalf of the management no witness has been examined but three documents Exts. M-1 to M-3 have been filed.

9. It is admitted on behalf of the workman that from 16-10-1974 to 18-9-1975 he was given a provisional promotion in Grade I and he received the difference of wages in between Grade II and Grade I. It is also admitted by both the parties that if from 16-10-1974 to 18-9-1975 the concerned workman be deemed to be in Grade I then automatically he was to get Technical Grade B from 19-9-1975 to 31-12-1978. But according to the management as in between the period 16-10-1974 to 18-9-1975 the concerned workman was in substantive post of Grade II hence from 19-9-1975 he was rightly placed in Technical Grade C and not in Technical Grade B.

10. The entire case however hinges on the interpretation of Ext. M-1 dated 31-10-1974. It reads as follows :

"Shri B. K. Lala, Despatch Clerk, Grade II, Kunustoria Colliery is promoted provisionally as Loading Supervisor Grade I at Kunustoria colliery subject to his regular promotion to the post along with other eligible employees through D.P.C.

Pending his regular promotion to his post, as stated above, he will be entitled to the difference between his existing basic wage and stage just above it in the scale of Loading Supervisor, Grade I. He will, however, till such time as he is promoted through D.P.C. continue to draw his salary in the scale of Despatch Clerk, Grade II.

This provisional promotion will not, however, create a claim for him for his regular promotion to the post of Despatch Supervisor. This orde.| shall take effect from 16-10-1974. This issues with the approval of A.G.M. Area IV."

Thus from a perusal of this office order it will appear that though the concerned workman was provisionally promoted as a Loading Supervisor Grade I, but it was subject to his regular promotion along with other eligible employees through D.P.C. and pending his regular promotion he was held to be entitled to the difference between his existing basic wage and Grade I in the scale of Loading Supervisor. It was also mentioned in this letter that till regular promotion is made through D.P.C. the concerned workman will continue to draw his salary in the scale of Despatch Clerk Grade II and this provisional promotion will not create a claim for him for his regular promotion to the post of Despatch Supervisor. In accordance with this letter another office order Ext. M-3 was issued to the concerned workman.

11 From a perusal of Ext. M-1 thus it will appear that the promotion to Grade I as Loading Supervisor to the concerned workman was a provisional one but he was substantially in Grade II. It is contended on behalf of the management that if the concerned workman would have been in substantial Grate I then automatically he would have got the Technical Grade B from 19-9-1975 but as his substantive post was in Grade II he was given Technical Grade C from the said date.

12. This contention of the management appears to be convincing on the basis of the aforesaid letter. From a perusal of Ext. M-2 it will however appear that a D.P.C. was

constituted in September, 1975 which showed that 16 Depatch Superintendents were required in the area and accordingly 16 persons were promoted to the post of Despatch Superintendents. Out of these 16, 11 were promoted to Technical and Supervisory Grade B as they were in clerical Grade I or in Technical and Supervisory Grade C. Further as there were no applicant in Clerical Grade I other 5 posts were filled up from the applicants who were in clerical Grade II but having sufficient experience in loading and despatch of coal they were placed in Technical and Supervisory Grade C. From this letter it will also appear that there are two categories of Despatch Superintendents viz Grade C and Grade B. In accordance with this letter as the applicant was substantially in Grade II hence he was placed in Technical and Supervisory Grade C.

13. The question would have been otherwise if the concerned workman would have been in substantive post of Grade I as in that case he was automatically entitled to Technical Grade B from 19-9-1975.

14. The letter Ext. M-1 clearly indicates that the promotion to Grade I to the concerned workman was only a provisional one subject to the recommendation of the D.P.C. No D.P.C. had been held and the concerned workman had not been given the Grade I by regular promotion. In such circumstances when the concerned workman was in substantive Grade II he could not claim Technical Grade B when such promotion was taken up in September, 1975. Taking into consideration the substantive post and grade of the concerned workman he was rightly placed in Technical Grade C by the management with effect from 19-9-1975. The concerned workman has already got Technical Grade B from 1-12-1979. Moreover the question of promotion is a function of the management and the Tribunal cannot direct the management to promote any of his employees.

15. Considering the evidence and documents on the record, I hold that the demand made by the workman is not justified and the action of the management in placing the concerned workman in Grade II from 16-10-1974 to 18-9-1975 and in Technical Grade C from 19-9-1975 to 31-12-1978 is justified. In the circumstances the concerned workman is not entitled to any relief.

16. I give my award accordingly.

J. N. Singh, Presiding Officer

[No. L-19012(60)/80-D.IV(B)]

S.O. 1217.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govtral Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery, P.O. Gelhapani, District Surguja (Madhya Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd March, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(22)/1980

PARTIES

Employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery, Post Office Gelhapani, District Surguja (M.P.),

AND

Their workman represented through the Secretary, Khan Mazdoor Parishad (CITU) North Chirimiri Colliery, P.O. Gelhapani, District Surguja (M.P.)

APPEARANCES

For Workman—Shri L. N. Malhotra, Advocate

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate

INDUSTRY : Coal DISTRICT : Surguja (M.P.)

AWARD

Dated February 22, 1982.

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour to this Tribunal for adjudication of the following dispute vide Notification No. L-22012/79-D.IV(B) dated 25th March, 1980 —

"Whether the action of the management of North Chirimiri Colliery, Post Office, Gelhapani, District Surguja (Madhya Pradesh) in not regularising Shri J. N. Ghosh as Canteen Manager is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The claim of the workman, Shri J. N. Ghosh, hereinafter referred to as the workman, is that since the year 1975 he was placed as a Canteen Incharge/Manager of the Chirimiri Colliery in the Surguja district and in that capacity has been discharging the duties of preparing summary of sales, Statement of purchases made, maintenance of account and all other registers, taking the attendance of the staff working in the canteen and submit all these accounts to the management. It is further stated by him that he has all along been addressed as a Canteen Incharge. Consequently, according to him, he is entitled to be regularised as a Canteen Manager.

3. The claim of the management is that the workman was appointed as a casual mazdoor in the beginning and that he was never placed either as a Canteen Incharge or as a Canteen Manager. The work which the workman, according to the manager, is doing is maintenance of rough accounts as Salesman under the control and supervision of the Labour Welfare Officer and looking to the sales and purchases for the canteen. It is further stated that there is neither any post of a Canteen Manager nor there is any justification to regularise the workman as the Canteen Manager. The Labour Welfare Officer, according to the management, looks after all the accounts, correspondences, disciplinary action pertaining to the canteen which is required to be maintained under the Mines Act. The post of a Canteen Manager, according to the management, requires certain educational qualifications and since neither the workman possesses these qualifications nor is there any post of a Canteen Manager the question of appointing or regularising him as a Canteen Manager does not and cannot arise. Lastly, according to the management, only when the post is created on account of necessity for a Canteen Manager the claims of other persons based on merit and/or seniority will be considered by the Departmental Promotion Committee and it is only then that a person can be appointed and/or regularised as a Canteen Manager. If, according to the management, this prescribed procedure is not followed then it would be violation of the rules by which the management is governed.

3. In the rejoinder filed by the workman the pleas taken by him in the statement were repeated and no new plea was raised. In view of the respective pleas of the parties the following issues were framed for decision —

ISSUES

(1) Whether the Khan Mazdoor Parishad has no membership in the colliery of the management and whether it has no locus-standi to espouse the cause of the workman Shri Ghosh?

(2) Whether the Canteen being a small there is no post of a Canteen Manager at the Colliery Canteen?

(3) Whether the workman Shri Ghosh has no experience and requisite qualification for being appointed as a Canteen Manager.

(4) Whether Shri Ghosh deserves to be regularised as a Canteen Manager?

(5) Relief and costs?

My findings on the aforesaid issues are as under :—

Issue No. 1.—This issue was not pressed by either party. Hence no finding on this issue is necessary.

Issue No. 2.—There is no post of a Canteen Manager in the Colliery and considering the nature and extent of the transactions the management is justified in not having the post of a Canteen Manager in this Canteen.

Issues No. 3 & 4.—No evidence has been given as to what experience is required for the appointment to the post of a Canteen Manager. But according to

the rules of promotion framed by the management the workman does not possess the necessary qualifications for being appointed and/or regularised as a Canteen Manager.

Issue No. 5.—The workman is not entitled to any relief.

4. Oral and documentary evidence has been given by both the parties in support of their respective claims. My reasons on the aforesaid findings are as under :—

5. Issue No. 1.—As already stated above, this issue was not pressed and therefore found against the management.

6. Issue Nos. 2 & 3.—According to the management, the Canteen, in which the workman is employed, is a small canteen and there is no post of a Canteen Manager in this Canteen. The workman has not given any documentary evidence to show that though there is a post of a Canteen Manager in this Canteen the managerial functions of the person incharge of this canteen are being performed only by the workman and not by any body-else. In his statement, the workman has stated that he maintains all the accounts of the canteen and does all such other work as is necessary for its proper working. Further, according to him, the canteen is run on no loss no profit basis but accounts are worked out to ascertain the profit and loss. He has referred to certain documents Ex. W/7, W/8, W/9, W/10 to W/13, W/14, W/15, W/18 to W/25 which according to him relate to the accounts of the canteen. These accounts are maintained in registers. On a perusal of the canteen accounts regarding sales and purchases it is found that in the accounts Ex. M/6, M/7, M/8, M/12, M/10 as also Exts. M/5, M/13, M/9 and M/11 for the period 12th February, 1975 to 28th July, 1980 the daily sales in the canteen made and accounted for by the workman varied between Rs. 60, 100, 150 and sometimes Rs. 200. On the purchase side in the accounts Ex. M/7, M/8 and Ex. M/12 purchases varied between Rs. 850—1200 to 2000 at a time. These purchases were made for storing provision in the canteen and were accounted for by the workman to the Labour Welfare Officer. No norms has been fixed by the mine management as to what should be the total purchases to be made for the canteen but one thing is clear that a lump sum is given to the workman for making certain purchases and they were accounted for in the accounts book.

7. In the first paragraph of his statement the workman says that besides him there is one cashier, a cook and a canteen boy. But besides this statement there is no evidence to show that such is the strength of the canteen. Thus so far as the oral and documentary evidence given by the workman concerned, it is not established that he is either qualified to become a Canteen Manager or that there is a post of Canteen Manager on which he is working or that he is entitled to be regularised as a Canteen Manager.

8. In his cross-examination he admits that he initially started as a daily paid mazdoor under a contractor and was then designated as a cook for about three months getting the wages of Category III workman. Regarding his educational qualification, he says that he has passed only VIII standard examination. At page 5 of his statement he admits that he works according to the instructions of the Labour Welfare Officer who occasionally comes to the canteen for inspection. Lastly he admits that he had neither any order in writing of the management nor any other documents to justify his claim for being appointed as a Canteen Manager. He professed ignorance regarding the minimum qualification for being appointed as a Grade II Clerk.

9. So far as the management is concerned, it is clear from Ex. M/1, M/3 and M/4 that the workman has all along been addressed by the management as a General Mazdoor (Canteen). Vide Ex. M/3 the Lab. Welfare Officer had called upon the workman to submit the statement of sales, purchase and profit for the period from April, May and June, 1976 so that the same may be put up before the Managing Committee. Vide Ex. M/4 the management directed the workman while addressing him as a General Mazdoor about certain wastage noticed in the items prepared at the canteen. Ex. M/15 is a letter from the Manager to the Administrative Officer by which certain details were furnished about the yearly sales from April to March, 1976 (about Rs. 36,709). Ex. M/16 shows that there is a Managing Committee of which the Labour Welfare Officer and three others are members. It was the function of this Committee to fix the prices of the canteen commodity and discuss some other allied matters. The management has also filed an office order dated 9th/10th June, 1978 indicating the norms for promotion of the members of the ministerial staff upto the level of U.D.C./ Grade I clerk. The qualifications and experience required for the post of a Canteen Manager are as under :—

A. **Grade III Clerk to UDC/Grade II Clerk.**

Experience :

(i) 1 year for matriculates or other equivalent qualification as Gr. III clerk.

(ii) 3 years in respect of non-matriculates as Gr. III Clerk.

Basis :

(i) For matriculate, seniority should be the main criteria subject to satisfactory performance.

(ii) For non-matriculate, test to determine the literacy and their fitness or otherwise for promotion is to be taken.

B. **LDC/Gr. II Clerk to UDC/Gr. I Clerk.**

Experience : one year as LDC/Gr. II Clerk.

Basis : Seniority should be the main criteria subject to fitness for the higher post.

The workman is admittedly a non-matriculate and according to the official records he has no experience on the clerical side. It is, therefore, not possible to say that according to the norms prescribed by the management he is eligible either for appointment or for promotion as a Grade II Clerk and entitled to the appointment on scale of pay admissible for the post of a Canteen Manager according to the Wage Board Recommendations.

10. The management's witness Shri G. G. Sachdeva (M.W. 1) has stated that from 1974 the workman was appointed as a General Mazdoor and attached as a Service Boy in the Canteen and occasionally he worked as a cook and for that he was paid the difference of wages between the wages of a cook and service boy. In 1977, according to him, he was regularised at Cat. II workman and since then he has been working and has been paid also as a Cat. II Mazdoor. He further stated that the Canteen is directly in the charge of the Labour Welfare Officer and the workman only maintains a rough account of the sales and purchase. This fact is clearly borne out from the registers, produced in this case and to which I have already made a reference above. He refers to the constitution of the Managing Committee and its functions. Regarding the man power budget the witness has stated that it is prepared and approved by the Manager and appointments are made only accordance with the man power budget. In the management there was never a proposal for the appointment of a canteen manager. The other witness, Shri S.I. Siddiqui (MW2) says that he is working as a Superintendent of the Hotel and the canteen and that there is no post of a Canteen Manager in the Canteen. Regarding the workman he has stated that though he started as a Service Boy then as a Cook but on his representation he was designated as Salesman. He also says that it was he who looked after all the accounts of the canteen and he used to sign them.

11. It was suggested to him in cross-examination that his signatures appearing on the accounts register were put by him only with a view to show that evidence may be created about the canteen being supervised by a person other than the workman Even if this suggestion is taken to be true that does not improve the case of the workman. Any salesman discharging his duties in the canteen has to maintain a rough account of the purchases made by him and the proceeds from sales received. This is the only work which the workman appears to be doing in this case. There is no evidence that he is exercising his managerial functions in the Canteen so as to justify his regularisation/promotion as a Canteen Manager. Some one who is put incharge of making some purchases of raw materials and selling for the canteen has to maintain some accounts. By doing this work only he cannot claim to be the position of the Canteen Manager. In my opinion, therefore, the management's evidence also does not help the workman. I therefore find that the canteen in the colliery is

not of such size that it requires a Canteen Manager to be posted therein and that the workman Shri J. N. Ghosh does not have either experience or qualifications for being appointed regularised as a Canteen Manager.

12. Issue No. 4.—In view of the findings given above the workman is not entitled to be regularised as a Canteen Manager.

13. Issue No. 5.—The workman is not entitled to any relief. Both the parties to bear their own costs as incurred in these proceedings.

AWARD

For the reasons aforesaid the award is that the management of the North Chirimiri Colliery Post Office Gelhapani, District Surguja (M.P.) is justified in not regularising Shri J. N. Ghosh as Canteen Manager and that the workman is not entitled to any relief.

Both the parties to bear their own costs as incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L-22012(19)/79-D.IV(B)]

S.O. 1218.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamuna Colliery of M/s. Western Coalfields Ltd., P.O. Kotma, District Shahdol (Madhya Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd March, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(17)/1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamuna Colliery of Messrs Western Coalfields Limited, Post Office, Kotma, District Shahdol (M.P.);

AND

Their workman represented through the General Secretary, Koyla Mazdoor Sabha, P.O. Dhanpuri, District Shahdol (M.P.).

APPEARANCES :

For Union—Shri Jagdish Singh.

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Shahdol (M.P.)

AWARD

Dated : February 22, 1982.

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour to this Tribunal for adjudication of the following dispute vide Notification No. L-22012(22)/80-D.IV(B) dated 13th April, 1981 :—

"Whether the action of the management of the Jamuna Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Kotma, District Shahdol, in superannuating with effect from 1st January, 1980 Shri Ram Garib, son of Govind, Pump Operator, is justified in view of the variations in the age of the workman recorded in different documents? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The claim of the workman, Shri Ram Garib, hereinafter referred to as the workman, is that his date of birth was 1st January, 1930 but the management of the Jamuna Subarea of the Western Coalfields Limited, hereinafter referred to as the management, treated his date of birth as 1st January, 1920 and by an order dated 18th December, 1979 retired him with effect from 1st January, 1980. According to the workman, he produced documentary evidence in the form of Identity Cards, School Leaving Certificate and Medical Certificate etc. but his date of retirement was not revoked. He accordingly raised his dispute as regards the date of retirement but without any success. Consequently after conciliation proceedings having failed the present dispute was referred to this Tribunal for adjudication.

3. The claim of the management is that from the management's records his date of birth was 1st January, 1920 and on completing the age of superannuation he was validly retired on 1st January, 1980.

4. In view of these respective contentions of both the parties as per order passed on 28th July, 1981 the only issue between the parties was as to whether the management was justified in retiring the workman from 1st January, 1980?

5. My finding on the issue referred to above is that the management was fully justified in retiring the workman from the post of Pump Operator with effect from 1st January, 1980 as from the management's records his date of birth was found as 1st January, 1920 and not 1st January, 1930. Reasons for the aforesaid findings are as under :

6. The workman examined himself and produced documentary evidence also. Ex. W/1 and Ex. W/2 are the Identity Cards which are usually given to a workman working in a mine to ascertain his identity for working in the mine. Ex. W/3 purports to be a certificate issued from a primary school on 3rd January, 1980 which shows his date of birth as 5th August, 1934. Similarly Ex. W/4 is another School Leaving Certificate dated 23rd June, 1950 in which the date of birth is shown as 5th August, 1934. Ex. W/5 is a Certificate from the Civil Surgeon, Shahdol in which the apparent age of the workman has been shown as 46 years on 5th January, 1980.

7. In his oral evidence the workman has not given any indication as to where and when he was born. No other witness has been examined by him who could give any evidence about either the actual or the probable date of birth of the workman. Accordingly the question about the date of birth has to be decided on the basis of the aforesaid oral and documentary evidence only.

8. Before I proceed further to decide the aforesaid question, I may refer to the documentary evidence given by the management. Form B Register is a Register which every Mine Manager is required to maintain under the Mines Act. At Serial No. 167 the workman's name is entered at Ex. M/2 in which his date of birth is shown as 1st January, 1920. This entry purports to bear thumb impression of the workman. Ex. M/1 is a statutory Declaration Form to be made by the workman working in a coal mine with regard to his Provident Fund account. In this declaration which bears the thumb impression of the workman and is signed by the Manager of the Colliery dated 16th June 1967 The workman has described his date of birth as 1st January, 1920. This declaration also contains the other particulars regarding the identity of the workman, the name of the nominee entitled to receive the Coal Mines Provident Fund account in the event of the workman's death.

9. According to the management's witness Shri M. S. Chandrashekher the entries in Ex. M/1 and Ex. M/2 are entered in the statutory document and he has referred to them from the official records.

10. It would thus appear that there are documents produced by both the sides in support of their respective claims In my opinion, the documentary evidence given by the workman is not only unworthy of reliance but not proved also. The persons who issued the Identity Cards have not been examined. It is, therefore, not clear as to on what basis the date of birth of the workman was entered as 1st January, 1930. The date of issue of those cards is not specified. The authority who issued those cards is also not indicated in any of these two documents In Ex. W/2 there appears some overwriting also. In the School Certificates Ex W/3 and W/4 the date of birth is given as 5th August, 1934 which according to the workman himself is not correct. The registers on the basis of which these two certificates were issued by the school Authorities have also not been produced. The

entries in Ex. W/4 are in two different inks. If the Certificate Ex. W/3 was issued on 3rd January, 1980 by the Headmaster of the Primary School, then it could not have been difficult for the applicant to summon all the records so that the entries made in these documents could have been ascertained. So far as the Certificate of the Civil Surgeon is concerned, it is of no evidentiary value. Any certificate given by a Doctor without radiological examination on the basis of physical appearance only is not even indicative, much less conclusive of the exact age of the person concerned. Radiological examination in marginal cases can fix the age of a particular person on the basis of assification test, but that too leaves a ma gin of couple of years on either side I, therefore, attach no importance to the Certificate of the Civil Surgeon who also has not been summoned to prove that it was he who had issued the certificate. Had he been examined he could have been questioned as to on what basis he put the apparent age of the workman as 46 years. This has not been done. The certificate, in my opinion, is not at all of any evidentiary value.

11. As regards the oral evidence given by the workman I have already indicated above that it is not at all indicative of his date of birth. Hence no reliance can be placed on it.

12. Thus on a consideration of oral and documentary evidence given by the workman I find that he has not proved that his date of birth was 1st January, 1930. So far as the management's documentary evidence is concerned it contains of entries in the statutory documents and the other document in the form of declaration by the workman himself. If the workman while subscribing to the Provident Fund and nominating his nominee gave his date of birth as 1st January, 1920 then unless it is proved that the entry was fraudulently made by the management with any ulterior motive till then this document should be deemed to conclusive evidence for the date of birth

13. In a mine hundreds and thousands workers are employed and every one is required to subscribe to the Provident Fund and fill up a Declaration Form to indicate his Nominee. It is not suggested that the entries made in this Declaration signed (thumb marked) by the workman any fraud or mispresentation or coercion was exercised by any officer of the management to facilitate his premature retirement. The entry in the statutory register Form B also shows his date of birth as 1st January, 1920 I am clearly therefore of the opinion that the management's documents are genuine and they have recorded the date of birth as given by the workman himself. No doubt, there are different dates mentioned in the Identity Cards, School Leaving Certificates and the Medical Certificate But the entries in all these documents are inconsistent to each other. These variations therefore do not help the workman As already stated above, the documentary evidence adduced by the workman is not reliable and is not conclusive of the workman's date of birth. Accordingly, in my opinion the date of birth of the workman was 1st January, 1920 and he was rightly retired on completing the age of 60 years on 1st January, 1980.

14 Accordingly for the reasons given above, the award of the dispute referred to in this case is that the management of the Jamuna Colliery of Messrs Weste n Coalfields Limited (inadvertantly mentioned as Eastern Coalfields Limited in the Schedule to the order of reference) Post Office Kotma, District Shahdol was justified in superannuating the workman, Shri Ram Garib S/o Govind, Pump Operator, with effect from 1st January, 1980. The workman is accordingly not entitled to any relief. Both the parties are directed to bear their own costs as incurred.

Sd/-
S. R. VYAS, Presiding Officer
[No L-22012(22)/80-D.IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 9th March, 1982

S.O. 1219—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Banki Colliery of Western Coalfields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th March, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(43)/1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Banki Colliery of Western Coalfields Ltd., P.O. Banki Mogra, District Bilaspur (M.P.) and their workman Shri Maniram S|o Shri Makhan represented through the Chhatishgarh Khadan Karkhana Mazdoor Union P.O. Bankimogra, District Bilaspur (M.P.).

APPEARANCES :

For Union—Shri Rambilash Shobhnath.
For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Bilaspur (M.P.)

AWARD

Dated : February 27, 1982

In exercise of the powers conferred by Clause (d) of Subsection (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide its Notification No. L-22012(47)|79-D.IV(B) dated 24th|26th July, 1980 :—

"Whether the management of Banki Colliery of M|s. Western Coalfields Limited, Post Office Bankimogra, District Bilaspur is justified in not regularising Shri Maniram S|o Makhan as Loader Operator and in denying him the wages of Category VI with effect from 22nd April, 1975 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Briefly stated the facts alleged by the workman in this dispute are these, Shri Maniram, hereinafter referred to as the workman, was employed as a Loader in the Banki Colliery, Post Office Bankimogra, District Bilaspur by the management of this Colliery, hereinafter referred to as the management, on 6-5-1965 in Category IV. On 15-10-1974 another employee by name Shri Dhani Ram Coal Cutter Loader Operator in Category VI had retired and on his place the workman was employed. Since then he is working as a Loader Operator. An order to this effect was passed by the Colliery Manager, Shri I. B. S. Sinha, on 22 4-1975. He was issued Identity Card also for this post. In spite of these facts the workman is not given the Category IV wages of a Loader Operator|Coal Cutter Operator though other employees have been given that designation and wages also. The workman, therefore, claims that he should be regularised from 22-4-1975 in Category VI as a Loader Operator with all the consequential benefits attached to that category.

3. The claim of the workman is denied by the management on the ground that prior to this reference the workman had filed an application under Sec. 33-C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act (L.C. Case No. 11|79) and in that case also the workman had made a claim similar to the claim made in this reference. The decision in that case was that the workman is not entitled to the computation of his wages on the basis that he was a Category VI worker. It is further urged by the management that there is neither any Coal Cutting Machine in the Banki Colliery nor is there any post of a Coal Cutter Operator. Consequently, there was neither any occasion nor any necessity to appoint the workman on the post claimed by him.

4. In the rejoinder filed by the management to the statement of the workman the same pleas were raised as were raised in the statement of claim. The workman does not appear to have filed any rejoinder to the statement of the management.

5. No issue appears to have been raised in this case for adjudication between the parties. However, considering the dispute referred to for adjudication the following issues appear to be the only issues for trial :—

ISSUES

1. Whether the workman, Shri Maniram S|o Shri Makhan is entitled to be regularised as a Loader Operator and the wages of a Category VI workman from 22-4-1975?

2. To what relief is the workman entitled to ?

My findings on the aforesaid issues are under :

Issue No. 1 :—The workman, Shri Maniram S|o Shri Makhan is not entitled to be regularised as a Loader Operator and placed in Category VI with effect from 22-4-1975 and that he is not entitled to the wages of this category.

Issue No. 2 :—The workman is not entitled to any relief.

Reasons for the Aforesaid Findings :

7. Issue No. 1:—In support of his claim the workman has examined himself and produced the Identity Card Ex. W|1, the Authorisation Ex. W|2 and three other documents Exts. W|3, W|4 and W|5. He also examined one Shri Kripa Ram (W.W.2). The management filed certain documents and examined Shri M. B. Mathur, Sub-Area Manager of the Colliery. Having considered the aforesaid evidence, I am clearly of the view that the workman is not entitled to the claim made by him.

8. Before proceeding further I may refer to the workmen's claim made by him in I.C. Case No. 11|79 decided on 28-7-1979. In that case the workman had contended that though he was authorised and confirmed on the post of a Loader Operator but instead of being paid the wages of Category VI he was being paid the wages of Category IV. Consequently, he claimed to be entitled to a sum of Rs. 4000 as the difference of wages between the two categories. The claim was denied by the management on merits. The decision in this case was that the workman was neither appointed nor he officiated as a Coal Cutter Loader Operator; that he was not appointed on that post; that the claim is frivolous and is liable to be rejected.

9. The claim thus decided in the previous case is precisely the same claim made in the present proceedings. No doubt under Sec. 33-C(2) the claim for regularisation|promotion|proper categorisation etc. could not be decided but the findings given in that case that he was not appointed as a Cutter Loader Operator is a finding which is conclusive between the parties. It was not shown as to how the workman could, inspite of the aforesaid finding, make the same claim in the present proceedings.

10. In his statement, the workman does not say as to when and by which authority he was appointed on the post claimed by him. Though in his statement of claim he alleged that by appointment order passed on 22-4-1975 the Colliery Manager appointed him as a Cutter Loader Operator but that appointment order has not been produced in that case. If such an appointment order had been in existence it could not have been difficult for the workman to produce it and if the same had been tendered the same could have concluded the issue between the parties. Accordingly I find that no such appointment order was issued in favour of the workman. The workman relies on Ex. W|1, W|2, W|3 and W|4. Ex. W|1 is an Identity Card in which his designation is shown as Cutter Loader Operator. It neither bears any date of issue nor there is any evidence to show as to by him it was issued. In Ex. W|2, he has been described as a Loader Operator. Similar is the description given in Ex. W|3 and Ex. W|4. On the basis of these documents only the workman cannot contend that he was duly appointed by a competent authority from one lower post to another higher post. It was necessary for the workman to examine the authority concerned and prove that his designation specified in the documents were correctly recorded.

11. In his cross-examination he was confronted with his statement in the previous case under Sec. 33-C(2) Ex. M|1 is a service record of the workman and when confronted with this he denied that it bears his thumb impression. In this service record maintained in the Colliery he has been designated as Assistant Loader Operator in Cat. IV from 1973 todate. The management's witness Shri Mathur, Sub-Area Manager of the Colliery, has also stated that the workman is employed only as a Category IV workman and that he is being paid wages of that category only. Regarding the authorisation Card Ex. W|5 the witness says that it only means that the workman is authorised, but is not indicative that he is appointed on a particular post. Lastly according to him, promotions are always made by written orders and not oral. He has referred to the office record viz wage sheets etc. and stated that the workman was never promoted as a Category VI workman at any time. It would thus appear from the evidence of both the parties that the workman has been holding the substantive post in Category IV only and was never promoted. There is also no evidence except that of the workman and his witness W.W.2 Shri Kripa Ram, who apparently had no knowledge about the nature of work done by the workman, to show that the workman is actually working from any particular date as Category VI worker. Consequently in my opinion, the workman has failed to prove that either he was appointed on 22-4-1975 on a post in Category VI or that he actually worked from any particular date in Category VI or that he is either on facts or in law entitled to be regularised as a Category VI workman. Consequently he is neither entitled to be regularised nor paid the wages of Category VI worker from 22-4-1976.

12. Issue No. 2:—The workman is not entitled to the relief claimed by him.

13. As a result of the above discussions I hold that the management of M/s. Western Coalfields Limited, Post Office Bankimogra, District Bilaspur is justified in not regularising Shri Maniram S|o Shri Makhan as Loader Operator and in denying him the wages of Category VI workman with effect from 22-4-1975. In the circumstances of the case both the parties shall bear their own cost : incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer.

[No. L-22012(47)|79D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer.

का० आ० 1220—मैसर्स ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डम-डम, कलकत्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं जो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा मे संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितो को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी का व्ययगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे, उन मृत सदस्यो के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसो को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/76/81-पी०एफ-2]

New Delhi, the 3rd March, 1982

S.O. 1220.—Whereas Messrs Gramophone Company of India Limited, Dum Dum, Calcutta (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and, where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/76/81-P.F. II]

का० आ० 1221.—मैसर्स स्टम्प शूले एंड सोमप्पा लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फैक्टरी, हसूर रोड, बंगलौर-560034 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/91/81-पी०एफ० 2]

S.O. 1221.—Whereas Messrs Stumpp Schucle and Somappa Limited Regd. Office and Factory, Harus Road, Bangalore-560024 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act with 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for the payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/91/81-P.F. II]

का०आ० 1222.—मैसर्स संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड यशवंतनगर, डाकघर बाया संदूर, जिला बल्लारी, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितियों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय आदि के किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/(93)/81-पी०एफ०-2]

S O 1222—Whereas Messrs Sandur Manganese and Iron Ores Limited, Yeshwanthnagar, P.O. Via Sandur Bellary Distt. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/(93)/81-P.F. II]

का०आ० 1223—मैसर्स दि अल्काली एंड केमिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, पो० बा० सं० 9093, 31, चौरंघी रोड, कलकत्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक चंदा या अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप संलबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यथापेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में, कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दे दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/115/81-पी० एफ०-2]

S.O. 1223.—Whereas Messrs. The Alkali & Chemicals Corporation Limited, P.O. Box. No. 9093, 34 Chouringhee Road, Calcutta, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said

Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014|(115)|81-P.F. II]

का० आ० 1224.—मैसर्स पणयम सिमेन्ट्स एण्ड मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वायर डिविजन बंगलौर-560068 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3(क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/106/81-पी० एफ०-2]

S.O. 1224.—Whereas Messrs. Panyam Cements and Mineral Industries Limited, Wire Division, Bangalore-560068 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance peremia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/106/81-P.F. II]

का० आ० 1225—मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 7 बंगलौर 560002, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में विफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014/67/78-पी एफ-2]

S.O. 1225.—Whereas Messrs. Bharat Earth Movers Ltd., P.B. No. 7, Bangalore-560002, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(67)/78-PF-II]

का० आ० 1226—एमको बैटरीज लिमिटेड, यूनिटी बिल्डिंगस, श्री नरसिम्हाराजा स्क्वेयर, पोस्ट बाक्स नं० 8 बंगलौर-560002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय

लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/62/81-एफ०-2]

S.O. 1226.—Whereas Messrs Amco Batteries Limited, Unity Buildings, Sri Narasinharaja Square, P.B. No. 8, Bangalore-2 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/62/81-PF.II]

का० आ० 1227.—मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कलामशेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक भविष्य निधि आयुक्त, केरल को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, केरल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो यह छूट न दिये जाने की दशा में उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35034/15/81 पी०एफ० II]

S.O. 1227.—Whereas Messrs. Hindustan Machine Tool Limited., Kalamassery, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Kerala and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014/(15)/81-P.F.II]

का० आ० 1228.—मैसर्स कर्नाटक स्माल इंडस्ट्रीज डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, राजाजी नगर, बंगलौर-44, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अत., केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3(क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती

को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014/73/81-पी०एफ-2']

S.O. 1228.—Whereas Messrs Karnataka Small Industries Development Corporation Ltd., Rajaji Nagar, Bangalore-44 (hereinafter referred to as the said establishment), have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment; a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a traslation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a rasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under th Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the date due, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In cas of default, ff any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for the payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of diceased members who would have been covered under the said Scheme, but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/73/81-PF II]

नई दिल्ली, 4 मार्च 1982

का० आ० 1229.—मैसर्स यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, डाकघर जोका, 24 परगनास, पिन कोड 743512, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सबन्ध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओ का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तो उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस; 35014/32/78-पी०एफ०2]

New Delhi, the 4th March, 1982

S.O. 1229.—Whereas Messrs. Universal Electrics Ltd., P. O. Joka, 24, Parganas, Pin Code 743512, West Bengal (hereina ter referred to as the said establishment), have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Sceneme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a memeber of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premiums in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if, the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Gorup Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Gorup Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Gorup Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme, but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[S. 35014/32/78-PF.II]

का०आ० 1230 मैसर्स दि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, मुख्यालय होस्पेट, जिला बेल्लारी (के०ए०न० 3009) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० 35014/19/78-पी०एफ-II]

S.O. 1230. Whereas Messrs The Ballary Cooperative Central Bank Limited, Hospet Head Office, Bellary District (KN, 30009) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme, but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[S. 35014/49/78-PF.II]

का०आ० 1231.—मैसर्स सिपलैक्स रेयन एण्ड सिल्क प्रोसेसर्स, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है, कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि करने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदत्त रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी का उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/54/80-पी० एफ-2]

S.O. 1231.—Whereas Messrs Simplex Rayon and Silk Processor's Amaraiwedi, Ahmedabad, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinfater referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years, from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujrat and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the said establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the reponsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[S. 35014(54)/80-PF II]

का०आ० 1232.—मैसर्स जी० डी० फार्मेसियूटिकल्स, लिमिटेड, बारोलीन हाउस, गिरीश एवेन्यू, कलकत्ता-3, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अंशदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदेय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, प्रस्ताव अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहा है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया गया है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मृत सदस्य के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त रकम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस०-35014/60/81-पी० एफ०-2]

S.O. 1232.—Whereas Messrs G. D. Pharmaceuticals Ltd., Boroline House, Gurish Avenue, Calcutta-3, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Gorup Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[S. 35014/60/80-PF-II]

का० आ० 1233.—मैसर्स दि कर्नाटक सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़ । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35011/8/81-पी० एफ-2]

S.O. 1233.—Whereas Messrs The Karnataka Central Co-operative Bank Ltd Dharward, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estabishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(8)/81 P.F. II]

का० आ० 1234.—नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता जिसके अन्तर्गत उसके खण्ड कार्यालय और शाखा कार्यालय भी है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अत, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब

उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कार्यचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ा दिये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में लिखी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन सम्बद्ध उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकेगी ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों का संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य के मृत्यु होने पर, उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

स्पष्टीकरण

[सं० एस०-35011/13/81-पी० एफ०-I]

S.O. 1234.—Whereas Messrs National Insurance Company Ltd., Calcutta including its Divisional & Branch Offices (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Scheduled annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of

assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensured prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014|13|81-PF.II]

का० आ० 1235—मैसर्स सूरत डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, सूरत, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को अन्तर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014/19/81-पी०एफ० 2]

S.O. 1235.—Whereas Messrs Surat District Cooperatiev Milk Producers Union Ltd., Surat, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujrat and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, trasfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in he language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee to the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujrat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of de eased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the dealth of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/19/81 P.F. II]

का०आ० 1236—अमैसर्स इन्गरसोल रैण्ड (इंडिया) लिमिटेड, पिन्या इंडस्ट्रियल एरिया, बंगलौर-560058, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सामुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसो को यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार/नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस–35014/60/81-पी०एफ० 2]

S.O. 1236.—Whereas Messrs Ingersoll Rand (India) Limited, Peenya Industrial Area, Bangalore-560058 (KN 16519) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of thte powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunit to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014|60|81-P.F. II]

का०आ० 1237—मैसर्स फेमर, इंडिया लिमिटेड, संसालया, सातवीं मंजिल, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष

की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिस के अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सामुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीना कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिस को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमामृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/75/81-पी एफ-2]

S.O. 1237.—Whereas Messrs Fenner India Limited, Hansalaya, 7th Floor, Barakhamba Road, New Delhi (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Wherean employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of tthe Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving the approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(75)/81-PF. II]

का०आ० 1238—मैसर्स दी प्रिन्टर्स (मैसूर) लिमिटेड, 14 महात्मा गांधी रोड़, पोस्ट बाक्स नं० 5381, बंगलौर-560001, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप अहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बताए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/89/81-पी०एफ०-II]

S.O. 1238.—Whereas Messrs The Printers (Mysore) Limited, 16, Mahatma Gandhi Road, P.B. No. 5331, Bangalore-560001 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

THE SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishments shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, with 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as when amended alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for the payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of diseased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(89)/81-PF. II]

का०आ० 1239.—मैसर्स किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, हुबली—580020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बन्द हो जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सामुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमा कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमामुक्त रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/97/81-पी०एफ० II]

S.O. 1239.—Whereas Messrs Kirloskar Electric Company Limited, Hubli-580020 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

THE SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(97)/81-PF. II]

का०आ० 1240.—मैसर्स इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड चेर्लापटी, हैदराबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनु-

सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उसको स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दे दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/105/81-पी०एफ० 2]

S.O. 1240.—Whereas Messrs Electronics Corporation of India Limited, Cherlapati, Hyderabad (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Schemes, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(105)/81-PF. II]

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1982

का०आ० 1241.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3329 दिनांक 19 नवम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायिकों के संगठनों के साथ परामर्श करके नाम निर्देशित ("शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक संख्या 30,31 और 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

30 डा०एन०जी० भिण्डे, 619, बुधवार पेठ, पूना-2

31. डा० (श्रीमती) ललिता राव, 141, कैलाश, शीव (पश्चिम), बम्बई.

32. डा० पी० के० वैरियर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस आयुर्वेद्यशाला, कोटाकल (केरल)।

[फाइल संख्या यू-16012/8/80-एच०आई०]

New Delhi, the 5th March, 1982

S.O. 1241.—In pursuance of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 3329, dated 19th November, 1981, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (g) of sub-section (1) of section 10, in consultation with organisations of Medical Practitioners recognised by the Government for the purpose)" for the entry against serial numbers 30, 31 and 32, the following entries shall be substituted, namely :—

"30. Dr. M. G. Bhide,
619, Budhwar Peth,
POONA-2.

31. Dr. (Mrs.) Lalita Rao,
141, Kailas,
Slon (West),
BOMBAY.

32. Dr. P. K. Warrior,
President,
All India Ayurvedic Congress Aryavaidyasala,
Kottakal, KERALA.

[File No. U-16012/8/80-HI]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1982

का०आ० 1242.—मैसर्स टाटा इंजीनियरी एण्ड लोको मोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 9) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदान या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही उक्त स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए यह फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. जीवन बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, निरीक्षण प्रभारों का संदाय भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद उक्त स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसे कर्मचारी के बाबत जो उक्त स्थापन छोड़ देता है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत के आने वाले किसी अन्य स्थापन में कार्यभार ग्रहण करता है, उस अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में छोड़कर बाहर जाने वाले कर्मचारी के नाम में वह आनुपातिक रकम अन्तरित करेगा जो उसे उस दशा में संदेय होती जब वह कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 का सदस्य होता।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक जीवन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि जीवन बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

8. जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर पूर्वोक्त जीवन बीमा स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

9. जीवन बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

10. यदि किसी कारणवश उक्त स्थापन के कर्मचारी, स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या पूर्वोक्त जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट उस तारीख से रद्द की गई समझी जाएगी और स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन समझा जाएगा।

11. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, जीवन बीमा स्कीम के अधीन आने वाले किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में कर्मचारी की मृत्यु होने के मास दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

12. उक्त स्थापन अपनी कर्मचारी निधि से कम से कम पांच लाख रुपए की रकम पृथक करेगा और उसे एक पृथक खाते में रखेगा जिसमें स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन उद्भूत होने वाली बाध्यता का निर्वहन किया जाएगा। उक्त पृथक खाते में जमा की गई रकम की समय-समय पर पूर्ति की जाएगी जिससे स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन संदाय तत्परता से सुनिश्चित किया जा सके।

[सं० एस 35014/24/77-पी एफ-2]

ए०के० भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 6th March 1982

S.O. 1242.—Whereas Messrs. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, Jamshedpur (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment or premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of life insurance, which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme, for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer in relation to the said establishment shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns and payment of inspection charges shall be borne by employer of the said establishment.

4. The employer in relation to the said establishment shall display, on the Notice Board of the said establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, with the

amendments thereof alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. The employer in relation to the said establishment shall arrange in respect of an employee who leave the said establishment and joins another establishment covered under the said Act to transfer to the Insurance Fund in respect of the other establishment the proportionate amount that would have been payable had been a member of the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 to the credit of the outgoing employees.

6. Where an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund under the said Act or the provident fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in the said establishment the employer in relation to the said establishment shall immediately enrol him as a member of the Life Cover Scheme.

7. The employer in relation to the said establishment shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding any thing contained in the Life Cover Scheme, if on the death of the employee, the amount payable under the Life Cover Scheme afo resaid be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay difference to the Legal heir or nominee of the employees.

9. No. amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to express their point of view.

10. Where, for any reason employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the establishment at already opted by the establishment or the benefits to the employees under the Life Cover Scheme are reduced by any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment be treated as covered under the said Scheme.

11. Upon the death of an employee covered under the Life Cover Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the death of the employee.

12. The said establishment shall set apart from their working fund sum of Rs. five lakhs and the same shall be kept in a separate account from which obligations arising under the Life Cover Scheme of the esfablishment shall be discharged. Amounts credited to the said separate account shall be replenished from time to time to ensure prompt payment under the Life Cover Scheme of the establishment.

[No. S. 35014/24/77-PF. II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1982

का०आ० 1243.—भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2242 तारीख 24 मई, 1971 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, गुन्टूर के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री नयनी कृष्णामूर्ति को उक्त श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एस-11020/3/82-डी० 1.ए०]
एल० के० नारायणन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1982

S.O. 1243.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court, Guntur, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2242 dated the 24th May, 1971;

Now, therefore in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Nayani Krishnamurthy, as the Presiding Officer of the said Labour Court.

[F. No. S-11020/3/82/DIA]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1982

का०आ० 1244.—भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 2 दिसम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3418 में, जो तारीख 19 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में पृष्ठ 3917 पर प्रकाशित की गई थी, पृष्ठ 3917 पर लाइन 21 में "श्रीमती ए० रेखा" के स्थान पर "श्रीमती ए० रोबा" पढ़ें।

[फा०सं०यू 23017/5/80 एम 4]
जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th March, 1982

S.O. 1244.—In the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3418 dated 2nd December, 1981 published at pages 3917-3918 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated December 19, 1981, at page 3918, in line 29 for "Mrs. A. Rekha" reads "Mrs. A. Roba".

[F. No. U-23017/5/80-MIV]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1981

का० आ० 1245.--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 36 के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट आम सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है:—

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की सूची, 1979-80

अध्यक्ष

श्री जे० बी० पटनायक

श्रम मंत्री

भारत सरकार

उपाध्यक्ष

श्री एन० आर० लस्कर

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,

भारत सरकार

सदस्य

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :

3 रिक्त

4. सचिव,
भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय

5 श्री आर० के सुब्रह्मण्य,
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय।

6. डा० बी० सकरन,
महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,
भारत सरकार ।

7 श्री एन० के पाण्डा,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय ।

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

8. श्री जी० आर० नायर,
सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,
श्रम, रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ।

9 श्री ए० अली,
सचिव, असम सरकार,
श्रम विभाग ।

10. श्री आई० सी० कुमार,
प्रधान सचिव, बिहार सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

11 श्री पी० पी० राठौर,
सचिव, गुजरात सरकार,
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन विभाग।

12. श्री एच० एल० गुगनानी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

13. श्री ओ० पी० यादव,
सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

14. श्री आई० डी० शर्मा,
श्रम आयुक्त, जम्मू व कश्मीर सरकार।

15. श्रीमती अचला मौलिक,
आयुक्त एवं सचिव, कर्नाटक सरकार,
समाज कल्याण तथा श्रम विभाग ।

16. श्री सी० पी० नायर,
विशेष सचिव, केरल सरकार,
श्रम विभाग ।

17. श्री फकीर चन्द,
सचिव, मध्य प्रदेश सरकार,
श्रम विभाग ।

18. श्री एन० वी० सुन्दरराजन,
विशेष सचिव, महाराष्ट्र सरकार,
नगर विकास तथा लोक स्वास्थ्य विभाग ।

19. श्री एस० मारवीन,
सचिव, मेघालय सरकार,
श्रम विभाग ।

20. श्री के० एस० पुरी,
सचिव, नागालैंड सरकार
गृह विभाग ।

21 श्री यू० एन० मलिक,
सचिव, उड़ीसा सरकार,
श्रम रोजगार तथा आवास विभाग ।

22. श्री हरदयाल सिंह,
सचिव, पंजाब सरकार,
स्वास्थ्य तथा कल्याण विभाग ।

23. श्री बृजेन्द्र सिंह
श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार,
श्रम विभाग ।

24. श्री सी० रामचन्द्रन,
सचिव, तमिलनाडु सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

25 श्री एस० के० घोसाल,
सचिव, त्रिपुरा सरकार,
श्रम विभाग ।

26. श्री प्रकाश चन्द्र सक्सैना,
आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,
श्रम विभाग ।

27. श्री एन० कृष्णा मूर्थी,
सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार,
श्रम विभाग ।

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि :

28 श्री एस० एल० चावड़ा,
श्रम आयुक्त,
दिल्ली प्रशासन ।

नियोजकों के प्रतिनिधि :

29. श्री आर० एन० जोशी
30 श्री सी० आर० पाल
31. श्री मदन मोहन मंगलदास
32 श्री पी० चेल्लमल राव
33 श्री एन० एस० राव

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

34. श्री जी० बी० चिटनिस
35. कुमारी ई० डिसूजा
36. श्री पी० के० शर्मा
37 श्री पी० बी० संकरानारायणन, विधान सभा सदस्य ।
38. रिक्त

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि :

39 डा० जे० मजूमदार
40. वैद्य श्री श्रीकृष्ण मुलतानी

संसद के प्रतिनिधि :

41. सैयद मब्बुल मलिक
42 रिक्त
43. रिक्त

पदेन सदस्य :

44 श्री हर मन्दर सिंह, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थाई समिति के सदस्यों की सूची 1979-80

अध्यक्ष

श्री आर० के० ए० सुब्रह्मण्य,
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय

सदस्य

2. रिक्त
3. डा० बी० संकरन, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार ।
4. श्री एन० के० पाण्डा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ।

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

5. श्री सी० पी० नायर, विशेष सचिव, केरल सरकार, श्रम विभाग ।
6. श्री एन० सी० सुन्दररामन, विशेष सचिव, महाराष्ट्र सरकार नगर विकास तथा लोक स्वास्थ्य विभाग ।
7. श्री एन० कृष्णा मूर्थी, सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार, श्रम विभाग ।

नियोजकों के प्रतिनिधि :

8. श्री सी० आर० पाल
9 श्री पी० चेल्लमल राव
10. श्री एन० एस० राव

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

11 श्री जी० बी० चिटनिस
12 कुमारी ई० डिसूजा
13 श्री पी० बी० संकरानारायणन, विधान सभा सदस्य ।

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि :

14 डा० जे० मजूमदार

संसद के प्रतिनिधि :

15. रिक्त

पदेन सदस्य :

16. श्री हर मंदर सिंह, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

चिकित्सा हितलाभ परिषद के सदस्यों की सूची, 1979-80

अध्यक्ष

महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार,

सदस्य

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :

2. डा० ईश्वर दास बजाज, उप-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (के० स० स्वा० यो०), भारत सरकार ।
3. डा० बी० एम० चरनालिया, चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

4 डा० टी० एन० साधी उप-निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं, आंध्र-प्रदेश सरकार ।
5 डा० बी० एल० दास प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, असम सरकार ।
6. डा० ए० पी० वर्मा, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, श्रम तथा रोजगार विभाग, बिहार सरकार ।
7. लैफ्टीनेंट कर्नल बी० डी० मिश्र, निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, (कर्मचारी राज्य बीमा योजना), गुजरात सरकार ।

8. डा० एस० शाह,
सहायक निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएं (सामाजिक बीमा)
हरियाणा सरकार ।

9. डा० एस० एल० ग्रोवर,
निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाए तथा परिवार नियोजन,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

10 श्री आई० डी. शर्मा,
श्रम आयुक्त, जम्मू तथा काश्मीर सरकार ।

11 डा० के० बी० हनुमन्था रेड्डी,
निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
(चिकित्सा सेवाएं), कर्नाटक सरकार ।

12. डा० एम० राघवन,
प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
केरल सरकार ।

13. डा० पी० एस० दावे,
प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
मध्य प्रदेश सरकार ।

14 डा० आर० सी० ढिंगे,
निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
महाराष्ट्र सरकार ।

15. श्री एस० मारबीन,
सचिव, मेघालय सरकार,
श्रम विभाग ।

16. श्री एस० के० कोचर,
सचिव, नागालैंड सरकार,
गृह विभाग ।

17. डा० पी० सी० रथ,
प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना
उड़ीसा सरकार ।

18. डा० आसा सिंह,
निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए,
पंजाब सरकार ।

19 डा० आर० आर० पुरोहित,
अतिरिक्त निदेशक,
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाए,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
राजस्थान सरकार ।

20 अर्नेस्ट जे० डैविड,
निदेशक, चिकित्सा सेवाए तथा परिवार कल्याण,
तमिलनाडु सरकार ।

21. श्री एम० के० घोसाल,
सचिव, त्रिपुरा सरकार,
श्रम विभाग ।

22. डा० एम० सी० चतुर्वेदी,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

23. श्रीमती आर० घोष,
निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा (चि० हि०) योजना,
पश्चिमी बंगाल सरकार ।

नियोजकों के प्रतिनिधि :

24. डा० बी० डी० कौशल

25. श्री आर० एन० जोशी

26. श्री आर० एल० मोदला

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

27 श्री ए० सी० सैकिया
विधान सभा सदस्य

28. श्री सुमेर सिंह

29. डा० समर राय चौधरी

चिकित्सा व्यावसाय के प्रतिनिधि :

30. डा० (श्रीमती) ललिता राव

31 डा० एन० एन० भट्टाचार्जी

32. आर्य वैद्यान पी० के० वारियर

"कर्मचारी राज्य बीमा निगम" एक नजर में

	31-3-79	31-3-80	1979-80 के दौरान प्रगति
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20	20	—
केन्द्र	375	395	20
कर्मचारी	58,15,900	59,83,000	1,67,100
बीमाकृत व्यक्ति	65,89,500	68,50,000	2,60,500
परिवार एकक	65,89,500	68,50,000	2,60,500
बीमाकृत महिलाए	4,90,650	5,38,750	48 100
कुल लाभाधिकारी	2,55,67,300	2,65,78,000	10,10,700
कर्मचारी जो अभी योजना के अंतर्गत लाने है ।	8,79,700	8,58,000	(-) 21,700
नकद भुगतान कार्यालय	684	691	7
निरीक्षण कार्यालय	169	195	26
क० रा० बी० अस्पताल	65	67	2
क० रा० बी० औषधालय	27	33	6

	31-3-79	31-3-80	1979-80 के दौरान प्रगति
विस्तार			
(क) क० रा० बी० अस्पताल	14,007	14,102	95
(ख) क० रा० बी० अनैक्सियां	550	670	120
(ग) आरक्षित	4,747	4,765	18
जोड़	19,304	19,537	233
राज्य बीमा औषधालय	990	10,30	40
बीमा चिकित्सा अधिकारी	2,992	3,101	109
बीमा चिकित्सा व्यवसायियों के क्लीनिक	4,565	4,734	169

पूंजीगत निर्माण (लाख रुपये में)

स्वीकृत राशि	8944.06	9712.44	768.38
अग्रिम राशि	6864.37	7490.49	626.12

आय तथा व्यय	1978-79	
राजस्व आय	15,765.48	16,979 04
राजस्व व्यय	13,704.52	15,918.80

उपलब्धियां :

1.1 वर्ष के दौरान विशेष रूप से उल्लेखनीय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 16 दिसम्बर, 1979 से उत्तर प्रदेश में 19 केन्द्रों पर 1,67,800 कर्मचारियों के परिवारों को पूर्ण चिकित्सा देख-रेख का विस्तार किया जाना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें लगभग 2,48,140 कर्मचारी परिवार एककों को केवल प्रतिबन्धित चिकित्सा देख-रेख प्रदान की जा रही थी। इन परिवार एककों के लिए पूर्ण चिकित्सा देख रेख का विस्तार करने की आवश्यकता पर काफी समय से उत्तर प्रदेश सरकार पर जोर दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में फिलहाल प्रतिबन्धित चिकित्सा देख-रेख प्राप्त कर रहे शेष 23,800 कर्मचारी परिवार एककों के लिए भी पूर्ण चिकित्सा देख-रेख के विस्तार के अब प्रयास किये जा रहे हैं।

1.2 वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण विकास/सुधार नीचे दिए गए हैं:

(क) निगम ने अपंग बीमाकृत व्यक्तियों को कृत्रिम अंग जुड़वाने, मरम्मत करवाने या बदलवाने के लिये प्रत्येक दिन के लिए कृत्रिम अंग केन्द्र में उनके दाखिल रहने की अवधि के दौरान बीमारी हितलाभ की दर पर पुनर्वास भत्ता मंजूर करने का अनुमोदन किया।

(ख) निगम ने परिवार कल्याण योजना को प्रोत्साहन देने के लिए नसबन्दी/नलीबन्दी आपरेशन करवाने वाले बीमाकृत व्यक्तियों को देय वर्धित बीमारी हितलाभ स्थायी आधार पर जारी रखने का अनुमोदन किया।

(ग) रोजगार चोट हितलाभ की मंजूरी के लिये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की तीसरी अनुसूची में व्यावसायिक बीमारियों की सूची में बारह अतिरिक्त बीमारियां जोड़ी गईं।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थायी अपंगता हितलाभ की आवधिक अदायगियों के रूपान्तरण के लिए एक मुश्त राशि निर्धारित करने की तालिका मौजूदा मृत्यु दर तथा हितसाधन के अनुभव के आधार पर परिशोधित की गई।

(ङ) उन मामलों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है (1) जहां बीमाकृत व्यक्ति एक स्थान पर कार्य करता है तथा रहता है और उसका परिवार उसी राज्य में ऐसे दूसरे स्थान पर रहता है जो एक कार्यान्वित केन्द्र है, तथा (2) जहां परिवार के सदस्य बीमाकृत व्यक्ति के छुट्टी या अस्थायी स्थानान्तरण पर उसके कार्य के स्थान से उसके साथ किसी ऐसे अन्य स्थान पर आते हैं जो उसी राज्य में या अन्य राज्य में एक कार्यान्वित केन्द्र है।

(च) निगम ने सक्रिय चिकित्सा उपचार की आवश्यकता न होने वाले लेकिन न्यूनतम चिकित्सा उपचार तथा देख-रेख की आवश्यकता होने वाले रोगियों के लिए बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य लाभ गृह बनाने का निर्णय किया।

(छ) बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के उपचार तथा पुनर्वास के लिये आवश्यक कृत्रिम अंग, उपकरण तथा साधन चिकित्सा हितलाभ के भाग के रूप में प्रदान किये जा रहे हैं तथा योजना के लाभाधिकारियों को उपलब्ध चिकित्सा देख-रेख के भाग के रूप में डायलैसिस, गुर्दे बदलने, हृदय-शल्य चिकित्सा तथा कार्डियक पेसमेकर की व्यवस्था को शामिल करके चिकित्सा हितलाभ के मान को उदार बनाया गया है।

नये क्षेत्रों में कार्यान्वयन :

1.3 रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान योजना आन्ध्र प्रदेश, बिहार गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में 41 नये क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई तथा इसमें लगभग 13,750 अतिरिक्त कर्मचारी शामिल किए गए। इसके ब्यौरे परिशिष्ट 1 भाग "क" में दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार भी बीमाकृत व्यक्तियों के स्वयं चिकित्सा हितलाभ के हकदार होने की तारीख से ही चिकित्सा हितलाभ के हकदार हो गये। जम्मू व कश्मीर, मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य में तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिये प्रयत्न जारी रहे। इन राज्यों में योजना अभी तक किसी भी केन्द्र पर कार्यान्वित नहीं हुई है। वर्ष के अन्त में योजना विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 395 केन्द्रों में लागू थी तथा स्थापनाओं के नये वर्गों में शामिल किए गए कर्मचारियों को मिलाकर इसमें कुल मिलाकर लगभग 58,59,650 कर्मचारी शामिल थे।

स्थापनाओं के नये वर्गों पर विस्तार :

1.4 आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में विभिन्न कार्यान्वित केन्द्रों में स्थापनाओं के नये वर्गों को योजना के अन्तर्गत लाया गया तथा लगभग 3,080 अतिरिक्त

कर्मचारियों को शामिल किया गया । इसके ब्यौरे परिशिष्ट-1 भाग-ख में दिये गये है । इन कर्मचारियों के परिवार भी बीमाकृत व्यक्ति के स्वयं चिकित्सा हितलाभ के हकदार होने की तारीख से ही चिकित्सा हितलाभ के हकदार हो गए ।

1.5 हरियाणा, केरल तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने शेष केन्द्रों में स्थापना के शेष नये वर्गों पर योजना का विस्तार करने के लिए अपने आशय का छह मास का नोटिस देते हुए प्रारंभिक अधिसूचनाएं जारी की ।

1.6 केन्द्रीय सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप से यथा-अनुमोदित महानगरों तथा शहरों में भवन निर्माण कामगारों पर योजना का विस्तार करने के मामले में राज्य सरकारों से चिन्ता पड़ी जारी रही जा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये समुचित सरकार है । लेकिन दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तावित विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार का विशेष रूप से अनुमोदन मांगे जाने के अलावा इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

1.7 प्रत्येक राज्य में योजना के नये क्षेत्रों में कार्यान्वयन तथा पहले से कार्यान्वित केन्द्रों में रोजगार के नये सैक्टरों पर इसके विस्तार के मामले में निगम प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एक दो-वर्षीय चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करता है तथा राज्य सरकारों से उसके कार्यान्वियन के लिये शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है । कार्यान्वियन/विस्तार के चरणबद्ध कार्यक्रम के पालन की आवश्यकता पर राज्य सरकारों को पत्र व अनुस्मारक लिखकर तथा निगम के प्रधान अधिकारियों द्वारा राज्यों के दौरे के दौरान राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा द्वारा भी दोनों तरह से जोर दिया जाता है । लेकिन योजना के कार्यान्वियन/विस्तार की प्रगति चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुई है जो मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के पास वित्तीय तथा भौतिक साधन उपलब्ध न होने से आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण है । यहां तक कि योजना के विस्तार का स्वयं प्रस्ताव करने वाली राज्य सरकार भी प्राय. कार्यक्रम का पालन नहीं कर पाई है । इसके बावजूद योजना के शीघ्र कार्यान्वियन/विस्तार की आवश्यकता पर समय-समय पर राज्य सरकारों पर जोर दिया जा रहा है । कुछ राज्य सरकार चिकित्सा देख-रेख पर व्यय की अधिकतम सीमा को भी अपर्याप्त बता रही हैं तथा योजना का आगे विस्तार शुरू करने से पहले इसको बढ़ाकर परिशोधित करने के लिए जोर दे रही है । अतः चिकित्सा देख-रेख पर व्यय की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रश्न एक उप-समिति के समीक्षाधीन है तथा आशा है कि अधिकतम सीमा में वृद्धि हो जाने की स्थिति में योजना के विस्तार की गति काफी मात्रा में बढ़ जायेगी ।

1.8 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 41 नये कार्यान्वित क्षेत्रों में लगभग 19,250 अतिरिक्त परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों, यानी लगभग 1,92,400 अतिरिक्त लाभाधिकारियों पर चिकित्सा देख-रेख का विस्तार किया गया । इसके ब्यौरे परिशिष्ट-1 भाग-क में दिये गए है । वर्ष के अन्त में चिकित्सा देख-रेख के अन्तर्गत आने वाले परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों की कुल संख्या 68,50,300 यानी लगभग 2,57,59,200 लाभाधिकारी इसमें बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवार और स्थापनाओं के नये वर्गों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधनों पर उच्चाधिकार उपसमिति की रिपोर्ट तथा उस पर निगम के निर्णय श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है । अक्तूबर, 1979 में श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा नियोजकों व कर्मचारियों के सभी केन्द्रीय संगठनों को उप-समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप संशोधन के प्रस्ताव (कर्मचारी राज्य बीमा निगम की शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना को केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से संबंधित सिफारिशों के अलावा) तथा संशोधन के अन्य प्रस्ताव उनके विचारों के लिये परिचालित किए थे । केन्द्रीय सरकार ने इन प्राधिकारियों/संगठनों से उनकी राय में आवश्यक होने वाले अन्य संशोधनों का सुझाव देने का भी अनुरोध किया था ।

3. अस्पताल में भर्ती

(1) चालू किए गए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा अनैक्सियां

(1) वर्ष के दौरान दो और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल चालू किए गए जिनमें से एक 25 बिस्तर वाला अस्पताल 1-8-1979 से जे.के.पुर (उड़ीसा) में तथा दूसरा 60 बिस्तर वाला अस्पताल 29-11-79 से मंगलौर (कर्नाटक) में चालू किया गया । 19-1-80 को क. रा. बी. अस्पताल मूलाकुन्नाथकावु (केरल) में 10 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई । इसके अलावा वर्ष के दौरान 6 अनैक्सियां, 24 बिस्तर वाली एक रामपुर (उत्तर प्रदेश) में 12 बिस्तर वाली एक मेरठ (उत्तर प्रदेश) में, 12 बिस्तर वाली एक सोनीपत (हरियाणा) में, 24 बिस्तर वाली एक मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में, 24 बिस्तर वाली एक मिरजापुर (उत्तर प्रदेश) में और 21 बिस्तर वाली एक शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) में भी चालू की गई ।

इन संस्थानों में बनाए गए बिस्तरों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

परियोजना का स्वरूप	परियोजनाओं की संख्या	बनाए गए बिस्तरों की संख्या सामान्य	क्षय रोग
अस्पताल	67	12722	1,380
अनैक्सियां	33	364	306
	जोड़	13,086	1,686
		—	14,772

इन अस्पतालों तथा अनैक्सियों के ब्यौरे परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं।

(2) निर्माणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा अनैक्सियां

31-3-1980 को निम्नलिखित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, तथा अनैक्सियां निर्माणाधीन थीं :—

क्रम सं०	स्थान तथा राज्य	बिस्तरों की संख्या सामान्य	क्षय रोग
	अस्पताल :		
1.	गोहाटी (असम)	50	..
2.	फुलवारी शरीफ, पटना (बिहार)	50	..
3.	आदित्यपुर (बिहार)	50	..
4.	बड़ौदा (गुजरात)	200	..
5.	सूरत (गुजरात)	150	.
6.	कलोल (गुजरात)	50	..
7.	राजकोट (गुजरात)	50	
8.	मैसूर (कर्नाटक)	100	.
9.	इंदिरा नगर, बंगलोर (कर्नाटक)	300	..
10.	कांदीवली बम्बई (महाराष्ट्र)	650	..
11.	थाना (महाराष्ट्र)	632	.
12.	शोलापुर (महाराष्ट्र)	120	..
13.	वेलोर (तमिलनाडु)	50	.
14.	नैनी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	100	
15.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	100	.
16.	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	100	.
17.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	100	.
18.	सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	50	..
19.	कल्याणपुर आसनसोल (पश्चिमी बंगाल)		150
20.	रणडेल (पश्चिमी बंगाल)		250
		जोड़ 2,902+400=3,302	

1	2	3
मंगलौर (मौजूदा अस्पताल में निर्माणाधीन विस्तार)		40
	जोड़	2,942+400=3,342

1 तिनसुखिया (असम)	20	..
2 गुलबर्गा (कर्नाटक)	20	.
3 रोबर्टसनपेट, के०जी०एफ० (कर्नाटक)	32	.
4 राजगंगपुर (उड़ीसा)	16	.
5. सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	24	.
6 उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	12	..
7. गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	24	.
8 इटावा (उत्तर प्रदेश)	12	.
जोड़	160	..

3 मंजूर शुदा अस्पताल तथा अनैक्सियां :

निम्नलिखित अस्पतालों तथा अनैक्सियों के नक्शे तथा प्राक्कलन मंजूर हो चुके है लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है :—

अस्पताल :

क्र० स० स्थान तथा राज्य	बिस्तरों की संख्या	
	सामान्य	क्षय रोग
1. राजामुण्डेरी (आन्ध्र प्रदेश)	50	..
2. रांची (बिहार)	50	..
3. कोटा (राजस्थान)	60	..
4. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	50	..
5. ठाकुरपुकुर (पश्चिमी बंगाल)	250	..
जोड़	460	
पाण्डीनगर, कानपुर (मौजूदा अस्पताल में मंजूर किए गए बिस्तर)	100	.
कुल जोड़	560	

अनैक्सियां :

1. कोहलवेर (बिहार)	.	20
2 पिंजोर (हरियाणा)	12	.
जोड़		12+20=32

4 सिद्धान्त रूप में मान लिये गये अस्पताल

निम्नलिखित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का निर्माण सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है। कुछ मामलों में भूमि का अर्जन/क्रय भी कर लिया गया है —

क्रम स० स्थान तथा राज्य		बिस्तरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
1	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	100	
2	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बिहार-शरीफ, पटना (बिहार)	50	
3	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सिमालसण्ला (बिहार)	50	
4	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल झिलमिल (दिल्ली)	200	भूमि खरीदी जा चुकी है।
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, दक्षिणी दिल्ली (दिल्ली)	200	भूमि खरीदी जा चुकी है।
6.	कर्मचारी राज्य बीमा क्षय रोग अस्पताल, दिल्ली (दिल्ली)	150	
7	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, भावनगर (गुजरात)	50	भूमि खरीदी जा चुकी है।
8	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नदियाड़ (गुजरात)	50	
9	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पोरबंदर (गुजरात)	50	
10.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जामनगर (गुजरात)	50	
11.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पटलाद (गुजरात)	50	
12	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात)	500	
13	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बल्लभगढ़ (हरियाणा)	100	भूमि खरीदी जा चुकी है।
14.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बहादुरगढ़ (हरियाणा)	50	
15	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, गुड़गांव (हरियाणा)	50	
16.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, भिवानी (हरियाणा)	50	
17.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, दावनगर (कर्नाटक)	50	भूमि खरीदी जा चुकी है।
18	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, ठोटाड़ा (केरल)	50	भूमि खरीदी जा चुकी है।
19.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पालघाट (केरल)	50	
20.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, फीरोक (केरल)	100	भूमि खरीदी जा चुकी है।
21.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, भोपाल (मध्य प्रदेश)	50	
22.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	100	
23.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	100	भूमि खरीदी जा चुकी है।
24.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नासिक (महाराष्ट्र)	100	भूमि खरीदी जा चुकी है।
25.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बिबेवाडी पूना (महाराष्ट्र)	100	भूमि खरीदी जा चुकी है।
26.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, चिंचवाड, पूना (महाराष्ट्र)	100	भूमि खरीदी जा चुकी है।
27.	कर्मचारी राज्य बीमा (क्षय रोग) अस्पताल लुधियाना (पंजाब)	100	
28	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मण्डी गोबिन्दगढ़ (पंजाब)	50	
29.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, फगवाड़ा (पंजाब)	50	

1	2	3	4
30.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सेलम (तमिलनाडु)	50	
31.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बरेली (उत्तर प्रदेश)	50	
32	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	50	
33.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पिपरी (उत्तर प्रदेश)	50	
34.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	50	
35.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	100	
36	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल श्याम नगर (पश्चिमी बंगाल)	250	भूमि खरीदी जा चुकी है।
37.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल गार्डन रीच (पश्चिमी बंगाल)	100	
38.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल)	100	भूमि खरीदी जा चुकी है।
	जोड़	3550	

5. वर्ष के अन्त तक देश भर में 202 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय (प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी के एक कार्यालय सहित) निगम के अपने भवनों में चल रहे थे। इनके अलावा वर्ष के अन्त तक सारे देश में 48 औषधालय (प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी के एक कार्यालय सहित) विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन थे तथा 9 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के नक्शे तथा प्राक्कलन मंजूर कर दिए गए हैं।

6. 31-3-80 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए मंजूर की गई राशि निम्न प्रकार है :—

परियोजनाओं का वर्ग	31-3-79 की स्थिति के अनुसार मंजूर की गई राशि	31-3-80 की स्थिति के अनुसार मंजूर की गई राशि
	(लाख रुपयों में)	
(क) अस्पताल/अनैक्सियां/औषधालय उपस्कर तथा स्टाफ क्वार्टर आदि	7733.65	8451.14
(ख) महाराष्ट्र सरकार को ऋण	362.15	362.15
(ग) सहायता अनुदान (एम. जी. एम. अस्पताल बम्बई)	100.00	100.00
(घ) निगम के कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर	748.26	799.15
जोड़	8944.06	9712.44

4. कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा देख-रेख का स्वरूप

परिवार (कर्मचारी) एककों को प्रदान की गई चिकित्सा देख-रेख के स्वरूप के संबंध में राज्यवार स्थिति परिशिष्ट-3 में दी गई है।

समितियां, आयोग और सम्मेलन

5. निगम

4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 22 दिसम्बर, 1979 और 18 फरवरी, 1980 की दो बैठकें हुई। इन बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय परिशिष्ट-4 में दिए गए है।

6. स्थायी समिति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति की 28 मई, 1979, 15 सितम्बर 1979, 21 दिसम्बर, 1979 और 17 फरवरी, 1980 को चार बैठकें हुई। इन बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय परिशिष्ट 5 में दिए गए हैं।

7. चिकित्सा हितलाभ परिषद

चिकित्सा हितलाभ परिषद की 17-3-1980 को एक बैठक हुई। परिषद की महत्वपूर्ण सिफारिशें परिशिष्ट-6 में दी गई हैं।

8 क्षेत्रीय बोर्ड

वर्ष के अन्त तक 17 क्षेत्रीय बोर्डों का गठन हो गया था विभिन्न क्षेत्रीय बोर्डों की वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या नीचे दी गई है:

क्षेत्रीय बोर्ड का नाम	बैठकों की संख्या	बैठकों की तारीख
1. आन्ध्र प्रदेश	2	25-6-79 तथा 27-9-79
2. असम	--	--
3. बिहार	1	18-11-79
4. दिल्ली	1	11-2-79
5. गुजरात	1	8-11-79
6. हरियाणा	--	--
7. कर्नाटक	1	20 11-79
8. केरल	3	30-6-79, 29-9-79 तथा 31-3-80
9 मध्य प्रदेश	1	18-12-79
10. महाराष्ट्र	2	18-10-79 तथा 15-1-80
11. उड़ीसा	--	--
12. पंजाब	--	--
13. पांडिचेरी	2	9-5-79 तथा 28-2-80
14 राजस्थान	--	--
15. तमिलनाडु	--	--
16. उत्तर प्रदेश	2	11-5-79 तथा 11-9-79
17. पश्चिमी बंगाल	--	--

अधिकतर क्षेत्रीय बोर्डों ने विभिन्न कारणों से यथा निर्धारित बैठकें नहीं की। आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के विचार से सदस्य सचिवों से विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया है।

9. स्थानीय समितियां

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-क के अधीन वर्ष के अन्त तक सारे देश में 207 स्थानीय सलाहकारों का गठन हो गया था।

10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चिकित्सा सेवाएं और विनिधान समिति द्वारा किए गए कार्य के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बैठकों की संख्या	सूची में शामिल किए गए मामलों में की संख्या	बकाया मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	8	24	—
2	बृहत्तर बम्बई	अनुपलब्ध	166	111
3	पश्चिमी महाराष्ट्र	9	30	4
4	पंजाब	अनुपलब्ध	55	7
5.	पश्चिमी बंगाल	अनुपलब्ध	11	—

11. सामान्य प्रयोजन उप समिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामान्य प्रयोजन उप-समिति ने 9 अक्तूबर, 1979 से 13 अक्तूबर 1979 तक मध्य प्रदेश राज्य का दौरा किया तथा राज्य में काम कर रही विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा संस्थाओं का निरीक्षण किया ।

प्रशासन

12. क्षेत्रीय संगठन

31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल मिलाकर 15 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 344 स्थानीय कार्यालय, 109 लघु स्थानीय कार्यालय, 1 उप स्थानीय कार्यालय और 237 भुगतान कार्यालय कार्य कर रहे थे ।

13. कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 1980 को निगम में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल प्राधिकृत संख्या, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय/कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को छोड़कर, 10,334 थी जबकि 31 मार्च, 1979 को यह संख्या 9715 थी । 31 मार्च, 1980 को मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों की संख्या परिशिष्ट-7 (भाग-1) में दिखाई गई है। निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, दिल्ली के कार्यालय के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों की संख्या परिशिष्ट-7 के भाग-2 में दिखाई गई है।

14. कर्मचारियों का स्थायीकरण

वर्ग "क" तथा "ख" के पदों पर अधिकारियों को स्थायी करने की कार्रवाई संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई है । अधिकांश क्षेत्रों/कार्यालयों में स्थायी रूप से मंजूर पदों पर वर्ग "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है । बाकी कार्यालयों में कर्मचारियों को स्थायी करने की कार्रवाई की जा रही है।

15. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा आरक्षण किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर समय समय पर निर्धारित किया जाये। निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से सीधी भर्ती से भिन्न भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से सीधी भर्ती द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना क्रमशः परिशिष्ट-8 भाग 1, 2 तथा 3 में दी गई है।

16. कर्मचारी राज्य बीमा निगम में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

निगम के कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्रवाई की गई -

1 मुख्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की देखभाल मुख्यालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा की जा रही है ।

2 सभी हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां पहले से ही कार्य कर रही है और हिन्दी कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए इन समितियों की नियमित बैठकें की जा रही हैं ।

3. विशेषकर हिन्दी भाषी राज्यों में काफी मात्रा में पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जा रहा है तथा हिन्दी में प्राप्त अधिकांश पत्रों और कर्मचारियों से प्राप्त अपीलों अभिवेदनों आदि का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है ।

4. सभी हिन्दी भाषी राज्यों में टाइपराइटरों की आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है । आवश्यकताओं का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है । अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिये भी कम से कम एक हिन्दी टाइपराइटर की व्यवस्था कर दी गई है।

5 अधिकांश फार्म द्विभाषी रूप में छपवा लिए गये हैं। नियम तथा नियम पुस्तकों आदि के अनुवाद के प्रबन्ध किये जा रहे है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 तथा निगम के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुवाद को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा इन्हें द्विभाषी रूप में छपवाने की व्यवस्था की जा रही है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम पेंशन नियम पुस्तक का अनुवाद भी किया जा चुका है तथा उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 25 हिन्दी कार्यशालाओं, यानी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में दो-दो, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर व बम्बई में तीन-तीन क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ में चार तथा क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में आठ हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है । अब तक कुल मिलाकर 61 कार्यशाला चलाई गई हैं । अधिक हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के प्रयास किये जा रहे है व अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों को भी, यदि वे चाहे तो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं के आधार पर हिन्दी कार्यशालायें चलाने की अनुमति दे दी गई है ।

7 विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के कार्य के लिए आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है।

8. इस विभाग का खुली तथा सीमित (विभागीय) भर्ती परीक्षाओं में निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती परीक्षा तथा निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक की पदोन्नति परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्रों को (अंग्रेजी के प्रश्नपत्र को छोड़कर) द्विभाषी रूप में छपवाने की व्यवस्था कर दी गई है । उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी में देने का विकल्प है ।

9 अब तक निगम के ग्यारह कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जा चुके हैं जिसका अभिप्राय है कि इन कार्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है ।

10. हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

11. निगम के सांख्यिकीय सार, वार्षिक रिपोर्ट, अधिसूचनायें, बजट तथा वार्षिक लेखे द्विभाषी रूप में छपवाए जा रहे हैं । टेंडर नोटिस करार, लाइसेंस, परमिट आदि भी द्विभाषी रूप में जारी करने के प्रयास किए जा रहे है।

12 राजभाषा नियमों के उपबंधों का कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर चैक-पाइंट्स निर्धारित किए गए हैं । सामान्य आदेश अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

13 लगभग सभी रबड़ की मोहरें द्विभाषी रूप में अथवा हिन्दी तथा अंग्रेजी में अलग-अलग बनवा ली गई है ।

14 मुख्यालय में तथा हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा पुस्तकों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जा रही हैं।

15. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जा रहे हैं।

16 निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक राजभाषा के प्रशिक्षण के लिए निगम के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित एक व्याख्यान दिया जाता है।

17. संगठन एवं पद्धति अध्ययन

वर्ष के दौरान संगठन एवं पद्धति प्रभाग ने ग्रेड-I क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मानक तथा मानदण्ड पर कार्य-मापन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। यह अध्ययन नमूने के तौर पर 3 क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया था।

संगठन एवं पद्धति प्रभाग द्वारा किया गया दूसरा महत्वपूर्ण अध्ययन दिल्ली में पांच से अधिक डाक्टरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में लिपिक वर्गीय, पैरा मैडिकल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मानक तथा मानदण्ड से सम्बन्धित था। उपर्युक्त के साथ-साथ निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली में भी कार्यमापन अध्ययन किया गया।

अंशदानों को बट्टे खाते डालने के कारणों का पता लगाने तथा उन में सुधार के सुझाव देने के विचार से कुछ क्षेत्रों में पिछले तीन वर्ष में बट्टे खाते से संबंधित मामलों का चयन करके अंशदानों के बट्टे खाते डालने के बारे में केस अध्ययन किया गया।

निगम मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं तथा चिकित्सा प्रभाग के अधिकारियों का भी कार्यमापन अध्ययन किया गया।

निगम कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फार्मों को युक्तिसंगत तथा मानक बनाने के विचार से श्रम मंत्रालय की इच्छानुसार निगम मुख्यालय में एक फार्म पुनरीक्षण तथा नियंत्रण एकक स्थापित किया गया। वर्ष के दौरान समिति ने 171 कूटबद्ध फार्मों का पुनरीक्षण किया।

संगठन एवं पद्धति प्रभाग ने नकद प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मानक तथा मानदण्ड तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में अंशदान एकत्र करने की नकद प्रणाली का अध्ययन किया। एक कार्यविधि संबंधी अध्ययन भी किया गया तथा परिशोधित कार्यविधि का सुझाव दिया गया।

उपर्युक्त के अलावा दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रों में नकद अंशदान प्रणाली का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया। इन अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि अंशदान एकत्र करने की नकद प्रणाली संतोषजनक रूप में कार्य कर रही है। अतः यह निर्णय किया गया कि इस प्रणाली का विस्तार एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी अन्य राज्यों में किया जाये।

18. सुझाव पुरस्कार योजना

सुझाव पुरस्कार योजना के अधीन सुझावों की समीक्षा करने के लिए बनाई गई केन्द्रीय समिति ने विभिन्न सुझावों पर विचार किया तथा स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक, कुरीजी को फार्म 6 (विनियम 26 के अन्तर्गत अंशदान कार्ड विवरणी) के परिवर्तन का सुझाव को प्रस्तुत करने में स्थानीय कार्यालय के टीम के रूप में कार्यचालन के दृष्टिकोण के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।

19. अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और बंगलौर में स्थापित किये गये चार मण्डलीय संस्थानों ने निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने स्थानीय कार्यालय प्रबन्धकों तथा बीमा निरीक्षकों के लिए बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता दिल्ली तथा जयपुर में 6 अभिविन्यास (ओरिएन्टेशन) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 118 अधिकारियों ने भाग लिया। इन पाठ्यक्रमों में प्राय 4 या 5 नजदीकी क्षेत्रों के फील्ड अधिकारी भाग लेते हैं और इनमें भाग लेने वाले अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन करने के अलावा स्वतन्त्र विचार विमर्श तथा समस्या समाधान सत्रों के आधार की व्यवस्था की गई।

नवम्बर, 1979 में निगम के मध्य प्रबन्ध स्तर के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में एक "सेवाकालीन" अभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 20 उप-क्षेत्रीय निदेशकों/लेखा अधिकारियों/सहायक क्षेत्रीय निदेशकों आदि ने भाग लिया। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्यविधियों तथा संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के अलावा अधिकारियों को कुछ आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों तथा सतर्कता पद्धति पर भी व्याख्यान दिये गये।

पहली बार बीमा चिकित्सा अधिकारियों के लिए 2 अल्पकालिक "सेवा कालीन" प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए जिनमें से एक पाठ्यक्रम अप्रैल, 1979 में तथा दूसरा पाठ्यक्रम फरवरी, 1980 में क्रमशः नई दिल्ली तथा इन्दौर में चलाया गया जिनमें 70 बीमा चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया।

निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिक/खजांचियों/प्रभारी उच्च श्रेणी लिपिकों/प्रधान लिपिकों के लिये विभिन्न केन्द्रों पर 16 "सेवाकालीन" प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गए जिनमें 306 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। निम्न श्रेणी लिपिकों के लिए मण्डलीय प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा आठ "प्रारम्भिक" प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 167 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा, विभिन्न केन्द्रों पर 28 विशेष "संक्षिप्त प्रारम्भिक" प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 615 नये भर्ती किए गए निम्न श्रेणी लिपिकों ने भाग लिया।

जहां कहीं अंशदान की नकद अदायगी प्रणाली लागू की जा रही है, हमारे प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा एक या दो दिन की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली के सहयोग से निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यकलापों का विस्तार किया गया। विद्यापीठ द्वारा एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डुप्लिकेटिंग मशीन आपरेटरों के लिए तथा एक पाठ्यक्रम चपरासी/संदेशवाहकों के लिए आयोजित किया गया था जिनमें निगम के 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भाग लिया। समीक्षाधीन वर्ष में कुल मिलाकर निगम ने 1324 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने और 70 बीमा चिकित्सा अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

नियोजकों के स्टाफ को प्रशिक्षण

हाल ही में तमिलनाडु में लागू की गई अंशदान की नकद अदायगी की नई प्रणाली में आसानी से बदलने तथा नियोजकों को उसे समझने में सहायता करने के लिए मार्च, 1980 में मद्रास, कोयम्बतूर तथा मदुरै में 9 अर्ध-दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए थे जिनमें नियोजकों के 1,143 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

20. प्रचार

प्रैस, रेडियो तथा टेलिविजन के माध्यम से योजना का प्रचार किया गया और योजना की प्रगति तथा उपलब्धियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से योजना पर वार्ताएं प्रसारित की गई। विभिन्न केन्द्रों पर निगम के अधिकारियों ने कामगारों तथा प्रशिक्षार्थियों को संबोधित किए। शिक्षाप्रद प्रचार के भाग के रूप में "आप और आपकी योजना" नामक पुस्तिका का वितरण किया गया जो विशेष तौर पर बीमाकृत व्यक्तियों को उनके अधिकार तथा दायित्व और हितलाभों को दावा करने की कार्य विधि का ज्ञान कराती है। योजना तथा नकद व चिकित्सा हितलाभों के बारे में पैम्फलेट परिशोधित करके उन्हें अद्यतन किया गया तथा वे अब छपवाये जा रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के फिल्म डिवीजन की सहायता से "कामगारों की सुरक्षा" नामक कर्मचारी राज्य

बीमा योजना पर वृत्त चित्र का निर्माण पूरा किया गया तथा वर्ष के दौरान फिल्म जन साधारण को दिखाने के लिए रिलीज की गई । कामगारो में विशेष प्रचार के लिए फिल्म के अतिरिक्त प्रिंट निगम के इस्तेमाल के लिये प्राप्त किए जा रहे हैं ।

21. **विस्तार क्षेत्र**

योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों आदि की संख्या (परिशिष्ट 9 तथा 10)

परिशिष्ट 9 तथा 10 में योजना के विस्तार क्षेत्र संबंधी ब्यौरे (रोजगार के अतिरिक्त क्षेत्रों को मिलाकर) दिए गए हैं । 31-3-80 को योजना के अन्तर्गत 67,807 नियोजक शामिल थे जबकि एक वर्ष पहले इसमें 61,726 नियोजक थे । इसमें से 64,600 नियोजक कार्यान्वित केन्द्रो में थे । पिछले वर्ष तदनुरूपी संख्या 50,054 थी । शेष 3207 नियोजक अभी कार्यान्वित किए जाने वाले क्षेत्रों में थे । कार्यान्वित केन्द्रो में कर्मचारियों की कुल संख्या 59.83 लाख थी । अभी कार्यान्वित किए जाने वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या 8.58 लाख थी । डाक्टरी इलाज के लिए हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 68.50 लाख तथा परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों की संख्या 6,850 लाख थी । कुल मिलाकर 31-3-80 को डाक्टरी इलाज के लिए हकदार लाभाधिकारियों की कुल संख्या (बीमाकृत व्यक्तियों को मिलाकर) लगभग 265.78 लाख थी ।

22. **चिकित्सा देख-रेख के स्तर में सुधार**

अंतरंग रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था :— 1979-80 वर्ष के दौरान निम्नलिखित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/ अनैक्सियों में 778 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई ।

1. क० रा० बी० अस्पताल, नरोदा अहमदाबाद (गुजरात)	25
2. क० रा० बी० अस्पताल, मंगलौर (कर्नाटक)	64*
3. क० रा० बी० अस्पताल, मुलुन्द (बम्बई)	50
4 क० रा० बी० अस्पताल, अंधेरी (बम्बई)	50
5 क० रा० बी० अस्पताल, वाशी (बम्बई)	200
6. क० रा० बी० अस्पताल, जे० के० पुर (उड़ीसा)	25*
7. क० रा० बी० अस्पताल, सेरामपुर (पश्चिमी बंगाल)	50
8. क० रा० बी० अस्पताल, उलुबेरिया (पश्चिमी बंगाल)	50
9 क० रा० बी० अस्पताल, मानिकटोला (पश्चिमी बंगाल)	100
10 क० रा० बी० अनैक्सी, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	24*
11. क० रा० बी० अनैक्सी, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	24*
12 क० रा० बी० अनैक्सी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	24*
13. क० रा० बी० अनैक्सी, उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	12*
14. क० रा० बी० अनैक्सी, इटावा (उत्तर प्रदेश)	12*
15. क० रा० बी० अनैक्सी, शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश)	24*
16 क० रा० बी० अनैक्सी, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	24*
17. क० रा० बी० अनैक्सी, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	24*

31-3-1980 तक की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कुल 18,512** बिस्तरों की व्यवस्था की गई जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 11 में दिया गया है ।

*नये चालू किए गए अस्पताल/अनैक्सियां ।

**"कर्मचारी राज्य बीमा निगम" एक नजर मे, विवरण मे बिस्तरो की कुल संख्या 19,537 है । यह अन्तर कुछेक निर्मित बिस्तरों के चालू न होने के कारण है ।

23. **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में भरे हुए बिस्तरों की प्रतिशतता और प्रतिदिन प्रति बिस्तर औसत आवर्ती लागत निम्न प्रकार थी ।**

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	व्यवस्था किए गए बिस्तरों की संख्या				1979-80 वर्ष में भरे हुए बिस्तरों की प्रतिशतता	1979-80 वर्ष में प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत
		सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश							
1.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सानथनगर, हैदराबाद	235	45	30	310	75 %	45.00
2.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सीरपुर, कागजनगर	60	—	—	60	72 %	52.30
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, विजयवाड़ा	94	—	16	110	78 %	50.16
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, वारंगल	40	—	10	50	90 %	48.79
5	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अडोनी	40	10	—	50	86 %	44.68
6.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, विशाखापट्नम	99	2	9	110	91 %	57.50
बिहार							
7	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मैथोन	100	—	—	100	79 %	27.89
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मुंगेर	30	—	—	30	57 %	28.37
9.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, डालमियानगर	50	—	—	50	68 %	30.03
दिल्ली							
10.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसई दारापुर	324	76	—	400	90 %	69.72(X)
गुजरात							
11.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बापूनगर, अहमदाबाद	500	—	—	500	91 %	48.45
12.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नरोदा, अहमदाबाद	—	—	225	225	78 %	28.75

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
13.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, फरीदाबाद ।	188	—	12	200	82%	32.11
14.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जगाधरी ।	13	—	47	60	58 %X	46.04
15.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पानीपत ।	15	—	35	50	81%	45.00
कर्नाटक							
16.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, राजाजीनगर बंगलौर ।	335	35	44	414	145%	36.22
17.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, डाण्डेली ।	24	—	—	24	125%	20.60
18.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मंगलौर ।	60	—	—	60	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
केरल							
19	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मुलाकुनाठाकावु (त्रिचूर जिला) ।	—	—	110	110	86%	20.44
20.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अलराम्म (क्विलोन जिला) ।	97	22	—	119	115%	70.49
21.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अलैप्पी ।	51	4	—	55	98%	33.23
22.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, परूरकाडा (त्रिवेन्द्रम जिला) ।	63	12	—	75	125%	23.54
23.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, ओलारीकाडा (त्रिचूर) ।	84	6	—	90	71%	20.33
24.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, उद्योग मंडल । (जिला अरनाकुलम) ।	130	25	—	155	47%	32.33
25.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अरनाकुलम ।	55	10	—	65	75%	32.31
26.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, वाडाक्कुर ।	59	6	—	65	66%	31.48
27.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पारीपल्ली ।	100	—	—	100	123%	21.50
28.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, एजूकोन ।	100	—	—	100	109%	22.12
मध्य प्रदेश							
29.	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) अस्पताल, इन्दौर ।	136	20	—	156	73%	30.96
30.	कर्मचारी राज्य बीमा (चैस्ट) अस्पताल, इन्दौर ।	—	—	52 ×	52	100%	21.92
31.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, उज्जैन ।	65	—	—	65	107%	19.00
32	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, ग्वालियर ।	75	—	—	75(क)	97%	29.27
महाराष्ट्र							
33.	एम० जी० एम० अस्पताल, बम्बई ।	668	17	15	700	94%	73.90(X)
34.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मुलुन्द, बम्बई ।	505	145	—	650	98%	58 88
35.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, वोरली, बम्बई ।	435	60	5	500	81%	59.00
36.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, उल्हास नगर, बम्बई ।	80	20	—	100	93%	68.58(X)
37.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अंधेरी, बम्बई ।	540	100	10	650	67%	64.35
38.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, वाशी, बम्बई ।	—	—	600	600	69%	41.87
39	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नागपुर	170	30	—	200	87%	55.68
40.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, आन्ध्र पूना ।	175	25	120	320	85%	48.00
उड़ीसा							
41.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, चौद्वार ।	44	6	—	50	110%	42.30
42.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कन्सावहल	47	3	—	50	70%	52.86
43	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बृजराज नगर ।	22	3	—	25	60%	79.36(X)
44.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जे० के० पुर ।	20	5	—	25	12%	388.668(?)
पांडिचेरी							
45.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पांडिचेरी ।	50	—	—	50	80%	64.37(X)
46	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अमृतसर ।	80	20	—	100(ख)	90%	73.75(X)

1	2	3	4	5	6	7	8
47	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, लुधियाना ।	80	20	—	100	82%	25 25
48.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जलधर ।	80	20	—	100	—	14 00
	राजस्थान						
49	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जयपुर ।	108	29	—	137	91%	42.60
	तमिलनाडु						
50	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मद्रास ।	486	100	39	625	66%	48 20
51	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कोयम्बटूर ।	370	100	30	500	75%	35.63
52	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मदुरै ।	110	50	12	202	77%	54 63
53.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, के० के० नगर मद्रास ।	140	40	26	206	50%	40 45
	उत्तर प्रदेश						
54.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पांडुनगर, कानपुर ।	212	—	—	212	103%	20.92
55	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, (चेस्ट) आजाद नगर, कानपुर ।	—	—	180	180	77%	14 72
56	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, (प्रसूति तथा सामान्य) कानपुर ।	104	10	—	144	139%	43 49
57	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मोतीनगर ।	76	21	—	100	113%	17 80
	पश्चिमी बंगाल						
58	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, स्यालदाह ।	212	18	—	240(ग)	79%	46.80
59.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कुमारहटी ।	172	4	—	176	100%	36 23
60	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बाल्टीकुरी ।	274	36	—	300(घ)	80%	37.64
61	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सेरामपुर ।	216	—	—	216	72%	36.76
62.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कल्याणी ।	250	—	—	250(ङ)	59% ×	49 11
63	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, उलूबेरिया ।	216	—	—	216	77%	27 93
64	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बलूरबल्ली ।	—	—	150	150	96%	34.86
65	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, गोरहटटी ।	216	—	—	216	90%	29.78
66	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बजबज ।	210	20	—	230(च)	69%	27.46
67	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मानिकटोला ।	150	—	—	150	75%	69.87(X

(क) मंजूर किए गए 100 बिस्तरों में से 65 बिस्तर चालू किए गए है ।

(ख) मंजूर किए गए 125 बिस्तरों में से 100 बिस्तर चालू किए गए है ।

(ग) मंजूर किए गए 250 बिस्तरों में से 230 बिस्तर चालू किए गए है ।

(घ) मंजूर किए गए 416 बिस्तरों में से 300 बिस्तर चालू किए गए है ।

(ङ) मंजूर किए गए 266 बिस्तरों में से 250 बिस्तर चालू किए गए है ।

(च) मंजूर किए गए 300 बिस्तरों में से 230 बिस्तर चालू किए गए है ।

(×) जिन अस्पतालों में कम बिस्तर चालू है उनके बारे में राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे मामले को देखें ।

(X) प्रति बिस्तर प्रति दिन लागत अधिक है । राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे मामले को देखें ।

(?) 1-8-79 को चालू किया गया । एक्सरे मशीन की लागत भी कुल व्यय में शामिल कर ली गई है ।

24 31-3-80 की स्थिति के अनुसार औषधालयों, विशेषज्ञों, बीमा चिकित्सा अधिकारियों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों और एम्बुलेंस संबंधी ब्यौरे परिशिष्ट-11 में दिए गए है ।

बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था ।

25 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 33 मामलों में (27 बीमाकृत व्यक्ति तथा परिवार के सदस्य) कृत्रिम अंग लगाये गए । कुल मिलाकर अब तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 1026 मामलों में (1020 बीमाकृत व्यक्ति तथा 6 परिवार के सदस्य) कृत्रिम अंग लगाये गए या दोबारा लगाये गए ।

बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कृत्रिम दांतों की व्यवस्था ।

25 1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 29 मामलों में (28 बीमाकृत व्यक्ति तथा एक परिवार का सदस्य) निःशुल्क दांत लगाये गए । कुल मिलाकर अब तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 103 मामलों में (102 बीमाकृत व्यक्ति तथा 1 परिवार का सदस्य) कृत्रिम दांत लगाये गए ।

बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चश्मों की व्यवस्था ।

25.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 3,999 मामलों में (2981 बीमाकृत व्यक्ति तथा 18 परिवार के सदस्य) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क चश्मे लगाए गए ।

परिवार कल्याण कार्यकलाप

26 कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने परिवार कल्याण के लिए शिक्षा, अभिप्रेरण तथा सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा योजना में वृद्धि के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रायोजित तथा जन संख्या कार्यकलापों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निधि (अनफपा) द्वारा दी गई निधियों से वर्ष 1976 में परियोजना संख्या आई० एन० डी/674/पी० ओ० 2 को चलाने की जिम्मेदारी ली थी । उक्त परियोजना आरम्भ में 31-12-78 को समाप्त 3 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर की गई थी । त्रिपक्षीय पुनरीक्षण समिति की दिनांक 25-9-1978 को हुई बैठक में इसके कार्य पुनरीक्षण तथा इसके द्वारा

की गई प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए इसके कार्यकलापों को अगले वर्ष, यानी 31-12-1979 तक के लिये बढ़ा दिया गया था और इसके बाद तीन माह यानी 31-3-1980 तक की अगली अवधि के लिये बढ़ा दिया गया था।

1979-80 वर्ष के दौरान परिवार कल्याण परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार है :—

1. नसबन्दी	2333
2. नलीबन्दी	12663
3. कुल बन्ध्यकरण	14996
4. अन्तःगर्भाशय साधन	4169
5. गर्भावस्था को चिकित्सा द्वारा समाप्त करना	3458
6 जारी किये गये निरोध	9,75,216
7 बांटी गई खाने की गोलियां	72,688
8. समकक्ष बन्ध्यकरण	17,429

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिरक्षण कार्यक्रम

27 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम 14 नवम्बर, 1973 को आरंभ किया गया था। योजना के प्रभारी प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों से "अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979-80" के दौरान बाल रोगों से बचाव की व्यवस्था के लिये इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने का निवेदन किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान देश भर में योजना के अन्तर्गत लाभाधिकारियों को 8 50 लाख से अधिक टीके/सेरा आदि की खुराकें दी गई जिससे वर्ष के अंत में दी गई खुराकों की संख्या कुल मिलाकर 31. 50 लाख हो गई।

चिकित्सा हितलाभ की व्यवस्था

28. औषधालयों तथा अस्पतालों में उपस्थिति तथा घर जाकर इलाज करना (परिशिष्ट 12 तथा 13)।

28.1 (क) प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति और प्रति 1000 परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एकक उपस्थिति (ख) बीमाकृत व्यक्तियों और परिवारों का घर जाकर इलाज करने और (ग) (1) अस्पताल में दाखिल किये गये और (2) विशेषज्ञ के पास जांच के लिये भेजे गये बीमाकृत व्यक्तियों के मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े इस परिशिष्टों में दिये गये है। ये आंकड़े मुख्य रूप से औषधालयों तथा पैनल डाक्टरों द्वारा भेजी गई विवरणियों पर आधारित है। चिकित्सा उपस्थितियों की दर का हिसाब लगाने के लिये केवल रिपोर्ट भेजने वाले औषधालयों/क्लीनिकों से संबंद्ध बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों की संख्या को "दिखलाया गया" माना गया है।

28 2 समीक्षाधीन वर्ष मे प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति नई उपस्थितियों की अखिल भारतीय दर 1978-79 की तुलना मे 2970 से घटकर 2867 रह गई। प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति पुरानी उपस्थितियों की संख्या भी 1978-79 की तुलना मे 6856 से घटकर 5893 रह गई। इस वर्ष नई उपस्थितियों की तुलना मे पुरानी उपस्थितियों का अनुपात 2 06 रहा जबकि 1978-79 में यह अनुपात 2 31 था।

28. 3 प्रति 1000 परिवार एकक नई उपस्थितियो की अखिल भारतीय दर 1978-79 की तुलना मे 3476 से घटकर 3245 रह गई। प्रति 1000 परिवार एकक पुरानी उपस्थितियों की संख्या भी 1978-79 की तुलना में 6818 से घटकर 6286 रह गई। नई उपस्थिति की तुलना में पुरानी उपस्थिति का अनुपात 1978-79 मे 1.96 था जो 1979-80 में घटकर 1.94 रह गया।

28 4 बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध मे घर जाकर इलाज करने की संख्या 1978-79 की तुलना में 14. 24 प्रतिशत घट गई है। लेकिन परिवारों के संबंध मे लगभग 7. 86 प्रतिशत की कमी हुई है। प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति विजिटों की संख्या के अनुसार घर जाकर इलाज करने की घटना मे कमी हुई है। ये घटनाएं 1978-79 में 55 थी जो 1979-80 में घटकर 45 रह गई है।

28. 5 अस्पतालों में दाखिल किये गये मामलों की कुल संख्या में कमी हुई है। ये मामले 1978-79 में 3,49,023 थे जो कि 1979-80 में घटकर 3,14,539 रह गये हैं। विशेषज्ञों के पास जांच के लिये भेजे गये मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये मामले 1978-79 में 14,27,617 थे जो 1979-80 में बढ़कर 14,28,381 हो गए हैं।

बीमारी प्रतिरूप (परिशिष्ट—14)

29.1 दिखलाए गए प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति नए मामलों की संख्या के रूप में व्यक्त की गई संपूर्ण देश के लिये बीमारी प्रतिरूप की सूचना 51 कारण समूहों में से प्रत्येक की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये अलग-अलग इस परिशिष्ट मे दिखाई गई है।

29.2 सभी कारण समूहों को मिलाकर घटना दरें 1978-79 की तुलना में 1979-80 में बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में तथा उनके परिवारों के संबंध में भी कम है। बीमाकृत व्यक्तियों से संबंधित प्रत्येक अवधि में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के संबंध मे इस वर्ष 1 132 नई अवधियां रही है जबकि 1978-79 वर्ष में ये 1.170 थी। यदि यह बात ध्यान में रखी जाये कि एक बीमाकृत व्यक्ति की तुलना मे 2 88 परिवार सदस्य हैं तो नये मामलों की घटनाओं के अनुसार अस्वस्थता की घटनाएं बीमाकृत व्यक्तियों की तुलना मे बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के संबंध में अधिक रही है।

29 3 बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध मे बीमारी के कारण समूहवार घटना सूची में दी गई लगभग सभी बीमारियो के लिये बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यो मे संबंधित तदनुरूपी दरों से काफी कुछ मिलती हैं। लेकिन कुछ कारण समूहों में घटना में बहुत अंतर से यह पता चलता है कि कुछ ऐसे विशिष्ट रोगों में अधिक इलाज की तो आवश्यकता होती है जो किसी विशेष समूह (यानी बीमाकृत व्यक्ति या परिवार) की अपेक्षाकृत आमानी से हो जाते है।

30. चिकित्सा निदेशी

वर्ष के अन्त में अलग-अलग राज्यों मे तैनात पूर्ण-कालिक और अंशकालिक चिकित्सा निर्देशियों और उनके द्वारा निपटाये गए मामलों की संख्या का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	चिकित्सा निदेशियों की संख्या		1979-80 वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या
		अंशकालिक	पूर्णकालिक	
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	9	—	11286
2.	असम	5	—	560
3.	बिहार	11	—	9791
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	—	35
5.	दिल्ली	—	2	19245
6	गोआ	1	—	146

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	11	3	51470
8.	हरियाणा	9	—	4249
9.	कर्नाटक	17	—	10328
10.	केरल	7	1	10208
11.	मध्य प्रदेश	10	—	11963
12.	महाराष्ट्र			
	(क) ग्रेटर बम्बई	6	4	23466
	(ख) नागपुर क्षेत्र	7	—	4294*
	(ग) पश्चिमी महाराष्ट्र	7	1	10894
13.	उड़ीसा	9	—	2262
14.	पांडिचेरी	1	—	3036
15.	पंजाब	14	—	2862
16.	राजस्थान	13	—	4786
17.	तमिलनाडु	3	2	117792
18.	उत्तर प्रदेश	26	1	**
19.	पश्चिमी बंगाल	6	7	31648
	जोड़	173	21	330311

* केवल 5 चिकित्सा निर्देशियों के संबंध में आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

** 1979-80 वर्ष के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

31. चिकित्सा हितलाभ की व्यवस्था पर खर्च—राज्य सरकारों को प्राधिकृत अदायगियां

समीक्षाधीन वर्ष में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ की व्यवस्था पर खर्च के अपने शेयर के रूप में निगम द्वारा राज्य सरकारों को अदायगी करने के लिए 60,23,42,106.57 रुपये की धनराशि प्राधिकृत की गई। उपर्युक्त राशि के ब्यौरे इस प्रकार है :—

	रुपये
1967-68 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	58,139.22
1971-72 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	2,98,645.00
1973-74 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	12,39,323.11
1974-75 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	47,70,506.28
1975-76 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	1,07,29,545.14
1976-77 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	1,54,49,959.50
1977-78 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	2,30,55,847.42
1978-79 वर्ष के लिए लेखागत अदायगी	7,16,63,000.00
1978-79 वर्ष के लिए अन्तिम अदायगी	+5,32,59,140.90
	7,49,22,140.90
1979-80 वर्ष के लिए लेखागत अदायगी	47,18,18,000.00
जोड़	60,23,42,106.57

32. चिकित्सा देख रेख के खर्च पर नियंत्रण के उपाय

समीक्षाधीन वर्ष में निगम ने 500 से अधिक दवाइयों, इन्जैक्शनों तथा औषधियों के लिये औषध निर्माताओं के साथ दर ठेके किए। दर ठेके राज्य सरकारों को अमल में लाने के लिये सूचित कर दिये गए हैं।

33. दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में सुविधाओं की व्यवस्था

दिल्ली (चिकित्सा) योजना के लिए स्वीकृत 2 आयुर्वेदिक औषधालय इस समय मौजूदा कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के जी-2 तथा एन आई० ए० भवनों में स्थित हैं।

34. स्थानीय कार्यालयों के कार्यचालन में कार्यकुशलता

समीक्षाधीन वर्ष में देश भर में 440 स्थानीय कार्यालयों (लघु स्थानीय कार्यालयों सहित) में से 379 स्थानीय कार्यालयों में खाता प्रणाली कार्य कर रही थी। 47 स्थानीय कार्यालयों में टेलर प्रणाली प्रयोग के तौर पर काम कर रही थी।

35. नकद हितलाभों में सुधार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1979 को हुई अपनी बैठक में बीमाकृत व्यक्तियों को कृत्रिम अंग केन्द्र में अंग जड़वाने या मरम्मत करवाने या बदलवाने के लिए दाखिल रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए मानक हितलाभ दर पर पुनर्वास भत्ता देने का संकल्प स्वीकार किया। पुनर्वास भत्ते का यह हितलाभ 1 जनवरी, 1980 से देय है।

36. अन्य सुधार

36.1 कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1979 को हुई अपनी बैठक में संकल्प किया है कि 16 जुलाई, 1976 को हुई निगम की बैठक में स्वीकार किये गये संकल्प के अनुसरण में नसबन्दी, नलीबन्दी आपरेशन कराने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को देय बीमारी हितलाभ उक्त संकल्प में निर्दिष्ट मान पर तथा शर्तों के अधीन स्थायी आधार पर इस परिवर्तन के साथ दिया जाता रहेगा कि नसबंदी/नलीबंदी आपरेशन कराने के लिए बीमारी हितलाभ की अदायगी से संबंधित दिनों की संख्या 1.5.77 से बीमाकृत व्यक्ति को देय 91 दिन के साधारण बीमारी हितलाभ के अलावा होगी।

36.2 कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति ने दिनांक 17 फरवरी, 1980 को हुई अपनी बैठक में अन्य नकद हितलाभों की तरह निगम के खर्च पर मनीआर्डर द्वारा अस्थेष्टि हितलाभ की अदायगी की सुविधा का विस्तार करने का अनुमोदन कर दिया है।

36.3 मूल्यांकक ने 31 मार्च, 1974 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पांचवें पंचवार्षिक मूल्यांकन पर अपनी रिपोर्ट में रूपांतरण के मामले में स्थायी अपंगता हितलाभ के पूंजीकृत मूल्य की गणना करने के लिए निगम द्वारा इस्तेमाल की जा रही रूपांतरण तालिका के परिशोधन की सिफारिश की। इस प्रयोजन के लिए मूल्यांकन ने अपनी सिफारिशों का आधार वर्तमान मृत्यु-दर तथा स्थायी

अपंगता हितलाभ के लिए मूल्यांकन आधार यानी .0025 द्वारा निकाली गई मृत्यु दर जीवन बीमा निगम (1961-64) यू० एल० टी० और 6 प्रतिशत ब्याज दर को बनाया है। निगम के तदनरूपी कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 76-ग की अनुसूची 3 के अन्तर्गत मौजूदा रूपांतरण तालिका को परिशोधित किया है। रूपान्तरण तालिका के उपर्युक्त परिशोधन से बीमाकृत व्यक्तियों को स्थायी अपंगता हितलाभ के रूपांतरण मूल्य की राशि बढ़ गई है।

नकद हितलाभ

(परिशिष्ट 16 से 18)

37. नकद हितलाभ अदायगियों की संख्या (परिशिष्ट 16 का कालम 4)

37.1 नकद हितलाभों की अदायगी निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्थानीय/लघु/उप-स्थानीय/भुगतान कार्यालयों में की जाती है। 31 मार्च, 1980 को इस प्रकार के कार्यालयों की संख्या 691 थी जबकि एक वर्ष पहले इनकी संख्या 684 थी।

37.2 1978-79 तथा 1979-80 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में की गई नकद हितलाभ अदायगियों की कुल संख्या कालम 4 में दिखाई गई है। 1979-80 वर्ष के दौरान कुल मिलाकर लगभग 85.47 लाख अदायगियां (स्थायी अपंगता दावों के रूपान्तरण के आवेदनों से संबंधित एकमुश्त अदायगियों के 10,477 दावों सहित) की गई। ये अदायगियां पिछले वर्ष की अदायगियों से लगभग 6.00 लाख अधिक थीं। औसत के रूप में प्रत्येक मास लगभग 7.12 लाख अदायगियां की गई जबकि 1978-79 वर्ष में 6.62 लाख अदायगियां की गई थीं। प्रति कर्मचारी अदायगियों की संख्या 1978-79 वर्ष में 1.43 थी जो 1979-80 वर्ष में बढ़कर 1.48 हो गई है।

38. बीमारी हितलाभ (परिशिष्ट 16 के कालम 3 तथा 6 से 8)

38.1 1 जुलाई, 1978 तथा 30 जून, 1979 के बीच नए केन्द्रों में तथा रोजगार के नए क्षेत्रों पर योजना के हितलाभ उपबन्धों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप तथा पहले से कार्यान्वित क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि होने के कारण समीक्षाधीन वर्ष में लगभग 2.05 लाख अतिरिक्त कर्मचारी बीमारी हितलाभ के पात्र हो गए। 1979-80 वर्ष के दौरान बीमारी हितलाभ का दावा करने के हकदार कर्मचारियों की कुल संख्या 57.44 लाख होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 56.39 लाख थी (कालम 3 देखिये)

38.2 वर्ष के दौरान बीमारी नकद हितलाभ के रूप में 4296.75 लाख रुपये की राशि की अदायगी की गई जबकि 1978-79 वर्ष में यह राशि 3350.41 लाख रुपये थी।

38.3 प्रति कर्मचारी नई अवधियों की औसत संख्या 1978-79 में 0.90 थी जो 1979-80 वर्ष में बढ़कर 1.00 हो गई है। 1979-80 के दौरान प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष हितलाभ दिनों की औसत संख्या भी बढ़कर 7.8 हो गई है जो 1978-79 में 6.8 थी। प्रति कर्मचारी हितलाभ की दैनिक दर की राशि 1978-79 में 8.92 रुपये थी जो 1979-80 में बढ़कर 9.54 रुपये हो गई है।

38.4 पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बीमारी हितलाभ दावों की घटना और अवधि के संबंध में राज्यों में परस्पर काफी घट-बढ़ रही। लेकिन विभिन्न केन्द्रों पर बीमारी दावों की अवधि पर महानिदेशक लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इस संबंध में मुख्यालय में प्रत्येक मास प्राप्त आंकड़ों का आवधिक रूप से विश्लेषण किया जाता है तथा किसी केन्द्र की किसी असामान्य घटना के बारे में क्षेत्रीय निदेशकों तथा प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया जाता है ताकि वे आवश्यक तथा संभव होने पर इस असामान्य घटना को दूर करने के लिए उपयुक्त व शीघ्र कार्रवाई कर सकें।

38.5 धारा 58(2) के अन्तर्गत अत्यधिक बीमारी लाभ

बीमाकृत व्यक्तियों की बीमारी हितलाभ अदायगी का भार कुछ राज्यों में अखिल भारतीय औसत से अधिक पाया गया है। 1978-79 वर्ष के अत्यधिक बीमारी हितलाभ को निगम तथा राज्य सरकारों के बीच निम्न प्रकार से बांटा गया है :—

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	राज्य में दी गई कुल बीमारी हितलाभ की राशि (वास्तविक)	अखिल भारतीय औसत से अधिक में राज्य सरकार का शेयर
		रु०	रु०
1.	तमिलनाडु	4,22,67,499	15,56,278
2.	बिहार	95,32,478	5,81,643
3.	मध्य प्रदेश	1,70,18,638	26,69,742

39. विस्तारित बीमारी हितलाभ (परिशिष्ट 16 के कालम 9 और 10)

39.1 क्षय रोग, कोढ़, मानसिक तथा दुर्दम्य रोग आदि जैसे कुछ विशिष्ट रोगों से पीड़ित बीमाकृत व्यक्ति बीमारी हितलाभ के 91 दिन के बाद विस्तारित अवधि के लिए विस्तारित बीमारी नकद हितलाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

39.2 1979-80 वर्ष में इस मद में बीमाकृत व्यक्तियों को 325.98 लाख रुपये की राशि अदा की गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 314.42 लाख रुपये थी।

39.3 प्रति 1000 जोखिम-ग्रस्त कर्मचारी दावों की संख्या और समाप्त दावों की अवधि के रूप में अभिव्यक्त विस्तारित बीमारी हितलाभ दावों की घटनाएं 1978-79 तथा 1979-80 वर्षों के लिए परिशिष्ट 16 के कालम 9 तथा 10 में दिखाई गई हैं।

40. प्रसूति हितलाभ (परिशिष्ट 16 के कालम 11 और 12)

40.1 प्रसूति हितलाभ के लिए पात्र महिला कर्मचारियों की संख्या 1978-79 में 4,18,200 थी जो 1979-80 में बढ़कर 4,58,600 हो गई है। प्रसूति दावों के रूप में अदा की गई कुल राशि 194.91 लाख रुपये थी जबकि 1978-79 में यह राशि 17[illegible]-90 लाख रुपये थी। प्रति प्रसूति दावा हितलाभ की औसत राशि 1978-79 में 907 रुपये थी जो 1979-80 में घटकर 860 रुपये रह गई है।

40.2 प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी दावों की संख्या 1978-79 में 45.9 थी जो 1979-80 में बढ़कर 49.4 हो गई है।

41. अस्थाई अपंगता हितलाभ (परिशिष्ट 17 के कालम 3 से 6)

1979-80 के वर्ष के दौरान रोजगार चोट से ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या 58.99 लाख थी जबकि 1978-79 में यह संख्या 56.79 लाख थी (देखिये कालम 2)। 1979-80 वर्ष में अस्थायी अपंगता हितलाभ के रूप में अदा की गई राशि 693.68 लाख रुपये थी जबकि 1978-79 वर्ष में यह राशि 645.92 लाख रुपये थी। नई अवधियों की औसत संख्या तथा प्रति कर्मचारी हितलाभ दिनों की संख्या और औसत हितलाभ दर क्रमशः 0.07, 1.10 तथा 10.72 रुपये है जबकि 1978-79 वर्ष में तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 0.08, 1.13 तथा 10.10 रुपये थे। (देखिए कालम 4 से 6) प्रति अवधि का औसत काल 14.23 से बढ़कर 14.66 दिन हो गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न राज्यों में इन दावों की घटनाओं और काल में घट बढ़ रही।

42. अस्थाई अपंगता हितलाभ (परिशिष्ट 17 के कालम 7 से 10)

42.1 1979-80 वर्ष के स्वीकृत नये मामलों की संख्या 15,622 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 16,532 थी। प्रति 1000 बीमाकृत कर्मचारी घटनाएं 1978-79 की 2.91 से घटकर 1979-80 में 2.65 रह गई।

42.2 वर्ष के आरम्भ में निधि के दावेदारों की संख्या 40,096 थी जो वर्ष के अन्त में बढ़कर 41,726 हो गई (देखिए कालम 10) हितलाभ के रूप में वास्तव में संवितरित राशि 578.70 लाख रुपये (291.20 लाख रुपये की रूपान्तरित राशि सहित) थी जबकि 1978-79 वर्ष में यह राशि 608.41 लाख रुपये (359.60 लाख रुपये की रूपान्तरित राशि सहित थी)।

42.3 वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए मामलों से संबंधित स्थायी अपंगता हितलाभ दावों का पूंजीकृत मूल्य 650.83 लाख रुपये था जबकि 1978-79 वर्ष में यह 638.60 लाख रुपये था। वर्ष के अन्त में स्थायी अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि 2005.66 लाख रुपये थी जबकि वित्तीय वर्ष के आरम्भ में तदनुरूपी राशि 1862.86 लाख रुपये थी।

42.4 आवधिक अदायगियों के बदले रूपान्तरित मूल्य लेने का विकल्प करने वाले स्थायी अपंगता हितलाभ के दावेदारों की संख्या 1978-79 में 11,751 थी जो 1979-80 वर्ष में घटकर 10,477 रह गई है।

43. अस्थायी अपंगता हितलाभ दावे (परिशिष्ट 18)

43.1 वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए स्थायी अपंगता के 15,622 मामलों का (क) उद्योग के मुख्य समूहों तथा (ख) उद्योगवार प्रदर्शित प्रति 1000 कर्मचारी दावों की घटनाओं के अनुसार विश्लेषण किया गया था। पिछले वर्ष की तरह, दुर्घटनाओं की सबसे अधिक संख्या "वस्त्र उद्योग" में पाई गई तथा इसके बाद "इंजीनियरी" और "धात्विक खनिज" का स्थान रहा। व्यय-भार "वस्त्रों उद्योग" में अधिक है। 1978-79 वर्ष के तदनुरूपी व्यय-भार की तुलना में यह देखा गया है कि इस वर्ष अनुभव किया गया व्यय भार अधिकांश उद्योगों में पिछले वर्ष अनुभव किये गये व्यय भार से काफी कुछ मिलता जुलता है।

43.2 स्थायी अपंगता की औसत डिग्री 8.27 अनुभव की गई जबकि पिछले वर्ष यह 8.25 थी। अधिकतम दुर्घटनाएं आठवें मजदूरी ग्रुप, यानी 16 रुपये और 24 रुपये के बीच दैनिक मजदूरी ग्रुप, में हुई। 43.3 महिला कर्मचारियों में स्थायी अपंगता हितलाभ के मामले की संख्या केवल 162 रही। इन घटनाओं के कम होने का कारण सम्भवत: यह है कि महिलाओं को आमतौर पर जोखिम वाले व्यवसायों, -कार्यों आदि पर नहीं लगाया जाता है।

44. आश्रितजन हितलाभ (परिशिष्ट 17 के कालम 11 और 12)

44.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आश्रित जन हित लाभ के लिए स्वीकार किए गए दावों की संख्या में वृद्धि हुई। 1978-79 वर्ष में 438 दावे स्वीकार किए गए थे जबकि इस वर्ष यह संख्या 525 हो गई (देखिए कालम 11)। वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए आश्रितों की कुल संख्या 1543 थी।

44.2 वर्ष के आरम्भ और अन्त में सभी आश्रितों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है—

विवरण	31 मार्च को	
	1979	1980
विधवाएं	5,025	5,437
पुत्र और पुत्रियां	8,324	8,995
पिता	752	821
माता	1,005	1,088
अन्य आश्रित बच्चे	691	761
जोड़	15,797	17,102

44.3 आश्रितजन हितलाभ के रूप में अदा की गई राशि 1978-79 में 100.69 लाख रुपये थी जो 1979-80 में बढ़कर 118.59 लाख रुपये हो गई है। वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए आश्रितजन हितलाभ दावों का पूंजीकृत मूल्य 176.48 लाख रुपये था जबकि 1978-79 वर्ष में यह 144.68 लाख रुपये था। 31 मार्च, 1980 को आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि 1148.83 लाख रुपये थी। जबकि 31 मार्च, 1979 को यह राशि 1,051.07 लाख रुपये थी।

अंशदान व प्रवर्तन:

45. अंशदानों से आय

1979-80 वर्ष के दौरान कुल 1,59,76,04,161 रुपये की राशि एकत्र की गई।

46. अंशदान एकत्र करने का तरीका

अब तक अंशदान सामान्यत: चिपकाई जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा टिकटों के रूप में एकत्र किए जाते रहे हैं जो निगम के बैंकरों के माध्यम से बेची जाती हैं। तथापि, दिनांक 30-11-75 से दिल्ली क्षेत्र में अंशदान टिकटों के स्थान पर नकद रूप में अंशदान एकत्र करने की प्रणाली प्रयोगात्मक आधार पर शुरु की गई थी। दिल्ली क्षेत्र में इस प्रणाली के संतोषजनक पाए जाने के अनुभव से प्रोत्साहित होकर, नकद प्रणाली कर्नाटक राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र तमिलनाडु असम, नागपुर, पूना, आन्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, गुजरात तथा उड़ीसा क्षेत्रों में भी शुरु कर दी गई है। उक्त प्रणाली जुलाई, 1980 मास में पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश क्षेत्रों में भी शुरु की जा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में यह सितम्बर, 1980 मास में शुरु की जायेगी। इस प्रकार सितम्बर, 1980 तक सभी क्षेत्रों में नकद प्रणाली लागू हो जायेगी। उपर्युक्त दो प्रणालियों के अलावा अंशदान फ्रैंकों द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 46 नए लाइसेंस जारी किए गए तथा 6 लाइसेंस रद्द किए गए जिससे प्रयोग में आ रही फ्रैंकिंग मशीनों की कुल संख्या 1041 हो गई है। तथापि फ्रैंकिंग मशीनों का प्रयोग करने वाले नियोजकों को नकद प्रणाली शुरु करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

47. निरीक्षण

समीक्षाधीन वर्ष में मुख्यालय ने निरीक्षण की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी। निरीक्षकों ने नियोजकों तथा उनके कर्मचारियों को रिकार्ड रखने और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए विनियमों के विभिन्न उपबंधों का पालन करने में मार्गदर्शन करना तथा प्रशिक्षण देना जारी रखा।

वर्ष के अन्त में 55 छुट्टी रिजर्व निरीक्षकों सहित कुल मिलाकर 381 बीमा निरीक्षक थे। वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 44,264 निरीक्षण किए गए।

48. क०रा०बी० बकायों की वसूली

"नियत" दिवस से 31 मार्च, 1980 तक चूककर्ता नियोजकों पर कुल 2,809.78 लाख रुपये की राशि बकाया थी। पिछले 3 वर्षों के लिए क० रा० बी० बकायों की तुलनात्मक स्थिति तथा 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार 1 लाख रुपये तथा उससे अधिक क० रा० बी० बकायों वाले चूककर्ता कारखानों/स्थापनाओं के सूचक क्षेत्रवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट 20 तथा 21 पर हैं।

क० रा० बी० बकायों की वसूली पर निगम द्वारा विशेष ध्यान दिलाया जाता रहा और इनकी अधिकतम सीमा तक वसूली के हर संभव प्रयास किए गए।

49. कर्मचारी बीमा न्यायालय

1979-80 वर्ष के दौरान निम्नलिखित राज्यों में नये कर्मचारी बीमा न्यायालय स्थापित किए गए है :—

राज्य	स्थान
(1) हिमाचल प्रदेश	सोलन
(2) पंजाब	होशियारपुर

50. कानूनी कार्यवाही

वर्ष के दौरान दायर किए गए न्यायालय/राजस्व वसूली मामलों से संबंधित राशि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन वसूल की गई राशि परिशिष्ट 19 में राज्य-वार दिखाई गई है।

बजट तथा वित्त

51. 1980-81 के बजट प्राक्कलन

51.1 1980-81 वर्ष के बजट प्राक्कलन निगम द्वारा 18-2-1980 को हुई अपनी बैठक में स्वीकार किए गए। इन प्राक्कलनों के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन 26-3-1980 को जारी किया गया। बजट प्राक्कलन लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर 28-3-1980 को प्रस्तुत किए गए।

निम्नलिखित तालिका मे 1978-79, 1979-80 वर्ष के दौरान निगम की आय तथा व्यय तथा 1980-81 के बजट प्राक्कलनो को दिखाया गया है :—

लेखा शीर्ष	1978-79	1979-80	1980-81
	(लाख रुपयो मे)		(बजट प्राक्कलन)
1. आय			
अंशदान	1,46,75.94	1,59,76.04	1,62,31,.00
अन्य आय	10,89.54	10,03.00	9,03.70
(सामान्य रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज, अस्पतालों, औषधालयों तथा स्टाफ क्वार्टरों के किराये से आय तथा अन्य विविध आय)			
जोड़	1,57,65 48	1,69,79.04	1,71,34.70
2 व्यय			
बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ			
क. चिकित्सा हितलाभ	32,87 31	63,59.28	68,72 45
ख. नकद हितलाभ	52,63.32	63,55.23	63,52 47
ग. अन्य हितलाभ	13.88	17.32	19.44
प्रशासनिक व्यय	9,95.03	11,37.56	12,12.44
अन्य व्यय	21,24.97	20,49.41	19,95.94
1 अस्पतालो, औषधालयो, कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास के लिये व्यवस्था			
2 पूंजीगत निर्माण तथा आपात आरक्षित निधि में अंशदान			
जोड़	1,37,04.51	1,59 18 80	1,64,52.74

बैंक व्यवस्था

52. निगम के कार्यालयो के लिए वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओ तथा इसके सहायक बैंको मे 23 बैंक खाते और राष्ट्रीयकृत बैंको में 3 खाते खोले गए। चार बैंक खाते बन्द किए गए। 31 मार्च, 1980 को बैंक खातों की कुल संख्या 532 थी।

भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंको की 10 और शाखाओं के साथ कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान टिकटें बेचने की व्यवस्था की गई। कुछ अन्य क्षेत्रो मे अंशदान टिकटों के स्थान पर नकद रूप में अंशदान एकत्र करने की पद्धति लागू करने के कारण बैंक की 43 शाखाओं द्वारा टिकटों की बिक्री बन्द कर दी गई है। 31 मार्च, 1980 को बैंक की कुल 405 शाखाओं में अंशदान टिकटों की बिक्री की जा रही थी।

आरक्षित निधियां तथा निवेश

53. 31 मार्च, 1979 तथा 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आरक्षित निधियों तथा सामान्य रोकड़ शेष के निवेश निम्नप्रकार थे :—

निधि/बकाया राशि का नाम	31-3-79 की स्थिति के अनुसार	31-3-80 की स्थिति के अनुसार
	(लाख रुपयों मे)	
1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप बीमा निधि	0.76	4.39
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि	4,88.55	5,21.25
3. भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि	1.08	1.66
4 अनुकंपा आरक्षित निधि	0.28	0.26
5. पेंशन आरक्षित निधि	8,29.88	9,39.20
6. निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	35.65	40.43
7. अस्पताल भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	3,98.78	4,61.80
8. स्टाफ कारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	6.12	6.22
9 निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत तथा अनुरक्षण आरक्षित निधि	28.12	26.03
10. अस्पताल भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण आरक्षित निधि	5,39.63	5,63.04
11 स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि	18,62.86	20,05.65
12 आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	10,51 07	11,48.83
13 पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि	36,42.89	47,26.24
14. आपात आरक्षित निधि	34,94.27	36,91.86
15. सामान्य रोकड़ शेष का निवेश	1,19,17.73	1,32,48.10
जोड़	2,42,97.67	2,75,84.96

निर्धारित आरक्षित निधियों तथा अनिर्धारित आरक्षित निधियों के अन्तर्गत राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

निर्धारित आरक्षित निधियां (पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि सहित)	88,85.67	1,04,45.00
अनिर्धारित आरक्षित निधियां (आपात आरक्षित निधि तथा सामान्य रोकड़ शेष)	1,54,12.00	1,71,39.96
जोड़	2,42,97.67	2,75,84.96

ऊपर क्रम संख्या 1 से 12 पर उल्लिखित आरक्षित निधियां निगम की संबंधित देयताओं को पूरा करने के लिए है। इन निधियों में वार्षिक वृद्धि मान्यता प्राप्त/अनुमोदित आधार/मानदण्ड पर की जाती है। पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि तथा आपात आरक्षित निधि में वार्षिक अंशदान निम्नलिखित आधार पर किया जाता है।

पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि

निगम ने 2 फरवरी, 1974 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया था कि नियोजक तथा कर्मचारी अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10 प्रतिशत 8 : 2 के अनुपात में क्रमश : अस्पताल/औषधालय/अन्य चिकित्सा संस्थानों तथा कार्यालय भवनों/स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा किया जाए।

आपात आरक्षित निधि

निगम द्वारा 17 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार व्यय से अधिक आय का 20 प्रतिशत (एक करोड़ रुपये से कम की स्थिति में आधिक्य की पूरी राशि) आपात आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

निधियों के निवेश के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

	31-3-79 की स्थिति के अनुसार	31-3-80 की स्थिति के अनुसार
	(लाख रुपयों में)	
सरकार की प्रतिभूतियां	3,14.92	2,35.34
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा	2,39,82.75	2,73,49.62
जोड़	2,42,97.67	2,75,84.96

54. 1979-80 वर्ष का आय व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 1980 की स्थिति का तुलनपत्र

1979-80 वर्ष का आय-व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र क्रमश परिशिष्ट 22 तथा 23 में दिए गए है।

55. लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1979-80 के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व से प्राप्त नहीं हुई है।

निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व ने निगम के 1978-79 वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को 19 दिसम्बर 1979 को भेजी थी। स्थायी समिति ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 को हुई बैठक में लेखा परीक्षित लेखों पर विचार किया तथा निगम को उन्हें स्वीकार करने की सिफारिश की। 22 दिसम्बर, 1979 को निगम द्वारा स्वीकार करने के बाद लेखा परीक्षित लेखे 31 दिसम्बर, 1979 को केन्द्रीय सरकार को भेज दिये गए थे। इन्हें लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर क्रमश: 24 जनवरी, 1980 तथा 29 जनवरी, 1980 को प्रस्तुत किया गया था।

56. प्रशासन की सापेक्ष लागत

परिशिष्ट-24 में दिए गए विवरण में 1974-75 वर्ष से लेकर प्रशासन की सापेक्ष लागत दिखाई गई है। प्रति एक लाख बीमाकृत कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्टाफ की संख्या प्रति कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी नकद हितलाभ अदायगियों की संख्या से संबंधित सूचना तथा नकद व चिकित्सा हितलाभों की लागत और वसूल किए गए अंशदानों की राशि के अनुपात में 1975-76 से 1979-80 तक के वर्षों के दौरान प्रशासन का तुलनात्मक खर्च नीचे दिया गया है—

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1. प्रति एक लाख बीमाकृत क० रा० बी० नि० स्टाफ की संख्या	1154.60	160	168	167	173
2. प्रति क० रा० बी० नि० कर्मचारी नकद हितलाभ अदायगियों की संख्या	635	656	770	818	827
3. प्रति क० रा० बी० नि० कर्मचारी वसूल किया गया अंशदान	95,872 रु०	1,42,621 रु०	1,41,355 रु०	1,51,065 रु०	1,54,597 रु०
4. नकद व चिकित्सा हितलाभों की तुलना में प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता . . .	13.59%	12.38%	10.98%	9.40%	8.93%
5. अंशदानों की तुलना में प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता .	10.24%	6.98%	7.24%	6.78%	7.12%

परिशिष्ट 1

1979—80 वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

भाग क—नए क्षेत्रों में कार्यान्वयन

राज्य	केन्द्र/क्षेत्र	कार्यान्वयन की तारीख	कर्मचारियों की संख्या (अनन्तिम आंकड़े)	परिवारों के लिए चिकित्सा देख-रेख: विस्तार की तारीख	परिवारों के लिए चिकित्सा देख-रेख: शामिल किए गए परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	रामचन्द्रपुरम तथा पट्टाचेरु	29-4-79	2,000	29-4-79	2,200
बिहार	कान्ड्रा	24-6-79	1,300	24-6-79	1,500
	गोविन्दपुर	13-1-80	2,400	13-1-80	2,750
	जासिडीह (देवघर)		1,500		1,750
	सकची तथा		1,000		1,150
	मानगो		2,500		2,900
गुजरात	जूनागढ़	15-7-79	2,800	15-7-79	3,150
	नवेसेरी	18-11-79	1,300	18-11-79	1,450
	टुंकी, मिगलपुर दभोली, बेद तथा फुलपाडा (सूरत की विस्तारित नगरपालिका सीमायें)	19-1-80	750	19-1-80	850
कर्नाटक	गोकाक	16-3-80	100	16-3-80	100
केरल	कोजुकुल्ली	15-7-79	50	15-7-80	50
	कनाकारी	2-12-79		2-12-79	
	कन्यापूर तथा मुलाशुरथी	23-12-79	400	23-12-79	400
	कमारगोड़ तथा	3-2-80	400	3-2-80	400
	होसदुर्ग		300		300
मध्य प्रदेश	सानावाड	16-9-79	500	16-9-79	550
महाराष्ट्र	पूना के आस पास के क्षेत्र	1-4-79	400	1-4-79	450
उड़ीसा	संबलपुर	22-4-79	2,500	22-4-79	2,650
	बालासोर	2-9-79	1,500	2-9-79	1,600
	जगनपुर	21-10-79	1,000	21-10-79	1,050
	कालारपुर तथा बंडारा	11-11-79	2,800	11-11-79	3,100
पंजाब	भासरो तथा रेलमाजरा	24-2-80	2,000	24-2-80	2,500
राजस्थान	मस्ताया औद्योगिक क्षेत्र, अलवर	24-6-79	2,000	24-6-79	2,450
	फलना औद्योगिक क्षेत्र	23-12-79	1,950	23-12-79	2,400
	कनकपुरा	30-3-80	150	23-3-80	200
तमिलनाडु	आरकोनम संकारी तथा तंजावूर	21-10-79	2,800	21-10-79	3,100
उत्तर प्रदेश	परतापुर (मेरठ)	29-4-79	1,500	29-4-79	1,650
	बाराबंकी	10-6-79	1,000	10-6-79	1,100
	अकबरपुर	16-9-79	1,150	16-9-79	1,250
	ऋषिकेश	25-11-79	4,500	25-11-79	4,950
	खुर्जा	10-2-80	1,200	10-2-80	1,300
			43,750		49,250

परिशिष्ट 1

भाग-ख

स्थापनाओं के नए वर्गों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

राज्य	केन्द्र	विस्तार की तारीख	शामिल की गई स्थापनाएं	कर्मचारियों की संख्या (अनन्तिम अनुमानित आंकड़े)	परिवारों के लिए चिकित्सा देखरेख (विस्तार की तारीख)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	अम्बरगांव, बसंतनगर राजामुंद्री के उपांत, कुड्डापाह के उपांत, श्री राम नगर, गोपालपटनम, गुंटूर के उपांत	20-2-80	1. विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाले कारखाने जिनमें 10 से 19 व्यक्ति काम करते हैं। 2. विद्युत शक्ति का प्रयोग न करने वाले कारखाने जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं। 3. होटल, रेस्तरां, दुकानें, सड़क मोटर परिवहन संस्थापनाएं, पूर्वदर्शन थियेटर सहित सिनेमा, समाचार पत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।	90	20-2-80
हिमाचल प्रदेश	सोलन	25-8-79	—वही—	160	25-8-79
केरल	कोरीक के उपांत, पालघाट तथा त्रिचूर, अर्णाकुलम जिले में किजाकम्बलम तथा एकारनाड नार्थ के राजस्व ग्राम।	4-11-79	—वही—	160	4-11-79
तमिलनाडु	1. नार्थ आरकोट जिले के वल्लाजाह तालुक में राजस्व ग्राम वनापाडी, नारासिंघापुरम, मनियमबट्टु, वाला-पेट तथा मुगुन्दरायापुरम की सीमाओं के अन्दर के क्षेत्र 2. चिंगलपुट जिला, सैदापेट तालुक में कोलूर	30-9-79	1. विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाले कारखाने जिनमें 10 से 19 व्यक्ति काम करते हैं। 2. विद्युत शक्ति का प्रयोग न करने वाले कारखाने जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं। 3. दुकानें, होटल, रेस्तरां, पूर्वदर्शन थियेटर सहित सिनेमा तथा समाचारपत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।	360	30-9-79

परिशिष्ट 2

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा अनैक्सियां

अस्पताल :

क्रम संख्या	राज्य	स्थान	बिस्तरों की संख्या		टिप्पणी
			सामान्य	क्षय रोग	
1	2	3	4(1)	4(2)	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	310	--	
2.	आन्ध्र प्रदेश	सीरपुर कागजनगर	110	--	
3.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	110	--	
4.	आन्ध्र प्रदेश	अडोनी	50	--	
5.	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल	50	--	
6.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	100	10	
7.	बिहार	मैथन	110	--	

1	2	3	4(1)	4(2)	5
8.	बिहार	मुंगेर	30	--	
9.	बिहार	डालमिया नगर	72	--	
10.	दिल्ली	दिल्ली	400	--	
11.	गुजरात	नरोडा, अहमदाबाद	--	200	
12.	गुजरात	बापू नगर अहमदाबाद	500	--	
13.	हरियाणा	फरीदाबाद	188	--	
14	हरियाणा	यमुनानगर	60	--	
15.	हरियाणा	पानीपत	15	35	
16.	केरल	मुलाकुनाठाकावू	--	110	
17.	केरल	असरामम	115	--	
18.	केरल	अलीप्पी	55	--	
19.	केरल	पेरूरकाडा	75	--	
20.	केरल	त्रिचूर	90	--	
21.	केरल	उद्योग मंडल	150	--	
22.	केरल	अर्नाकुलम	65	--	
23.	केरल	बाडावयूर	65	--	
24.	केरल	पारीपल्ली	100	--	
25.	केरल	एजुकोन	150	--	
26.	कर्नाटक	राजाजी नगर, बंगलौर	380	40	
27.	कर्नाटक	डांडेली	50	--	
28.	कर्नाटक	मंगलौर	60	--	29-11-79 को चालू किया गया तथा 40 और बिस्तर निर्माणाधीन हैं
29.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	150	--	
30.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	--	75	
31.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	85	15	
32.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	75	--	
33.	महाराष्ट्र	एम०जी०एम० बम्बई	700	--	
34.	महाराष्ट्र	वर्ली	550	--	
35.	महाराष्ट्र	नागपुर	200	--	
36.	महाराष्ट्र	मुलन्द	110	540	
37.	महाराष्ट्र	ठाणे	410	--	
38.	महाराष्ट्र	उल्हास नगर	200	--	
39.	महाराष्ट्र	अंधेरी	650	--	
40.	महाराष्ट्र	वाशी	650	--	
41.	उड़ीसा	चौद्वार	50	--	
42.	उड़ीसा	कंसबहल	50	--	
43.	उड़ीसा	ब्रजराज नगर	*50	--	
44.	उड़ीसा	जे०के० पुर	25	--	1-8-79 से चालू किया गया।

1	2	3	4(1)	4(2)	5
45.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	50	--	
46	पंजाब	अमृतसर	125	--	
47.	पंजाब	लुधियाना	80	--	
48.	पंजाब	जालंधर	100	--	
49.	राजस्थान	जयपुर	@139	--	
50.	तमिलनाडु	मद्रास	625	--	
51.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	500	--	
52.	तमिलनाडु	मदुरै	177	25	
53.	तमिलनाडु	दक्षिणी मद्रास	£500	--	
54	उत्तर प्रदेश	कानपुर (सामान्य)	212	--	
55.	उत्तर प्रदेश	कानपुर (चैस्ट)	--	180	
56.	उत्तर प्रदेश	कानपुर (स्त्रियां तथा शिशु)	144	--	
57.	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर	100	--	
58.	प० बंगाल	कामर हाट्टी	175	--	
59.	प० बंगाल	बेलूर बल्ली	--	150	
60.	प० बंगाल	सेरामपुर	216	--	
61.	प० बंगाल	उलुबेरिया	216	--	
62.	प० बंगाल	बाल्टिकुरी बाँकरा	416	--	
63	प० बंगाल	कल्याणी	266	--	
64.	प० बंगाल	सियालवाह	250	--	
65.	प० बंगाल	गौरहाटी	216	--	
66.	प० बंगाल	बज-बज	300	--	
67.	प० बंगाल	मानिकटोला	500	--	
			जोड़ 12722+1380=14102		

*निर्माणाधीन 25 बिस्तर शामिल है ।

@ निर्माणाधीन 26 बिस्तर शामिल हैं ।

£ निर्माणाधीन 294 बिस्तर शामिल हैं ।

धर्मार्थ बिस्तर :

क्र०सं०	राज्य	स्थान	बिस्तरों की संख्या		टिप्पणी
			सामान्य	क्षय रोग	
1	2	3	4(1)	4(2)	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	इर्रगड्डा	--	24	
2.	बिहार	इटकी	--	20	
3.	हरियाणा	फरीदाबाद	--	12	
4.	हरियाणा	हिसार	--	--	
5.	हरियाणा	सोनीपत	12	--	24-1-79 को चालू की गई ।

1	2	3	4(1)	4(2)	5
6.	हिमाचल प्रदेश	धर्मपुर	--	12	
7.	कर्नाटक	बंगलौर	--	32	
8.	केरल	पुलायानारकोटा	--	24	
9.	महाराष्ट्र	नागपुर	--	25	
10.	उड़ीसा	चौद्वार	--	12	
11	पंजाब	अमृतसर	--	12	
12	चंडीगढ़	चंडीगढ़	40	--	
13.	राजस्थान	जयपुर	--	15	
14.	राजस्थान	बारी-उदयपुर	--	16	
15.	राजस्थान	पाली	12	--	
16.	राजस्थान	भीलवाड़ा	24	--	(12 निर्माणाधीन हैं)
17.	राजस्थान	जोधपुर	20	--	
18.	राजस्थान	श्री गंगानगर	12	--	
19.	राजस्थान	कोटा	24	--	
20.	राजस्थान	उदयपुर	12	--	
21.	राजस्थान	भरतपुर	24	--	(12 निर्माणाधीन हैं)
22.	तमिलनाडु	सिवाकासी	12	--	
23.	तमिलनाडु	ताम्बरम	--	52	
24.	तमिलनाडु	कोइलपट्टी	32	--	
25.	तमिलनाडु	लालगुडी	10	--	
26.	तमिलनाडु	नागरकोइल	--	26	
27.	तमिलनाडु	कावेरीनगर	10	--	
28.	उत्तर प्रदेश	मोदीनगर	--	--	
29.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	24	--	15-6-79 को चालू की गई।
30.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	12	--	2-10-78 को चालू की गई।
31.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	24	--	2-10-79 को चालू की गई।
32.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	24	--	20-6-79 को चालू की गई
33.	उत्तर प्रदेश	शिकोहाबाद	24	--	3-8-79 को चालू की गई।
		जोड़	364 +	306=670	

परिशिष्ट 3

31-1-79 और 31-3-80 को परिवार (कर्मचारी) एककों की चिकित्सा देख-रेख का स्वरूप

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सीमित देख-रेख		विस्तारित देख-रेख		पूर्ण देख-रेख	
		31-3-79	31-3-80	31-3-79	31-3-80	31-3-79	31-3-80
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	700	700	2,34,300	2,39,300
2.	असम	—	—	—	—	29,000	32,000
3.	बिहार	—	—	85,700	1,02,200	39,300	37,800
4.	चंडीगढ़	—	—	14,000	14,300	—	—
5.	दिल्ली	—	—	—	—	2,45,000	2,65,000
6.	गुजरात	—	—	1,45,000	1,55,100	3 90,000	3,94,900
7.	हरियाणा	—	—	—	—	1,96,000	1,94,000
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	9,000	1,200	—	—
9	कर्नाटक	—	—	69,000	73,500	2,17,000	2,26,500
10	केरल तथा माही	—	—	—	—	3,07,000	3,08,000
11.	मध्य प्रदेश	—	—	2,100	—	1,67,900	1,60,000
12.	महाराष्ट्र :—						
	(क) बम्बई क्षेत्र	—	—	—	—	11,46,000	11,46,000
	गोआ क्षेत्र	—	—	—	—	19,000	19,500
	(ख) नागपुर क्षेत्र	—	—	35,000	31,100	35,000	43,900
	(ग) पूना क्षेत्र	—	—	54,000	52,500	1,81,000	1,92,500
13.	उड़ीसा	—	—	—	—	92,000	1,09,000
14.	पांडिचेरी	—	—	—	—	15,000	15,000
15	पंजाब	—	—	—	—	1,56,000	1,65,000
16.	राजस्थान	—	—	—	—	1,15,000	1,24,000
17.	तमिलनाडु	—	—	1,25,300	24	3,19,700	4,50,000
18.	उत्तर प्रदेश	2,40,000	23,800	—	—	1,95,000	4,21,200
19.	पश्चिमी बंगाल	—	—	5,95,000	6,31,600	3,70,000	3,53,400
	जोड़	2,40,000	23,800	11,26,700	10,62,200	44,49,200	48,97,000

परिशिष्ट 4

1979-80 वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय

22 दिसम्बर, 1979

(1) निगम ने निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया :—

"संकल्प किया गया कि 16 जुलाई, 1976 को हुई निगम की बैठक में स्वीकार किये गये संकल्प के अनुसरण में नसबन्दी/नलीबन्दी आपरेशन कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्तियों को देय बीमारी हितलाभ उपरिलिखित संकल्प में निर्दिष्ट मान पर तथा उन्हीं शर्तों के अधीन स्थायी आधार पर इस परिवर्तन के साथ दिया जाता रहेगा कि नसबंदी/नलबंदी आपरेशन कराने के लिये बीमारी हितलाभ की अदायगी से संबंधित दिनों की संख्या 1-5-77 से बीमाकृत व्यक्ति को देय 91 दिन के साधारण बीमारी हितलाभ के अलावा होगी।

(2) निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत रोजगार चोट हितलाभ प्रदान करने के प्रयोजनों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की तीसरी अनुसूची में व्यावसायिक रोगों की सूची में निम्नलिखित रोग जोड़ने का अन्तिम रूप से अनुमोदन किया।

भाग—क

व्यावसायिक रोग

(1) ट्रिकेसाइल फासफेट द्वारा विषाक्तीकरण

(2) डायथलिन डाय आक्साइड (डाय-आक्सन) द्वारा विषाक्तीकरण

(3) निकिल कार्बोनिल द्वारा विषाक्तीकरण

रोजगार

ट्रिकेसाइल फासफेट के इस्तेमाल से संबंधित अथवा उसके धूएं या वाष्प के इस्तेमाल से संबंधित कोई रोजगार।

डायथलिन डाय-आक्साइड (डाय-आक्साइड) से संबंधित अथवा उसके धूएं या वाष्प के इस्तेमाल से संबंधित कोई रोजगार।

निकिल कार्बोनिल गैस के निकलने से संबंधित कोई रोजगार।

भाग—ख

व्यावसायिक रोग

(1) बाह्य व्युत्पत्ति का असंक्रामक त्वचाशोथ (जिसमें चमड़ी के पुराने रोग शामिल है परन्तु विष द्वारा त्वचा शोथ शामिल नहीं है) विकिरित उष्मा के अलावा विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कण।

(2) शोर से उत्पन्न श्रवण हानि।

रोजगार

ऐसा कोई रोजगार जिसमें धूल, तरल पदार्थ अथवा वाष्प अथवा चर्म में जलन करने वाला कोई अन्य बाह्य कारक का प्रभाव हो (इसमें उष्मा के अर्पण शामिल है परन्तु विकिरित उष्मा के अलावा विद्युत चुम्बकीय विकिरण के विषाक्त कण शामिल नहीं हैं)।

ऐसा कोई रोजगार जिसमें लम्बी अवधि तक उच्च शोर स्तर का प्रभाव हो।

(3) डीनाइट्रोफिनोल द्वारा विषाक्तीकरण अथवा समजातीय अथवा प्रतिस्थापी डीनाइट्रोफिनोल द्वारा अथवा ऐसे पदार्थों के लवणों द्वारा विषाक्तीकरण।

(4) बैरिलियम अथवा बैरिलियम के मिश्रण द्वारा विषाक्तीकरण

(5) काडमियम द्वारा विषाक्तीकरण।

(6) मूत्राशय के इपीथिलियल अस्तर (मूत्राशय का पापिलोमा) अथवा गुर्दे की श्रेणी के इपीथिलियल अस्तर अथवा मूत्रवाहिनी के इपीथिलियल के अस्तर का प्रारम्भिक अर्बुद।

ऐसा कोई रोजगार जिसमें डीनाइट्रोफिनोल के इस्तेमाल अथवा डीनाइट्रोफिनोल अथवा उसका समजातीय अथवा प्रतिस्थापी डीनाइट्रोफिनोल अथवा ऐसे पदार्थों के लवण से युक्त धूएं अथवा वाष्प का इस्तेमाल हो।

ऐसा कोई रोजगार जिसमें बेरिलियम अथवा उसके मिश्रण अथवा ऐसे पदार्थ जिसमें बैरिलियम हो के प्रयोग अथवा स्पर्श अथवा उसके वाष्पीकरण, धूल, धुआं का प्रभाव हो।

ऐसा कोई रोजगार जिसमें काडमियम धुए का प्रभाव हो।

(क) ऐसा कोई रोजगार जिसमें निम्नलिखित पदार्थों में से किसी ऐसे पदार्थ के प्रयोग स्पर्श अथवा प्रभाव हो :—

(1) बिटा नेपथीलमाइन और इसके लवण

(2) बेनजाडाइन और इसके लवण

(3) 4-अमीनो डीफिनाइल और इसके लवण

(4) नाइट्रोडीफिनाइल और इसके लवण

(5) अल्फा नेपथीमाइन और इसके लवण

(6) आरथो-टेल्डाइन और इसके लवण

(7) डायनिसिडाइन और इसके लवण

(8) डिक्लोरोबेनजिडाइन और इसके लवण

(9) ओरामाइन

(10) मैगनेटा

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित किसी पदार्थ के उत्पाद, स्पर्श अथवा संमाधन के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मशीन के किसी भाग का अनुरक्षण अथवा सफाई।

(ग) किसी लांडरी, जो रोजगार के स्थान का एक भाग हो, में ऊपर (क) में उल्लिखित पदार्थों में से किसी पदार्थ से काम करने वाले कामगारों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कपड़ों की सफाई।

भाग—ग

व्यावसायिक रोग

बाइसिनोसिस

पुरानी सूखी घास की धूल से अन्दर सांस लेना अथवा पुरानी मिट्टी से उत्पन्न अन्य रोग तथा ऐसे रोग लक्षण और चिन्ह जिससे श्वसन फुफ्फुसीय प्रणाली के बाह्य भाग में प्रतिक्रिया हो सकती हो तथा गैस केन्द्र में खराबी को बढ़ावा देने वाले हों, के कारण पारमर का फुफ्फुसीय रोग नूमाकोनिओसिस।

3 निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 98 के उप-विनियम (ii) तथा विनियम 103-क के उप-विनियम (3) में विस्तारित बीमारी हितलाभ के लिये रोगों की सूची में "एकांगघात" को शामिल करने का अन्तिम रूप से अनुमोदन किया।

4. निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के फार्म संख्या 8, 9, 10 तथा 11 में संशोधन का अनुमोदन किया ताकि प्रत्येक फार्म के ऊपरी सिरे पर निम्नलिखित चेतावनी टिप्पणी जोड़ी जा सके :—

"विनियम 64 के अधीन हितलाभ की संभाव्य हानि से बचने के लिये इस प्रमाण पत्र को 3 दिन के अन्दर स्थानीय कार्यालय में जमा करें।"

रोजगार

किसी कमरे में ऐसा रोजगार जिसमें कताई अथवा कच्चे अथवा बेकार रुई अथवा फ्लेक्स के फेर बदल का काम करने वाली फैक्ट्रियों में कार्डिंग संमाधन किया जाता है।

ऐसा व्यवसाय जिसमें निम्नलिखित रोजगार के कारण से पुरानी सूखी घास अथवा खाद मिट्टी से उत्पन्न अन्य पदार्थ की धूल का प्रभाव हो।

क कृषि कामकाजी अथवा बागान अथवा

ख. सूखी घास अथवा खाद मिट्टी के अन्य उत्पाद के भंडारण में लदाई, उतराई, अथवा

ग. खोई का संचालन ।

कोई रोजगार बशर्ते कि ऐसी स्थिति का निदान सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा किया गया हो और उसकी पुष्टि की गई हो।

5. निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के फार्म 2 में मौजूदा कालम "शिफ्ट, यदि कोई हो" के स्थान पर "नियुक्ति की तारीख" कालम प्रतिस्थापित करने के संशोधन का अनुमोदन किया।

6. निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 76-ख के अन्तर्गत तीसरी अनुसूची-स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए रूपान्तरण मूल्य के संशोधन का अनुमोदन किया ताकि मौजूदा तीसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जा सके :—

अनुसूची—3

स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए रूपान्तरण मूल्य

(विनियम 76-ख)

जिस तारीख से उपयुक्त कार्यालय में रूपान्तरण के लिए बीमाकृत व्यक्ति का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें पिछले जन्म-दिवस पर उसकी आयु	वह गुणक जिससे दैनिक हितलाभ दर को गुणा किया जाता है
1	2
17 वर्ष और कम	5690
18 वर्ष	5670
19 वर्ष	5660
20 वर्ष	5640
21 वर्ष	5620
22 वर्ष	5600
23 वर्ष	5580
24 वर्ष	5560
25 वर्ष	5540
26 वर्ष	5520
27 वर्ष	5480
28 वर्ष	5460
29 वर्ष	5420
30 वर्ष	5390
31 वर्ष	5360
32 वर्ष	5320
33 वर्ष	5280
34 वर्ष	5240
35 वर्ष	5200
36 वर्ष	5160
37 वर्ष	5110
38 वर्ष	5070
39 वर्ष	5020
40 वर्ष	4970
41 वर्ष	4910
42 वर्ष	4860
43 वर्ष	4800
44 वर्ष	4740
45 वर्ष	4670
46 वर्ष	4610

अनुसूची—3

स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए रूपान्तरण मूल्य

(विनियम—76ख)

जिस तारीख से उपयुक्त कार्यालय में रूपान्तरण के लिए बीमाकृत व्यक्ति का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें पिछले जन्म-दिवस पर उसकी आयु	वह गुणक जिससे दैनिक हितलाभ दर को गुणा किया जाना है
1	2
47 वर्ष	4540
48 वर्ष	4470
49 वर्ष	4400
50 वर्ष	4330
51 वर्ष	4250
52 वर्ष	4180
53 वर्ष	4100
54 वर्ष	4020
55 वर्ष	3930
56 वर्ष	3850
57 वर्ष	3760
58 वर्ष	3670
59 वर्ष	3590
60 वर्ष	3500
61 वर्ष	3400
62 वर्ष	3310
63 वर्ष	3220
64 वर्ष	3130
65 वर्ष	3030
66 वर्ष	2940
67 वर्ष	2850
68 वर्ष	2750
69 वर्ष	2660
70 वर्ष	2570
71 वर्ष	2470
72 वर्ष	2380
73 वर्ष	2290
74 वर्ष	2200
75 वर्ष	2120
76 वर्ष	2030
77 वर्ष	1950
78 वर्ष	1860
79 वर्ष	1780
80 वर्ष	1700

7 निगम ने कृत्रिम अंग जुड़वाने या मरम्मत कराने या बदलवाने के लिए कृत्रिम अंग केन्द्र पर जाने वाले अपंग व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ते की मजूरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा निम्नलिखित संकल्प किया :—

"कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 28 के खण्ड (xi) के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 23-क के अनुसार संकल्प किया जाता है कि निगम ऐसे सबूत की शर्त के अधीन पुनर्वास भत्ता मजूर कर सकता है जो अंग जुड़वाने या मरम्मत कराने या बदलवाने के लिए कृत्रिम अंग केन्द्र में दाखिल रहने वाले प्रत्येक दिन के संबंध में निगम बीमाकृत व्यक्ति से लिखित रूप में मांगे/पुनर्वास भत्ता निम्नलिखित दरों पर मजूर किया जायेगा —

1 कृत्रिम अंग केन्द्र पर ठहरने की अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति के बीमारी हितलाभ का पात्र होने पर यह भत्ता बीमारी हितलाभ की दर पर दिया जाये। (यह अवधि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 47 के अन्तर्गत स्वीकार्य बीमारी हितलाभ की अवधि में समायोजित नहीं की जायेगी)।

2 कृत्रिम अंग केन्द्र पर ठहरने की अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति के बीमारी हितलाभ का पात्र न होने पर यह भत्ता स्थानीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार निर्धारित देय या लागू बीमारी हितलाभ पर दिया जाये, तथा

3 कृत्रिम अंग केन्द्र पर ठहरने की अवधि बीमाकृत व्यक्ति की प्रथम हितलाभ अवधि शुरु होने से पहले की होने पर यह भत्ता प्रथम अंशदान अवधि के लिए अंशदान पर निर्धारित करने से संबंधित आधार पर दैनिक औसत मजदूरी के तदनुरूपी मानक हितलाभ पर दर दिया जाये।"

8 (i) निगम ने निर्णय किया कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में प्रारम्भिक उपस्कर की व्यवस्था पर 1973 में निर्धारित की गई व्यय की सीमा को 1 1 79 से निम्न प्रकार बढ़ाया जाये —

1. 150 बिस्तरों तक	प्रति बिस्तर 5,000/– रुपये से बढ़ाकर 8,000/– रुपये।
2. 151 से 300 बिस्तरों तक।	प्रति बिस्तर 4,000/– रुपये से बढ़ाकर 6 500 – रुपये
3. 300 तथा अधिक	प्रति बिस्तर 3 500/– रुपये से बढ़ाकर 5,500/- रुपये।

(ii) निगम ने डिस्पेंसरियों/डिटेंशन वार्डों/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों से सम्बद्ध साधारण वार्डों में 3,500/–रुपये प्रति बिस्तर तक प्रारम्भिक उपस्कर की व्यवस्था करने का भी निर्णय किया।

(iii) निगम ने चालू अस्पताल में अतिरिक्त उपस्कर (एक्सरे मशीन जैसे कुछ कीमती उपस्कर बदलना तथा अस्पतालों में नये विभाग खोलना आदि) की व्यवस्था पर 1973 में निर्धारित की गई व्यय की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का अनुमोदन किया।

(iv) निगम ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली लागू होने वाले कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा संस्थानों में इस्तेमाल के लिए कर्मचारी राज्य बीमा आयुर्वेदिक फार्मूलरी परिशोधित की।

(v) निगम ने 200 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए पी० बी० एक्स टेलीफोन सुविधा तथा छोटे अस्पतालों के लिए इंटर-काम टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था का भी अनुमोदन किया।

9 निगम ने बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा देख रेख पर किए गए व्यय की प्रति पूर्ति के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को 500/- रुपए से बढ़ाकर 1000/- रुपए प्रति मामला करने का निर्णय किया।

10 निगम ने स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 31 मार्च 1974 की स्थिति के अनुसार पांचवीं पंचवार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आपरेटिव भाग को स्वीकार किया। लेकिन निगम ने निर्णय किया कि मूल्यांकन की रिपोर्ट के भाग 4 (अनुभाग-1) में दी गई सामान्य सिफारिशों की जांच उप-समिति द्वारा की जाएगी। उप-समिति अपनी सिफारिशें निगम को प्रस्तुत करेगी।

परिशिष्ट—5

1979–80 वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

क—28 मई, 1979

(1) स्थायी समिति ने बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या, भौगोलिक दूरी तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक को किसी भी क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में निर्णय करने के लिए प्राधिकृत किया।

ख—21 दिसम्बर, 1979

(1) स्थायी समिति ने केन्द्रीय खजाना नियमों के नियम 217(1) के उपबन्धों में ढील देने तथा कुछ आपवादिक मामलों में वेतन संवितरण के लिए निर्धारित तारीख से पहले वेतन तथा भत्तों के संवितरण की अनुमति देने के लिए महानिदेशक को इस शर्त पर प्राधिकृत किया कि जिस मास में ढील की अनुमति दी जाये, उसके बाद स्थायी समिति की अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(2) स्थायी समिति ने संगठन में मितव्ययता का वातावरण बनाने के भाग के रूप में पैट्रोल तथा कागज के इस्तेमाल में बचत तथा आकस्मिक व्यय आदि में कमी जैसे किफायत के कुछेक उपायों का अनुमोदन किया।

(3) स्थायी समिति ने किराया कार्यविधि के अनुपालन की शर्त पर महानिदेशक को निगम कार्यालयों के लिए स्थान किराये पर लेने के लिए पेशगी देने तथा उसके समायोजन/वापसी की शर्तें निर्धारित करने के लिए पूर्ण शक्तियां सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।

ग—17 फरवरी, 1980

(1) स्थायी समिति ने अन्त्येष्टि हितलाभ के दावेदारों द्वारा इच्छा व्यक्त किए जाने पर निगम के खर्चे पर मनीआर्डर द्वारा अदायगी करने का अनुमोदन किया। इस संबंध में अनुदेश 17-4-1980 से लागू हो गये हैं।

(2) स्थायी समिति ने निगम की स्टाफ प्रशिक्षण योजना का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त सचिव, श्री आर०के०ए० सुब्रह्मण्य नियोजकों के प्रतिनिधि श्री एन०एस० राव तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्री जी० वी० चिटनिस को मिलाकर एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त करने का निर्णय किया।

परिशिष्ट 6

1979—80 वर्ष के दौरान चिकित्सा हितलाभ परिषद् की महत्वपूर्ण सिफारिशें

17 मार्च, 1980

1. चिकित्सा हितलाभ परिषद् ने उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार परिशोधित फार्माकोपिया का अनुमोदन किया तथा कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों में इसके परिचालन और निगम द्वारा इसको स्वीकार करने की सिफारिश की।

2. चिकित्सा हितलाभ परिषद् ने सिफारिश की कि निम्नलिखित मामलों में लाभाधिकारियों को एलोपैथी के अलावा अन्य प्रणाली में इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मौजूदा निर्णय को चालू रखा जाये।

(i) जहां उस प्रणाली के लिए काफी कामगारों की मांग हो, और

(ii) जहां राज्य सरकार ने इस प्रकार की प्रणाली में योग्यताओं को मान्यता प्रदान की हो।

परिषद् ने यह भी सिफारिश की कि किसी भी हालत में दो प्रणालियों को आपस में मिलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3. परिषद् ने सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की :—

(क) दवाईयों, शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा, विकलांग विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान की मूलभूत विशेषताओं में सुधार को प्राथमिकता दी जाये। इसके बाद नेत्र विज्ञान तथा कान-नाक-गले की विशेषताओं में सुधार को प्राथमिकता दी जाये।

चिकित्सा हितलाभ परिषद् ने यह भी सिफारिश की कि शिक्षण अस्पतालों में मौजूदा अति विशिष्ट सेवाओं का कर्मचारी राज्य बीमा लाभाधिकारियों के लिए उपयोग किया जाए।

(ख) परिषद् ने यह भी सिफारिश की कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत एम्बुलैंस गाड़ी की व्यवस्था के लिये गाईडस्टिक निम्न प्रकार परिशोधित की जानी चाहिए :—

(1) 10,000 से कम लेकिन 7,000 से अधिक कर्मचारियों वाले केन्द्र	मैटाडोर आदि जैसी छोटी किस्म की गाड़ी जिसे एम्बुलैंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
(2) 10,000 या अधिक कर्मचारियों वाले केन्द्र	एक एम्बुलैंस
(3) 30,000 या अधिक कर्मचारियों वाले केन्द्र	दो एम्बुलैंस
(4) 60,000 या अधिक कर्मचारियों वाले केन्द्र	तीन एम्बुलैंस
(5) 1,00,000 कर्मचारियों वाले केन्द्र	चार एम्बुलैंस
(6) 1 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले केन्द्र	प्रत्येक 50,000 कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त एम्बुलैंस की व्यवस्था की जाये।

एक एम्बुलैंस गाड़ी के लिए स्वीकार्य अधिकतम स्टाफ में प्रति गाड़ी तीन चालक तथा छह क्लीनर व स्ट्रेचर वाहक होने चाहिएं ताकि चौबीस घंटे प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ग. विशेषज्ञ सेवाओं में सुधार

(1) 50 बिस्तर वाले अस्पतालों सहित छोटे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में भी विकलांग विज्ञान तथा शिशु रोग विज्ञान के एक-एक विशेषज्ञ की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(2) 20,000 परिवार एककों से कम वाले केन्द्रों तथा प्रत्येक 20,000 परिवार एककों अथवा उसके भाग के लिये औषध विज्ञान तथा शिशु रोग विज्ञान में अंशकालिक विशेषज्ञों के सत्रों की संख्या दो सत्र प्रति सप्ताह से बढ़ाकर तीन सत्र प्रति सप्ताह कर दी जाये।

(3) क्षय तथा यौन संप्रेषित रोगों में विशिष्ट सेवा के लिए विशेषज्ञ केन्द्रों में सेवाओं में वृद्धि करके 20,000 परिवार एककों से कम वाले केन्द्रों तथा प्रत्येक 20,000 परिवार एककों और उसके भाग के लिये एक सत्र प्रति सप्ताह से दो सत्र प्रति सप्ताह कर दी जाये।

(4) अंशकालिक विशेषज्ञों का पारिश्रमिक सप्ताह में एक सत्र के लिए 125/- रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 200/- रुपये प्रति मास कर दिया जाये तथा प्रत्येक अतिरिक्त सत्र के लिये 100/- रुपये की अदायगी की जाय जिसकी अधिकतम सीमा 1,000 रुपये प्रति मास हो।

घ. कर्मचारी राज्य बीमा अनैक्सी के लिये स्टाफ की व्यवस्था

प्रत्येक कर्मचारी राज्य बीमा अनैक्सी में एक चिकित्सा अधिकारी तथा न्यूनतम पैरा-मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक अनैक्सी के साथ एक छोटा औषध भण्डार खोला जाए।

ङ. रात्रि के दौरान रेडियोलाजी प्रयोगशाला सेवाएं आदि

जिन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में रात्रि के दौरान प्रयोगशाला, एक्स-रे विभाग, अन्त्यकरण विभाग, ई०सी०जी० कक्ष आदि सेवाओं की व्यवस्था है, रात्रि ड्यूटी के लिये मानकों के अलावा न्यूनतम पैरा-मैडिकल स्टाफ (तकनीशियन/सहायक) की व्यवस्था की जाए।

च. अंशकालिक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाए। लगभग 500 बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक के लिये एक लघु कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय खोला जाये।

छ. राज्य सरकारों से निवेदन किया जाये कि :—

(1) निगम द्वारा निर्धारित मानक तथा मानदण्ड लागू करें।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के मौजूदा रिक्त पदों को भरें।

(3) अनुमोदित मानदण्ड के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में खुराक की व्यवस्था करें।

(4) अनुमोदित फार्माकोपिया के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों में औषधियों और दवाइयों की व्यवस्था करें।

औषधालयों, विशेषज्ञ केन्द्रों तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का आवधिक निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टर बनाया हुआ है, शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है तथा तुरन्त सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

4. चिकित्सा हितलाभ परिषद् ने सिफारिश की कि कर्मचारी राज्य बीमा लाभाधिकारियों के इस्तेमाल के लिये सरकारी/राज्य सरकार के गैर सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण प्रभार 25/- रुपये प्रति दिन प्रति भरे बिस्तर तक की अनुमति दी जाये।

5. परिषद् ने यह भी सिफारिश की कि नियोजक उपयोग औषधालयों द्वारा विशेष दवाइयों की पूर्ति के लिये राशि 6/- रुपये से बढ़ाकर 15/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक प्रति वर्ष कर दी जाये।

31 मार्च 1980 को कर्मचारी राज्य बीमा

क्रम संख्या	पदनाम	मुख्यालय	आन्ध्र प्रदेश		असम		बिहार		दिल्ली		गुजरात		तमिलनाडु	
			क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	महानिदेशक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	बीमा आयुक्त	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	चिकित्सा आयुक्त	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बीमांकक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	निदेशक (प्रशासन)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	क्षेत्रीय उप-चिकित्सा आयुक्त	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	संयुक्त बीमा आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड-1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9.	निदेशक (संगठन एवं पद्धति)/क्षे.नि. ग्रेड-2/नि. (यो.एवं वि.)/निदेशक (सतर्कता)	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10.	प्रशासन अधिकारी/उप बीमा आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड-3/उप मुख्य लेखा अधिकारी/संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक/सतर्कता अधिकारी/सहायक बीमांकक	11	—	—	—	—	1	—	1*	—	—	—	1	—
11	उप-चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा निर्देशी	4	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	4	—
12.	क्षे.नि. ग्रेड-4/उप प्र.अ./लेखा अ./उप क्षे.नि./सहायक निदेशक (यो.एवं वि.)	10	3	—	1	—	2	—	5	—	8	—	7	—
13.	सहायक क्षे.नि./प्र. ग्रेड-1/उप ले. अ./अनुभाग अधिकारी	23	2	7	1	—	3	2	3	—	5	10	4	17
14.	सहायक इंजीनियर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	अनुभाग अधिकारी (हिन्दी)	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
16.	बीमा निरीक्षक/लै.परी.नि./प्र. ग्रेड-2/उप प्र./निरीक्षक (सं. एवं प.)/वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	8	24	10	4	3	13	6	32	7	35	21	43	35
17.	महानिदेशक के निजी सचिव	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	प्रबंधक ग्रेड-3/प्रधान लि./सहायक/प्रधान लिपिक खजांची/हिन्दी अनुवादक	86	23	13	3	5	16	15	27	7	49	19	34	37
19.	कनिष्ठ इंजीनियर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*दिल्ली क्षेत्र के सतर्कता अधिकारी का पद मुख्यालय में शाइफ्टेड।

परिशिष्ट 7

भाग I

निगम का प्राधिकृत कर्मचारी वर्ग

केरल		मध्य प्रदेश		महाराष्ट्र			उड़ीसा		पंजाब		राजस्थान		कर्नाटक		उत्तर प्रदेश		पश्चिमी बंगाल		जोड़	
क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का. पूना	उ.क्षे. का. नागपुर		उ.क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.	क्षे. का.	स्था. का.		स्था. का.
16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4
—	—	—	—	1	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
1	—	1	—	3	1		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	24
2	—	—	—	6+2	—		—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	3		9	—	44
4	—	3	5	15	2		1	—	1	—	6	—	1	—	5	—	6	—	14	—	94
4	6	2	5	10	3		1	36	2	—	5	—	3	—	3	5	6	3	9	22	202
1	—	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
—	—	1	—	1	—		—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	9
32	25	13	12	99	16		6	50	5	3	40	14	12	8	20	22	31	19	86	42	796
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
30	15	16	12	84	18		8	55	11	11	33	13	14	9	26	19	36	21	72	36	873
2	—	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	वैयक्तिक सहायक	14	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
21.	तकनीकी सहायक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	कलाकार	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	पुस्तकाध्यक्ष	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	स्वागती	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	प्रभारी उ.श्रे लि/उ.श्रे.लि. खजांची/उ.श्रे लि./ उ.श्रे लि. रखवाल	85	70	54	9	5	45	23	78	25	146	107	135	156
26	आशुलिपिक	21	3	—	1	—	3	—	—	—	6	—	7	—
27.	सगणक	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	नि श्रे लि./एक्रीमा आपरेटर/ टैलैक्स आपरेटर/टेलीफोन आपरेटर	86	70	81	11	7	37	29	73	29	139	114	117	188
29.	गैस्टेटनर आपरेटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
30.	स्टाफ कार चालक/डिलीवरी गाड़ी चालक	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
31.	कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	जमादार	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	रिकार्ड सार्टर/दफ्तरी (स्लैकशन ग्रेड दफ्तरियों सहित)	30	19	20	2	8	11	18	19	8	37	31	36	66
34.	चपरासी	58	12	28	4	2	10	8	17	17	25	42	20	54
35.	चौकीदार	3	2	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—
36.	फराश	7	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—
37	माली	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	लिफ्टमैन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
39.	सफाई कर्मचारी	9	2	—	—	—	1	—	2	—	4	—	3	—
	जोड़	485	236	213	38	30	149	101	265	93	470	344	422	553

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
93	85	53	58	298	57	22	273	29	12	104	28	40	19	87	94	110	61	261	184	2907
4	—	2	—	15	3	1	—	2	—	5	—	2	—	5	—	6	—	16	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
90	110	54	48	308	43	23	333	28	11	93	32	36	23	89	91	116	77	294	253	3133
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	7
1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	32	15	22	91	12	4	87	7(*)	14	27	27	7	17	23	30	36	33	80	78	970
17	35	10	20	60	8	5	140	8	4	22	15	7	6	16	39	24	33	49	112	927
2	—	2	—	6	1	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	4	—	42
2	—	1	—	9	1	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	2	—	6	—	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3
2	—	11	—	9	1	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	2	—	8	—	53
311	308	176	177	1023	167	75	974	98	55	354	129	132	82	288	300	388	247	924	727	10,334

अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट ।

(*) एक चालक—व—चपरासी शामिल है।

परिशिष्ट 7

भाग 2

31-3-80 को निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में प्राधिकृत तथा तैनात कर्मचारी वर्ग की स्थिति का विवरण

क्रम. सं०	पदनाम	निदेशालय (चि.) दिल्ली		कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय		का.रा.बी. अस्पताल		जोड़		कैफियत
		प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	प्राधिकृत	तैनात	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली	1	1	—	—	—	—	1	1	—
2.	चिकित्सा अधीक्षक	शून्य	—	—	—	1	1	1	1	—
3.	प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी	1	1	—	—	—	—	1	1	—
4.	उप मुख्य लेखा अधिकारी (चि)	1	1	—	—	—	—	1	1	—
5.	उप प्रशासन अधिकारी (चि.)/अस्पताल	1	1	—	—	1	1	2	2	—
6.	लेखा अधिकारी (चिकित्सा)	1	1	—	—	—	—	1	1	—
7.	उप लेखा अधिकारी	—	—	—	—	1	1	1	1	—
8	हिन्दी अधिकारी	1	1	—	—	—	—	1	1	—
9	पूर्णकालिक विशेषज्ञ, शल्य, चिकित्सा, विकलांग, स्त्री रोग, रेडियोलाजी, नेत्र तथा ई.एन. टी।	—	—	—	—	14	10	14	10	—
10.	सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड-1/2	—	—	217 (200 पद भरने के लिए प्राधिकृत)	165	30	30	247-(17)	195	—
11.	रजिस्ट्रार	—	—	—	—	8	6	8	6	—
12.	हाउस सर्जन	—	—	—	—	14	14	14	14	—
13.	अंशकालिक विशेषज्ञ	—	—	सत्रानुसार	11+8 (लो.ना.ज.प्र./आर.बी.टी.बी. अस्पताल)	7+3	5+2*	11+8 7+3 (सत्रानुसार स्वीकृत)	11+7 5+2	*पूर्णकालिक विशेषज्ञों के स्थान पर 2 अंशकालिक विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं
14.	लेखा परीक्षा निरीक्षक/बीमा निरीक्षक	4	4	—	—	—	—	4	4	—
15.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	—	—	—	—	1	1	—
16.	नर्सिंग अधीक्षक	—	—	—	—	1	—	1	—	—
17.	आयुर्वेदिक चिकित्सक	—	—	2	2	—	—	2	2	—
18.	निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/चिकित्सा अधीक्षक के वैयक्तिक सहायक	1	1	—	—	1	1	2	2	—
19.	प्रधान लिपिक	8	8	—	—	5	5	13	13	—
20.	सहायक	4	4	—	—	—	—	4	4	—
21.	आशुलिपिक	6	6	—	—	2	1	8	7	—
22.	उच्च श्रेणी लिपिक खजांची	1	1	—	—	1	1	2	2	—
23.	उच्च श्रेणी लिपिक	35	35	26	26	12	12	73	73	—
24.	रखवाल	—	—	—	—	1	1	1	1	—
25.	निम्न श्रेणी लिपिक/हिन्दी/टंकक	44	44	107	107	16	15	167	166	—
26.	एम्बुलेंस/स्टाफकार/डिलीवरी वैन चालक	7	6	1	1	5	5	13	12	—
27.	गैस्टेटनर चालक	1	1	—	—	—	—	1	1	—
28.	दफ्तरी/सलेक्शन ग्रेड दफ्तरी	7	7	5	5	2	2	11	11	—
29.	चपरासी	20	16	100	94	8	7	128	117	—
30.	एम्बुलेंस परिचर	2	2	—	—	3	—	5	2	—
31.	सोशल गाइड	2	1	—	—	—	—	2	1	—
32.	एल.एच.वी./ए.एन.एम./एन.आर.एन./मिडवाइफ/दाई	—	—	139	115	—	—	139	115	—
33.	औषधकारक व लिपिक/भंडार पाल/औषधकारक/आयुर्वेदिक औषधकारक	11	11	132	120	—	—	143	131	—
34.	मुख्य औषधकारक	—	—	—	—	1	—	1	—	—
35.	प्रयोगशाला सहायक	—	—	11	10	6	4	17	14	—
36.	प्रयोगशाला तकनीकियन	—	—	—	—	6	6	6	6	—
37.	फराश	3	3	—	—	—	—	3	3	—
38	ड्रेसर	—	—	79	78	6	6	85	84	—
39.	सहायक मैट्रन	—	—	—	—	2	2	2	2	—
40.	नर्सिंग सिस्टर	—	—	—	—	22	22	22	22	—
41.	स्टाफ नर्स	—	—	—	—	113	103	113	103	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	श्राहारविद	—	—	—	—	1	1	1	1	—
43	रेडियोग्राफर (2 कम वेतनमान मे)	—	—	—	—	7	5	7	5	—
44	डार्क रूम सहायक	—	—	—	—	2	2	2	2	—
45	ई सी जी तकनीशियन	—	—	—	—	2	2	2	2	—
46	श्रो टी सहायक	—	—	—	—	6	6	6	6	—
47	श्रो टी तकनीशियन	—	—	—	—	4	4	4	4	—
48	सी एस श्रार सहायक	—	—	—	—	4	4	4	4	—
49	सी एस श्रार तकनीशियन	—	—	—	—	1	1	1	1	—
50	भौतिक चिकित्सक	—	—	—	—	1	1	1	1	—
51	व्यावसायिक चिकित्सक	—	—	—	—	1	1	1	1	—
52	श्राप्टा मीटरिस्ट	—	—	—	—	1	1	1	1	—
53	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	—	—	—	—	1	शून्य	1	शून्य	—
54	वरिष्ठ रक्त बैंक तकनीशियन	—	—	—	—	1	—	1	—	—
55	लिनन मिस्ट्रैस	—	—	—	—	2	—	2	—	—
56	बायलर परिचर	—	—	—	—	1	1	1	1	—
57	लांड्री पर्यवेक्षक	—	—	—	—	1	1	1	1	—
58	धातु कमचारी व मिस्त्री	—	—	—	—	1	—	1	—	—
59	चिकित्सा रिकार्ड तकनीशियन	—	—	—	—	1	1	1	1	—
60	कनिष्ठ चिकित्सा रिकार्ड तकनीशियन	—	—	—	—	1	1	1	1	—
61	टेलीफोन श्रापरेटर	—	—	—	—	2	—	2	—	
62	पुस्तकाध्यक्ष	—	—	—	—	1	—	1	—	—
63	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	—	—	—	—	1	1	1	1	—
64	हवलदार	—	—	—	—	1	—	1	—	—
65	लान्ड्री श्रापरेटर	—	—	—	—	10	10	10	10	—
66	प्रधान रसोइया	—	—	—	—	3	3	3	3	—
67	रसोइया व मसालची तथा मट रसोइया	—	—	—	—	26	24	26	24	—
68	स्ट्रेचर वाहक	—	—	—	—	9	8	9	8	—
69	नर्सिंग श्रर्दली	—	—	—	—	98	93	98	93	—
70	श्राया	—	—	34	24	4	4	38	28	—
71	चौकीदार	—	—	34	32	23	23	57	55	—
72	दर्जी	—	—	—	—	2	1	2	1	—
73	सफाई कर्मचारी	3	3	94	94	63	63	160	160	—
74	वाहक	—	—	—	—	6	4	6	4	—
75	हिन्दी सहायक	2	1	—	—	—	—	2	1	—

टिप्पणी —मंगोलपुरी श्रौषधालय के लिए मंजूर स्टाफ विवरण मे शामिल नही किया गया है।

परिशिष्ट 8

भाग 1

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली

1-1-80 को स्थिति के श्रनुसार निगम कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से श्रनुसूचित जाति तथा श्रनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या का सूचक विवरण

श्रेणी	स्थाई/श्रस्थायी	कर्मचारियों की कुल संख्या	श्रनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियो के साथ प्रतिशतता	श्रनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियो के साथ प्रतिशतता	कैफियत
प्रथम श्रेणी	स्थायी	62	4	6 45	—	—	—
	श्रस्थायी	64	12	18 75	—	—	—
द्वितीय श्रेणी	स्थायी	32	—	—	4	12 50	—
	श्रस्थायी	103	9	8 74	4	3 88	—
तृतीय श्रेणी	स्थायी	4579	463	10 11	12	0 26	—
	श्रस्थायी	2672	247	9 24	23	0 86	—
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारियो को छोड़ कर)	स्थायी	1419	362	25 51	17	1 19	—
	अस्थायी	977	211	21 59	39	3 99	—
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारी)	स्थायी	95	95	100 00	—	—	—
	श्रस्थायी	124	123*	99 19	3	2 41	—

*एक पद खाली

हस्ताक्षरित हरिकृष्ण श्राहूजा

स्थानीय प्रशासन अधिकारी

परिशिष्ट

भाग

1.1.80 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के कार्यालय में सीधी भर्ती द्वारा अनुसूचित जातियों

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या		अनुसूचित जाति				
	अधिसूचित	भरी गई	आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अग्रेनीत तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अग्रेनीत तीन वर्षों के बाद समाप्त आरक्षित पदों की संख्या
			कालम 2 में से	कालम 3 में से			
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम श्रेणी	6	6	1	1	4	—	—
द्वितीय श्रेणी	29	29	4	2	1	—	—
तृतीय श्रेणी	463	456	70	65	52	1	8
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर)	—	—	—	—	—	—	—
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट

भाग

1-1-1980 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के कार्यालय में सीधी भर्ती के अलावा अन्य माध्यम

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या		अनुसूचित जाति				
	अधिसूचित	भरी गई	आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अग्रेनीत तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अग्रेनीत तीन वर्षों के बाद समाप्त आरक्षित पदों की संख्या
			कालम 2 में से	कालम 3 में से			
प्रथम श्रेणी	12	12	3	3	3	—	—
द्वितीय श्रेणी	27	27	6	6	—	—	—
तृतीय श्रेणी	680	678	90	83	91*	2	4
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर)	117	117	9	14	34	1	—
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारी)							

* नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया है लेकिन कार्य-भार अभी सम्भालना है ।

एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को अभी कार्य-भार संभालना है ।

तथा अनुसूचित जनजातियो के सदस्यों द्वारा भरे गए आरक्षित रिक्त पदो की संख्या का सूचक विवरण ।

अनुसूचित जन जाति					
आरक्षित रिक्तियो की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	तीसरे अग्रेनीत वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारो की संख्या	अग्रेनीत 3 वर्षों के बाद समाप्त आरक्षित पदों की संख्या	कैफियत
कालम 2 में से	कालम 3 में से				
9	10	11	12	13	14
1	1	4	--	--	--
2	2	--	--	--	--
48	51	4	2	6	—
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरे गये आरक्षित रिक्त पदों की संख्या का सूचक विवरण ।

अनुसूचित जन जाति					
आरक्षित रिक्तियो की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	तीसरे अग्रेनीत वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अग्रेनीत 3 वर्षों के बाद समाप्त आरक्षित पदों की संख्या	कैफियत
कालम 2 में से	कालम 3 में से				
9	10	11	12	13	14
1	1	--	-	--	--
3	3	2	--	--	--
56	56	9	10	6	--
7	8	10	2	--	-

परिशिष्ट 9

31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किए गए नियोजकों और कर्मचारियों की संख्या

क्षेत्रवार

राज्य	कार्यान्वित क्षेत्र**		अकार्यान्वित क्षेत्र		सभी क्षेत्र	
	नियोजकों की संख्या	31-3-80 को कर्मचारियों की संख्या	नियोजकों की संख्या	31-3-80 को कर्मचारियों की संख्या	नियोजकों की संख्या	31-3-80 को कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	3,760	2,40,000	83	16,200	3,843	2,56,200
असम	578	32,000	108	10,500	686	42,500
बिहार	1,682	1,40,000	235	2,00,000	1,917	3,40,000
चंडीगढ़	296	14,300	--	--	296	14,300
दिल्ली	6,025	2,65,000	--	--	6,025	2,65,000
गुजरात	4,037	5,50,000	638	1,00,000	4,675	6,50,000
हरियाणा	2,491	1,94,000	168	15,000	2,659	2,09,000
हिमाचल प्रदेश	11	1,200	68	4,100	79	5,300
जम्मू और कश्मीर	--	--	अनुपलब्ध	11,600	अनुपलब्ध	11,600
कर्नाटक	2,336	3,00,000	207	28,000	2,543	3,28,000
केरल और माही	3,520	3,08,000	12	2,600	3,532	3,10,600
मध्य प्रदेश	1,686	1,60,000	62	75,000	1,748	2,35,000
महाराष्ट्र						
बम्बई क्षेत्र	11,078	11,46,000	135	14,000	11,213	11,60,000
गोआ	271	19,500	--	--	271	19,500
नागपुर क्षेत्र	847	75,000	153	23,000	1,000	98,000
पूना क्षेत्र	2,155	2,45,000	127	37,500	2,282	3,82,500
उड़ीसा	454	1,09,000	68	82,000	522	1,91,000
पाण्डिचेरी	124	15,000	-	--	124	15,000
पंजाब	3,696	1,65,000	315	13,000	4,011	1,78,000
राजस्थान	1,732	1,24,000	67	11,500	1,799	1,35,500
तमिलनाडु	5,802	4,50,000	215	32,000	6,017	4,82,000
उत्तर प्रदेश	3,002	4,45,000	370	34,000	3,372	4,79,000
पश्चिमी बंगाल	9,017	9,85,000	176	1,48,000	9,193	11,33,000
समस्त भारत 1980	64,600	59,83,000	3,207	8,58,000	67,807	68,41,000
समस्त भारत 1979	59054	58,15,900	2,672	8,79,700	61,726	66,95,600

**अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत व्यक्ति शामिल हैं ।

परिशिष्ट 10

31-3-80 की स्थिति के अनुसार योजना के अन्तर्गत केन्द्रों, कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों, परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों और लाभाधिकारियों की संख्या राज्यवार (अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत योजना के विस्तार को शामिल करके)

राज्य	केन्द्रों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	परिवार (बीमाकृतव्यक्ति) एककों की संख्या	लाभाधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	44	2,40,000	2,74,000	2,74,000	10,63,100
असम	13	32,000	36,000	36,000	1,39,700
बिहार	29	1,40,000	1,71,000	1,71,000	6,63,500
चंडीगढ़	1	14,300	17,500	17,500	67,900
दिल्ली	1	2,65,000	3,30,000	3,30,000	12,80,400
गुजरात	15	5,50,000	5,92,000	5,92,000	22,97,000
हरियाणा	18	1,94,000	2,42,500	2,42,500	9,40,900
हिमाचल प्रदेश	1	1,200	1,300	1,300	5,000
जम्मू और कश्मीर	--	--	--	--	--
कर्नाटक	18	3,00,000	3,28,000	3,28,000	12,72,600
केरल और माही	33	3,08,000	3,35,000	3,35,000	12,99,800
मध्य प्रदेश	22	1,60,000	2,00,000	2,00,000	7,76,000
महाराष्ट्र					
बम्बई क्षेत्र	1	11,46,000	12,20,000	12,20,000	47,33,600
गोआ क्षेत्र	7	19,500	20,700	20,700	80,300
नागपुर क्षेत्र	10	75,000	82,000	82,000	3,18,100
पूना क्षेत्र	15	2,45,000	2,60,000	2,60,000	10,08,800
उड़ीसा	22	1,09,000	1,16,000	1,16,000	4,50,100
पांडिचेरी	1	15,000	16,000	16,000	62,100
पंजाब	27	1,65,000	2,06,000	2,06,000	7,99,300
राजस्थान	19	1,24,000	1,55,000	1,55,000	6,01,400
तमिलनाडु	44	4,50,000	5,27,000	5,27,000	20,44,800
उत्तर प्रदेश	47	4,45,000	4,90,000	4,90,000	19,01,200
पश्चिमी बंगाल	7	9,85,000	12,30,000	12,30,000	47,72,400
समस्त भारत 1980	395	59,83,000	68,50,000	68,50,000	2,65,78,000
समस्त भारत 1979	375	58,15,900	65,89,500	65,89,500	2,55,67,300

परिशिष्ट

31-3-1980 को बिस्तरों, विशेषज्ञों औषधालयों,

क्र० सं०	राज्य का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बिस्तरों की कुल संख्या				विशेषज्ञ	
		सामान्य	प्रसूति	क्षयरोग	जोड़	पूर्ण कालिक	अंश कालिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	582	58	92	732	39	68
2.	असम	90	--	10	100	--	1
3.	बिहार	206	--	30	236	6	--
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	40	--	--	40	--	4
5.	दिल्ली	374	76	105	555	10	25
6	गोआ	33	--	--	33	--	16
7.	गुजरात	1067	59	312	1438	17	263
8.	हरियाणा	456	--	100	556	16	22
9.	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--
10.	कर्नाटक	998	69	137	1204	15	77
11.	केरल	810	110	175	1095	28	76
12.	मध्य प्रदेश	433	22	117	572	4	110
13.	महाराष्ट्र						
	(क) बृहत्तर बम्बई	2455	432	865	3752	48	116
	(ख) नागपुर क्षेत्र	219	31	47	297	3	66
	(ग) प० महाराष्ट्र	352	25	191	568	--	125
14.	उड़ीसा	133	17	12	162	3	3
15.	पाण्डिचेरी	68	4	10	82	--	12
16.	पंजाब	532	65	34	631	26	21
17.	राजस्थान	238	30	31	299	8	82
18.	तमिलनाडु	1343	335	410	2088	40	71
19.	उत्तर प्रदेश	761	157	224	1142	32	58
20.	पश्चिमी बंगाल	2158	78	694	2930	--	410
	जोड़	13348	1568	3596	18512	295	1626

परिशिष्ट

1978-79 तथा 1979-80 में उपस्थिति जारी, किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अस्पतालों में भर्ती,

(बीमाकृत व्यक्तियों

राज्य	अवधि	जोखिम ग्रस्त माने गए बीमाकृत व्यक्तियो की संख्या	उपस्थिति		
			नये मामले	पुराने मामले	कुल मामले
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश (से० प्र०)	1978-79	2,58,000	9,47,590	27,74,335	37,21,925
	1979-80	2,67,500	7,79,908	21,40,963	29,20,871
असम (से० प्र०)	1978-79	31,500	96,101	88,190	1,84,291
	1979-80	34,500	1,15,987	1,13,662	2,29,649
बिहार (से० प्र०)	1978-79	1,39,000	1,81,699	2,29,517	4,11,216
	1979-80	1,57,500	1,83,314	2,23,931	4,07,245
चंडीगढ़ (से० प्र०)	1978-79	14,750	39,830	97,602	1,37,432
	1979-80	17,500	44,917	1,81,431	1,63,348
दिल्ली (से० प्र०)	1978-79	2,82,000	3,45,681	16,46,458	19,92,139
	1979-80	3,17,000	3,63,671	13,81,668	17,45,339
गोवा (से० प्र०)	1978-79	18,100	39,605	12,392	51,997
	1979-80	20,500	43,664	13,257	56,921

—11

पैनल डाक्टरों तथा एम्बुलैंसों की संख्या

औषधालयों की कुल संख्या	बीमा चिकित्सा अधिकारियों की संख्या		बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या	नियोजक उपयोग औषधालयों में डाक्टरों की संख्या	एम्बुलैंस	कैफियत
	स्वीकृत	मौजूदा				
9	10	11	12	13	14	15
87	201	186	2	1	13	1 ईएसो शामिल है।
19	22	22	—	—	2	
47	145	120	—	—	21	
2	8	8	—	—	—	
29	217	165	—	—	5	
—	—	—	59	—	—	
91	449	434	259	1	18	
54	126	119	—	—	4	
1	1	1	—	—	—	
113	250	226	—	60	12	
121	242	220	—	—	9	
54	152	127	5	1	8	
18	14	8	2326	11	22	
26	85	80	—	—	4	
27	60	48	390	—	6	
24	67	63	—	—	7	
7	19	18	—	—	1	
39	115	108	83	—	4	
41	126	108	—	1	4	
121	390	360	—	14	23	
106	315	302	—	—	14	
3	97	—	1610	14	21	
1030	3101	2723	4734	103	198	

—12

विशेषज्ञों को निर्देशित मामलों की संख्या तथा घर पर किए गए निरीक्षणों की संख्या—राज्यवार

के सम्बन्ध में)

प्रति वर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति उपस्थितियों की संख्या		जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्रों की संख्या	अस्पतालों में दाखिल किए गए मामलों की संख्या	जांच के लिए विशेषज्ञों को निर्देशित मामलों की संख्या	घर पर किए गए निरीक्षणों की संख्या।
नये मामले	पुराने मामले				
7	8	9	10	11	12
3,673	10,753	6,82,472	1,16,627	1,72,388	अनुपलब्ध
2,916	8,004	5,52,764	23,978	1,14,043	अनुपलब्ध
3,051	2,800	59,439	377	3,721	2,326
3,362	3,295	75,749	425	4,693	1,811
1,307	1,651	1,63,150	364	12,317	4,817
1,164	1,422	1,72,421	259	17,931	8,825
2,700	6,617	11,213	251	5,420	अनुपलब्ध
2,567	6,767	11,840	1,309	8,510	अनुपलब्ध
1,226	5,839	2,75,990	3,233	54,954	54,588
1,147	4,359	2,37,730	3,107	51,040	51,704
2,188	685	24,615	अनुपलब्ध	1,083	413
2,130	647	26,799	अनुपलब्ध	1,094	500

1	2	3	4	5	6
गुजरात (से० प्र०)	1978-79	5,47,800	6,50,271	60,15,049	75,65,320
	1979-80	5,26,400	6,23,124	33,36,844	39,59,968
गुजरात (पे० प्र०)	1978-79	51,700	2,11,340	2,01,440	4,12,780
	1979-80	56,500	2,25,530	2,05,317	4,30,847
हरियाणा (से० प्र०)	1978-79	2,04,000	4,43,517	6,30,812	10,74,329
	1979-80	2,29,250	3,85,863	5,48,819	9,34,682
कर्नाटक (से० प्र०)	1978-79	2,99,000	15,88,912	29,09,573	44,98,485
	1979-80	3,16,000	15,70,441	27,48,300	42,18,741
केरल (से० प्र०)	1978-79	3,23,900	9,26,762	23,72,596	32,99,358
	1979-80	3,28,900	13,10,935	30,33,948	43,44,883
केरल (पे० प्र०)	1978-79				
	1979-80	—	—	—	(पैनल प्रणाली)
मध्य प्रदेश (से० प्र०)	1978-79	1,84,850	4,16,049	20,49,810	24,65,859
	1979-80	1,93,100	4,69,501	20,89,625	25,59,126
मध्य प्रदेश (पे० प्र०)	1978-79	2,900	6,719	16,618	23,337
	1979-80	2,400	6,116	14,878	20,994
महाराष्ट्र					
1. बम्बई क्षेत्र (से० प्र०)	1978-79	6,050	19,097	42,294	61,391
	1979-80	4,750	20,365	40,909	61,274
2. बम्बई क्षेत्र (पे० प्र०)	1978-79	1,72,200	9,21,631	7,43,148	16,64,779
	1979-80	1,68,500	9,23,616	7,15,749	16,39,365
3. नागपुर क्षेत्र (से० प्र०)	1978-79	79,000	2,42,314	9,06,705	11,49,019
	1979-80	81,500	2,62,336	9,81,471	12,43,807
4. पूना क्षेत्र (से० प्र०)	1978-79	32,950	1,36,540	3,79,528	5,16,068
	1979-80	48,250	1,82,772	4,17,718	6,00,490
5. पूना क्षेत्र (पे० प्र०)	1978-79	40,850	3,14,080	2,69,331	5,83,411
	1979-80	35,350	2,36,189	2,02,711	4,38,900
उड़ीसा (से० प्र०)	1978-79	93,500	2,62,038	3,20,492	5,82,530
	1979-80	1,07,000	2,17,373	3,05,322	5,22,695
पांडिचेरी और माही (से० प्र०)	1978-79	17,600	44,965	1,95,701	2,40,655
	1979-80	17,100	63,646	1,98,381	2,62,027
पंजाब (से० प्र०)	1978-79**	15,350	1,06,221	1,43,883	2,50,104
	1979-80**	15,550	1,67,875	1,21,152	2,89,027
पंजाब (पे० प्र०)	1978-79	37,500	1,65,516	88,626	2,54,142
	1979-80	17,350	93,207	59,441	1,52,548
राजस्थान (से० प्र०)	1978-79	1,35,500	3,71,230	7,58,001	11,29,231
	1979-80	1,48,500	4,13,188	8,06,822	12,20,010
तमिलनाडु (से० प्र०)	1978-79	4,75,400	13,16,394	44,94,667	58,11,061
	1979-80	5,05,350	13,00,393	50,41,457	63,41,850
तमिलनाडु (पे० प्र०)	1978-79	5,600	22,358	64,474	86,832
	1979-80	5,650	20,996	69,098	90,094
उत्तर प्रदेश (से० प्र०)	1978-79	4,75,500	13,56,297	17,13,116	30,69,413
	1979-80	4,85,000	12,46,948	15,83,391	28,30,330
प० बंगाल (पे० प्रे०)	1978-79	7,14,850	26,67,376	18,82,131	45,49,507
	1979-80	7,14,350	26,52,798	19,00,352	45,53,150
समस्त भारत	1978-79	46,59,350	1,38,40,132	3,19,46,489	4,57,86,621
	1979-80	48,21,250	1,38,24,673	2,84,13,617	4,22,38,290

से० प्र० : सेव प्रणाली

पे० प्र० : पेनल प्रणाली

**कुछ महीनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए । भारित औसत ली गई है ।

7	8	9	10	11	12
1,187	12,623	6,47,126	16,002	1,54,111	3,698
1,184	16,339	6,40,494	15,774	1,79,745	4,409
4,088	3,896	1,74,378	707	13,519	1,673
3,992	3,634	1,84,742	590	14,335	1,692
2,174	3,092	71,655	7,699	36,239	13,363
1,683	2,394	54,348	9,077	37,682	4,8 25
5,314	9,731	8,56,988	27,887	2,12,134	41,245
4,653	8,697	8,70,551	59,143	2,04,106	23,314
2,861	7,325	4,15,687	34,594	30,667	742
3,986	9,225	6,36,527	63,645	42,500	578
समाप्त	—	—	—	—	—
2,251	11,089	6,49,726	9,132	1,12,363	11,629
2,431	10,821	7,42,465	8,993	1,49,749	11,115
2,317	5,730	5,048	18	1,056	105
2,548	6,199	4,708	23	937	60
3,157	6,991	16,827	65,790	42,165	अनुपलब्ध
4,287	8,612	11,486	73,174	2,313	1
3,352	4,316	6,24,251	2,961	48,165	4,857
5,481	4,248	5,99,252	2,063	44,658	5,431
3,067	11,477	3,06,351	12,173	32,424	7,415
3,219	12,043	3,15,428	14,321	33,083	6,724
4,144	11,518	1,28,304	372	16,550	96
3,788	8,657	1,50,513	503	18,634	352
7,689	65,593	2,50,143	अनुपलब्ध	20,015	1,232
6,681	5,734	1,90,695	अनुपलब्ध	8,704	545
2,803	3,428	1,25,003	3,962	28,245	14,076
2,032	2,853	1,37,731	4,497	34,524	14,392
2,555	11,119	49,008	2,316	12,415	1,983
3,722	11,601	56,557	3,186	11,346	2,191
6,920	9,373	26,490	621	3,198	5,454
10,796	7,791	28,509	अनुपलब्ध	7,169	4,349
4,414	2,363	39,576	675	17,445	6,129
5,372	3,426	17,715	अनुपलब्ध	11,059	2,816
2,740	5,594	1,99,398	11,198	64,309	4,034
2,782	5,433	2,03,733	11,595	73,690	4,221
2,769	9,454	17,55,697	15,315	1,79,044	16,885
2,573	9,976	25,42,546	11,077	1,52,760	12,446
3,993	11,513	20,342	1,700	2,767	अनुपलब्ध
3,716	12,230	19,701	1,163	3,194	अनुपलब्ध
2,852	3,603	6,35,638	15,049	71,645	8,317
2,571	3,265	6,83,775	15,636	76,231	5,682
3,731	2,633	10,94,403	अनुपलब्ध	1,22,754	50,524
3,714	2,660	12,12,484	अनुपलब्ध	1,24,650	50,914
2,970	6,856	93,08,918	3,49,023	14,27,617	2,55,303
2,867	5,893	1,03,81,263	3,14,539	14,28,381	2,18,940

परिशिष्ट

1978-79 तथा 1979-80 में उपस्थितियों, तथा घर पर किए गए

(बीमाकृत व्यक्तियों के

राज्य	अवधि	जोखिम ग्रस्त माने गए परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों की संख्या	उपस्थितियां	
			नये मामले	पुराने मामले
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश (से० प्र०)	1978-79	2,58,000	11,30,192	29,54,296
	1979-80	2,67,500	9,81,315	26,55,035
असम (से० प्र०)	1978-79	31,500	81,613	45,663
	1979-80*	34,500	1,04,779	68,722
बिहार (से० प्र०)	1978-79	1,39,000	2,37,465	2,52,563
	1979-80	1,57,500	2,69,160	2,70,645
चंडीगढ़ (से० प्र०)	1978-79	14,750	45,081	46,484
	1979-80	17,500	52,781	58,204
दिल्ली (से० प्र०)	1978-79	2,82,500	8,92,928	14,68,219
	1979-80	3,17,000	8,29,444	11,34,341
गोवा (से० प्र०)	1978-79	18,100	38,769	9,138
	1979-80	20,500	41,511	10,135
गुजरात (से० प्र०)	1978-79	5,47,800	9,77,120	41,12,014
	1979-80	5,26,400	9,20,127	37,34,294
गुजरात (पे० प्र०)	1978-79	51,700	2,42,899	2,13,628
	1979-80	56,450	2,56,597	2,18,425
हरियाणा (से० प्र०)	1978-79	2,04,000	5,09,520	6,72,877
	1979-80	2,29,250	4,43,948	5,13,127
कर्नाटक (से० प्र०)	1978-79	2,99,000	21,45,273	38,58,454
	1979-80	3,16,000	19,88,867	36,65,878
केरल (से० प्र०)	1978-79	3,23,900	10,30,703	26,60,360
	1979-80	3,28,900	14,01,158	34,27,158
केरल (पे० प्र०)	1978-79			
	1979-80	—	———	पेनल प्रणाली
मध्य प्रदेश (से० प्र०)	1978-79	1,84,600	6,41,688	17,87,534
	1979-80	1,93,100	6,41,889	17,57,055
मध्य प्रदेश (पे० प्र०)	1978-79	2,900	10,126	13,401
	1979-80	2,400	9,445	11,801

13

निरीक्षणों की संख्या—राज्यवार

परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में)

	प्रति वर्ष प्रति 1000 परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एकों की उपस्थितियों की संख्या			घर पर किए गए निरीक्षणों की संख्या
कुल मामले	नये मामले		पुराने मामले	
6	7		8	9
40,84,488	4,381		11,451	22,466
36,36,350	3,668		9,925	20,392
1,27,276	2,591		1,450	112
1,73,501	3,037		1,992	216
4,90,028	1,708		1,817	2,733
5,39,805	1,709		1,718	6,025
91,565	3,056		3,151	1,668
1,10,985	3,016		3,326	2,311
23,61,147	3,166		5,206	10,843
19,63,785	2,617		3,578	10,168
47,907	2,142		505	259
51,646	2,025		494	276
50,89,134	1,784		7,506	2,740
46,54,421	1,748		7,094	2,951
4,56,527	4,698		4,132	379
4,75,022	4,546		3,869	391
11,82,397	2,498		3,298	3,847
9,57,075	1,937		2,238	3,835
60,03,727	7,175		12,905	9,667
56,54,745	6,294		11,601	12,559
36,91,063	3,182		8,214	246
48,28,316	4,260		10,420	143
समाप्त	—	—	—	—
24,29,222	3,476		9,683	718
23,98,944	3,324		9,099	597
23,527	3,492		4,621	44
21,246	3,935		4,917	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
1. बम्बई क्षेत्र (से० प्र०)	1978-79	6,050	18,983	34,065
	1979-80	4,750	20,300	35,600
2. बम्बई क्षेत्र (पे० प्र०)	1978-79	1,61,450	4,98,225	3,62,358
	1979-80	1,66,700	4,94,778	3,45,993
3. नागपुर क्षेत्र (से० प्र०)	1978-79	79,000	2,87,697	12,30,985
	1979-80	81,500	3,02,770	13,38,699
4. पूना क्षेत्र (से० प्र०)	1978-79	32,950	1,46,992	3,75,862
	1979-80	48,300	2,00,856	4,24,342
5. पूना क्षेत्र (पे० प्र०)	1978-79	40,850	3,00,195	2,17,436
	1979-80	35,850	2,16,755	1,66,045
उड़ीसा (से० प्र०)	1978-79	93,500	3,17,241	4,40,119
	1979-80	1,07,000	2,81,788	3,98,179
पांडिचेरी तथा माही (से० प्र०)	1978-79	17,600	49,282	2,74,644
	1979-80	17,100	74,898	2,83,329
पंजाब (से० प्र०)	1978-79*	7,450	1,06,620	1,00,269
	1979 80*	10,250	1,81,095	65,556
पंजाब (पे० प्र०)	1978-79*	31,000	1,60,233	92,736
	1979-80*	16,150	1,00,200	58,169
राजस्थान (से० प्र०)	1978-79	1,35,500	5,98,159	10,67,014
	1979-80	1,48,500	6,31,510	10,70,102
तामिलनाडु (से० प्र०)	1978-79	4,75,400	15,50,741	54,68,546
	1979-80	5,05,350	13,39,994	51,03,446
तामिलनाडु (पे० प्र०)	1978-79	5,600	28,598	98,269
	1979-80	56,50	22,875	91,437
उत्तर प्रदेश (से० प्र०)	1978-79	4,75,500	13,51,222	17,75,324
	1979-80	4,85,000	11,73,033	14,39,683
प० बंगाल (पे० प्र०)	1978-79	6,04,300	23,24,722	12,08,193
	1979-80	6,03,500	22,79,441	12,12,976
समस्त भारत	1978-79	45,23,400	1,57,22,287	3,08,40,391
	1979-80	47,02,600	1,52,61,312	2,95,58,376

*कुछ महीनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं । भारित औसत ली गई है ।

से० प्र० : सेवा प्रणाली

पे० प्र० : पेनल प्रणाली

6	7	8	9
53,048	3,138	5,631	58
55,900	4,274	7,495	4
8,80,583	3,086	2,144	2,367
8,40 769	2,968	2,076	2 145
15,18 682	3,642	15,582	3,645
16,41,469	3 715	16,426	4,158
5 22,854	4,461	11,407	8
6 25 198	4 159	8,786	9
5,17,631	7,349	5,323	927
3,84,800	6,046	4,632	521
7,57,360	3 393	4,707	7 506
6,79,967	2,634	3 721	5 795
3,23,926	2 800	15,605	2 783
3,58,227	4,380	16,569	2,353
2,06,889	14 311	13 459	1 920
2,46,651	17 668	8 396	1 03
2,52,969	5 162	2 991	2,831
1,58,369	6 204	3,602	2,561
16,65,173	4,414	7 875	894
17,01,612	4,253	7,206	934
70,19,287	3,262	11,503	22,058
64,43,440	2,652	10,099	18,785
1,26,807	5,107	17,537	1,305
1,14,312	4,049	16 184	1,558
31,26,546	2 842	3,734	36,112
26,12,716	2,419	2,968	25,158
35 32,915	3,847	1 999	23,427
34,92,417	3,777	2,010	22,350
4,65,62,678	3 476	6,818	7,61,533
4,48,19,688	3,245	6,286	1,48,843

परिशिष्ट 14

1978-79 तथा 1979-80 में अस्वस्थता की घटनाएं यानी प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों और 1000 परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों के नये मामलों की संख्या—समस्त भारत

क्रम संख्या	रोग	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		1978-79	1979-80	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6
1.	श्वसन प्रणाली का क्षय रोग	11.8	9.9	10.2	8.9
2.	अन्य प्रकार का क्षय रोग	4.3	3.8	4.7	4.1
3.	सिफलिस और उसके अनुगम	1 9	1.7	1.1	1.3
4.	गोनोकोकल संक्रमण	4.3	3.1	2.9	2.6
5.	सभी प्रकार की पेचिश	215.7	200.5	215.7	205.7
6.	हैजा, आन्त्र ज्वर, आन्त्रपथ में होने वाले अन्य संक्रामक रोग	20.5	19.9	24.4	22.7
7.	स्कारलेट ज्वर, डिप्थीरिया, कुकरखांसी, खसरा, कनपेड़, छोटी माता	5.9	6.5	22.4	22.9
8.	टाइफस और अन्य रिकेट्सिया	0.3	0.3	0.4	0.3
9.	मलेरिया	35.3	32.0	41.5	39.4
10.	फाइलेरिया रोग, अंकुशकृमि रोग व अन्य कृमि	58.7	58.6	98.3	91.9
11.	संक्रामक और परजीवी वर्ग के अन्य सभी रोग	51.9	49.5	60.1	57.3
12.	पुर्दम अर्बुद सभी साइट	0.3	0.3	0.2	0.2
13.	सुघात्म्य अर्बुद सभी साइट	0.8	2.1	0.5	0.2
14.	एलर्जिक विकार	95.9	97.3	122.5	119.1
15.	अवटु ग्रन्थि के रोग	1.0	1.3	1.4	1.4
16.	मधुमेह मेलीटस	5.9	4.4	6.9	4.2
17.	अभिटामिनता व अन्य कमियों की स्थिति	113.3	109.4	135.5	129.7
18.	अरक्तता	84.8	83.2	119.7	111.6
19.	विक्षिप्ति और मनोविक्षिप्ति	1.9	1.7	2.0	2.0
20.	स्वतंत्र विक्षिप्ति सी० एन० एस०	2 7	0.7	1.7	0.6
21.	नेत्र रोग	88.5	91.2	117.5	114.9
22.	कान और मोसटाइट प्रक्रिया के रोग	54.7	54.2	79.2	73.8
23.	रुमेटी ज्वर	5.6	5.4	4.9	4.7
24.	जीर्ण रुमेटी हृदय रोग	0 8	0.6	1.6	0 8
25.	अमनी काठिन्यज और व्यापजनक हृदय रोग	0.6	0.5	0.7	0.5
26.	अतितनाव रोग	8.9	8.3	13.3	9.9
27.	शिराओं के रोग	7.1	6.1	7.9	5.5
28.	तीव्र नेजोफेरिनजाइटिस (सामान्य नजला)	289.4	260.2	309.9	301.4
29.	तीव्र ग्रसनीशोथ और टान्सिल शोथ	74.5	74.0	97.3	94.8
30.	इन्फ्लूएंजा	120.5	116.8	125.6	119.1
31.	निमोनिया	2.8	2.8	6.6	5.8
32.	श्वसनी शोथ	219.4	214.8	238.6	226.7
33.	सिकतामयता और व्यवसायिक फुफ्फुसी तन्तुमयता	0.1	0.3	0.1	0.2
34.	अन्य श्वसन रोग	70.7	67.0	82.3	77.4
35.	आमाशय तथा पक्वाशय के रोग	126.0	119.4	134.8	127.2
36.	वंक्षण पूयशोथ	1.9	2.0	1.3	1.0
37.	उदरीय गुहिका हर्निया	1.7	1.3	1.2	0.8
38.	प्रवाहिका और आन्त्रशोथ	169.5	163.6	216.7	200.8

1	2	3	4	5	6
39.	पित्ताशय और पित्तवाहिनी के रोग	1.7	1.3	3.5	1.3
40.	पाचन तंत्र के अन्य रोग	138.9	133.3	158.2	139.3
41.	वृक्कशोथ और अपवृक्कता	2.1	1.5	2.0	2.0
42.	जननांगों के रोग	15.5	17.1	34.3	31.6
43.	प्रसव, गर्भ धारण की जटिलताएं, शिशु जन्म और प्रसवोत्तरकाल	27.4*	24.0*	11.2	10.4
44.	फुन्सी, फोड़े, संयोजक अतिशोथ और अन्य त्वचा संक्रमण	182.1	169.7	215.2	187.2
45.	त्वचा के अन्य रोग	100.3	95.2	124.1	110.8
46.	श्वसनीशोथ और आमवात	128.3	124.9	112.2	108.7
47.	हड्डियों और संचालन के अन्य अंगों के रोग	9.5	9.9	8.0	7.7
48.	जन्म-जात संरचना और शिशु काल में होने वाली बीमारियां	0.7	0.6	0.8	0.3
49.	अन्य विशिष्ट और अपरिभाषित रोग	258.9	246.1	314.3	290.9
50.	दुर्घटनाएं, विष देना और हिंसा	188.4	181.0	178.3	161.6
51.	अन्य विविध ग्रुप	1.9	2.0	2.2	2.1
	नए मामलों की कुल संख्या	2,970.4	2,867.4	3,475.8	3,245.3

*प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी

परिशिष्ट 15

1979-80 के दौरान चिकित्सा हितलाभ पर किया गया अनुमानित व्यय

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जोखिम ग्रस्त माने गये कर्मचारियों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया चिकित्सा हितलाभ पर कुल अनुमानित व्यय	प्रति व्यक्ति लागत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,37,500	3,34,47,901.37	140.83
2.	असम	30,500	23,50,000.00*	77.04
3.	बिहार	1,32,500	1,25,32,848.35	94.58
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	14,150	17,44,731.95	123 30
5.	दिल्ली	2,55,000	3,26,34,581.69	127.97
6.	गोवा	19,250	12,82,185.51	66.60
7.	गुजरात	5,42,500	7,23,88,000.00	133.43
8.	हरियाणा	1,85,000	1,71,11,533.46	92.49
9.	हिमाचल प्रदेश	1,050	अनुपलब्ध	----
10.	कर्नाटक	2,93,000	3,96,34,626.37	135.27
11.	केरल	3,07,000	3,86,05,048.40	125.74
12.	मध्य प्रदेश	1,65,000	1,74,06,145.00	105.49
13.	महाराष्ट्र	14,58,500	19,66,91,554.00	134.85
14.	उड़ीसा	1,00,500	98,19,000.00	97.70
15.	पांडिचेरी	15,000	24,39,000.00	162.60
16.	पंजाब	1,60,500	2,05,25,950.75	127.88
17.	राजस्थान	1,19,500	1,66,97,000.00*	139.72
18.	तमिलनाडु	4,47,500	6,89,64,600.00*	154.11
19.	उत्तर प्रदेश	4,40,000	3,90,60,965.85	88.77
20.	पश्चिमी बंगाल	9,75,000	12,33,45,500.00	126.50
	जोड़	58,99,450	74,66,81,172.70	126.56

*अनुमानित

परिशिष्ट

1978-79 तथा 1979-80 में बीमारी तथा प्रसूति

राज्य	अवधि	बीमारी/विस्तारित बीमारी हितलाभ के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाभ अवाप्तियों की कुल संख्या	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाभ अवाप्तियों की औसत संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1978-79	231,350	4,10,354	1 8
	1979-80	2,35,150	3,66,622	1 6
असम	1978-79	26,100	42,864	1 6
	1979-80	28,250	42,991	1 5
बिहार	1978-79	1,19,300	1,72,197	1 4
	1979-80	1,24,050	1,92,680	1.6
चंडीगढ़	1978-79	10,150	4,209	0.4
	1979-80	12,900	5,144	0.4
दिल्ली	1978-79	2,22,800	1,43,911	0.6
	1979-80	2,40,000	1,36,284	0.6
गुजरात	1978-79	5,01,900	6,55,335	1.3
	1979-80	5,24,200	6,61,132	1.3
हरियाणा	1978-79	1,68,800	78,993	0.5
	1979-80	1,74,300	76,742	0.4
हिमाचल प्रदेश	1978-79	700	462	0.7
	1979-80	850	442	0 5
कर्नाटक	1978-79	2,73,900	5,47,290	2.0
	1979-80	2,83,900	6,28,715	2 2
केरल और लक्षद्वीप	1978-79	2,91,700	5,43,651	1 9
	1979-80	3,06,750	5,95,963	1.9
मध्य प्रदेश	1978-79	1,65,800	3,42,774	2 1
	1979-80	1,69,700	3,68,929	2. 2
महाराष्ट्र	1978-79	13,20,400	19,39,621	1.5
	1979-80	14,27,200	19 35,939	1.4
उड़ीसा	1978-79	81,850	74,993	0.9
	1979-80	90,300	83,282	0 9
पांडिचेरी	1978-79	15,000	22,303	1.5
	1979-80	15,000	24,731	1.6
पंजाब	1978-79	1 54,400	66 163	0 4
	1979-80	1 54,600	66,425	0 4
राजस्थान	1978-79	1 10,150	1,27,069	1.2
	1979-80	1,13,900	1 43,445	1 3
तमिलनाडु	1978-79	4,42,950	10,99,634	2 5
	1979-80	4 43 750	15 46,239	3 5
उत्तर प्रदेश	1978-79	4,37,200	4,06,510	0 9
	1979-80	4 33 900	4 24 654	1 0
पश्चिमी बंगाल	1978-79	9,65,000	12,68,801	1 3
	1979-80	9,65,600	12,46,908	1 3
योग	1978-79	55,39,450	79,47,134	1 4
	1979-80	57,44,300	85,47,287	1 5

12

16

हितलाभ दावों की घटनायें—राज्यवार

	बीमारी हितलाभ		विस्तारित बिमारी हितलाभ		प्रसूति हितलाभ	
प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी नई प्रविष्टियों की दर	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक दरें	प्रति वर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामला औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी माने गए प्रसव की दर	प्रति प्रसव औसत राशि (रुपये)
6	7	8	9	10	11	12
1.13	7.7	7.19	4.0	235.1	90.4	774
0.97	8.0	7.59	1.9	243.3	44.3	1,116
1.00	7.0	6.16	2.4	250.8	76.4	688
1.02	7.9	6.60	2.2	245.5	74.2	764
0.83	10.3	7.79	3.7	313.0	14.6	760
1.18	11.9	8.16	3.9	323.1	12.2	839
0.25	2.8	9.36	0.6	—	58.8	1,347
0.29	2.3	9.30	1.1	—	126.2	982
0.27	3.5	8.70	3.0	229.2	33.6	998
0.27	3.4	9.25	3.1	266.0	35.6	1,076
0.60	5.5	9.15	6.0	222.8	54.1	583
0.58	5.7	9.68	5.5	260.9	49.6	769
0.23	2.7	7.44	1.2	198.6	11.8	1,420
0.23	2.4	8.08	2.3	183.1	18.3	1,121
0.36	2.9	10.50	1.4	—	—	—
0.27	2.4	10.00	1.2	100.0	—	—
1.39	7.9	9.17	2.3	215.1	67.5	1,284
1.62	9.4	9.77	2.3	354.5	101.5	866
1.17	6.6	6.76	2.8	245.6	55.3	702
1.26	8.6	7.20	2.6	250.1	62.0	638
0.80	12.2	8.42	3.4	260.1	31.0	728
1.64	14.4	8.76	4.8	270.7	23.0	756
0.95	6.8	9.06	5.2	189.3	41.3	1,369
0.90	6.6	10.40	4.9	182.3	44.3	1,479
0.53	4.7	7.75	1.9	291.3	27.6	752
0.59	5.1	8.00	1.6	273.3	22.0	686
0.68	5.5	9.67	2.4	216.7	46.7	789
1.43	6.9	9.57	3.9	189.5	20.0	[illegible]
0.24	2.1	6.36	1.4	198.9	21.5	611
0.22	2.3	6.97	2.0	202.2	20.5	435
0.66	4.9	8.41	7.0	197.3	24.7	755
0.77	5.8	9.48	4.9	291.1	33.1	614
2.04	9.5	10.01	3.1	197.4	46.6	722
2.83	18.3	10.64	2.0	262.8	64.7	490
0.60	7.5	7.90	2.4	290.3	24.6	926
0.57	8.6	9.37	2.5	227.3	39.0	752
0.80	6.7	8.88	6.6	246.9	29.6	884
0.94	6.9	9.44	5.8	228.0	22.8	[illegible]
0.90	6.8	8.92	4.4	220.9	45.9	907
1.00	7.8	9.54	4.0	225.6	49.4	860

परिशिष्ट

1978-79 तथा 1979-80 में स्वीकृत अपंगता

राज्य	अवधि	जोखिम ग्रस्त माने गये कर्मचारियों की संख्या	अस्थाई अपंगता हितलाभ		
			प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी नए मामलों की दर	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी अस्थायी अपंगता हितलाभ दिनों की संख्या	अस्थायी अपंगता हितलाभ की औसत दैनिक दर (रुपये)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1978-79	2,35,000	0.06	0.75	7.57
	1979-80	2,37,500	0.05	0.75	8.28
असम	1978-79	27,500	0.05	0.92	6.75
	1979-80	30,500	0.04	0.78	6.73
बिहार	1978-79	1,22,500	0.03	0.65	8.20
	1979-80	1,32,500	0.03	0.60	7.68
चण्डीगढ़	1978-79	12,000	0.02	0.77	6.64
	1979-80	14,150	0.05	0.71	7.77
दिल्ली	1978-79	2,35,000	0.06	0.92	11.09
	1979-80	2,55,000	0.04	0.84	11.46
गुजरात	1978-79	5,15,000	0.14	1.91	10.89
	1979-80	5,42,500	0.13	1.76	11.56
हरियाणा	1978-79	1,72,000	0.04	0.79	7.88
	1979-80	1,85,000	0.04	0.71	8.59
हिमाचल प्रदेश	1978-79	800	0.11	1.00	12.55
	1979-80	1,050	0.12	1.08	9.67
कर्नाटक	1978-79	2,81,500	0.08	0.86	8.71
	1979-80	2,98,000	0.09	0.96	9.04
केरल और माही	1978-79	3,06,500	0.07	0.89	9.23
	1979-80	3,07,500	0.07	1.03	10.27
मध्य प्रदेश	1978-79	1,70,000	0.17	3.34	10.87
	1979-80	1,65,000	0.19	3.33	10.87
महाराष्ट्र	1978-79	13,93,000	0.06	0.77	11.39
	1979-80	14,77,750	0.06	0.79	11.63
उड़ीसा	1978-79	88,000	0.03	0.53	6.90
	1979-80	1,00,500	0.03	0.55	7.23
पांडिचेरी	1978-79	15,000	0.12	0.98	11.69
	1979-80	15,000	0.10	0.99	11.63

17

और आश्रितजन हितलाभ वाले—राज्यवार

स्थायी अपंगता हितलाभ				आश्रित जन हितलाभ	
स्वीकृत नये मामलों की संख्या	प्रति वर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एक मुश्त के लिए रूपान्तरित मामलों की संख्या	वर्ष के अन्त में लाभाधिकारियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अन्त में लाभाधिकारियों की संख्या
7	8	9	10	11	
636	2.77	469	776	8	686
14S					
572	2.44	476	771	--	686
7S					
52	1.89	73	126	2	101
95	3.11	82	159	2	105
104	0.85	63	451	13.	344
145	1.09	113	490	9	375
63	5.25	25	28	5	30
41	2.90	35	28	2	36
1,841	7.94	1,605	1,022	21	598
24S					
2,382	9.47	1,540	1,186	30	666
33S					
2,410	4.86	2,657	1,962	39	1,539
95S					
2,129	4.53	1,592	2,337	53	1,658
326S					
828	4.79*	570	871	42	570
722	3.88	606	932	34	619
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
395	1.40	443	710	52	823*
559	1.91	429	811	49	947
832	2.71	679	794	25	690
949	3.09	678	984	31	771
376	2.21	189	680	16	584
327	1.98	170	745	18	622
4,169	3.13	2,563	12,075	53	3,895
197S					
3,584	2.59	2,326	12,252	120	4,259
248S					
105	1.19	78	215	2	181
156	1.55	86	278	12	208
6	0.40	7	22	2	17
7	0.47	5	28	1	18

1	2	3	4	5	6
पंजाब	1978-79	1,53,000	0.03	0 68	6 71
	1979-80	1,60,500	0 03	0 66	7 19
राजस्थान	1978-79	1,12,500	0 08	1 00	9 30
	1979-80	1,19,500	0.09	1 00	10.21
तमिलनाडु	1978-79	4,32,500	0 09	0 78	10 20
	1979-80	4,47,500	0.08	0 69	10.78
उत्तर प्रदेश	1978-79	4,32,500	0.05	1.23	9 21
	1979-80	4,40,000	4 04	1.21	11.12
पश्चिमी बंगाल	1978-79	9,65,000	0 10	1 51	9 97
	1979-80	9,75,000	0 10	1 46	10 66
जोड	1978-79	58,79,300	0 08	1 13	10 10
	1979-80*	58,99,450	0.07	1 10	10 72

*परिशोधित आंकड़े

7	8	9	10	11	12
516	3 37	433	699	41	585
723	4 50	454	950	35	642
259	2 30	235	360	15	490
235	1 97	209	385	18	541
796	1 83	582	1,271	27	951
14S					
645	1 54	652	1,283	17	982
5S					
468	1,08	242	1,754*	21	1,334
1S					
454	1,03	318	1,852	34	1,432
2,329	2 41	838	16,280	54	2,379
1,278	1 31	706	16,329	60	2,556
16,187	2 91	11,751	40,096*	438	15,797
345S					
15 003	2 65	10,477	41 736	526	17,102
619S					

परिशिष्ट 18

1978-79 तथा 1979-80 में स्वीकृत स्थायी अपंगता हितलाभ दावों का घटना उद्योगवार ||

उद्योग	अवधि	जोखिम ग्रस्त कर्मचारियो की अनुमानित सख्या	दुर्घटनाओ के स्वीकृति मामलो की सख्या	प्रति वर्ष प्रति 1000 कर्मचारी स्थायी अपंगता हितलाभ मामलो की दर
1	2	3	4	5
खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	1978-79	3 90,650	305	0. 78
	1979-80	4,33,800	187	0, 43
वस्त्र	1978-79	19,10,950	10,746	5. 62
	1979-80	19,96,750	11,947	5. 98
चमडा तथा रबड़	1978-79	1,52,000	212	1 39
	1979-80	1,55,500	167	1,07
रसायन तथा रसायनिक	1978-79	3,60,900	436	1. 21
उत्पाद	1979-80	3,67,250	334	0 9
अधात्विक खनिज	1978-79	2,50,350	467	1. 87
	1979-80	2,58,500	327	1. 26
धात्विक खनिज	1978-79	4,60,400	1,209	2. 63
	1979-80	4,88,950	714	1 46
इंजीनियरी	1978-79	9,05,300	1,652	1. 82
	1979-80	9,22,050	970	1 05
परिवहन	1978-79	3,94,050	569	1. 44
	1979-80	4,02,500	351	0 87
कागज तथा मुद्रण	1978-79	2,42,550	342	1. 41
	1979-80	2,59,100	238	0. 92
विविध	1978-79	3,92,450	594	1. 51
	1979-80	3,83,850	387	1. 01
वाणिज्यिक संस्थापनाए	1978-79	1,16,150	—	—
	1979-80	1,24,200	—	—
होटल तथा रेस्तरां	1978-79	73,950	—	—
	1979-80	79,400	—	—
सिनेमा तथा थियेटर	1978-79	29,600	—	—
	1979-80	27,600	—	—
जोड़	1978-79	56,79,300	16,532	2. 91
	1979-80	58,99,450	15,622	2. 65

परिशिष्ट

1979–80 वर्ष के दौरान दायर किए गए

क्रम सं०	क्षेत्र/उप क्षेत्र	निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत दायर किए गए मामले							
		धारा 66		धारा 67		धारा 73ब		धारा 73(2) 45 (ख)	
		मामले	राशि रुपए	मामले	राशि रुपए	मामले	राशि रुपए	मामले	राशि रुपए
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	7	10,192	999	45,48,010
2.	असम	—	—	—	—	—	—	26	2,64,278
3.	बिहार	—	—	—	—	2	428	230	35,40,458
4.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	50,75,363
5.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	220	11,54,995
6.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	39,10,140
7.	केरल और माही	—	—	—	—	3	63,889	974	34,61,527
8.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	76	3,02,078
9.	महाराष्ट्र (गोआ सहित)	—	—	—	—	16	28,222	308	43,54,644
10.	नागपुर	—	—	—	—	—	—	49	6,07,168
11.	पूना	—	—	—	—	11	14,609	—	—
12.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	11	53,792
13.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	699	82,85,631
14.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	225	13,20,749
15.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	9,13,054	332	33,89,484
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	91	20,79,687
17.	पश्चिमी बंगाल	—	—	—	—	84	3,29,805	320	3,05,197
	जोड़	—	—	—	—	233	13,63,541	5,294	5,16,43,201

19

कानूनी मामलों की संख्या

निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई द्वारा वसूल की गई राशि				
धारा 66	धारा 67	धारा 73-घ	धारा 75(2) 45(ख)	धारा 85 के अंतर्गत दायर किए गए अभियोजन के मामलों की संख्या
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	
—	—	633	2,95,136	48
—	—	—	13,288	—
—	—	—	1,88,651	35
—	—	—	5,39,468	138
—	—	737	10,38,190	83
—	—	—	8,24,275	17
—	—	10,015	14,66,948	4
8,358	—	26,980	3,76,601	26
10,823	—	24,842	3,38,552	99
—	—	3,342	47,744	22
—	—	4,494	—	81
—	—	—	6,75,320	4
—	—	43,536	17,66,135	66
—	—	—	11,67,922	67
—	—	1,57,820	6,42,749	30
—	—	—	8,48,546	12
—	—	9,00,755	2,47,047	119
19,181	—	11,73,154	1,04,76,570	851

परिशिष्ट 20

तालिका

कर्मचारी राज्य बीमा बकायों की क्षेत्रवार स्थिति

क्रम सं०	क्षेत्र	मार्च, 1978 की समाप्ति तक बकाया (लाख रुपयों में)	मार्च, 1979	मार्च, 1980
1.	आन्ध्र प्रदेश	82.32	86.03	137 73
2.	असम	5.42	12.13	12.86
3.	बिहार	89.08	125.49	144.23
4.	दिल्ली	120.91	151.21	184.78
5.	गुजरात	67.45	64.64	54.83
6.	कर्नाटक	112.43	137.36	86.39
7.	केरल	104.04	150.89	129.82
8.	मध्य प्रदेश	141.51	170.34	182.92
9.	बम्बई	256.56	304.08	317 66
10.	नागपुर	36.69	41.71	31 27
11.	पूना	85.98	61.23	71.61
12.	उड़ीसा	24.40	31.97	74 06
13.	पंजाब	61.89	100.04	147 05
14.	हरियाणा	48.42	68.22	119.30
15.	राजस्थान	37.39	42.93	45 42
16.	तमिलनाडु	112.76	135.93	184.98
17.	उत्तर प्रदेश	216.94	241.58	286.74
18.	पश्चिमी बंगाल	490.59	535.66	593.13
	जोड़	2,094.78	2,461.44	2,809.78

परिशिष्ट 21

31-3-1980 की स्थिति के अनुसार 1 लाख रुपए व इससे अधिक कर्मचारी राज्य बीमा बकायों वाले चूककर्ता कारखानों/स्थापनाओं के ब्यौरों का सूचक विवरण

क्रम सं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)
	(1) आन्ध्र प्रदेश	
1.	मैसर्स अनाम इलैक्ट्रिकल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, क्वाडियम	1.37
2.	मैसर्स राष्ट्रीय बीज निगम, विजयवाड़ा	2.84
3.	मैसर्स हिन्दुस्तान शिप यार्डस, विशाखापट्टनम	2.04
4.	मैसर्स तिरुपति काटन मिल्स, रेनीगुंटा	2.75
5.	मैसर्स श्री वेंकटाचलपति मिल्स, तिरुपति	2.19
6.	मैसर्स अब्दुल रहीम (करीम बीड़ी फैक्टरी) मरसमपेट रोड, वारंगल	1 47
7.	मैसर्स आन्ध्र काटन मिल, प्रोद्दटूर	1 72
8.	पशु-चिकित्सा जैविक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	2.94
9.	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश खादी उद्योग बोर्ड, काचीगुडे, हैदराबाद	1.59
10.	मैसर्स कुमा बीड़ी फैक्टरी, वारंगल	4 38
11.	मैसर्स वैन्डेज एण्ड गोगा क्लाथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हैदराबाद।	1 17
12.	मैसर्स अडोनी काटन मिल, अडोनी	1.49
13.	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, राजामुन्दरी	1 57
14.	मैसर्स एलविन मैटल्स लि०, हैदराबाद	1.12
15.	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, हैदराबाद	2.03
16.	मैसर्स आजमजाही मिल्स, वारंगल	5.36
17.	मैसर्स आन्ध्र पाठ्य पुस्तक प्रैस, हैदराबाद	15.55
18.	करीमनगर सहकारी कताई मिल, करीमनगर	1.81
19	मैसर्स अंधेरगांव टैक्सटाइल्स को-आपरेटिव प्रोडक्शन, एण्ड सेल्स सोसाइटी, करीम नगर	1.71
20.	मैसर्स आन्ध्र साइन्टिफिक कं०, मछलीपटनम	4.98
21.	मैसर्स ड्रेनेज स्टार्स वर्कशाप, हैदराबाद	1.60
	(2) असम	
1.	मैसर्स असम सरकारी प्रेस, गोहाटी	1.95
	(3) बिहार	
1.	मैसर्स टैल्को, जमशेदपुर	8.13
2.	मैसर्स टिस्को, जमशेदपुर	2.38
3.	मैसर्स प्रदीप लैम्प वर्क्स, पटना सिटी, पटना	3.28
4.	मैसर्स न्यूज पेपर प्रकाशन प्रा० लि० पटना	1.18
5.	मैसर्स इण्डिया मशीनरी स्टोर्स, ककरबाग, पटना	1 14
6.	मैसर्स आर० बी० एच० एम० जूट मिल, कटिहार	22.24
7.	मैसर्स कटिहार जूट मिल, कटिहार	18.21
8.	मैसर्स रिलाऐन्स फायर ब्रिक्स, चास, धनबाद	11.28
9.	मैसर्स बराई कोक एण्ड बाई प्रोडक्टस वर्क्स, डाकखाना कुसंडा, धनबाद	7.16
10	मैसर्स के० ई० डब्ल्यू (प्रा०) लि०, डाकखाना कुमारधूबी, धनबाद	10 36

क्रमसं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)
11.	मैसर्स मुंघेर गन मैन्युफैक्चरिंग सहकारी समिति, जिला मुंघेर	1.55
12.	मैसर्स इलैक्ट्रिक सप्लाई सब डिवीजन, देहुरियनसन, रोहताम	1.72
13	मैसर्स ईगल रोलिंग मिल लि०, कुमारडूबी	1.48
	दिल्ली	
1	मैसर्स ए०टी० मिल	1.38
2	मैसर्स दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	149.45
3.	मैसर्स कैक्सटन प्रेस (प्रा०) लि०	1.21
4.	मैसर्स टैक्स क्राफ्ट एक्सपोर्ट्स	1.42
5.	मैसर्स फैशन एक्सपोर्ट आफ इंडिया	1.19
6.	मैसर्स इंडिया काफी वर्क्स सहकारी समिति लि०	1.55
	(5) गुजरात	
1	मैसर्स राजनगर टैक्सटाइल	6.58
2.	मैसर्स न्यू मानिक चौक मिल	1.21
3.	मैसर्स अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल	4.48
4	मैसर्स केशव मिल	1.13
5.	मैसर्स पी०जी० टैक्सटाइल	4.66
6.	मैसर्स मानिक चौक अहमदाबाद प्रा० मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	8.79
7.	मैसर्स अनन्त मिल	1.54
8.	मैसर्स बाकी फोर्ट वर्क्स	1.18
9.	मैसर्स प्रियलक्ष्मी मिल	5.15
10.	मैसर्स नवजीवन मिल	2.08
	(6) कर्नाटक	
1.	मैसर्स मैसूर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग लि०	2.52
2.	मैसर्स मैट्रो मैलिवेबल्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, बंगलौर	1.43
3.	मैसर्स नेशनल एरोनाटिक्स लि०, बंगलौर	6.16
4.	मैसर्स कर्नाटक एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०, बंगलौर	1.21
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, बंगलोर	5.12
6.	मैसर्स वानीविलास वाटर वर्क्स, मैसूर	3.31
7.	मैसर्स के०आर० मिल, मैसूर	1.57
8.	मैसर्स सरकारी पाठ्य पुस्तक प्रेस, मैसूर	1.46
9.	मैसर्स बल्लारी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, बल्लारी	4.26
10.	मैसर्स कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन	1.06
11.	मैसर्स शंकर टैक्सटाइल बाबंगेर	1.09
12.	मैसर्स महादेव टैक्सटाइल्स, हुबली	8.07
13.	मैसर्स ब्रोडे डिस्टेलरी डिवीजन, बंगलौर	1.12
	(7) केरल	
1.	मैसर्स स्टेण्डर्ड एण्ड कने वर्क्स फैरोक	5.25
2.	मैसर्स स्टार टाइल वर्क्स, कालीकट	1.84
3	मैसर्स मालाबार स्पिनिंग वीविंग मिल्स, कालीकट	3.55
4.	मैसर्स माडर्न वुड क्राफ्टसे, टेलीचेरी	1.14
5.	मैसर्स केरल सिरेमैक्स, फ़ैरोक	1.61
6	मैसर्स मालरा मोटर परिवहन सहकारी समिति, कालीकट	1.28
7.	मैसर्स केरल सिरेमिक्स, फेरोक	1.37
8.	मैसर्स पार्वती मिल, क्विलोन	2.63
9.	मैसर्स अलगप्पा टैक्सटाइल्स गवर्नमैंट (प्रा०) लि०, त्रिचूर	5.79

क्रमसं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)
10.	मैसर्स जनयुगम पब्लिकेशन्स प्रा० लि०, क्विलोन	1.85
11.	मैसर्स थामसन कैश्यू फैक्टरी, मुधाथला, क्विलोन	1.64
12.	मैसर्स यूनुस कुंज कैश्यू फैक्ट्री, क्विलोन	1.50
13.	मैसर्स पालघाट को-आपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन लि०, पालघाट	1.32
14.	मैसर्स अजीकोड बीड़ी प्रा० वर्क्स इन्डस्ट्रीज, कन्ननोर	2.01
15.	मैसर्स पय्यानूर बीड़ी वर्क्स इन्डस्ट्रियल सहकारी समिति, कन्ननोर।	2.08
16.	मैसर्स गनमुगाविलास कैश्यू इन्डस्ट्रीज, क्विलोन	1.72
17.	मैसर्स इंडिया सी फूड्स, कोचीन	1.13
18.	मैसर्स गनमुगाविलास कैश्यू इन्डस्ट्रीज, क्विलोन	1.10
19.	मैसर्स गनमुगाविलास कैश्यू इन्डस्ट्रीज, कोट्टारकारा	1.42
20	मैसर्स जनरल इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, क्विलोन।	1.90
	(8) मध्य प्रदेश	
1.	मैसर्स बुरहानपुर ताप्ती मिल, बुरहानपुर	2.41
2.	मैसर्स न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल, भोपाल	6.32
3.	मैसर्स जे० सी० मिल, ग्वालियर	1.50
4.	मैसर्स हीरा मिल, उज्जैन	7.32
5.	मैसर्स मालवा यूनाइटेड मिल, इन्दौर	40.27
6.	मैसर्स कल्याण मल मिल, इन्दौर	11.10
7	मैसर्स स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल, इन्दौर	13.31
8.	मैसर्स होप टैक्सटाइल मिल, इन्दौर	33.09
9.	मैसर्स माउथ जवारोड यूनियन, ग्वालियर	2.09
10.	मैसर्स सेण्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं०, ग्वालियर	1.49
11.	मैसर्स जे० बी० मंधाराम एण्ड कं०, ग्वालियर	3.03
12.	मैसर्स बी० एन० सी० मिल, राजनंदगांव	6.65
13.	मैसर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वर्कशाप, ग्वालियर	1.13
14.	मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, रायपुर	1.26
15.	मैसर्स विनोद स्टील इंडस्ट्रीज, इन्दौर	1.36
16.	मैसर्स हितवाद प्रेस, भोपाल	1.04
	(9) महाराष्ट्र (बम्बई व गोवा)	
1.	मैसर्स आलकाक एशडाउन कं० लि०	4.07
2	मैसर्स न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल	1.01
3.	मैसर्स अपोलो टैक्सटाइल मिल	2.28
4.	मैसर्स ब्रैडबरी मिल लि०	41.15
5.	मैसर्स श्री शक्ति मिल लि०	3.14
6	मैसर्स सीता राम लि०	8.10
7.	मैसर्स दिग्विजय एंड स्पिनिंग वीविंग क० लि०	8.76
8	मैसर्स इंडिया यूनाइटेड मिल	7.28
9.	मैसर्स इंडिया यूनाइटेड मिल	6.53
10.	मैसर्स इंडिया यूनाइटेड मिल	7.33
11.	मैसर्स इंडिया यूनाइटेड मिल	13.36
12.	मैसर्स लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स	1.92
13.	मैसर्स एडवर्ड टैक्सटाइल मिल	5.77
14.	मैसर्स धनराज मिल	2.04
15	मैसर्स बम्बई टैक्सटाइल मिल	1.39
16	मैसर्स फिनिक्स मिल लि०	18.52
17.	मैसर्स न्यू इंडिया रेयन मिल	7.79
18.	मैसर्स मैकनवर्माज लि०	2.93
19	मैसर्स वैस्टर्न इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कं०	11.08
20.	मैसर्स प्रीमियर रबड़ एंड केमिकल	1.31

क्र० सं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)
21.	मैसर्स बम्बई फाइन आर्ट	1 34
22.	मैसर्स इंडिया यूनाइटेड मिल	4.60
23.	मैसर्स इंडिया यूनाइटेड मिल	4.41
24.	मैसर्स यूफार्मा लेबोरेट्रीज	1.05
25.	मैसर्स बम्बई अलायज एंड कास्टिंग	1.45
26.	मैसर्स एलिन केयरब्रिन्स (प्रा०) लि०	1.84
27.	मैसर्स कृष्ण ग्लास	2.80
28.	मैसर्स एल्डी वायर एंड रोप्स	1.56
29.	मैसर्स इंडिया गोडी मिल	1.17
30.	मैसर्स राधा डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल	1.47
31.	मैसर्स कृष्णा वीविंग मिल	2.66
32.	मैसर्स सन एण्ड सैंड होटल	2.70
33.	मैसर्स गवर्नमेंट गारगेज	1.31
34	मैसर्स पायनियर रबड़ मिल	2.13
35.	मैसर्स सेन्चुरी रेयन	1.30
36	मैसर्स के० टी० स्टील	1.11
37.	मैसर्स श्री कृष्ण वूलन मिल प्रा० लि०	1.48
38.	मैसर्स देवनगर अल्बाटोयर	4.54
39.	मैसर्स एलोरा सिल्क मिल	3.10
40.	मैसर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग	1.50
	नागपुर (उप क्षेत्रीय कार्यालय	
1.	मैसर्स आर० एम० आर० जी० मोहता मिल अकोला	1.55
2.	मैसर्स आसमानशाही मिल, नान्देड़	8.56
3.	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, अकोला	1.29
4.	मैसर्स मेकेनिकल डिवीजन, नान्देड़	1.72
	पूना (उप क्षेत्रीय कार्यालय)	
1.	मैसर्स एग्रीकलचरल इंजीनियरिंग वर्कशाप पूना	2.18
2.	मैसर्स बीमवायरलैस स्टेशन, पूना	1.35
3.	मैसर्स इंडियन मैट्रोलाजिकल वर्कशाप, पूना	2.31
4.	मैसर्स शोलापुर स्पिनिंग वीविंग मिल, शोलापुर	3.01
5.	मैसर्स शोलापुर म्युनिसिपल वर्कशाप, शोलापुर	1.90
6.	मैसर्स जयशंकर मिल, बारशी शोलापुर	1.33
7.	मैसर्स सांगली, म्युनिसिपल वर्क्स, सांगली	1.05
8	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, सतारा	2.42
9.	मैसर्स न्यू प्रताप स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, धूले	4.13
	(10) उड़ीसा	
1.	मैसर्स सारस्वत प्रैस, कटक	1.00
2.	मैसर्स सत्यवादी प्रैस, कटक	3.16
3.	मैसर्स दुर्गा ग्लास वर्कस, बारंग	1.65
4.	मैसर्स बरहामपुर विद्युत प्रदाय निगम लि० बरहामपुर	1.07
5.	मैसर्स प्रजातंत्र प्रचार समिति, कटक	1.77
6.	मैसर्स उड़ीसा टैक्सटाइल मिल, चौद्वार	21.47
7.	मैसर्स उड़ीसा सीमेन्ट लि० राजगंगपुर	2.35
8.	मैसर्स कलिंग ट्यूब्स लि० चौद्वार	2.28
9.	मैसर्स हीराकुण्ड इंडस्ट्रियल वर्क्स सम्बलपुर	1.05
10.	मैसर्स लोक निर्माण विभाग वर्कशाप, भुवनेश्वर	2.22
11.	मैसर्स उड़ीसा राज्य सहकारी विपणन समिति, भुवनेश्वर	1 23
12.	मैसर्स उड़ीसा सड़क परिवहन क० बरहामपुर	1.33
13.	मैसर्स पाठ्यपुस्तक प्रैस, भुवनेश्वर	4.57
14	मैसर्स उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी, कटक	1 32
15	मैसर्स उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम, कटक	2 80
16.	मैसर्स उड़ीसा सड़क परिवहन क०, बरहामपुर	1.67

क्र० सं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)
	(11) पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	
1.	मैसर्स पंजाब रोडवेज वर्कशाप अमृतसर	1.30
2.	मैसर्स म्युनिसिपल पावर हाऊस, अमृतसर	20.83
3	मैसर्स हरियाणा सरकार मुद्रणालय, चण्डीगढ़	2.70
4.	मैसर्स पेप्सू रोडवेज परिवहन निगम, पटियाला	4.16
5.	मैसर्स ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लुधियाना	1.05
6.	मैसर्स चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम, चंडीगढ़	1.28
7.	मैसर्स न्यू सूरज ट्रांसपोर्ट क० (प्रा०) लि०, अमृतसर	2.70
	(12) हरियाणा	
1.	मैसर्स लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स, फरीदाबाद	1.48
2.	मैसर्स हरियाणा रोडवेज वर्कशाप, करनाल	1.18
3.	मैसर्स इलैक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कं, सोनीपत	3.10
4.	मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, दादरी	3.32
	(13) राजस्थान	
1.	मैसर्स मैन इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर	3.13
2.	मैसर्स जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर	2.37
3.	मैसर्स एस० जोरेस्टर एंड कं०, जयपुर	1.03
4.	मैसर्स धौलपुर ग्लास एंड वर्क्स धौलपुर	1.01
5.	मैसर्स जयपुर ग्लास पाटरीज वर्क्स	1.09
6.	मैसर्स महालक्ष्मी मिल, बियावर	2.53
7.	मैसर्स वाटर वर्क्स, बीकानेर	2.02
8.	मैसर्स वाटर वर्क्स, जोधपुर	1.95
9.	मैसर्स वाटर वर्क्स, कोटा	1.87
10.	मैसर्स वाटर वर्क्स, उदयपुर	2.28
11.	मैसर्स चम्बल प्रोजेक्ट (वर्कशाप), कोटा	1.08
12.	मैसर्स अकलगढ़ हैड वाटर वर्क्स, कोटा	2.87
13.	मैसर्स राजस्थान नहर बोर्ड, बीकानेर	1.05
14.	लोक निर्माण विभाग, जयपुर	1.62
	(14) तामिलनाडु	
1.	मैसर्स सीमा सुन्दरम मिल	5.83
2.	मैसर्स कालीश्वर मिल	6.03
3.	मैसर्स पंकेजा मिल	1 20
4.	मैसर्स प्रकाश मिल	1 16
5.	मैसर्स एनफील्ड इंडिया लि०	1.26
6.	मैसर्स पायलट पैन कम्पनी	2.05
7.	मैसर्स भारती मिल	4.36
8.	मैसर्स स्वदेशी मिल	10.18
9.	मैसर्स एंग्लोफ्रेंच टैक्सटाइल	16.42
10.	मैसर्स रामलिंग चोदम्बिका मिल	1.98
11.	मैसर्स भवानी मिल	1.56
12.	मैसर्स मीजराम इंजीनियरिंग	1.82
13.	मैसर्स इंडियन रेफ्रिजरेशन	2.17
14.	मैसर्स मद्रास मशीन टूल्स	3.31
15	मैसर्स कामधेनु ड्रिक्स	1.40
16.	मैसर्स महालक्ष्मी टैक्सटाइल	7.65
17.	मैसर्स पलानिअप्पा मैच इंडस्ट्रीज	1.02
18.	मैसर्स साउथ इंडिया ग्लास एंड इनेमल वर्क्स	2.44
19	मैसर्स दीनमणि प्रैस	1.68
20.	मैसर्स चेमफाब वैल्डर्स	2.07
21.	मैसर्स सुदर्शन फाइनैंस कारपोरेशन	2.91
22	मैसर्स सदर्न पैट्रो कैमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन	1 13
23	मैसर्स वारोमवल स्टोल्स	1 11

क्र० सं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)
1		
	(15) उत्तर प्रदेश	
1	मैसर्स मुइर मिल, कानपुर	21.18
2.	मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर	11.62
3.	मैसर्स स्वदेशी काटन मिल, कानपुर	25.78
4.	मैसर्स एलबर्टन वेस्ट एंड कं०, कानपुर	29.95
5.	मैसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर	16.67
6	मैसर्स कानपुर सहकारी दूध बोर्ड, कानपुर	17.79
7.	मैसर्स कानपुर जूट उद्योग, कानपुर	4.76
8.	मैसर्स आर० एम० स्टील वर्क्स	1.99
9.	मैसर्स अमौसी टैक्सटाइल	3.36
10	मैसर्स मुरादाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	8.62
11.	मैसर्स वाटर वर्क्स, लखनऊ	3.57
12.	मैसर्स टाइगर प्रोडक्ट्स, अलीगढ़	3.39
13.	मैसर्स इलाहाबाद वर्क्स, नैनी	1.82
14.	मैसर्स वाटर वर्क्स, इलाहाबाद	2 31
15.	मैसर्स वाटर वर्क्स, इलाहाबाद	3.36
16.	मैसर्स लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल, सहारनपुर	4.09
17.	मैसर्स अमिताभ टैक्सटाइल, सहारनपुर	3.32
18.	मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राइसिस, गाजियाबाद	1.50
19.	मैसर्स आर० आर० इंजीनियरिंग, बरेली	1.46
20.	मैसर्स पंजाब आयल मिल	1.36
21.	मैसर्स मेरठ एस्ट्रो बोर्ड	2.07
22.	मैसर्स शादीलाल डिस्टीलरी	1.05
23.	मैसर्स वाटर वर्कस डिपो	1 37
24.	मैसर्स एसोसियेटिड जरनल्स	6.41
25.	मैसर्स वाटर वर्क्स, लखनऊ	2.63
26.	मैसर्स बिजली काटन मिल	8.35
27	मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स	55.21
	(16) पश्चिमी बंगाल	
1.	मैसर्स नेशनल कं० लि०	21.27
2.	मैसर्स श्री अम्बिका जूट मिल लि०	8 66
3.	मैसर्स नसकारपारा जूट मिल कं० लि०	1.29
4.	मैसर्स प्रेमचन्द जूट मिल कं० 7 लि०	22.00
5.	मैसर्स भारत जूट मिल लि०	4.92
6	मैसर्स इंडिया रबड़ मैन्यूफैक्चरिंग लि०	1.33
7.	मैसर्स गोविन्द देव ग्लास वर्क्स लि०	1.11
8.	मैसर्स नैशनल आयरन एंड स्टील कं० लि०	2 12
9.	मैसर्स मार्केन देव प्रसाद राधाकृष्ण (प्रा०) लि०	1.00
10.	मैसर्स भारत आयरन एण्ड स्टील कं० (प्रा०) लि०	1.95
11.	मैसर्स नैशनल स्क्रू वायर (प्रा०) लि०	1.09
12.	मैसर्स हावड़ा वायर एंड स्टील वर्क्स (प्रा०) लि०	1.55
13.	मैसर्स इंडिया मशीनरी कं० लि०	2.56
14.	मैसर्स हुगली डोकिंग एंड इंजीनिरिंग कं लि०	1.61
15.	मैसर्स शालीमार वर्क्स	5.89
16.	मैसर्स सैण्ट्रल काटन मिल लि०	1.12
17.	मैसर्स वेल्लूर ग्लास वर्क्स (प्रा०) लि०	1.41
18.	मैसर्स अग्रवाल हार्डवेयर इंडस्ट्रीज	1.37
19.	मैसर्स फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि० (केबिल डिवीजन)	2.08
20.	मैसर्स बासूमति प्रा लि०	1.34
21.	मैसर्स लाइम्क्स मशीनरी	1.44
22.	मैसर्स बासुमति कारपोरेशन लि०	1.38
23.	मैसर्स लिली बिस्कुट कं० (प्रा०) लि०	1.56
24.	मैसर्स श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	4.79
25	मैसर्स बंगश्री काटन मिल	1.26
26.	मैसर्स मोहनी मिल लि० संख्या-2	5 34
27.	मैसर्स यूनियन जूट कं० लि० (नार्थ मिल)	3 83
28.	मैसर्स खरदाह जूट मिल	7 38
29	मैसर्स कैल्विन जूट मिल	11.45
30.	मैसर्स बज बज अमलगमेटिड मिल लि०	1.45
31.	मैसर्स मेघना मिल कं० लि०	1 31
32.	मैसर्स अलैक्जेंडर जूट मिल लि०	7.47
33.	मैसर्स विक्ट्री जूट मिल	1.36
34.	मैसर्स किनीसन जूट मिल संख्या 2	27.47
35.	मैसर्स ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग क० लि०	10.32
36.	मैसर्स केन्टन कारपेन्टरी वर्क्स प्रा० लि०	2.22
37.	मैसर्स अलक उद्योग वनस्पति एंड प्लाईवुड (1971)	5 07
38.	मैसर्स टीटागढ़ पेपर मिल कं० लि०	1.71
39.	मैसर्स इंडिया पेपर एंड पल्प कं०	3 26
40	मैसर्स यूनियन पेपर एंड बोर्ड मिल लि०	1 53
41.	मैसर्स इंटरनेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरिंग क०	1 50
42	मैसर्स बाटा (इंडिया) लि०	4 92
43.	मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरिंग लि०	5.76
44.	मैसर्स एसोसियेटिड रबड़ मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स	1.35
45.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०	1.30
46.	मैसर्स बर्न एंड कं० (प्रौसेज इंजीनियरिंग डिवीजन)	1.22
47.	मैसर्स कलकत्ता ग्लास एंड सिलीकेट वर्क्स (1936) (प्रा०) लि०	1.38
48.	मैसर्स कृष्णा सिलीकेट एंड ग्लास वर्क्स	2 56
49.	मैसर्स बंगाल पोटरीज लि०	16.40
50.	मैसर्स मोदपुर पोटरीज (प्रा०) लि०	1.25
51.	मैसर्स हिन्दुस्तान आयरन एंड स्टील कं०	1.61
52.	मैसर्स सूर एंड कम्पनी	1.82
53.	मैसर्स इंडिया मालीबल कास्टिंग लि०	3.80
54.	मैसर्स अल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कं० (इंडिया) लि०	1.00
55.	मैसर्स बंगाल इनेमल वर्क्स लि०	2.92
56.	मैसर्स अन्नपूर्णा मैटल वर्क्स	2.64
57.	मैसर्स एम० जी० टी० इंजीनियरिंग (प्रा०) लि०	1.55
58.	मैसर्स एसोसियेटिड एस्बे इन्डस्ट्रीज लि०	1.99
59.	मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कं० (इंडिया) लि०	2.49
60	मैसर्स माया इंजीनियरिंग वर्क्स (प्रा०) लि०	1.11
61.	मैसर्स बेरी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग (प्रा०) लि०	1.09
62	मैसर्स मोटर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं०	3.51
63	मैसर्स नेशनल कार्बन कं० (यू०सी०आई० लिमिटेड रा डिवीजन)	4.48
64.	मैसर्स ईस्ट बंगाल इंजीनियरिंग वर्क्स	4.00
65.	मैसर्स सी० टी० सी० लि० (मोनापुकुर वर्कशाप)	17.11
66.	मैसर्स गुप्ता पैंसिल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	1.00
67.	मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि०	2.84
68.	मैसर्स बंगाल स्टीम लान्डरी	1.56
69.	मैसर्स इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन	1.26
70.	मैसर्स कार्टर पूलर एंड कं० लि०	3.10
71.	मैसर्स पोद्दार सेनिटरी वर्क्स	1.38
72.	मैसर्स सी० टी० सी० लि० (बेलगछिया डिपो)	2.96
73.	मैसर्स सी० टी० सी० लि० (किदरपुर डिपो)	1.89
74	मैसर्स सी० टी० सी० लि० (पी/सर्कस डिपो)	1.64
75.	मैसर्स सी० टी० सी० लि० (राजाबाजार डिपो)	2.83
76	मैसर्स सी० टी० सी० लि० (टालीगंज डिपो)	1.58

क० सं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)	क० सं०	कारखाने/स्थापना का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा बकाया (लाख रुपयों में)
77.	मैसर्स सी० टी० सी० लि० (गड़ियाट डिपो)	1.79	89	मैसर्स कैल्विन जूट कं० लि० (प्रेडलूम अनुभाग)	2.70
78.	मैसर्स स्टेशमेन प्रा० लि०	2.11	90.	मैसर्स बंगाल लक्ष्मी काटन मिल	8.46
79.	मैसर्स परिवहन निदेशालय (बेलघोरिया डिपो)	1.04	91	मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लि०	2.45
80.	मैसर्स परिवहन निदेशालय (लेक डिपो)	1.14	92	मैसर्स रामपुरिया काटन मिल	5.93
81.	मैसर्स दी मैटल बाक्स कं० आफ इंडिया लि०	3.30	93	मैसर्स केमर बागशा मैन्युफैक्चरिंग कं० (प्रा०) लि०	1.38
82.	मैसर्स बंगाल पाटरीज लि०	10.39	94	मैसर्स लक्ष्मीनारायण काटन मिल	6.63
83.	मैसर्स मार्डर्न इंडिया कंसट्रक्शन कं० लि०	2.35	95.	मैसर्स बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लि०	3.38
84.	मैसर्स श्री कृष्ण रबड़ वर्क्स लि०	1.15	96.	मैसर्स श्री इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लि०	1.10
85.	मैसर्स ओरिएन्टल मशीनरी एंड सिविल कंसट्रक्शन लि०	1.16	97.	मैसर्स दुर्गापुर कैमिकल्स लि०	1.05
86.	मैसर्स काले आयरन एंड स्टील क०	4.59	98.	मैसर्स एटलस वर्क्स (प्रा०) लि०	1.04
87.	मैसर्स किरन गैस कं० (कलकत्ता) प्रा० लि०	1.45	99.	मैसर्स कृष्णा सिलीकेट एंड ग्लास वर्क्स लि०	1.20
88.	मैसर्स अंडमान टिम्बर (इंडिया) लि०	2.01	100.	मैसर्स कल्याणी स्पिनिंग मिल लि० (संख्या 2)	6.72

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1980 को समाप्त

व्यय

पिछला वर्ष (1978-79)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	1. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों का हितलाभ		
	क. चिकित्सा हितलाभ		
49,90,29,859	(i) चिकित्सा देखरेख तथा प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था पर होने वाले खर्च में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों को अदायगियां।	60,23,42,106(क)	
2,97,00,515	(ii) चिकित्सा देखरेख तथा प्रसूति सुविधाएं (निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया व्यय)	3,35,85,407	
52,87,30,374	जोड़-क-चिकित्सा हितलाभ		63,59,27,513
	ख. नकद हितलाभ		
33,50,40,594	1. बीमारी हितलाभ	42,96,75,462(ख)	
3,14,41,961	2. विस्तारित बीमारी हितलाभ	3,25,97,884	
6,08,336	3. परिवार नियोजन के लिए वर्धित बीमारी हितलाभ	6,51,570	
1,73,89,593	4. प्रसूति हितलाभ	1,94,90,537	
	5. अपंगता हितलाभ		
6,45,53,267	(क) अस्थायी	6,93,67,776	
6,38,60,000	(ख) स्थायी (पूंजीकृत मूल्य)	6,50,83,000	
	6. आश्रितजन हितलाभ	1,76,48,000	
1,44,68,000	(पूंजीकृत मूल्य)		
9,70,530	7. अन्त्येष्टि हितलाभ	10,08,398	
52,83,32,281	जोड़-ख-नकद हितलाभ		63,55,22,627
1,05,70,62,655	आगे ले जाया गया जोड़		1,27,14,50,140

(क) अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.1 देखिये।

(ख) अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.2 देखिये।

बीजा निगम
वर्ष का आय-व्यय लेखा

आय

पिछला वर्ष (1978-79)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड
रुपये		रुपये	रुपये
	अंशदान		
1 45 78,73,675	नियोजक तथा कर्मचारियो के शेयर	1,58,68,28,298(ग)	
17,57,264	केवल नियोजको का शेयर	15,72,055(घ)	
71,05,946	केवल कर्मचारियों का शेयर	77,46,520(ङ)	
8,57,102	अंशदानो पर ब्याज	14,57,288	
1,46,75,93 987	कुल अंशदान		1,59,76,04,161
	निगम द्वारा चिकित्सा हितलाभ पर प्रारम्भ मे किये गये व्यय मे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों का शेयर	28 21,875	
1 10,49,500			28,21,875
	अन्य राजस्व शीर्ष		
5 28,26,924	ब्याज तथा लाभांश	4 83,70,143(छ)	
12,33 772	क्षतिपूर्ति	48 42,590(च)	
	किराया महसूल तथा कर		
7,26,478	(1) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरो सहित)	7,92,757	
3,55,53,611	(2) अस्पताल, औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर	3 85,18,880	
30,07,792	शुल्क, जुर्माना तथा समपहरण	32,52,980(ज)	
15,56,277	विविध	17,00,879(झ)	
9,79,04,854	अन्य राजस्व शीर्षों का जोड		9,74,78,229
1,57,65,48,341	आगे ले जाया गया जोड		1,69,79,04,265

(ग) अनुबंध 1 मे व्याख्यात्मक टिप्पणियो का पैरा 1.3 देखिये।
(घ) अनुबंध 1 मे व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1 4 देखिये।
(ङ) अनुबंध 1 मे व्याख्यात्मक टिप्पणियो का पैरा 1 5 देखिये।
(च) अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक-टिप्पणियों का पैरा 1 6 देखिये।
(छ) अनुबंध 1 मे व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.7 देखिये।
(ज) अनुबंध 1 मे व्याख्यात्मक टिप्पणियो का पैरा 1.8 देखिये।

पिछला वर्ष (1978-79)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,05,70,62,655	पीछे से लाया गया जोड़		1,27,14,50,140
	ग.—अन्य हित लाभ		
28,424	(क) अपंग बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय	7,523	
3,74,438	(ख) चिकित्सा बोर्ड तथा अपील अधिकरण	4,48,754	
	(ग) बीमाकृत व्यक्तियों को अदायगियां		
3,42,560	1 सवारी खर्च तथा/या मजदूरी की हानि	3,57,660	
50	2. परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रासंगिक व्यय	—	
6,42,799	(घ) विविध	9,18,182 ण.	
13,88,271	जोड़-ग—अन्य हित लाभ		17,32,119
1,05,84,50,926	बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को कुल हित लाभ		1,27,31,82,259
	2 प्रशासन व्यय		
	क—अधीक्षण		
54,960	1. निगम, स्थायी समिति, क्षेत्रीय बोर्ड आदि	69,013	
2,04,345	2 प्रधान अधिकारी	1,98,232	
58,29,336	3. अन्य अधिकारी	61,73,200	
3,00,47,548	4. लिपिकवर्गीय स्थापना	3,36,26,149	
50,26,425	5 ग्रुप घ स्टाफ	54,26,092	
1,03,09,418	6 आकस्मिक व्यय	1,21,06,975	
5,14,72,032	जोड़-क—अधीक्षण		5 75,99,661
	ख—क्षेत्रीय कार्य		
14,64,847	1. अधिकारी	19,00,798	
2,97,84,952	2 लिपिकवर्गीय स्थापना	3,33,56,058	
45,52,562	3. ग्रुप घ स्टाफ	50 71,313	
39,10,651	4. आकस्मिक व्यय	39,49,877	
3,97,13,012	जोड़ ख-क्षेत्रीय कार्य		4,42,78,046
	ग—अन्य खर्चे		
5,13,116	(1) कानूनी खर्चे	4,85,068	
67,752	(2) बीमा न्यायालय	53,445	
1,05,851	(3) प्रचार तथा विज्ञापन खर्च	1,37,783	
8,45,465	(4) बैंक लेखे रखने के लिए खर्चे	99,226 ञ.	
2,55,430	(5) लेखा परीक्षा फीस	2,16,298	
1,38,869	(6) छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	1,07,964	
3,54,834	(7) कार्यालय भवन/स्टाफ कार का मूल्यह्रास	3,70,872	
9,66,332	(8) कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	9,93,727	
	(9) सेवा निवृत्ति हितलाभ		
12,44,042	(क) निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि	53,42,509 ट	
2,58,737	(ख) क०रा०बी० निगम भविष्य निधि में निगम का अंशदान	39,401 ट	
34,24,462	(ग) क०रा०बी० निगम भविष्य निधि में दिया गया ब्याज	37,01,309	
24,261	(घ) प्रोत्साहन बोनस	1,57,579	
35,000	(10) अनुकंपा आरक्षित निधि	35,000	
80,000	(11) भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि	90,000	
12	(12) हानियां	9,000	
4,227	(13) विविध	39,532 ठ	
83,18,390	जोड़-ग—अन्य खर्चे		1,18,78,713
9,95,03,434	जोड़ शीर्ष-2-प्रशासन व्यय		11,37,56,420
1,15,79,54,360	आगे ले जाया गया जोड़		1,38,69,38,679

ण. अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.9 देखिये।

ञ. अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.10 देखिये।

ट. अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1.11 देखिये।

ठ अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1 12 देखिये

पिछला वर्ष (1978-79)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,57,65,48,341	पीछे से लाया गया जोड़		1,69,79,04,265
1,57,65,48,341	आगे ले जाया गया जोड़		1,69,79,04,26

पिछला वर्ष (1978-79)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,15,79,54,360	पीछे से लाया गया जोड़		1,38,69,38,679
	3 अस्पताल और औषधालय		
36,44,523	(1) अस्पताल भवनों के मूल्यह्रास के लिए धन व्यवस्था जो निधि मे अन्तरित की गई।	47,88,913	
1,05,69,117	(2) अस्पताल/औषधालयो की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए धन व्यवस्था जो निधि में अंतरित की गई	1,38 87,848	
	जोड़ शीर्ष 3—अस्पताल तथा औषधालय		
1,42,13,640	4 पूंजीगत निर्माण/-आपात आरक्षित निधि		1,86,76,761
14,67,59,400	(1) पूंजीगत निर्माण	15,97,60,416 ङ	
5,15,24,188	(2) आपात आरक्षित निधि	2,65,03,682 ङ	
	जोड़ शीर्ष 4—पूंजीगत निर्माण/आपात		
19,82,83,588	आरक्षित निधि		18,62,64,098
1,37,04,51 588	राजस्व लेखे मे कुल व्यय		1,59,18,79,538
20,60,96,753	व्यय से अधिक आय को तुलन पत्र में ले जाना	10,60,24,727	10,60,24,727
1,57,65,48,341	कुल जोड़		1,69,79,04,265

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 1980

ङ अनुबंध 1 मे व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1 13 देखिये।

ङ अनुबंध 1 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 1 14 देखिये।

कर्मचारी राज्य

31 मार्च 1980 को स्थिति

पिछला वर्ष (1978-79)	देयताए	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	व्यय से अधिक आय का अतिशेष		
1,36,35,42,434	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,56,96,49,187	
20,60,96,753	वर्ष के दौरान संचयन	10,60,24,727	
1,56,96,49,187			1,67,56,73,914
	आरक्षित निधिया		
	1. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
58,65,21,536	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	74,89,66,131	
14,67,59,400	जोड़ें—वर्ष मे की गई धन व्यवस्था	15,97,60,416	
1,56,85,195	निवेशों से प्राप्त ब्याज	1,38,19,243	
74,89,66,131			92,25,45,790 क
	2. स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि		
17,43,15,231	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	18,62,85 906	
6,38,60,000	वर्ष मे की गई धन व्यवस्था	6 5 0,83,000	
89,54,711	निवेशो से प्राप्त ब्याज	70,66,776	
24,71,29,942	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़	25,84,35,682	
2,31,86,15,318	आगे ले जाया गया जोड़		2,59,82,19,704

क. विवरण 'क' मे आय तथा अदायगी लेखा देखिये।

पिछला वर्ष (1978-79)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,57,65,48,341	पीछे से लाया गया जोड़		1,69,79,04,265
1,57,65,48,341	कुल जोड़		1,69,79,04,265

(एम.एल सोबती)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

बीमा निगम
का तुलन पत्र

पिछला वर्ष (1978-79)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	भूमि तथा भवन निगम के पूर्ण स्वामित्व में)		
	क. निगम कार्यालयों के लिए भवन		
2,00,22,893	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,09,71,171	
1,09,48,278	वर्ष के दौरान वृद्धि	64,89,351	
3,09,71,171	जोड़ (क)	3,74,60,522	
	ख. अस्पताल तथा औषधालय		
32,32,08,822	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	43,05,68,012	
10,73,59,190	वर्ष के दौरान वृद्धि	7,98,66,232	
43,05,68,012	जोड़ (ख)	51,04,34,244	
46,15,39,183			54,78,94,766ख
	भूमि तथा भवन (निगम तथा राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व में)		
	निगम का शेयर		
	अस्पताल तथा औषधालय		
9,26,807	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,26,807	
—	वर्ष के दौरान वृद्धि	2,58,278	
9,26,807			11,85,085
46,24,65,990	आगे ले जाया गया जोड़		54,90,79,851

ख. अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.1 देखिये।

पिछला वर्ष (1978-79)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,31,86,15,318	पीछे से लाया गया जोड़		2,59,82,19,704
24,71,29,942	इस शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़	25,84,35,682	
(—) 6,08,44,036	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 5,78,70,146	
18,62,85,906			20,05,65,536
	3 आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		
9,57,86,859	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,51,06,740	
1,44,68,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,76,18,000	
49,20,649	निवेशों से प्राप्त ब्याज	39,87,292	
(—) 1,00,68,768	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 1,18,59,142	
10,51,06,740			11,48,82,890
	1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ख ख भविष्य निधि		
4,12,24,332	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,88,54,926	
	जोड़े—वर्ष में जमा की गई राशि		
1,23,56,746	(1) कर्मचारियों का अंशदान	1,38,09,901	
2,65,372	(2) निगम का अंशदान	39,401	
34,24,462	(3) कर्मचारी तथा निगम के शेयरों पर ब्याज	37,01,309	
24,261	(4) प्रोत्साहन बोनस	1,57,579	
5,72,95,173	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़	6,65,63,116	
5,72,95,173	उप शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़	6,65,63,116	
(—) 84,26,704	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 1,06,61,268	
	घटाएं-निम्नलिखित में अंतरित राशि		
(—) 6,635	1. पेंशन आरक्षित निधि	(—) 37,41,674	
(—) 6,908	2. अदावी जमा राशि	(—) 35,108	
4,88,54,926	3. भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि		5,21,25,066
75,063	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,08,482	
80,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	90,000	
3,853	निवेशों से प्राप्त ब्याज तथा आय	4,055	
(—) 50,434	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 36,614	
1,08,482			1,65,923
	6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप बीमा निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार	75,880	
3,15,880	वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	4,93,928	
—	निवेशों से प्राप्त ब्याज तथा लाभ	2,857	
—	जीवन बीमा निगम से प्राप्त राशि	65,000	
(—) 2,40,000	घटाएं—जीवन बीमा निगम को दिया गया प्रीमियम	(—) 1,88,858	
—	लाभाधिकारियों को दी गई बीमित राशि	(—) 10,000	
	सेवा निवृत्ति पर दिया गया		
—	बंदोबस्ती हितलाभ	(—) 1,20	
75,880			4,33,687
2,65,90,47,252	आगे ले जाया गया जोड़		2,99,63,97,806

ख ख—विवरण ध देखिए ।

पिछला वर्ष (1978-79)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपए		रुपये	रुपये
46,24,65,990	पीछे से लाया गया जोड़		54,90,79,851
	पूंजीगत व्यय के लिए दी गई राशि		
	(क) सामान्य रोकड़ शेष में से दी गई राशि		
4,54,36,075	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,03,95,046	
54,469	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	—	
(—) 50,95,498	घटाएं—समायोजन तथा वसूलियां	(—) 41,51,368	
4,03,95,046	जोड़ (क)	3,62,43,678	
	(ख) पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में से दी गई राशि		
19,18,99,835	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	15,87,69,716	
8,05,49,148	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	6,63,80,460	
(—) 11,36,79,267	घटाएं—समायोजन तथा वसूलियां	(—) 8,37,13,516	
15,87,69,716	जोड़ (ख)	14,14,36,660	
19,91,64,762	स्टाफ कारें		17 76,80,338
5,65,196	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,65,196	
—	वर्ष के दौरान संचयन	—	
5,65,196			5,65,196
	निगम के कार्यालय अध्यक्षों को स्थायी पेशगी		
78,766	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	86,911	
8,385	जोड़े —वर्ष में की गई अदायगियां	5,120	
(—) 2,40	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 1,000	
86,911			91,031
	निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर वेतन की अग्रिम अदायगी		
20,358	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,547	
1,16,471	जोड़े-वर्ष मे की गई अदायगियां	1,51,396	
(—) 108,282	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 1,05,930	
28,547			74,013
	निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते की अग्रिम अदायगी		
79,236	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	95,064	
1,78,346	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	1,54,562	
(—) 1,62,518	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 1,37,772	
95,064			1,11,854
66,24,06,470	आगे ले जाया गया जोड़		72,76,02,283

पिछला वर्ष (1978-79)	वेयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,65,90,47,252	पीछे से लाया गया जोड़		2,96,63,97,806
	7. निगम कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
30,73,809	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	35,64,911	
3,33,218	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	3,42,670	
1,57,884	निवेशों से प्राप्त ब्याज तथा लाभ	1,35,309	
35,64,911			40,42,890
	8. अस्पताल भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
3,44,63,168	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,98,78,158	
36,44,523	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	47,88,913	
17,70,467	निवेशों से प्राप्त ब्याज	15,12,736	
3,98,78,158			4,61,79,807
	9. स्टाफकारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
5,95,318	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,12,202	
21,616	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	28,202	
28,848	निवेशों से प्राप्त ब्याज	23,136	
(—) 33,580	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 41,826	
6,12,202			6,21,714
	10. निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
49,41,497	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	56,12,696	
9,66,332	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	9,93,727	
1,43,929	निवेशों से प्राप्त ब्याज	1,06,735	
(—) 4,39,062	घटाएं—व्यय के प्रमाणित विवरणों की प्राप्ति पर समायोजित राशि	(—) 7,33,477	
56,12,696			59,79,681 ग
	11. अस्पताल भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
7,13,44,246	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,19,81,321	
1,05,69,117	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,38,87,848	
24,76,467	निवेशों से प्राप्त ब्याज घटाएं—व्यय के प्रमाणित विवरणों की प्राप्ति पर	20,47,060	
(—) 24,08,509	समायोजित राशि	(—) 60,52,312	
8,19,81,321			9 18,63,917 घ.
2,79,06,96,540	आगे ले जाया गया जोड़		3,11,50,85,815

ग. विवरण 'ख' में आय तथा अदायगी लेखा देखिए ।

घ. विवरण 'ग' में आय तथा अदायगी लेखा देखिए ।

पिछला वर्ष (1978-79)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
66,24,06,470	पीछे से लाया गया जोड़		72,76,62,283
	निगम के कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिए पेशगी		
10,40,844	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,54,727	
9,86,490	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	9,78,021	
(—) 6,72,607	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 7,66,157	
13,54,727			15,66,591
	निगम के कर्मचारियों को विविध पेशगियां (त्योहार पेशगियां, बाढ़ पेशगियां तथा पंखा पेशगियां)		
6,69,672	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,98,729	
32,94,188	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	18,73,966	
(—) 10,65,131	घटाए—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 25,73,823	
28,98,729			21,98,872
	गृह निर्माण पेशगी		
83,81,477	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	99,57,060	
27,57,935	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	26,39,100	
(—) 11,82,352	घटाए—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 16,45,252	
99,57,060			1,09,50,908
	राज्य सरकारों की ओर से अग्रिम अदायगियां		
1,463	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,327	
2,358	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	1,860	
(—) 2,494	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 948	
			2,239
1,327			
	निगम के अस्पतालों औषधालयों/कार्यालयों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की बाबत राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभाग आदि को दी गई राशि।		
	(क) निगम के कार्यालय		
21,37,929	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,00,546	
10,48,311	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	11,17,049	
(—) 3,85,694	घटाएं—नकद वापसियां	(—) 5,41,250	
28,00,546	(ख) अस्पताल/औषधालय/अनेक्सियां		33,76,345
2,31,36,821	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,80,17,996	
64,54,893	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	1,11,27,409	
(—) 15,73,718	घटाए—नकद वापसियां	(—) 35,85,218	
2,80,17,996			3,55,60,187
	विविध पेशगियां ★		
20,82,545	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	15,49,008	
15,04,776	जोड़े—वर्ष में की गई अदायगियां	30,43,537	
(—) 20,38,313	घटाएं-वर्ष में प्राप्तियां	(—) 23,87,155	
15,49,008			22,05,390
70,89,85,863	आगे ले जाया गया जोड़		78,34,62,815

★ अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.2 देखिए।

पिछला वर्ष (1978-79)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,79,06,96,540	पीछे से लाया गया जोड़		3,11,50,85,815
	12 निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि		
7,85,80,959	पिछले तुलनापत्र के अनुसार	8,29,87,739	
51,71,765	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	60,22,295	
40,36,770	निवेशों से प्राप्त ब्याज	31,48,153	
	मूल्यांकन पर पांचवीं पंच वर्षीय रिपोर्ट के अनुसार		
(—) 33,66,688	समायोजन	—	
(—) 14,41,702	घटाए—वर्ष मे की गई अदायगियां	(—) 19,80,077	
6,635	जोड़ें—कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि से अंतरित राशि	37,41,674	
8,29,87,739			9,39,19,784
28,33,47,207	13. आपात आरक्षित निधि पिछले तुलनापत्र के अनुसार	34,94,27,240	
5,15,24,188	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	2,65,03,682	
1,45,55,845	निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	1,32,55,332	
34,94,27,240			38,91,86,254
	14. निगम के कर्मचारियों के लिये अनुकंपा आरक्षित निधि		
10,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	27,768	
35,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	35,000	
521	निवेशों से प्राप्त ब्याज	1,013	
(—) 17,753	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 37,479	
27,768			26,302
	जमा राशि .		
	प्रतिभूतियों की जमा राशि		
3,85,964	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,94,014	
5,33,608	जोड़ें—वर्ष में जमा राशि	6,90,720	
(—) 3,25,558	घटाएं—वर्ष में लौटाई गई जमा राशि	(—) 3,86,937	
5,94,014			8,97,797
	अन्य पार्टियों को देय बिलों से कटौती		
31,755	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	57,378	
14,08,355	जोड़ें—वर्ष में जमा की गई राशि	15,98,313	
(—) 13,82,732	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 15,74,917	
57,378			80,774
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि में अदायी जमा राशि		
50,706	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	25,253	
6,908	जोड़ें—वर्ष में जमा की गई राशि	35 108	
(—) 32,361	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 9,246	
25,253			51,115
3,22,38,15,932	आगे ले जाया गया जोड़		3,59,92,47,841

पिछला वर्ष (1978-79)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
70,89,85,863	पीछे से लाया गया जोड़		
	राज्य सरकारों को कर्ज		
2,73,23,100	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,48,05,967	78,34,62,815
—	जोड़—वर्ष में की गई अदायगियां	—	
(—) 25,17,133	घटाएं—राज्य सरकारों द्वारा लौटाई गई राशि	(—) 25,17,133	
2,48,05,967			2,22,88,834
	प्रेषण		
	नकद प्रेषण छ.		
6,00,419	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	(—) 22,45,890	
2,97,53,81,683	जोड़ें—वर्ष में डैबिट	3,40,35,52,264	
(—) 2,97,32,27,902	घटाए—वर्ष में क्रेडिट	(—) 3,45,21,93,838	
(—) 22,45,890			(—) 3,08,87,464
	अन्य प्रेषण		
	विनिमय लेखा ज		
36,745	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	(—) 60,401	
8,92,65,278	जोड़ें—वर्ष में डेबिट	14,96,99,900	
(—) 8,93,62,424	घटाएं—वर्ष में क्रेडिट	(—) 13,74,20,844	
(—) 60,401			1,22,18,655
	लागत पर निवेश		
	1. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
30,53,29,804	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	36,42,88,655	
5,89,58,851	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	10,83,35,805	
	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता		
—	या बिक्री पर वसूली	—	
36,42,88,655			47,26,24,460
	2 स्थाई (आंशिक तथा पूर्ण)		
	अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि		
17,43,15,230	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	18,62,85,906	
1,19,70,676	जोड़ें—वर्ष मे किए गए निवेश	1,42,79,630	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
18,62,85,906			20,05,65,536
	3 आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		
9,57,86,859	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,51,06,740	
93,19,881	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	97,76,150	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
10,51,06,740			11,48,82,890
1,38,71,66,840	आगे ले जाया गया जोड़		1,55,51,55,725

ज अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.3 देखिये ।

छ अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.4 देखिये ।

ज अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2 5 देखिये ।

पिछला वर्ष (1978-79)	देयतायें	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
3,22,38,15,932	पीछे से लाया गया जोड़		3,59,92,47,841
	परिवार नियोजन परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त जमा राशि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	—	
7,00,000	जोड़े-वर्ष में जमा राशि	4,25,000	
(—) 7,00,000	घटाए-परिवार नियोजन परियोजना को की गई अदायगियां	(—) 4,25,000	
	विविध जमा राशि*		
28,12,557	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,85,608	
29,95,780	जोड़े-वर्ष में प्राप्त जमा राशि	30,92,265	
(—) 52,22,729	घटाए-वर्ष में लौटाई/समायोजित की गई जमा राशि	(—) 18,80,531	
5,85,608			17,97,342
3,22,44,01,540	आगे ले जाया गया जोड़		3,60,10,45,183

*इसमें निम्नलिखित शीर्षों का निवल जोड़ शामिल है :

(1) अवधीकृत आय उचंत लेखा (2) अवधीकृत अदायगियां (उचंत लेखा) (3) महंगाई भत्ता जमा (4) विविध

पिछला वर्ष (1978-79)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,38,71,66 840	पीछे से लाया गया जोड़		1,55,51,55,726
	4 कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि		
4,12 24 332	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,88 54,926	
76 30,594	जोड़े वर्ष मे किए गए निवेश	32 70 140	
—	घटाए-निवेशो की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
4,88,54 926			5,21,25,066
	5 भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा आरक्षित निधि		
75 063	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,08 482	
33 419	जोड़े-वर्ष मे किए गए निवेश	57,441	
—	घटाए-निवेशो की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
1,08,482			1,65,923
	6 ग्रुप बीमा निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	75,880	
75 880	जोड़े-वर्ष मे किए गए निवेश	3,62,807	
	घटाए निवेशो की परिपक्वता या बिक्री पर वसूला		
75,880			4,38,687
	7 निगम के कार्यालय भवनो (स्टाफ क्वार्टरो सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
30,73 808	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	35,64 911	
4,91,103	जोड़े-वर्ष मे किए गए निवेश	4 77,979	
—	घटाए निवेशो की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
35,64 911			40,42,890
	8 अस्पताल भवनो की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
3 44 63 168	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,98,78,158	
54,14,990	जोड़े-वर्ष मे किए गए निवेश	63 01,649	
—	घटाए- निवेशो की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
3,98,78,158			4,61,79,807
	9 स्टाफ कारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
5 61 738	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,12,202	
50,464	जोड़े-वर्ष में किए गए निवेश	9 512	
—	घटाए-निवेशो की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
6 12 202			6,21,714
1 18 02 61,349	आगे ले जाया गया जोड़		1,65,87 29 813

पिछला वर्ष (1978-79)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
3,22,44,01,540	पीछे से लाया गया जोड़		3,60 10,45,183
3,22 44,01,540	कुल जोड़		3,60,10,45,183

नई दिल्ली,

दिनांक 31 मई, 1980

पिछला वर्ष (1978-79)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,48,02,61,399	पीछे से लाया गया जोड़		1,65,87,29,813
	10 निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत का अनुरक्षण आरक्षित निधि		
28,03,568	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,12,150	
8,582	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	—	
	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 2,08,814	
28,12,150			26,03,336
	11. अस्पताल भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
4,82,07,426	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,39,63,325	
57,55,899	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	23,40,405	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
5,39,63,325			5,63,03,730
	12. निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि		
7,85,80,959	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,29,87,739	
44,06,780	जोड़ें—वर्ष के किए गए निवेश	1,09,32,045	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
8,29,87,739			9,39,19,784
	13. आपात आरक्षित निधि		
28,33,47,207	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	34,94,27,240	
6,60,80,033	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	3,97,59,014	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
34,94,27,240			38,91,86,254
	14. अनुकंपा आरक्षित निधि		
9,999	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	27,768	
17,769	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	(—) 1,466	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
27,768			26,302
	सामान्य रोकड़ शेष		
95,95,31,370	पिछले तुलनपत्र के अनुसार निवेश	1,19,17,73,449	
50,45,98,079	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	76,95,16,003	
(—) 27,23,56,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 63,84,79,700	
1,19,17,73,449			1,32,48,09,752
32,90,768	हाथ रोकड़	48,82,242	
5,98,57,702	बैंकरों के पास रोकड़	7,05,83,970	
6,31,48,470			7,54,66,212
1,25,49,21,919	कुल रोकड़ शेष		1,40,02,75,964
3,22,44,01,540	कुल जोड़		3,60,10,45,183

ह. अनुबन्ध 2 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2.6 देखिये।

ह/०
एम० एस० सोबती,
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अनुबंध-1

आय व्यय लेखे पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1.1 पृष्ठ (ii) पर 'क'

इस राशि में अस्पतालों के लिये खरीदे गये प्रारम्भिक उपस्कर पर व्यय में निगम का शेयर शामिल है।

1967-68 से 1971-72 तथा 1973-74 से 1979-80 तक (1972-73 वर्ष की सूचना एकत्र की जा रही है) उपस्कर की खरीद पर कुल व्यय 1,50,67,801.80 रुपये है। इसे तुलनपत्र में परिसम्पत्तियों के रूप में नहीं दिखाया गया है। इस व्यय के पंजीकरण का मामला अभी निगम के विचाराधीन है।

1.2 पृष्ठ (ii) पर 'ख'

व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से अतिरिक्त व्याप्ति तथा मजदूरी में परिशोधन के परिणाम-स्वरूप हितलाभ की औसत दैनिक दर की राशि में वृद्धि के कारण हुई है।

1.3 पृष्ठ (iii) पर 'ग'

1-7-73 से पहले नियोजकों का विशेष अंशदान तथा कर्मचारियों का अंशदान "केवल नियोजकों का शेयर तथा कर्मचारियों का शेयर" उप शीर्ष के अन्तर्गत अलग-अलग दर्ज किये जाते थे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अध्याय 5 के निरसन के परिणामस्वरूप अंशदान अब "नियोजक तथा कर्मचारी शेयर" उप शीर्ष के अन्तर्गत इकट्ठे दिखाये जा रहे हैं। अंशदान आय में वृद्धि मुख्य रूप से अतिरिक्त व्याप्ति तथा मजदूरी में परिशोधन के परिणाम-स्वरूप अंशदान की औसत दर की राशि में वृद्धि के कारण हुई है।

प्राप्त सूचना के अनुसार 31-3-1980 को 31-3-79 तक की अवधि के 28,09.78 लाख रुपये की राशि के वसूल न किये गये बकाया थे। 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 32 46 लाख रुपये की अंशदानों की अदायगी की वसूल न की गई डिफेंरल राशि भी थी।

1.4 पृष्ठ (iii) पर 'घ'

1-7-73 से पहली अवधि के बकाया की वसूली की सूचक है।

1.5 पृष्ठ (iii) पर 'ङ'

"ब्याज तथा लाभांश" के अन्तर्गत आय में कमी। अक्तूबर, 1976 में भारतीय स्टेट बैंक की "पुनः निवेश योजना" के अन्तर्गत किए जा रहे सावधि निवेशों के कारण है। जिसके अन्तर्गत देय होने वाला ब्याज किसी निवेश की परिपक्वता पर निगम के खाते में जमा किया जायेगा।

पुनर्निवेश योजनाओं में 1979-80 वर्ष में निवेशों पर प्राप्त ब्याज की 9,71.90 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है क्योंकि निगम को राशि निवेशों की परिपक्वता पर देय होगी।

1.6 पृष्ठ (iii) पर 'च'

"क्षतिपूर्ति" के अन्तर्गत आय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(2) के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकार से वसूल की गई उस राशि की सूचक है जो किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी अदायगियों का व्यय भार अखिल भारतीय औसत से अधिक हो जाने पर वसूल की जाती है।

1.7 पृष्ठ (iii) पर 'छ'

इसमें नियोजकों से फ्रैंकिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिये प्राप्त लाइसेंस फीस तथा निगम की देय राशि की अदायगी न करने पर नियोजकों पर लगाए गए हर्जाने और अंशदान कार्ड समय पर न भेजने के कारण लगाये गये जुर्माने भी शामिल है।

31-3-79 की स्थिति के अनुसार अंशदानों की अदायगी में देरी के कारण देय हर्जानों के संबंध में 347.89 लाख रुपये की राशि वसूली के लिये बकाया थी।

1.8 पृष्ठ (iii) पर 'ज'

इसमें डुप्लीकेट पहचान पत्रों की लागत, अधिक अदायगियों तथा लेखा परीक्षा में नामंजूर की गई राशि की वसूली, छुट्टी, वेतन तथा पेंशन अंशदान की वसूली, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की बाबत कर्मचारियों के अंशदान तथा अन्य आय शामिल हैं।

1.9 पृष्ठ (iv) पर 'झ'

इसमें बीमाकृत व्यक्तियों की शव परीक्षा के लिये दी गई फीस तथा रोजगार चोट आदि के मामलों में निर्णय लेने के लिये पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य विवरण प्राप्त करने के लिये पुलिस प्राधिकारियों को देय प्रभारों सहित विविध व्यय शामिल हैं।

1.10 पृष्ठ (vi) पर 'ञ'

इसमें बैंक अंतरण पर तार खर्च तथा अंशदान टिकटों की बिक्री के लिये भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों द्वारा कमीशन प्रभार शामिल है। व्यय में कमी आंशिक रूप से 1-9-1979 से निधि के तार अंतरण की दर को 7 रुपये से कम करके 3 रु० करने तथा अंशदान की नकद वसूली पर कमीशन में छूट लागू करने के कारण हुई है।

1.11 पृष्ठ (vi) पर 'ट'

इसमें 6,79,786 रुपये की राशि शामिल नहीं है जो निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं से संबंधित है तथा 1--क(ii) चिकित्सा हितलाभ के अन्तर्गत शामिल की गई है क्योंकि यह राशि दिल्ली प्रशासन के साथ व्यय में शेयर की जानी है।

निगम के पांचवें पंचवार्षिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार 2 प्रतिशत अधिक धन व्यवस्था की सूचक 33.66 लाख रुपये की राशि तथा उस पर 1-4-1974 से 31-3-1978 तक ब्याज सहित 1978-79 वर्ष के लेखों में समायोजित की गई थी। मूल्यांकक ने सिफारिश की थी कि पेंशन आरक्षित निधि के लिये वार्षिक धन व्यवस्था 14 प्रतिशत की बजाय कर्मचारियों की परिलब्धियों के 12 प्रतिशत की दर पर की जानी चाहिये।

मुख्यालय की स्थापना शाखा–4 के पत्र संख्या एफ–22/11/11/1/78—स्थापना-4 दिनांक 10-10-79 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले 454 व्यक्तियों ने निगम की पेंशन योजना के अन्तर्गत आने का विकल्प दिया। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में संचित पेंशन देयता के लिए भी 1979-80 वर्ष के दौरान पेंशन आरक्षित निधि में धन व्यवस्था की गई है।

1.12 पृष्ठ (vi) पर 'ठ'

यह व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि में व्यपगत जमा की वापिसी से संबंधित अदायगियों तथा विविध आय में अंतरित कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि की अदायगी का सूचक है।

1.13 पृष्ठ (viii) पर 'ड'

निगम की स्थायी समिति के दिनांक 1-2-74 के निर्णय के अनुसार नियोजकों तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10 प्रतिशत भाग अस्पताल/औषधालय/अन्य चिकित्सा संस्थान तथा कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

1.14 पृष्ठ (viii) पर 'ढ'

यह 17 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में लिये गये निगम के निर्णय के अनुसार आपात आरक्षित निधि में अंतरण की सूचक है। निगम ने निर्धारित किया है कि व्यय से अधिक आय का 20 प्रतिशत भाग (जब आधिक्य एक करोड़ रुपये से कम हो तो सम्पूर्ण राशि) आपात आरक्षित निधि में जमा किया जाना चाहिये।

अनुबन्ध-2

तुलन-पत्र पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां

2.1 पृष्ठ (xi) पर 'ख'

इसमें सामान्य रोकड़ शेष में से 23, 94, 10, 096 रुपये की परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

2.2 पृष्ठ (xix) पर 'ङ'

इसमें ये शामिल हैं :—

1. लेखन सामग्री के नियंत्रक कलकत्ता को पेशगियां।
2. लोक निर्माण विभागों को पेशगियां।
3. राज्य सरकारों के मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभागों की पेशगियां।
4. निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अन्य कार्यालयों की पेशगियां।
5. नगरपालिका, स्थानीय निकायों आदि को पेशगियां।
6. कानूनी प्रभारों के लिए पेशगियां।
7. निगम की विभागीय केन्टीनों को, पेंशगियां।
8. अन्यत्र वर्गीकृत न की गई अन्य पेशगियां।
9. विशेष पेशगियां।

2.3 पृष्ठ (xxi) पर 'ज'

यह 1977-78 से पहले महाराष्ट्र सरकार की राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा परियोजनाओं के निर्माण तथा विस्तार के लिए दिए गए कर्जों की सूचक है।

2.4 पृष्ठ (xxi) पर 'छ'

'नकद प्रेषण' शब्द का अर्थ एक लेखा मंडल से दूसरे तथा दूसरे से पहले में निधियों (नकद) के अन्तरण से है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से टिकटों की बिक्री/नकद वसूली करके एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा सं० 1 (संग्रह लेखा) तथा अन्त में मुख्यालय के लेखा सं० 1 (केन्द्रीय) में अन्तरित किये जाते हैं। प्रशासनिक व्यय तथा बीमाकृत व्यक्तियों की हितलाभ- की अदायगियों के लिए निधियां लेखा सं० 1 (मुख्यालय) से अन्तरण करके क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थानीय कार्यालयों को भेजी जाती हैं। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय की निधियों के अन्तरण से सम्बन्धित इस तरह के सभी लेनदेन को नकद प्रेषण कहा जाता है।

'नकद प्रेषण' शीर्ष के अन्तर्गत 5,08,87,464/- रुपये का माइनस शेष निगम के लेखों में कुछेक जमा राशियों के समायोजन का सूचक है जिसके लिए बैंक से डेबिट सूचना न होने के कारण दूसरी ओर डेबिट नहीं दिखाया जा सका। तथापि इस शीर्ष के अन्तर्गत राशि अप्रैल, 1980 माह में समायोजित की जा चुकी है।

2.5 पृष्ठ (xxi) पर 'झ'

'अन्य प्रेषण'—विनिमय लेखा' शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से दूसरे के बीच तथा दूसरे से पहले के बीच पुस्तक समायोजन से है। निगम के कार्यालय से प्रारम्भ होने वाले तथा दूसरे निगम से कार्यालय की पुस्तकों में समायोजित किये जाने वाले लेन देन विनिमय लेखा द्वारा अन्तरित किए जाते हैं।

'अन्य प्रेषण—विनिमय लेखा' शीर्ष के अन्तर्गत 1,22,18,655/- रुपये की राशि का शेष निगम के लेखों में कुछेक जमा राशियों के समायोजन का सूचक है जिसके लिए 1979-80 के लेखे बन्द करने से पहले दूसरी ओर क्रेडिट (तदनुरूपी मद) नहीं दिखाया जा सका।

2.6 पृष्ठ (xxxiii) पर 'ख'

बैंकरों के पास नकद धनराशि में निम्नलिखित शामिल है :--

(i) क्षेत्रीय कार्यालय लेखा सं० 1 (संग्रह खाता) में शेष (लाख रुपयों में) 67.38

क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा संख्या 1 (संग्रह लेखा) में उपलब्ध नकद धनराशि 30 तथा 31 मार्च, 1980 की प्राप्त अंशदानों की सूचक है ।

(ii) प्रशासनिक व्यय और दिल्ली में चिकित्सा सेवा रेख पर व्यय को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/निदेशालय (चि०) दिल्ली के लेखा संख्या 2 में शेष 218.46

क्षेत्रीय कार्यालय लेखा संख्या 2 में राशि 1-4-80 को वेतन संवितरण तथा अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित थी ।

(iii) स्थानीय कार्यालयों के लेखा सं० 2 में शेष 420.00

बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभों की साप्ताहिक औसत अदायगी लगभग 123.00 लाख रुपये है । स्था० का० के लेखा सं० 2 में 420 00 लाख रुपये का शेष उनकी तीन सप्ताह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है ।

2-7 लेखा आंकड़ों तथा निम्नलिखित रूप में शेषों के पुनरीक्षण के अनुसार आंकड़ों के बीच अन्तर का समाधान किया जा रहा है ।

लेखा शीर्ष	लेखा आंकड़े	बाह्य शीट आंकड़े	अन्तर
1. प्रतिभूतियों की जमा जैसे ठेकेदार आदि	8,97,797-00	8,97,975-00	178-00
2. विविध जमा अवर्गीकृत आय (उचंत लेखा)	17,97,342-00	17,91,072-22	6,269-78
3. कर्मचारियों को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते की अग्रिम अदायगी	1,11,854-00	1,11,514-00	340-00
4. निगम कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिये पेशगी	15,66,591-00	15,66,699-58	108-58
5. निगम के कर्मचारियों को विविध पेशगियां ।	21,98,872-00	21,99,089-00	217-00
6. निम्नलिखित की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिये लोक निर्माण विभाग आदि को पेशगियां			
(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय	33,75,345-00	33,98,533-00	22,188-00
(ख) अस्पताल/औषधालय भवन	3,55,60,187-00	3,57,23,332-00	1,63,145-00
7. विविध पेशगियां	22,05,390-00	21,80,594-00	24,796-00

विवरण-क

31 मार्च, 80 की स्थिति के अनुसार 1979-80 वर्ष का पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा ।

	रु०	रु०		रु०	रु०
आदि शेष	74,89,66,131 म		पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से उत्पन्न परिसम्पत्तियां	30,84,84,670	
वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	15,97,60,416 म.		निर्माण एजेन्सियों को दी गई पेशगियां	14,14,36,660	
निवेशों पर ब्याज	1,38,19,243 य.		निधि में उपलब्ध राशि	47,26,24,460	
		92,25,45,790			92,25,45,790
		अस्पताल तथा औषधालय		अन्य भवन	
	आदि शेष	म. 59,91,72,905		14,97,93,226	
	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	म. 12,78,08,333		3,19,52,083	
	निवेश पर ब्याज	य. 1,10.55,395		27,63,848	

विवरण ख

निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत तथा अनुरक्षण आरक्षित निधि का प्राप्ति तथा अवायगी लेखा

	रु०	रु०		रु०	रु०
आदि शेष	56,12,696		निगम के कार्यालयों के मरम्मत तथा अनुरक्षण की बाबत राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों को दी गई राशि	'क' 46,51,072	
वर्ष मे की गई धन व्यवस्था	9,93,727				
निवेशों पर ब्याज	1,06,735		निधि में उपलब्ध राशि	26,03,336	
राज्य सरकारो/राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा उपयोग न की गई पेशगियों की नकद वापसी	5,41,250				
		72,54,408		72,54,408	
			'क' राज्य सरकारों को दी गई पेशगियां	46,51,072	
			घटायें—प्रयोग न की गई पेशगियों की नकद वापिसी	5,41,250	
			घटायें—प्रमाणित व्यय विवरण की प्राप्ति पर समायोजित राशि	7,33,477	
					12,74,727
			तुलनपत्र के अनुसार शेष (पृष्ठ xix)		33,76,345

विवरण ग

अस्पताल भवनों/कार्यालयों/अनैक्सियों आदि की मरम्मत तथा अनुरक्षण आरक्षित निधि का प्राप्ति तथा अवायगी लेखा

	रु०	रु०		रु०	रु०
आदि शेष	8,19,81,421		अस्पतालों/औषधालयों/ अनैक्सियों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की बाबत		
वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,38,87,848		राज्य सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों को दी गई राशि	4,51,97,717 'क'	
निवेशो पर ब्याज	20,47,060				
राज्य सरकारो/राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा उपयोग न की गई पेशगियों की नकद वापिसी	35,85,218		निधि में उपलब्ध राशि	5,63,03,730	
		10,15,01,447			10,15,01,447
			'क' राज्य सरकारों को दी गई पेशगियां		4,51,97,717
			घटायें— प्रयोग न की गई पेशगियों की नकद वापिसी	35,35,218	
			घटायें—प्रमाणित व्यय विवरण की प्राप्ति पर समायोजित राशि	60,52,312	
					96,37,530
			तुलन पत्र के अनुसार शेष (पृष्ठ xix)		3,55,60,187

विवरण ब

कर्मचारी राज्य-बीमा सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि का 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार

ब्यौरों का सूचक विवरण

	सामान्य भविष्य निधि	अंशदायी भविष्य निधि	जोड़
	रु०	रु०	रु०
1. आदि शेष	3,88,41,621	1,00,13,305	4,88,54,926
2. कर्मचारियों का अंशदान	1,26,02,508	12,07,393	1,38,09,901
3. निगम का अंशदान	—	39,401	39,401
4. कर्मचारी तथा निगम के शेयर पर ब्याज	31,91,270	5,10,039	37,01,309
5. प्रोत्साहन बोनस	1,27,129	30,450	1,57,579
6. जोड़	5,47,62,582	1,18,00,588	6,65,63,116
(क) घटायें—वर्ष में की गई अदायगियां	98,48,190	8,13,078	1,06,61,268
(ख) घटायें—निम्नलिखित में अंतरित राशि			
(i) पेंशन आरक्षित निधि	—	37,41,674	37,41,674
(ii) अदावी जमा	21,103	14,005	35,108
अन्त शेष	4,48,93,235	72,31,831	5,21,25,066

विवरण ग

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

भविष्य निधि का 1979-80 वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

प्राप्तियां		राशि	अदायगियां	राशि
(1) आदि शेष कर्मचारियों का अभिदान			अभिदाता को 1979-80 वर्ष के दौरान की गई अदायगी	
(i) सा० भ० नि०	3,88,337.01 रु०	4,88,56,642.30	(1) सा० भ० नि० 98,45,255.20 रु०	1,06,59,691.10
(ii) अं० भ० नि०	1,00,13,305.29 रु०		(2) अं० भ० नि० 8,14,436.00 रु०	
(2) वर्ष के दौरान प्राप्ति कर्मचारियों का अभिदान			अंत शेष	
(i) सा० भ० नि०	1,26,43,523.50 रु० (1) 29,374.30 रु०	1,38,09,704.20	(1) सा० भ० नि० 4,49,08,960.70 रु०	
(ii) अं० भ० नि०	11,95,555 रु०		(2) अ० भ० नि० 72,18,635.29 रु०	5,21,27,595.99*
(3) ब्याज				
(क) निजी शेयर पर				
(i) सा० भ० नि०	31,91,269.74 रु०	36,49,021.74		
(ii) अं० भ० नि०	4,57,752.00 रु०			
(ख) निगम के शेयर पर				
सा० भ० नि०	52,287.00 रु०	52,287.00		
(4) 1979-80 वर्ष का निगम के अंशदान का शेयर	39,401.00 रु०	39,401.00		
(5) प्रोत्साहन बोनस				
(i) सा० भ० नि०	1,27,129.00 रु०	1,57,579.00		
(ii) अ० भ० नि०	30,450.00 रु०			

(6) निम्नलिखित में अंतरित राशि

(क) अदायी जमा

(i) सा० भ० नि०	21,669.15 रु०		
(ii) अं० भ० नि०	14,005.00 रु०		
(ख) पेंशन आरक्षित निधि			
अं० भ० नि०	37,41,674.00 रु०	(—) 37,77,348.15	
	कुल जोड़	6,27,87,287.09	6,27,87,287.09
लेखों का अंत शेष		5,21,25,066.00 रु०	
ब्राड शीट का अंत शेष		5,21,27,596.00 रु०	
	अन्तर	27,530.00	(ब्राड शीट में अधिक)

* ब्राड शीट के अनुसार अंत शेष 5,21,27,596.00 रु० है। 2,530.00 रु० के अन्तर का पता लगा लिया है और उसे 1980-81 के लेखों में ठीक कर लिया जाएगा।

परिशिष्ट 24

हितलाभों आदि की अदायगी की तुलना में प्रशासनिक लागत

	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
			रुपयों में			
1. कुल प्रशासनिक लागत	6,60,68,976	7,77,62,505	8,77,45,918	9,55,40,440	9,95,0[illegible],434	11,37,56,42
2. अंशदान :						
(1) नियोजकों तथा कर्मचारियों के शेयर	60,34,74,995	73,15,86,339	1,23,61,94,824	1,31,11,81,105	1,45,78,73,675	1,58,68,28,298
(2) केवल नियोजकों का शेयर	2,16,80,542	1,78,07,427	93,97,151	25,97,022	17,57,264	15,72,055
(3) केवल कर्मचारियों का शेयर	1,00,74,058	1,00,09,537	1,07,22,754	48,90,5[illegible]9	71,05,946	77,46,520
(4) ब्याज	—	--	1,78,865	5,97,322	8,57,102	14,57,288
जोड़ :	63,52,39,595	75,94,0[illegible],20[illegible]	1,25,64,93,594	1,31,92,65,988	1,46,75,93,987	1,59,76,04,161
3. राजस्व लेखे पर कुल व्यय	63,49,05,056	75,58,05,845	1,01,91,84,702	1,17,71,52,092	1,[illegible]7,04,51,588	1,59,18,79,538
4. कुल हितलाभ निम्नलिखित के साथ प्रशासनिक लागत की प्रतिशतता :	46,45,26,360	57,23,86,508	70,85,36,816	87,03,56,722	1,05,84,50,926	1,27,31,82,259
अंशदान	10.40%	10.24%	6.98%	7.23%	6.78%	7.12%
राजस्व लेखे में व्यय	10.57%	10.29%	8.61%	8.12%	7.26%	7.15%
हितलाभ	14.22%	13.59%	12.38%	1[illegible].98%	9.40%	8.93%

टिप्पणी —4 में राज्य सरकारों द्वारा किये गये चिकित्सा हितलाभ व्यय का शेयर शामिल नहीं है।

[सं० जैड–16016/3/80-एच०आई०]

एस० बी० चावला, उप सचिव

New Delhi, the 31st August, 1981

S.O.1245.—In pursuance of section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Annual Report of the Employees' State Insurance Corporation for the year 1979-80 is hereby published for general information.

List of Members of the Employees' State Insurance Corporation, 1979-80

Chairman

Shri J.B. Patnaik

Minister for Labour, Govt. of India

Vice-Chairman

Shri N.R. Laskar

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare Government of India

Members

Representative of Central Government

3. Vacant
4. Secretary to the Government of India, Ministry of Labour.
5. Shri R.K.A. Subrahmanya, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour.
6. Dr. B. Sankaran, Director General of Health Services, Government of India.
7. Shri N.K. Panda, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance.

Representative of State Governments

8. Shri G.R. Nair, Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment and Technical Education Department.
9. Shri A. Ali, Secretary to the Government of Assam, Labour Department.
10. Shri I.C. Kumar, Principal Secretary to the Government of Bihar, Labour & Employment Department.
11. Shri P.P. Rathod, Secretary to the Government of Gujarat, Health & Family Planning Department.
12. Shri H.L. Gugnani, Commissioner and Secretary to the Government of Haryana, Labour and Employment Department.
13. Shri O.P. Yadav, Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Labour & Employment Department.
14. Shri I.D. Sharma, Labour Commissioner, Government of Jammu and Kashmir.
15. Shrimati Achala Maulik, Commissioner & Secretary to the Government of Karnataka, Social Welfare and Labour Department.
16. Shri C.P. Nair, Special Secretary to the Government of Kerala, Labour Department.
17. Shri Faqir Chand, Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Labour Department.
18. Shri N.V. Sundararaman, Special Secretary to the Government of Maharashtra, Urban Development & Public Health Department.
19. Shri S. Marwein, Secretary Government of Meghalaya, Labour Department.
20. Shri K.S. Puri, Secretary to the Government of Nagaland, Home Department.
21. Shri U.N. Mallik, Secretary to the Government of Orissa, Labour Employment and Housing Department.
22. Shri Hardial Singh, Secretary to the Government of Punjab, Health and Welfare Department.
23. Shri Brijendra Singh, Labour Commissioner, Government of Rajasthan, Labour Department.
24. Shri C. Ramachandran, Secretary to the Government of Tamil Nadu, Labour and Employment Department.
25. Shri S.K. Ghosal, Secretary to the Government of Tripura, Labour Department.
26. Shri Prakash Chandra Saxena, Commissioner-cum-Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Labour Department.
27. Shri N. Krishna Murthy, Secretary to the Government of West Bengal, Labour Department.

Representative of Union Territories

28. Shri S.L. Chopra, Labour Commissioner, Delhi Administration.

Representatives of Employers

29. Shri R.N. Joshi.
30. Shri C.R. Paul.
31. Shri Madanmohan Mangaldas.
32. Shri P. Chentsal Rao.
33. Shri N.S. Rao.

Representatives of Employees

34. Shri G.V. Chitnis.
35. Miss E.D' Souza.
36. Shri P.K. Sharma.
37. Shri P.V. Sankaranarayanan, MLA.
38. Vacant.

Representatives of Medical Profession

39. Dr. J. Majumdar.
40. Vaidya Shri Shree Krishan Multani.

Representatives of Parliament

41. Shri Syed Abdul Malik.
42. Vacant
43. Vacant

Ex-officio Member

44. Shri Har Mander Singh, Director General, ESI Corporation.

List of Members of the Standing Committee of ESI Corporation, 1979-80

Chairman

Shri R.K.A. Subrahmanya

Additional Secretary to the Government of India

Ministry of Labour

Members

2. Vacant
3. Dr. B. Sankaran, Director General of Health Services, Government of India.

4. Shri N.K. Panda,
Joint Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance.

Representatives of State Government

5. Shri C.P. Nair,
Special Secretary to the Government of Kerala,
Labour Department.

6. Shri N.V. Sundararaman,
Special Secretary to the Government of
Maharashtra, Urban Development and Public
Health Department.

7. Shri N. Krishna Murthy,
Secretary to the Government of West Bengal,
Labour Department.

Representatives of Employers

8. Shri C.R. Paul.

9. Shri P. Chentsal Rao.

10. Shri N.S. Rao.

Representatives of Employees

11. Shri G.V. Chitnis.

12. Miss E. D'Souza.

13. Shri P.V. Sankaranarayanan, MLA.

Representative of Medical Profession

14. Dr. J. Majumdar.

Representative of Parliament

15. Vacant

Ex-officio Member

14. Shri Har Mandar Singh,
Director General, ESI Corporation.

List of Members of the Medical Benefit Council 1979-80

Chairman

Director General of Health Services

Government of India

Members

Representatives of Central Government

2. Dr. Ishwar Dass Bajaj,
Deputy Director General of Health Services,
(CGHS), Government of India.

3. Dr. V.M. Charnalia,
Medical Commissioner, ESI Corporation.

Representatives of State Government

4. Dr. T.N. Sanghi,
Deputy Director of Medical Health Services,
Government of Andhra Pradesh.

5. Dr. B.L. Das,
Administrative Medical Officer, ESI Scheme,
Government of Assam.

6. Dr. A.P. Verma,
Administrative Medical Officer, ESI Scheme,
Department of Labour & Employment,
Government of Bihar.

7. Lt. Col. B.D. Misra,
Director of Medical Services, ESI Scheme,
Government of Gujarat.

8. Dr. S. Shah,
Assistant Director, Health Services, (Social Insurance)
Government of Haryana.

9. Dr. S.L. Grover,
Director, Health Services & Family Planning,
Government of Himachal Pradesh.

10. Shri I.D. Sharma,
Labour Commissioner, Government of Jammu & Kashmir.

11. Dr. K.B. Hannumantha Reddy,
Director, ESI Scheme, (Medical Services),
Government of Karnataka.

12. Dr. M. Raghvan,
Administrative Medical Officer, ESI Scheme,
Government of Kerala.

13. Dr. P.S. Dave,
Administrative Medical Officer, ESI Scheme,
Government of Madhya Pradesh.

14. Dr. R.C. Digho,
Director, ESI Scheme, Government of
Maharashtra.

15. Shri S. Marwein,
Secretary to the Government of Meghalaya,
Labour Department.

16. Shri S.K. Kochar,
Secretary to the Government of Nagaland,
Home Department.

17. Dr. P.C. Rath,
Administrative Medical Officer, ESI Scheme,
Government of Orissa.

18. Dr. Asa Singh,
Director Health Services,
Government of Punjab.

19. Dr. R.R. Purohit,
Addl. Director, Medical & Health Services,
ESI Scheme, Government of Rajasthan.

20. Dr. Ernest J. David,
Director of Medical Services and Family
Welfare, Government of Tamil Nadu.

21. Shri S.K. Ghosal,
Secretary to the Government of Tripura,
Labour Department.

22. Dr. S.C. Chaturvedi,
Joint Director of Health Services, ESI Scheme,
Government of Uttar Pradesh.

23. Smt. R. Ghosh,
Director, ESI (MB) Scheme,
Government of West Bengal.

Representatives of Employers

24. Dr. B.D. Kaushal.

25. Shri R.N. Joshi.

26. Shri R.L. Moitra.

Representatives of Employees

27. Shri A.C. Saikia, MLA.

28. Shri Sumer Singh.

29. Dr. Samar Roy Choudhury.

Representatives of Medical Profession

30. Dr. (Mrs.) Lalita Rao.

31. Dr. N.N. Bhattacharjee.

32. Aryavaidyan P.K. Warrier.

E.S.I C.' AT A GLANCE

	31-3-79	31-3-80	Progress during 1979-80
STATES/UNION TERRITORIES	20	20	—
CENTRES	375	395	20
EMPLOYEES	58,15,900	59,83,000	1,67,100
INSURED PERSONS	65,89,500	68,50,000	2,60,50
FAMILY UNITS	65,89,500	68,50,000	2,60,500
INSURED WOMEN	4,90,650	5,38,750	48,100
TOTAL BENEFICIARIES	2,55,67,300	2,65,78,000	10,10,700
EMPLOYEES YET TO BE COVERED	8,79,700	8,58,000	(—)21,700
CASH OFFICES	684	691	7
INSPECTION OFFICES	169	195	26
ESI HOSPITALS	65	67	2
ESI ANNEXES	27	33	6
BEDS			
(A) ESI HOSPITALS	14,007	14,102	95
(B) ESI ANNEXES	550	670	120
(C) RESERVED	4,747	4,765	18
TOTAL	19,304	19,537	233
STATE INSURANCE DISPENSARIES	990	1,030	40
INSURANCE MEDICAL OFFICERS	2,992	3,101	109
INSURANCE MEDICAL PRACTITIONERS CLINICS	4,565	4,734	169
CAPITAL CONSTRUCTION (RUPEES IN LAKHS)			
SANCTIONED UP TO	8,944.06	9,712.44	768.38
ADVANCED UP TO	6,864 37	7,490.49	626.12
INCOME & OUTGO	1978-79	1979-80	
REVENUE INCOME	15,765.48	16,979.04	
REVENUE EXPENDITURE	13,704.52	15,918.80	

1. ACHIEVEMENTS:

1.1. A significant achievement during the year which deserves special mention has been the extension of full medical care to the families of 1,67,800 employees in 19 implemented centres in Uttar Pradesh with effect from 16th December, 1979. Efforts are being continued to extend full medical care to the remaining 23,800 employees' family units also in Uttar Pradesh presently receiving restricted medical care.

1.2. Other important developments and improvements achieved during the year are as under:

(a) The Corporation approved grant of rehabilitation allowance at sickness benefit rate to disabled insured persons for the period they remain admitted in the artificial limb centre for fixation, repair or replacement of artificial limbs.

(b) The Corporation approved continuance of enhanced sickness benefit payable to insured persons for vasectomy/tubectomy operations as an incentive for family welfare planning, on a permanent basis.

(c) Twelve additional diseases were added to the list of occupational diseases in the III Schedule of the ESI Act, 1948 for grant of employment injury benefit.

(d) The table for determining a lump-sum amount for commutation of periodical payment of permanent disablement benefit under the ESI (General) Regulations, 1950, was revised on the basis of current mortality and interest exprience.

(e) Medical facilities have been extended to the families of insured persons (i) where the insured person works and resides at one station and his family resides at another station which is an implemented centre in the same state, and (ii) where the family members move alongwith the insured person from his place of duty either on leave or on temporary transfer to any other station which is implemented centre in the same State or in a different State.

(f) The Corporation decided to construct convalescent homes in bigger industrial areas for patients who do not require active medical treatment but need minimum medical attention and care.

(g) Artificial limbs, appliances and aids necessary for treatment and rehabilitation of insured persons and their families are being provided as part of medical benefit and the scale of medical benefit has been liberalised by including dialysis, kidney transplant, open heart surgery and provision of cardiac pace-maker as part of medical care available to the beneficiaries of the Scheme.

(h) The system of cash collection of contribution, replacing the contribution stamps, was introduced in the Bihar, Orissa, Gujarat Chandigarh and Tamil Nadu regions and in Pune and Nagpur sub-region.

Implementation in New Areas

1.3 During the year under report, the Scheme was implemented to cover 41 new areas affording protection to about 43,750 additional employees in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Details are given in Appendix I Part A. The families of insured persons in these areas also became entitled to medical benefit from the same date(s) as the insured persons. Efforts were continued for implementation of the Scheme in the States of Jammu & Kashmir, Meghalaya and Tripura and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands where the scheme has not been implemented at any centre so far. At the close of the year, the Scheme was in force at 395 centres in various States and in the Union Territories covering a total number of abou

59,83,000 employees, including those covered in new classes establishments and normal growth during the year in the factories/establishments already covered.

Extension to new classes of establishments

1.4 New classes of establishments were covered in different implemented centres in the States of Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Kerala, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu covering about 3,080 additional employees. Details are given in Appendix I Part B. The families of these employees also became entitled to medical benefit from the same date(s) as the insured persons.

1.5 The State Governments of Haryana, Kerala and Rajasthan issued preliminary notifications giving six months' notice of their intention to extend the Scheme further to the remaining new classes of establishments in the remaining centres.

1.6 The matter about extension of the Scheme to building construction workers in metropolitan cities and towns as approved in principle by the Central Government was continued to be pursued with the State Governments, who are the appropriate Governments for this purpose under Section 1(5) of the ESI Act. There has, however, been no progress in the matter except that Delhi Administration has sought specific approval of the Central Government to the proposed extension.

1.7 In the matter of implementation of the Scheme to new areas and its extension to new sectors of employment in the already implemented centres in every State, the Corporation in consultation with the State Governments concerned formulate annually a two-year phased programme and the State Governments are requested to take speedy action for its implementation. The need to adhere to the phased programme of implementation/extension is emphasised to the State Governments through correspondence as well as through personal discussions with the State Government authorities.

Extension of medical care to families

1.8 Medical care was extended to about 49,250 additional family (insured person) units i.e. about 1,92,400 additional beneficiaries in 41 newly implemented areas in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The details are given in Appendix I Part A. The total number of family (insured persons) units covered for medical care at the close of the year was about 66,38,750 i.e. about 2,65,78,000 beneficiaries including insured persons and their families.

1.9 The implementation/extension of the Scheme has however, not progressed according to the phased programmes mainly due to non-availability of financial and physical resources with the State Governments concerned who have not been able to make necessary medical arrangements. Even where the State Governments themselves gave proposals for extension of the Scheme, they have been often unable to adhere to the programme. Nevertheless, the need for speedy implementation/extension of the Scheme is being emphasised to the State Governments from time to time. Some of the State Governments have also been pleading inadequacy of funds due to the ceiling on expenditure on medical care and pressing for its upward revision before further extension of the Scheme could be undertaken. The question of increase in ceilings on expenditure on medical care is, therefore, under review by a Sub-Committee and it is expected that the pace of extension of the Scheme may gather momentum in the event of the ceilings being enhanced.

2. Proposals for Amendment of ESI Act

The report of the High Powered Sub-Committee on amendments to the ESI Act, together with the Corporation's decision thereon, has been under consideration of the Ministry of Labour. In October, 1979, the Ministry of Labour circulated among all the States/Union Territories and all the central organisations of employers and employees, the proposals for amendments emanating from the recommendations of Sub-Committee (othe than those relating to delegation of powers to the ESI Corporation and the Central Government's financial assistance to the ESI Scheme) and other proposals for amendments, for their comments The Central Government also requested these authorities/organisations to suggest any other amendments which they considered necessary.

3. Hospitalisation

(1) ESI Hospitals and Annexes already commissioned

(i) Two more ESI Hospitals, one at Jaykaypur (Orissa) with 25 beds on 1-8-1979 and one at Mangalore (Karnataka) with 60 beds on 29-11-1979 were commissioned during the year. Additional 10 beds were also commissioned at the ESI Hospital, Mulakunnathkavu (Kerala) on 19-1-1980. In addition, 6 Annexes one at Rampur (Uttar Pradesh) with 24 beds, one at Meerut (Uttar Pradesh) with 12 beds, one at Sonepat (Haryana) with 12 beds, one at Moradabad (Uttar Pradesh) with 24 beds, one at Mirzapur (Uttar Pradesh) with 24 beds and one at Sikohabad (Uttar Pradesh) with 24 beds were also commissioned during the year.

The position with regard to beds constructed in these institutions is as under:—

Type of Project	No. of Projects	No. of beds constracted	
		Genl.	T.B.
Hospitals	67	12,722	1,380
Annexes	33	364	306
Total		13,086 +	1,686
		=	14,772

Details of these Hospitals and Annexes are given in Appendix II.

(ii) ESI Hospitals and Annexes under construction:

The following ESI Hospitals and Annexes were under construction as on 31-3-1980 :—

Sl. No.	Place and State	No. of beds		Remarks
		Genl.	T.B.	
1	2	3	4	5
Hospitals				
1.	Gauhati (Assam)	50	—	
2.	Phulwarisharif, Patna (Bihar)	50	—	
3.	Adityapur (Bihar)	50	—	
4.	Baroda (Gujarat)	200	—	
5.	Surat (Gujarat)	150	—	
6.	Kalol (Gujarat)	50	—	
7.	Rajkot (Gujarat)	50	—	
8.	Mysore (Karnataka)	100	—	

1	2	3	4	5
9.	Indiranagar Bangalore (Karnataka)	300	—	
10.	Kandivalli, Bombay (Maharashtra)	650	—	
11.	Thane, Bombay (Maharashtra)	632	—	
12.	Sholapur (Maharashtra)	120	—	
13.	Vellore (Tamil Nadu)	50	—	
14.	Naini, Allahabad (Uttar Pradesh)	100	—	
15.	Agra (Uttar Pradesh)	100	—	
16.	Ghaziabad (Uttar Pradesh)	100	—	
17.	Lucknow (Uttar Pradesh)	100	—	
18.	Saharanpur (Uttar Pradesh)	50	—	
19.	Kanyapur-Asansol (West Bengal)	—	150	
20.	Bandel (West Bengal)	—	250	
	Total:	2,902	+ 400	=3,302
	Mangalore (Beds under construction in existing hospital)	40	—	
	Grand Total :	2,942	+ 400	=3,342

Annexes

1.	Tinsukia (Assam)	20	—	
2.	Gulbarga (Karnataka)	20	—	
3.	Robertsonepet, KGF (Karnataka)	32	—	
4.	Rajgangpur (Orissa)	16	—	
5.	Sitapur (Uttar Pradesh)	24	—	
6.	Unnao (Uttar Pradesh)	12	—	
7.	Gorakhpur (Uttar Pradesh)	24	—	
8.	Etawa (Uttar Pradesh)	12	—	
	Total:	160	—	

(iii) Hospitals and Annexes sanctioned

The plans and estimates in respect of the following hospitals and Annexes have been sanctioned but the construction work is yet to start:—

Hospitals

Sl. No.	Place and State	No. of beds. Genl.	T.B.	
1	2	3	4	5
1.	Rajahmundry (Andhra Pradesh)	50	—	
2.	Ranchi (Bihar)	50	—	
3.	Kota (Rajasthan)	60	—	
4.	Varanasi (Uttar Pradesh)	50	—	
5.	Thakurpukur (West Bengal)	250	—	
	Total:	460	—	
	Pandunagar, Kanpur (Beds sanctioned in existing hospital)	100	—	
	Grand Total:	560	—	

Annexes

1.	Koilver (Bihar)	—	20	
2.	Pinjore (Haryana)	12	—	
	Total:	12	+ 20	= 32

(iv) Hospitals agreed in principle

The construction of the following ESI Hospitals has been agreed to in principle. In certain cases land has also been acquired/purchased:—

Sl. No.	Place and State	No. of beds	Remarks
1.	ESI Hospital, Hyderabad (Andhra Pradesh)	100	
2.	ESI Hospital, Biharsharif (Bihar)	50	
3.	ESI Hospital, Simaltalla (Bihar)	50	
4.	ESI Hospital, Jhilmil (Delhi)	200	Land already purchased
5.	ESI Hospital, South Delhi (Delhi)	200	Land already purchased
6.	ESI T.B. Hospital, Delhi (Delhi)	150	
7.	ESI Hospital, Bhavnagar (Gujarat)	50	Land already purchased
8.	ESI Hospital, Nadiad (Gujarat)	50	
9.	ESI Hospital, Porbandar (Gujarat)	50	
10.	ESI Hospital, Jamnagar (Gujarat)	50	
11.	ESI Hospital, Petlad (Gujarat)	50	
12.	ESI Hospital, Ahmedabad (Gujarat)	500	
13.	ESI Hospital, Ballabhgarh (Haryana)	100	Land already purchased
14.	ESI Hospital, Gurgaon (Haryana)	50	
15.	ESI Hospital, Bahadurgarh (Haryana)	50	
16.	ESI Hospital, Bhiwani (Haryana)	50	
17.	ESI Hospital, Davangere (Karnataka)	50	Land already purchased
18.	ESI Hospital, Thottada (Kerala)	50	Land already purchased

1	2	3	4	5
19.	ESI Hospital, Palghat (Kerala)	50		
20.	ESI Hospital, Feroke (Kerala)	100	Land already Purchased	
21.	ESI Hospital, Bhopal (Madhya Pradesh)	50		
22.	ESI Hospital, Kolhapur (Maharashtra)	100		
23.	ESI Hospital, Aurangabad (Maharashtra)	50	Land already purchased	
24.	ESI Hospital, Nasik (Maharashtra)	100	Land already purchased	
25.	ESI Hospital, Bibewadi Poona (Maharashtra)	100	Land already purchsaed	
26.	ESI Hospital, Chinchwad Poona (Maharashtra)	100	Land already purchased	
27.	ESI (T.B.) Hospital, Ludhiana (Punjab)	100		
28.	ESI Hospital, Mandi, Govindgarh (Punjab)	50		
29.	ESI Hospital, Phagwara (Punjab)	50		
30.	ESI Hospital, Salem (Tamil Nadu)	50		
31.	ESI Hospital, Bareilly (Uttar Pradesh)	50		
32.	ESI Hospital, Aligarh (Uttar Pradesh)	50		
33.	ESI Hospital, Pipri (Uttar Pradesh)	50		
34.	ESI Hospital, Hardwar (Uttar Pradesh)	50		
35.	ESI Hospital, Jajmau, Kanpur (Uttar Pradesh)	100		
36.	ESI Hospital, Shyam Nagar (West Bengal)	250	Land already purchased	
37.	ESI Hospital, Garden Reach, (West Bengal)	100		
38.	ESI Hospital, Durgapur (West Bengal)	100	Land already purchased	
	Total	3,500		

(v) 201 Employees' State-Insurance dispensaries and one Administrative Medical Officer's Office were located in Corporation's own buildings at the close of the year 45 dispensaries and one Administrative Medical Officer's Office were at the different stages of construction and Plans and estimates in respect of 100 Employees' State Insurance dispensaries have been sanctioned during the year.

(vi) The amount sanctioned as on 31-3-1980 towards capital construction under the ESI Scheme is as under.

Category of the Projects	Amount sanctioned as on 31-3-1979 (Rs. in lakhs)	Amount sanctioned as on 31-3-1980
(a) Hospitals/Annexes/Dispensaries equipment and staff quarters etc,	7733.65	8451.14
(b) Loan to the Government of Maharashtra	362.15	362.15
(c) Grant-in-aid (M.G.M. Hospital, Bombay)	100.00	100.00
(d) Office buildings and staff quarters of the Corporation	748 26	799.15
Total :	8,944 06	9,712.44

4. Type of Medical care of families to employees

The State-wise position in regard to the type of Medical Care provided to family (Employees) Units is given in Appendix III.

COMMITTEES, COMMISSIONS AND CONFERENCES

5. Corporation

The ESI Corporation held two meetings on 22nd December 1979 and 18th February, 1980. Important decisions arrived at these meetings are given in Appendix IV.

6. Standing Committee

The Standing Committee of the ESI Corporation held four meetings on 28 May, 1979, 15th September, 1979, 21st December 1979 and 17th February, 1980. Important decisions arrived at these meetings are given in Appendix V.

7. Medical Benefit Council

The Medical Benefit Council held one meeting on 17-3-1980. Important recommendations of the Council are given in Appendix VI.

8. Regional Boards

At the close of the year, 17 Regional Boards were in position. The number of meetings of various Regional Boards held during the year is given below :—

Name of the Regional Board	Number of meetings	Date of Meeting
1. Andhra Pradesh	2	25-6-79 and 27-9-79
2. Assam	—	—
3. Bihar	1	18-11-79
4. Delhi	1	11-2-80
5. Gujarat	1	8-11-79
6. Haryana	—	—
7. Karnataka	1	20-11-79
8. Kerala	3	30-6-79, 29-9-79 and 31-3-80
9. Madhya Pradesh	1	18-12-79
10. Maharashtra	2	18-10-79 and 15-1-80
11. Orissa	—	—
12. Punjab	—	—
13. Pondicherry	2	19-5-79 and 28-2-80
14. Rajasthan	—	—
15. Tamil Nadu	—	—
16. Uttar Pradesh	2	11-5-79 and 22-9-79
17. West Bengal	—	—

Several Regional Boards did not hold meetings as prescribed, for various reasons. Member secreteries have been asked to assure that meetings of Regional Boards are held regularly.

9. Local Committees

At the close of the year, 207 Local Committees were functioning, under Regulation 10-A of the ESI (General) Regulations, 1950.

10. Medical Service and Allocation Committees

The details of the work done by the Medical Services and Allocation Committee during the year under report is as under :

Sl. No.	Name of the State	No. of Meetings	No. of cases brought on the list	No. of cases pending
1.	Gujarat	8	24	—
2.	Gr. Bombay	N.A.	166	111
3.	West Maharashtra	9	30	4
4.	Punjab	N.A.	55	7
5.	West Bengal	N.A	11	—

11. General Purposes Sub-Committee

During the year under report, General Purposes Sub-Committee of the ESI Corporation visited Madhya Pradesh State from 9th October, 1979 to 13th October, 1979 and inspected various ESI Institutions functioning in the State.

ADMINISTRATION

12. Regional Organisation

15 Regional Offices, 2 sub-Regional Offices, 344 Local Offices, 109 Mini Offices, 1 sub-Local Office and 237 Pay Offices were functioning in the States and the Union Territories as on 31-3-1980

13. Strength of Staff

The total authorised strength of officers, and staff [excluding D (M) D Office/ESI Dispensaries/ESI Hospital] in the Corporation as on 31-3-1980 was 10334 as against 9715 as on 31-3-1979. The staff authorised for HQrs. Office and various Regional Offices as on 31-3-80 is shown in Appendix VII /(Part-I). The staff authorised for the office of D(M) D and ESI Hospital/ ESI Dispensaries, Delhi is shown in Part II of the Appendix VII

14. Confirmation of Staff

Action for confirmation of officers against groups 'A' and 'B' posts has been taken in consultation with the Union Public Service Commission. The confirmation of staff in Groups 'C' and 'D' has been made against the permanently sanctioned posts in most of the Regions/Offices. Action is being taken for confirmation of staff in the remaining offices.

15. Representation of Scheduled Castes & Scheduled Tribes among the Employees of the ESI Corporation

Recruitment to various categories of posts which are required to be filled by direct recruitment or promotion is subject to such reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as is specified from time to time on the basis of directions issued by Central Government. The Information relating to the total number of Corporation employees and the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them, the number of reserved vacancies filled by members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes other than by direct recruitment and the number of reserved vacancies filled by the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes by direct recruitment are indicated at Appendix VIII Parts I, II and III.

16. Progressive use of Hindi in the E.S.I. Corporation

During the year under report, following measures have been taken for the progressive use of Hindi in the Offices of the Corporation :—

1. Progressive use of Hindi at Hqrs. Office and in the Regional Offices is being watched by the Hindi Section at Hqrs. Office.

2. Official Language Implementation Committees are already functioning in all the Hindi and Non-Hindi speaking States and the meetings of these Committees are being held regularly to review the progress of Hindi work and implementation of Instructions issued by the Govt. of India from time to time.

3. A good deal of the correspondence is being done in Hindi, particularly in Hindi Speaking States and most of the letters received in Hindi including appeals, representations etc. from employees are replied to in Hindi.

4. Necessary provision of Hindi typewritiers has been made in all Hindi speaking States. The needs are periodically reviewed. Provision has also been made for at least one Hindi typewriter in every Regional Office situated in non-Hindi speaking states.

5. Most of the forms have been printed bilingually. Arrangements are being made for the translation of Rules and Manuals etc. Translation of E.S.I.C. (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 and the list of major and Minor Heads of Accounts of the Corporation have been finalised and arrangements are being made to get these printed bilingually. Translation of E.S.I.C. Pension Manual has also been completed.

6. During the year under report, 25 Hindi workshop, two each in Hqrs. Office and Regional Office, Jaipur, three each in D(M) D's Office, R.O., Kanpur and R.O. Bombay, four in R.O. Chandigarh and 8 workshops in Regional Office, Indore have been organised. In all 61 workshops have been held so far. Efforts are being made to organize more Hindi workshops. Offices situated in non-Hindi speaking States have also been allowed to organize Hindi workshops on the pattern of workshops set up in Hindi speaking areas, if they so desire.

7. Necessary staff for Hindi work has been provided in the various offices.

8. Arrangements have been made to print question papers (except that of English) bilingually for the recruitment examinations of this Department for open as well as limited (Departmental) tests for recruitment to the posts of L.D.Cs. and promotion tests from L.D.Cs. to U.D Cs. Candidates have the choice to answer questions either in English or in Hindi.

9. So far 11 offices of the Corporation have been notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976 which means that 80% staff of these offices possess working knowledge of Hindi.

10. Original correspondence in Hindi with the offices situated in Hindi speaking States is increasing progressively.

11. Statistical Abstract, Annual Report, Notifications, Budget and Annual Accounts of the Corporation are being issued bilingually. Efforts are being made to issue tender notices, agreements, licences, permits, etc. also bilingually.

12. In order to implement the provisions of Official Languages Rules, check points have been fixed at different levels. Arrangements have been made to issue general orders both in English & Hindi.

13. Almost all the rubber stamps have been made bilingual or separately in Hindi and English

14. Entries in Service Books are being made in Hindi in the Hqrs. Office and in the Regional Offices situated in Hindi speaking areas.

15. Addresses on envelopes being sent to Offices etc. in Hindi speaking regions are being written in Hindi.

16. One lecture relating to Official Languages Policy of the Govt. of India is being delivered in the Training Course of the Corporation for training of L.D.Cs./U.D.Cs./U.D.C. Cashiers.

17. O & M Studies

During the year, the O&M Division finalised the Work-measurement Report on norms and standards for various functionaries in Grade-I Regional Offices. The study was conducted in 3 sample Regional Offices.

Another important study undertaken by the O&M Divisional related to norms and standards for the clerical, para-medical and Group IV employees in ESI Dispensaries in Delhi having more than five doctors. Alongside, work-measurement study was also conducted in the Directorate (Medical), Delhi.

A case study was undertaken in respect of write-off of contributions selecting write-off cases of last three years in a few Regions with a view to identifying the causes for write-off and to suggest improvement.

A Work-measurement study of the various branches in Hqrs. Office of the Corporation and also the Officers of the Medical Division was also conducted.

As desired by the Ministry of Labour, a Forms Review & Control Unit was set up at the Hqrs. Office of the Corporation with a view to rationalising and standardising the various forms in use in the offices of the Corporation. During the year, the Committee reviewed 172 coded forms.

The O & M Division conducted a study of the System of cash collection of contribution in Regional Office, Delhi for the purpose of evolving norms and standards for the functionaries under the cash system. A procedure study was also conducted and a revised procedure was suggested.

In addition to the above, an evaluation study of the Cash Contribution System was undertaken in Delhi, Rajasthan, Karnataka and Andhra Pradesh Regions. As a result of this study it was found that the cash system of collection of contributions was working satisfactorily and it was, therefore, decided to extend this system to all the other States according to a phased programme.

18. Suggestion Award Scheme

The Central Committee which has been set up under the Suggestion Award Scheme to scrutinise the suggestions considered the various suggestions and the Local Office Manager, Kurichy was issued a letter of appreciation for the approach of the Local Office working as a team in submitting the suggestion for modification of Form-6 (Return of Contribution Cards under Regulation 26).

19. Training of Officers & Staff

During the year under report the Central Training Institute and the four Zonal Training Institutes set up at New Delhi, Calcutta, Bombay and Bangalore conducted regular training courses for the Officers and staff of the Corporation. The Central Training Institute conducted 6 Orientation Training Courses for Local Office Managers and Insurance Inspectors at Bombay, Bangalore, Calcutta, Delhi and Jaipur in which 118 officers participated. These Courses which are attended by Field Officers from 4 or 5 neighbouring Regions apart from updating the knowledge of the participants, provided a forum for free discussions and problem solving sessions. In addition, 5 special training courses for the new appointees/promotees to the post of Insurance Inspectors/Managers Gr. II were conducted in January-February, 1980 by Zonal Training Officers in which 89 Officers participated.

In November, 1979, an 'In-Service' Orientation Training Course was organised at New Delhi for the Officers of mid-Management level of the Corporation, which was attended by 20 Dy. Regional Directors/ Accounts Officers/Assistant Regional Directors, etc. Apart from discussions on procedures under the E.S.I. Scheme and related problems, the Officers received lectures on some modern management techniques and on vigilance methods.

For the first time, 2 part-time 'In-Service' training courses for Insurance Medical Officers were conducted one in April, 1979 and the other in February, 1980 at New Delhi and Indore respectively in which 70 Insurance Medical Officers participated.

For Lower Division Clerks/Upper Division Clerks/Cashier/Upper Division Clerks Incharge/Head Clearks, 16 'In-Service' Training Courses were conducted at various centres in which training was imparted to 306 employees. Eight 'Induction' Training Courses for Lower Division Clerks were conducted by the Zonal Training Officers in which 167 employees received the training. In addition, 28 special abbreviated 'Induction' training courses were conducted in different centres which were attended by 615 newly recruited Lower Division Clerks.

Wherever Cash System of Payment of Contributions is being introduced, training courses for 1 or 2 days' duration are being organised by our Training Officers.

During the year under report, training activities were also extended to the Class-IV employees of the Corporation in collaboration with the Shramik Vidyapeeth, Delhi. A training course for Duplicating Machine Operators and a course for Peons/Messengers was organised by the Vidyapeeth in which 9 Class-IV employees of the Corporation participated.

In all, 1324 officers and staff of the Corporation and 70 Insurance Medical Officers received training during the year under report.

TRAINING OF EMPLOYERS' STAFF

To facilitate smooth change-over and to help employers in understanding new System of Payment of Contributions in cash recently introduced in Tamil Nadu, 9 half-day training sessions were conducted at Madras, Coimbatore and Maduari during March, 1980 which were attended by 1,143 representatives of employers.

20. Publicity

The publicity of the Scheme was carried on through the media of press, radio and television and the progress and achievements of the Scheme were highlighted. Talks on the Scheme were broadcast over various stations of All India Radio. Lectures were delivered by the Officers of the Corporation to the workers and trainees at different centres. As a part of educative publicity, the booklet 'You and Your Scheme' specially intended to educate the insured persons in regard to their rights and obligations as also the procedures for claiming benefits, was distributed. The pamphelts on the Scheme and on cash and medical benefits, were revised and brought up-to-date and were under print.

The production of the documentary film on ESI Scheme titled 'Protecting the Workers' with the assistance of the Films Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India was completed and the film was released for public

exhibition during the year. Additional prints of the film were being obtained for use in the Corporation for special publicity among the workers.

With a view to making the employers conscious of their obligation under the ESI Scheme, periodical notices were inserted in the leading newspapers in all the States .

21. Coverage

No. of Employees etc. covered (Appendices IX & X)

Appendices IX and X give particulars regarding coverage under the Scheme (including additional sectors of employment). 67,807 employers stood covered under the scheme as on 31-3-80 as against 61,726 a year back, of these 64,600 employers were in the implemented centres, the corresponding number last year being 59,054 and the remaining 3,207 employers in areas yet to be implemented. The total number of employees in the implemented centres was 59.83 lakhs; the number of employees in the areas yet to be covered was 8.58 lakhs. The number of insured persons entitled to medical treatment was 68.50 lakhs and the number of family (insured persons) units 68.50 lakhs. In all, the total number of beneficiaries (including the insured persons) entitled to medical treatment on 31-3-80 was estimated at 265.78 lakhs.

Definition of the terms 'Employees', 'Insured Persons' and 'Beneficiaries'

(a) The number of the 'employees' as on a specified date is the estimated number of effective posts in the factories/establishments covered under the Scheme. This would broadly represent the average number of employees per day employed by the factories/establishments round about that date and normally may not vary significantly from the number of employees actually employed on that date. It should, however, be noted that the actual number of persons who have occupied a particular sanctioned post during a period may be more, in as much as a leave reserve or badli worker may have officiated temporarily during absence, leave etc. of a regular worker.

(b) The number of 'insured persons' on any date indicates for purposes of this Report, the number of persons who may be deemed to be entitled to medical benefit on such date. Further, the number of 'insured persons' on any day would normally be in excess of the number of 'employees' as on that day because, under the eligibility conditions for medical benefit under the Act the persons entitled to medical benefit on any day would comprise not only the persons actually employed on that day but also the ex-employees, who by virtue of the contribution conditions during the period earlier to that would be entitled to such benefit on that date.

(c) The total number of 'beneficiaries' on any date represents all the persons who may be deemed to be entitled to medical benefit under the Scheme on that date. It comprises the 'insured persons', and where medical benefit has been extended to families of insured persons, the members of their families. The total number of members of the family of insured persons (not including the insured person) is arrived at by assuming an average of 2.88 members, for each 'insured person.'

22. Improvement in standard of medical care. Provision of hospital, beds for in-patient treatment.

During the year 1979-80, 778 additional beds were provided in the following ESI Hospitals/Annexes :--

(i) ESI Hospital, Narod, Ahmedabad	(Gujarat)	25
(ii) ESI Hospital, Mangalore	(Karnataka)	60*
(iii) ESI Hospital, Mulund	(Bombay)	50
(iv) ESI Hospital, Andheri	(Bombay)	50
(v) ESI Hospital, Washi	(Bombay)	200
(vi) ESI Hospital J.K. Pur	(Orissa)	25*
(vii) ESI Hospital, Serampore	(West Bengal)	50
(viii) ESI Hospital, Uluberia	(West Bengal)	50
(ix) ESI Hospital, Manicktola	(West Bengal)	100
(x) ESI Annexe, Gorakhpur	(Uttar Pradesh)	24*
(xi) ESI Annexe, Sitapur	(U.P.)	24*
(xii) ESI Annexe, Rampur	(U.P.)	24*
(xiii) ESI Annexe, Unnao	(U.P.)	12*
(xiv) ESI Annexe, Etawah	(U.P.)	12
(xv) ESI Annexe, Shikohabad	(U.P.)	24*
(xvi) ESI Annexe, Moradabad	(U.P.)	24*
(xvi) ESI Annexe, Mirzapur	(U.P.)	24

Total number of beds provided under the ESI Scheme as on 31-3-1980 was 18,512 @ the details of which are given in appendix XI.

*Newly commissioned Hospitals/Annexes.

@ Total No. of beds in the Statement Employees' State Insurance Corporation at a Glance is 19537. The difference is due to non commissioning of certain constructed beds.

23. During the year under report, percentage of occupancy and the average recurring cost per bed per day in the ESI Hospitals was as under

Sl. No.	Name of the Hospital	No. of Beds Provided				Percentage of occupancy during the year 1979-80	Cost per bed per day during the year 1979-80
		Gen.	Maternity	T.B	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
Andhra Pradesh							
1.	ESI Hospital, Sanathnagar, Hyderabad	235	45	30	310	75%	45.00
2.	ESI Hospital, Sirpur, Kagaznagar	60	—	—	60	72%	52.30
3.	ESI Hospital, Vijayawada	94	—	16	110	78%	50.16
4.	ESI Hospital, Warangal	40	—	10	50	90%	48.79
5.	ESI Hospital, Adoni	40	10	--	50	86%	44.88
6.	ESI Hospital, Visakhapatnam	99	2	9	110	91%	57.50

1	2	3	4	5	6	7	8
	Bihar						
7.	ESI Hospital, Maithon	100	—	—	100	79%	27.89
8.	ESI Hospital, Monghyr	30	—	—	30	57%*	28.37
9.	ESI Hospital, Dalminagar	50	—	—	50	68%	30 03
	Delhi						
10.	ESI Hospital, Basaidarapur	324	76	—	400	90%	62 72@
	Gujarat						
11.	ESI Hospital, Bapunagar, Ahmedabad	500	—	—	500	91%	48 45
12.	ESI Hospital, Naroda, Ahmedabad	—	—	225	225	78%	28 75
	Haryana						
13.	ESI Hospital, Faridabad	188	—	12	200	82%*	32.11
14.	ESI Hospital, Jagadhri	13	—	47	60	58%	46.04
15.	ESI Hospital, Panipat	15	—	35	50	81%	45.00
	Karnataka						
16.	ESI Hospital, Rajajinagar, Bangolore	335	35	44	414	145%	36.22
17.	ESI Hospital, Dandeli	24	—	—	24	125%	20.60
18.	ESI Hospital, Mangalore	60	—	—	60	N.A	N.A.
	Kerala						
19.	ESI Hospital, Mulakunathakavu (Trichur Distt.)	—	—	110	110	86%	20.44
20.	ESI Hospital, Asramam (Quilon Distt.)	97	22	—	119	115%	20.49
21.	ESI Hospital, Alleppey	51	4	—	55	98%	33.23
22.	ESI Hospital, Peroorkada (Trivandrum Distt.)	63	12	—	75	125%	23.54
23.	ESI Hospital, Olarikkara, Trichur	84	6	—	90	71%	20.33
24.	ESI Hospital, Udyogamandal (Ernakulam Distt)	130	25	—	155	47%*	32.33
25.	ESI Hospital, Ernakulam	55	10	—	65	75%	32.31
26.	ESI Hospital, Vadavathoor	59	6	—	65	66%	31.48
27.	ESI Hospital, Parippally	100	—	—	100	123%	21.50
28.	ESI Hospital, Ezhukone	100	—	—	100	109%	22.1
	Madhya Pradesh						
29.	ESI Hospital, (Gen.) Indore	136	20	—	156	73%	30.96
30.	ESI (Chest) Hsopital, Indore	—	—	52	52	100%	21.92
31.	ESI Hospital, Ujjain	65	—	—	65(a)	107%	19.00.
32.	ESI Hospital, Gwalior	75	—	—	75	97%	29.27
	Maharashtra						
33.	M.G.M. Hospital, Bombay	668	17	15	700	94%	73.90
34.	ESI Hospital, Mulund, Bombay	505	145	—	650	98%	58.88
35.	ESI Hospital, Worli, Bombay	435	60	5	500	81%	59.00
36.	ESI Hospital, Ulhasnagar, Bombay	80	20	—	100	93%	68.58@
37.	ESI Hospital, Andheri, Bombay	540	100	10	650	67%	64.35
38.	ESI Hospital, Washi, Bombay	—	—	600	600	69%	41.87
39.	ESI Hospital, Nagpur	170	30	—	200	87%	55.68
40.	ESI Hospital, Aundh, Pune	175	25	120	320	85%	48.00
	Orissa						
41.	ESI Hospital, Choudwar	44	6	—	50	110%	42.30
42.	ESI Hospital, Kansabahal	47	3	—	50	70%	52.86
43.	ESI Hospital, Brajrajnagar	22	3	—	25	60%	79.36@
44.	ESI Hospital, J.K. Pur	20	5	—	25	N.A.	N.A.
	Pondicherry						
45.	ESI Hospital, Pondicherry	50	—	—	50	80%	63.37@

1	2	3	4	5	6	7	8
Punjab							
46.	ESI Hospital, Amritsar.	80	20	—	100(b)	90%	73.75@1
47.	ESI Hospital, Ludhiana	80	20	—	100	82%	25.25
48.	ESI Hospital, Jullundur	80	20	—	100	—	14.00
Rajasthan							
49.	ESI Hospital, Jaipur	108	29	—	137	91%	42.60
Tamil Nadu							
50.	ESI Hospital, Madras	486	100	39	625	66%	48.20
51.	ESI Hospital, Coimbatore	370	100	30	500	75%	35.63
52.	ESI Hospital, Madurai	140	50	12	202	77%	54.65
53.	ESI Hospital, K.K. Nagar, Madras	140	40	26	206	50%*	40.45
Uttar Pradesh							
54.	ESI Hospital, Pandunagar, Kanpur	212	—	—	212	103%	20.92
55.	ESI Hospital (Chest) Azadnagar, Kanpur	—	—	180	180	77%	14.72
56.	ESI Hospital, (Genl. & Mat.) Kanpur	104	40	—	144	139%	33.49
57.	ESI Hospital, Modinagar	76	24	—	100	113%	37.80
West Bengal							
58.	ESI Hospital, Sealdah	212	18	—	230(c)	79%	40.80
59.	ESI Hospital, Kumarhati	172	4	—	176	100%	36 23
60.	ESI Hospital, Baltikuri	264	36	—	300(d)	80%	37. 64
61.	ESI Hospital, Serampore	216	—	—	216	72%	36.76
62.	ESI Hospital, Kalyani	250	—	—	250 (e)	59%*	49.11
63.	ESI Hospital, Ulubaria	216	—	—	216	77%	37.93
64.	ESI Hospital, Ballur-Bally	—	—	150	150	96%	34.86
65.	ESI Hospital, Gaurhati	216	—	—	216	90%	29.78
66.	ESI Hospital, Budge-Budge	210	20	—	230(f)	69%	37 46
67.	ESI Hospital, Manicktola	150	—	—	150	75%	69.87 @

(a) Out of 100 beds sanctioned 65 beds have been commissioned.
(b) Out of 125 beds sanctioned 100 beds have been commissioned.
(c) Out of 250 beds sanctioned 230 beds have been commissioned.
(d) Out of 416 beds sanctioned 300 beds have been commissioned.
(e) Out of 266 beds sanctioned 250 beds have been commissioned.
(f) Out of 300 beds sanctioned 230 beds have been commissioned.
*Hospital having low occupancy. State Government requested to look into the cases.
@Cost per bed per day is high. State Government requested to look into the matter.

24. Particulars in respect of Dispensaries, Specialists Insurance Medical Officers/Insurance Medical Practitioners and Ambulances as on 31-3-80 are shown in Appendix 'XI'.

25. Provision of Artificial Limbs to Insured Persons and their family members.

During the year under report 27 Insured Persons and 6 family members were provided artificial limbs. In all 1020 Insured Persons and 6 family members have been fitted or refitted with artificial limbs so far, under the ESI Scheme.

25.1 Provision of Artificial Dentures to Insured Persons and their family members :

During the year under report, 28 Insured Persons and one family member were provided dentures free of cost. In all, 102 Insured Persons and one family member have been provided with Artificial Dentures so far, under the ESI Scheme.

25.2 Provision of Spectacles to Insured Persons and their family members :

During the year under report, 2981 Insured Persons and 18 family members were provided with spectacles free of cost under the E. S. I. Scheme

26. Family Welfare Activities.

The ESI Corporation in the year 1976 took the responsibility to run Project No. IND/674/P02 sponsored by the International Labour Organisation and funded by UNFPA for augmentation of the ESI Medical Scheme for education, motivation and provision of services for Family Welfare. The Project was sanctioned initially for a period of three years ending on 31-12-1978. On review of its performance in the Tripartite Review meeting held on 25-9-1978 and keeping in view the progress made by it, its activities were extended for another one year i. e., upto 31-12-1978, and subsequently for another period of three months *i.e.*, upto 31-3-1980.

The achievements made under the Family Welfare Project during the year 1979-80 are as under :—

1.	Vasectomy	2,333
2.	Tubectomy	12,663
3.	Total Sterilisation performed	14,996
4.	Interuterine device inserted	4,169
5.	Medical termination of pregnancy	3,458
6.	Nirodh issued	9,75,216
7.	Oral pills distributed	72,689
8.	Equivalent sterilisations	17,42

27. **Immunisation Programme under ESI Scheme**

All India Immunisation Programme under ESI Scheme was launched on 14th November, 1973. The Administrative Medical Officers In-charge of the Scheme were requested to focus special attention on this Programme for providing protection against diseases to the children during the "International Year of the Child—1979-80." During the year under report, over 8.50 lac doses of vaccines/sera etc. were administered to the beneficiaries under the scheme, in the country, bringing the total number of doses administered at the close of the year to over 31.50 lacs.

PROVISION OF MEDICAL BENEFIT

28. **Attendances at Dispensaries and Hospitals and Home visits (Appendices XII & XIII)**

28.1 Statistics relating to (a) the attendance per annum per 1000 insured persons and also per 1000 family (insured person) units (b) the number of home visits in respect of Insured Persons and families and (c) the number of cases (i) admitted in hospitals and (ii) referred for specialist investigations in respect of insured persons are given in these appendices. These figures are based on returns furnished primarily by the dispensaries and panel practitioners. For working out the level of medical attendance, the number of insured persons/family (Insured Person) units attached to the reporting dispensaries/clinics only are deemed to be "exposed."

28.2 During the year under report, the All India rate of new attendance per 1000 insured persons decreased from 2970 in 1978-79 to 2867; the number of old attendance per 1000 insured persons has also registered a decrease from 6856 in 1978-79 to 5893. This year the proportion of old attendance to new has been 2.06 against 2.31 experienced in 1978-79.

28.3 The All India rate of new attendance per 1000 family units decreased from 3476 in 1978-79 to 3245, the number of old attendance per 1000 family units has also decreased from 6818 in 1978-79 to 6286. The proportion of old attendance to new has decreased from 1.96 during 1978-79 to 1.94 in 1979-80.

28.4 The total number of home visits in respect of insured persons has decreased by 14.24% compared to that in 1978-79. However, in respect of families, there is a decrease of 7.86%. The incidence of home visits as measured by the number of visits per 1000 insured persons has shown a decrease from 55 in 1978-79 to 45 in 1979-80.

28.5 The total number of cases admitted in hospitals has shown a decrease from 3,49,023 in 1978-79 to 3,14,539 in 1979-80. The number of cases referred for Specialists investigation has registered an increase from 14,27,617 in 1978-79 to 14,28,381 in 1979-80.

29. **Sickness Pattern (Appendix XIV)**

29.1 Information on the Sickness pattern for the country as a whole expressed as number of new cases per 1000 insured persons, exposed is indicated in this appendix for each of 51 cause groups, separately for the insured workers and members of their families.

29.2 The incidence rates for all cause groups taken together is lower in 1979-80 than in 1978-79 in respect of insured persons and also in respect of their families. For every spell in respect of an insured person, there has been this year 1.132 fresh spells in respect of the members of the family of an insured person as against 1.170 in the year 1978-79. When it is borne in mind that as against one insured person, there are 2.88 family members, the incidence of morbidity, as measured by incidence of new cases, continues to be lower among members of the family of the insured persons when compared with the insured persons themselves.

29.3 Cause group-wise incidence of sickness in respect of insured persons bears a close resemblance to the corresponding rates experienced by members of the family of insured persons for almost all the diseases listed. However, wide deviation in incidence in a few cause groups only, bring out in high relief the peculiar ailments to which the particular group (*viz.* insured persons or families) is comparatively more prone.

30. **Medical Referee**

The following is a detailed statement of Full-time and Part-time Medical Referee posted at the end of the year in the respective states alongwith the number of cases disposed of by them :—

Sl. No.	Name of the State or Union Territory	No. of Medical Referee		No. of cases disposed of during the year 1979-80
		Part-Time	Full-Time	
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	9	—	11286
2.	Assam	5	—	560
3.	Bihar	11	—	9791
4.	Chandigarh Administration	1	—	35
5.	Delhi	—	2	19245
6.	Goa	1	—	146
7.	Gujarat	11	3	51470
8.	Haryana	9	—	4249
9.	Karnataka	17	—	10328
10.	Kerala	7	1	10208
11.	Madhya Pradesh	10	—	11963
12.	Maharashtra			
	(a) Greater Bombay	6	4	23466
	(b) Nagpur Area	7	—	4294**
	(c) Western Maharashtra	7	1	10894

1	2	3	4	5
13.	Orissa	9	—	2262
14.	Pondicherry	1	—	3036
15.	Punjab	14	—	2862
16.	Rajasthan	13	—	4786
17.	Tamil Nadu	3	2	117792
18.	Uttar Pradesh	26	1	@
19.	West Bengal	6	7	31648
	Total:	173	21	330311

**Information received in respect of five Medical Referees only.
@ Figures for the year 1979-80 not received.

31. Expenditure on the Provision of Medical Benefit Payments Authorised to State Governments

During the year under report, a sum of Rs. 60,23,42,106.57 was authorised by the Corporation for payment to the State Governments against its share of the expenditure on the provision of medical benefit under the ESI Scheme. The break-up of the above amount is as under :

YEAR	AMOUNT Rs. P.
Final payment for the year 1967-68	58,139.22
Final payment for the year 1971-72	2,98,645.00
Final payment for the year 1973-74	12,39,323.11
Final payment for the year 1974-75	47,70,506.28
Final payment for the year 1975-76	1,07,29,545.14
Final payment for the year 1976-77	1,54,49,959.50
Final payment for the year 1977-78	2,30,55,847.42
"On Account" payment for the year 1978-79	7,16,63,000.00
Final payment for the year 1978-79	+32,59,140.00
"On Account" payment for the year 1979-80	7,49,22,140.90
	47,18,18,000.00
TOTAL	60,23,42,106.57

32. Measures for Control Over Expenditure on Medical Care

The Corporation has entered into Rate Contract with manufacturers of drugs in respect of more than 500 medicines, injections and drugs during the year under report. The Rate Contracts have been communicated to the State Governments for their operation.

33. Provision of facilities in Ayurvedic system of Medicine in Delhi

The Ayurvedic Dispensaries sanctioned for Delhi (Medical) Scheme are currently located in the premises of existing ESI dispensaries at Kishan Ganj No. II and New Industrial Area.

34. Efficiency in the working of the Local Offices

During the year under report, the Ledger System was in operation in 379 Local Offices out of 440 Local Offices (including Mini-Local Offices) in the country. The Teller System has been operating in 47 Local Offices on an experimental basis.

35. Improvement in the Cash Benefits

The E.S.I. Corporation in its meeting held on 22nd December, 1979 adopted a resolution to grant Rehabilitation Allowance, to the Insured Persons for each day on which they remain admitted in the Artificial Limb Centre for fixation or repair or replacement of Artificial Limbs, at the Standard Benefit rate. This benefit of Rehabilitation Allowance is payable with effect from 1st January, 1980.

36. Other Improvements

36.1 The E.S.I. Corporation in its meeting held on 22nd December, 1979 resolved that Sickness Benefit payable to insured persons for undergoing Vasectomy/Tubectomy operations in pursuance of the Resolution adopted by the Corporation at its meeting held on 16th July, 1976 shall continue to be granted on permanent basis on the same scale and subject to the same conditions as specified in the said Resolution with the change that the number of days for which sickness benefit will be paid for undergoing Vasectomy/Tubectomy operations will be paid in addition to 91 days of ordinary Sickness Benefit admissible to an insured person with effect from 1-5-1977.

36.2 The Standing Committee of the E.S.I. Corporation in its meeting held on 17th February, 1980 has accorded its approval for extending the facility of remittance of Funeral Benefit by Money Order, as in the case of other Cash Benefits, at the cost of the Corporation.

36.3 The Valuer in his Fifth Quinquennial Valuation Report of the Employees' State Insurance Corporation as on 31st March 1974 recommended the revision of the Commutation Table used by the Corporation to arrive at the capitalised value of Permanent Disablement Benefit in commutation cases. For this purpose, the Valuer has based his recommendations on the current Mortality and valuation bases for Permanent Disablement Benefit *viz.* Mortality LIC (1961-64) ULt., rated up by .0025 and interest rate of 6%. The Corporation has accordingly revised the existing Commutation Table under Schedule III to Regulation 76-B of E.S.I. (General) Regulations, 1950. The above revision of the Commutation Table has generally increased the amount of commutable value of Permanent Disablement Benefit to insured persons.

CASH BENEFITS

(Appendices: XVI to XVIII)

37. Number of cash benefit payments (Col. 4 of Appendix XVI)

37.1 Cash Benefit are paid at the local/Miniature/Sub-Local Pay offices set up by the Corporation in different areas. The number of such offices was 691 on 31 March, 1980 as against 684 a year earlier.

37.2 The total number of cash benefit payments made in each state during the years 1978-79 and 1979-80 is shown in column 4. In all, 85.47 lakhs payments (including 10,477 claims relating to lump-sum payments in respect of request for commutation of permanent disablement claims) were effected during the year 1979-80. These were 6.00 lakhs more than those during the preceding year. On the average, 7.12 lakhs payments were effected every month as against 6.62 lakhs payments during 1978-79. The number of payments per employee has increased from 1.43 in 1978-79 to 1.48 in 1979-80.

38. Sickness Benefit (Columns 3 and 6 to 8 of Appendix XVI)

38.1 As a result of the implementation of the benefit provisions of the Scheme in new centres and to new sectors of employment between 1 July, 1978 and 30 June, 1979 and also due to the increase in employment in the already implemented areas, an additional 2.05 lakh employees became eligible for sickness benefit during the year under report. The total number of employees entitled to claim sickness benefit during 1979-80 is estimated at 57.44 lakhs as against 55.39 lakhs last year (vide column 3).

38.2 During the year, an amount of Rs. 42,96.75 lakhs was paid as sickness cash benefit as against Rs. 33,50.41 lakhs in 1978-79.

38.3 The average number of fresh spells per employee during 1979-80 has increased from 0.90 in 1978-79 to 1.00 in 1979-80 ; the average number of benefit days per annum per employee during 1979-80 has also increased from 6.8 in 1978-79 to 7.8 in 1979-80. The amount of daily rate of benefit per employee has increased from Rs. 8 92 in 1978-79 to Rs. 9 54 in 1979-80.

38.4 As in the preceding years this year also witnessed wide variations among the States in respect of incidence and duration of sickness benefit claims. The incidence was high in Bihar, Madhya Pradesh & Tamil Nadu The Director General has been keeping continuous watch over the duration of sickness claims at various centres. The relevant statistics received at the Headquarters every month are analysed periodically, and any abnormal variation in the trend in any centre is taken up with the Regional Directors and Administrative Medical Officers with a view to enabling them to take suitable and prompt remedial measures whenever necessary and possible.

Excessive Sickness Benefit under Section 58 (2)

38.5 The incidence of Sickness Benefit payment to Insured Persons had been found to exceed the All India Average in certain States. The excessive Sickness Benefit for the year 1978-79 has been shared between the Corporation and the State Governments as under :

Sl. No.	Name of the State Govt.	Total Sickness Benefit amount paid (Actual)	Excess over All India Average borne by the State Govt.
1.	Tamil Nadu	Rs. 4,22,67,499	Rs. 15,56,278
2.	Bihar	Rs. 95,32,478	Rs. 5,81,643
3.	Madhya Pradesh	Rs. 1,70,18,638	Rs. 26,69,742

39. *Extended Sickness Benefits* (Cols. 9 & 10 of Appendix XVI)

39.1 Insured Persons suffering from certain specified diseases, e.g. tuberculosis, leprosy, mental and malignant diseases etc. are eligible for Extended Sickness Cash Benefit for an extended period beyond 91 days of sickness benefit.

39.2 For the year 1979-80, a sum of Rs. 325.98 lakhs was paid to insured persons on this account as against Rs. 314.42 lakhs in the previous year.

39.3 The incidence of Extended Sickness Benefit claims expressed as the number of claims per 1,000 employees exposed to risk and also the duration of terminated claims are shown for the years 1978-79 and 1979-80 in columns 9 and 10 of Appendix XVI. The incidence was high in Gujarat & West Bengal.

40. Maternity Benefit (Columns 11 and 12 of Appendix XVI)

40 1 Number of women employees eligible for Maternity Benefit has increased from 4,18,200 in 1978-79 to 4,58,600 in 1979-80. The total amount paid as maternity claims was Rs. 194.91 lakhs, as against Rs. 173.90 lakhs in 1978-79. The average amount of benefit per maternity claims has decreased from Rs. 907 in 1978-79 to Rs. 860 in 1979-80.

40.2 The number of claims per 1000 insured women employees has increased from 45.9 in 1978-79 to 49.4 in 1979-80.

41. Temporary Disablement Benefit (Columns 3 to 6 of Appendix XVII).

During the year 1979-80 the number of employees exposed to employment injury was 58.99 lakhs, as against 56.79 lakhs during 1978-79 (vide col. 3). The sum paid as temporary disablement benefit during 1979-80 was Rs. 693.68 lakhs as against Rs. 645.53 lakhs in 1978 79. The average number of fresh spells and the number of benefit days per employee and the average benefit rate are 0.07, 1.10 and Rs. 10.72 respectively as against corresponding figures of 0.08, 1.13 and Rs. 10.10 in 1978-79 (vide col. 4 to 6). The average duration per spell has increased from 14.23 to 14.66 days. As in the last year, this year also recorded variations in different states in the incidence and duration of these claims. The incidence was high in Gujarat, Madhya Pradesh and West Bengal.

42. Permanent Disablement Benefit (Cols. 7 to 10 of Appendix XVII).

42.1 The number of fresh cases admitted during the year 1979-80 was 15,622 as against 16,532 during the previous year. The incidence per 1000 insured employees decreased from 2.91 in 1978-79 to 2.65 in 1979-80.

42.2 The number of claimants on the Fund increased from 40,096 (revised) at the beginning of the year to 41,736 at the end (vide column 10). The actual amount disbursed as benefit was Rs. 578.70 lakhs (including the commuted amount of Rs. 291.20 lakhs) as against Rs. 608.44 lakhs including the commuted amount of Rs. 359.60 lakhs in 1978-79.

42.3 The Capitalised value of Permanent Disablement Benefit claims in respect of fresh cases admitted during the year was Rs. 650.83 lakhs as against Rs. 638.60 lakhs in 1978-79. The Permanent Disablement Benefit Reserve Fund stood at Rs. 2,005.66 lakhs at the close of the year, the corresponding amount at the beginning of the financial year being Rs. 1862.86 lakhs.

42.4 The number of claimants to Permanent Disablement Benefit who have opted for receipt of commuted value in lieu of periodic payments decreased from 11,751 in 1978-79 to 10,477 in 1979 80.

43. Permanent Disablement Benefit Claims (Appendix XVIII)

43.1 Analysis of 15,622 cases of permanent disablement admitted during the year was made according to (a) the main groups of industry and (b) the incidence of claims per 1000 employees exposed industrywise. As in the last year, the highest number of accidents was recorded in 'Textiles' followed at a distance by 'Engineering' and 'Metallic Minerals'. The incidence is high in 'Textiles'. From a comparison of the corresponding incidence for the year 1978 79 it is observed that the incidence experienced this year bears a close resemblance to that experienced last year in most of the industries.

43.2 The average degree of permanent disablement experienced was 8.37 as against 8.25 as for the last year. The largest number of accidents occurred in the eight wage group *i.e.*, between the daily wages of Rs. 16 and Rs. 24.

43.3 The number of permanent disablement benefit cases that arose among women employees is only 163. The incidence is low presumably because women are not generally employed on hazardous occupations.

44. Dependants Benefit (Columns 11 and 12 of Appendix XVII)

44.1 The number of fresh claims admitted for Dependants' Benefit during the year under review increased from 438 in 1978-79 to 525 (*vide* column 11). The total number of dependants admitted during the year was 1543.

44.2 The category-wise distribution of all the dependants as at the beginning and end of the year is as under—

Description	As on 31st March	
	1979	1980
Widow	5,025	5,437
Son and Daughter	8,324	8,995
Father	752	821
Mother	1,005	1,008
Other dependant children	691	761
Total :	15,797	17,102

44.3 The amount paid as dependants' benefit has increased from Rs. 100.69 lakhs in 1978-79 to Rs. 1,18.59 lakhs in 1979-80. The capitalised value in respect of dependants' benefit claims admitted during the year was Rs. 176.48 lakhs as against Rs. 144.68 lakhs in 1978-79. The dependants' Benefit Reserve Fund stood at Rs. 1,148.83 lakhs on 31st March, 1980 as against Rs. 1,051.07 lakhs on 31st March, 1979).

Contribution Enforcements

45. Income from Contributions :

During the year 1979-80 total amount collected by way of contributions was Rs. 1,59,76,04,161.

46. Mode of Collection of Contributions

The collection of contribution has so far generally been in the form of adhesive ESI Stamps which are sold through the Bankers of the Corporation. However as an experimental measure, collection of contribution by cash system in place of contribution stamps was introduced in Delhi Region w.e.f. 30-11-1975. Encouraged by the experience gained in Delhi Region, where this system was found to be working satifactorily The cash System has further been introduced in Karnataka, Rajasthan, Punjab, Maharashtra (including Pune-Nagpur Sub-region), Tamilnadu, Assam, Andhra Pradesh, Kerala, Bihar, Gujarat, and Orissa Regions. The said system is further being introduced in West Bengal and Madhya Pradesh Regions in the month of July, 1980 whereas in Uttar Pradesh Region, it will be introduced in the month of September, 1980. Thus all Regions would be under the cash system by September, 1980. Besides the above two systems Contributions are also received by frank. During the year 46 new licences were issued and 6 licences cancelled bringing the total number of franking machines in use to 1041 Employers who use Franking Machines are however being encouraged to switch over to the cash system.

47. Inspection

During the year under report, progress of the inspection work continued to be under the close watch of the Headquarters Office. Inspectors continued to provide guidance and training to employers and their staff in maintaining record and complying with the various provisions of the ESI Act, and Regulations framed thereunder.

At the end of the year, there were in all 381 ESI Insurance Inspectors including 55 leave reserve Inspectors. The total number of Inspections conducted during the year was 44,264.

48. Realisation of ESI Arrears :

A total sum of Rs. 2,809.78 lakhs was in arrears against the defaulting employers since 'A' Day upto 31st March, 1980. Region-wise statement showing the comparative position of ESI arrears for the last three years and the factories/establishments which are in default of ESI dues of Rs. 1 lakh and above as on 31-3-1980 are at Appendices XX and XXI respectively.

The realisation of ESI arrears continued to receive special attention of the Corporation and all-out efforts were made to realise these to the maximum extent possible.

49. Employees' Insurance Courts

New Employees' Insurance Courts have been set up in the following States during the year 1979-80.

State	Place
(i) Himachal Pradesh	Solan
(ii) Punjab	Hoshiarpur.

50. Legal Action

The amount involved in respect of Court/Revenue Recovery cases instituted during the year as also the amount recovered under various Sections of the ESI Act, is shown Region-wise in Appendix XIX.

51. Budget and Finance

Budget Estimates 1980-81

The budget Estimates for the year 1980-81 were adopted by the Corporation at its meeting held on 18-2-1980. The approval of the Central Government to these estimates was conveyed on 26-3-1980. The Budget Estimates were laid on the tables of the Lok Sabha and the Rajya Sabha on 28-3-1980.

The following table shows the income and expenditure of the Corporation during the years 1978-79, 1979-80 and Budget Estimates 1980-81.

Head of Account	1978-79	1979-80	1980-81 (Budget Estimates)
			(In lakhs of rupees)
I. INCOME :			
Contributions	1,46,75.94	1,59,76.04	1,62,31.00
Other Income	10,89.54	10,03.00	9,03.70
(Interest on investment of General Cash Balance, Receipts from rents of hospitals, dispensaries and staff quarters and other miscellaneous receipts)			
Total	1,57,65.48	1,69,79.04	1,71,34.70
II. EXPENDITURE			
Benefits to Insured persons and their families :			
A-Medical Benefit	52,87.31	63,59.28	68,72.45
B-Cash Benefits	52,83.32	63,55.23	63,52.47
C-Other Benefits	13.88	17.32	19.44
Administrative Expenses	9,95.03	11,37.56	12,12.44
Other Expenses	21,24.97	20,49.41	19,95.94

[Provision for (1) repairs and maintenance and depreciation of hospitals, dispensaries, office building and staff quarters (2) Contribution to Capital Construction & Emergency Reserve Funds]			
TOTAL	1,37,04.51	1,59,18.80	1,64,52.74

52. Banking Arrangements

During the year, 23 bank accounts were opened for the offices of the Corporation with the branches of the State Bank of India, its Associates and 3 accounts with the Nationalised Banks. 4 Accounts were closed. The total number of bank accounts as on the 31st March, 1980 was 532.

Arrangements for sale of the Employees' State Insurance Contribution Stamps were made with 10 more branches of the State Bank of India and its Associates. Consequent on introduction of the system of collection of contribution through cash in place of contribution stamps in some more regions, sale of stamps by 43 branches has been dispensed with. The total number of bank branches handling the sale of contribution a stamps as on the 31st March, 1980 was 405.

53. Reserve Funds and Investment

The investments of the Corporation pertaining to different funds/Reserve Funds and General Cash Balance as on the 31st March, 1979 and 31st March, 1980, were as under :

Name of Fund/Balance	As on 31-3-79	As on 31-3-80
	(Rupees in lakhs)	
1. ESIC Group Insurance Fund	0.76	4.39
2. ESIC Provident Fund	4,88.55	5,21.25
3. Provident Fund Deposit Linked Insurance Fund	1.08	1.66
4. Compassionate Reserve Fund	0.28	0.26
5. Pension Reserve Fund	8,29.88	9,39.20
6. Depreciation Reserve Fund of Buildings for the offices of the Corporation (including staff quarters)	35.65	40.43
7. Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings	3,98.78	4,61.80
8. Depreciation Reserve Fund of Staff Cars	6.12	6.22
7. Repairs and Maintenance Reserve Fund of Buildings for the offices of the Corporation (including staff quarters)	28.12	26.03
10. Repairs and Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings	5,39.63	5,63.04
11. Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund	18,62.86	20,05.65
12. Dependant's Benefit Reserve Fund	10,51.07	11,48.83
13. Capital Construction Reserve Fund	36,42.89	47,26.24
14. Emergency Reserve Fund	34,94.27	38,91.86
15. Investment of General Cash Balance	1,19,17.73	1,32,48.10
TOTAL	2,42,97.67	2,75,84.96

The amounts under earmarked reserve funds and non-earmarked reserve funds are shown as under :

Earmarked Reserve Funds (including the Capital Construction Reserve Fund)	88,85.67	1,04,45.00
Non-earmarked Reserve Funds (Emergency Reserve Fund and General Cash Balance)	1,54,12.00	1,71,39.96
TOTAL	2,42,97.67	2,75,84.96

The Reserve Fund at Serial Numbers 1 to 12 above are to meet the respective liabilities of the Corporation. Annual accretions to these funds are made on recognised/approval basis/ norms. Yearly contribution to Capital Construction Reserve Fund and Emergency Reserve Fund is made on the following basis.

Capital Construction Reserve Fund

In its meeting held on 2nd February, 1974, the Corporation decided that 10% of the total revenue derived from Employers' and Employees' contribution may be credited to the Capital Construction Reserve Fund for Construction of hospitals/dispensaries/other Medical institutions and office buildings/staff quarters in the ratio of 8 : 2 respectively.

Emergency Reserve Fund

As decided by the Corporation in its meeting held on 17th March, 1973, 20% of the excess of income over expenditure (whole of the excess when it is less than rupees one crore) is to be credited to the Emergency Reserve Fund.

The Funds stand invested as under :

	As on 31-3-79	As on 31-3-80
	(Rupees in lakhs)	
Government Securities	3,14.92	2,35.34
Term Deposits with State Bank of India	2,39,82.75	2,73,49.62
TOTAL	2,42,97.67	2,75,84.96

54. Income and Expenditure Account for 1979-80 and Balance Sheet as at the 31st March, 1980.

The Income and Expenditure Account for the year 1979-80 and Balance Sheet as at the 31st March, 1980, are at Appendix XXII and XXIII, respectively.

55. Audit Report

The Audit Report of the Director of Audit, Central Revenues on the accounts of 1979-80 is awaited.

The Audit Report on the accounts of the Corporation for the year 1978-79 was forwarded by the Director of Audit, Central Revenues, to the Ministry of Labour on the 19th December, 1979. As its meeting held on the 21st December, 1979, the Standing Committee considered the audited accounts and recommended adoption thereof by the Corporation. After adoption by the Corporation on the 22nd December, 1979, the audited accounts were sent to the Central Government on the 31st December, 1979. These were laid on the tables of Lok Sabha, and Rajya Sabha on the 24th January, 1980 and 29th January 1980 respectively.

56. Relative Cost of Administration

The Statement of Appendix XXIV shows the relative cost of administration since the year 1974-75. Information regarding the number of ESIC staff per lakh insured employees, number of cash benefit payments per ESIC employee and the comparative cost of administration during the years from 1975-76 to 1979-80 with reference to cost of cash and medical benefits and amount of contributions collected is given below :

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1. No. of ESIC staff per lakh insured employees.	154	160	168	167	173
2. No. of cash benefit payments per ESIC employee.	635	656	770	818	827
3. Contribution collected per ESIC employee.	Rs. 95,872	Rs.1,42,621	Rs. 1,41,355	Rs. 1,51,065	Rs. 1,54,597
4. Percentage of Administrative expenditure in relation to cash and medical benefits.	13.59%	12.38%	10.98%	9.40%	8.93%
5. Percentage of Administrative expenditure in relation to contrition	10.24%	6.98%	7.24%	6.78%	7.12%

APPENDIX-I

Extension of Employees' State Insurance Scheme during 1979-80

Part —A—Implementation in new areas.

State	Centre/Area	Date of implementation	No. of employees (provisional figure)	Medical care for families	
				Date of extension	No. of families (I.P.) units covered.
1	2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	Ramachandrapuram &Pattancheru	29-4-79	2,000	29-4-79	2,200
Bihar	Kandra	24-6-79	1,300	24-6-79	1,500
	Govindpur	13-1-80	2,400	13-1-80	2,750
	Jasidih (Deoghar)		1,500		1,750
	Sakchi and		1,000		1,150
	Mango		2,500		2,900
Gujarat	Junagadh	15-7-79	2,800	15-7-79	3,150
	Nandesseri	18-11-79	1,300	18-11-79	1,450
	Tunki, Singanpore, Dabholi, Ved & Phulpada (Extended Municipal limits of Surat)	19-1-80	750	19-1-80	850
Karnataka	Gokak	16-3-80	100	16-3-80	100
Kerala	Kozhukully	15-7-79	50	15-7-79	50
	Kanakkari	2-12-79	—	2-12-79	—
	Kanayannur & Mulanthuruthy	23-12-79	400	23-12-79	400
	Kasargod &	3-2-80	400	3-2-80	400
	Hosdrug		300		300
Madhya Pradesh	Sanawad	16-9-79	500	16-9-79	550
Maharashtra	Surrounding area of Poona.	1-4-79	400	1-4-79	450
Orissa	Sambalpur	22-4-79	2,500	22-4-79	2,650
	Balasore	2-9-79	1,500	2-9-79	1,600
	Jagatpur	21-10-79	1,000	21-10-79	1,050
	Kalarpur & Pandara	11-11-79	2,800	11-11-79	3,100
Punjab	Asron & Rail-majra	24-2-80	2,000	24-2-80	2,500
Rajasthan	Mastaya Indl. Area, Alwar.	24-6-79	2,000	24-6-79	2,450
	Falna Indl. Area	23-12-79	1,950	23-12-79	2,400
	Kanakpura	30-3-80	150	30-3-80	200
Tamilnadu	Arkonam, Sankari & Thanjavur	21-10-79	2,800	21-10-79	3,100
Uttar Pradesh	Partapur (Meerut)	29-4-79	1,500	29-4-79	1,650
	Barabanki	10-6-79	1,000	10-6-79	1,100
	Akbarpur	16-9-79	1,150	16-9-79	1,250
	Rishikesh	25-11-79	4,500	25-11-79	4,950
	Khurja	10-2-80	1,200	10-2-80	1,300
			43,750		49,250

APPENDIX-I

Part—B—Extension of E.S.I. Scheme to New Classes of Establishments

State	Centre	Date of Extension	Establishments covered	No. of employees (Provisional estimated figure)	Medical care to families (Date of Extension)
1	2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	Anthergaon, Basanthnagar outskirts of Rajahmundry, Outskirts of Cuddapah, Sriramnagar, Gopalpatnam, Outskirts of Guntur.	20-2-80	1. Power using factories employing 10-19 persons; 2. Non-power using factories employing 20 or more persons; 3. Hotels, Restaurants, Shops, Road Motor Transport Establishments, Cinemas including preview theatres and Newspaper Establishments employing 20 or more persons.	90	20-2-80
Himachal Pradesh	Solan	25-8-79	—do—	160	25-8-79
Kerala	Outskirts of Feroke, Palghat and Trichur. Revenue villges of Kizhakkambalam and Aikkarnad North in Ernakulam District.	4-11-79	—do—	160	4-11-79
Punjab	Mohali, Dinanagar, Moga and Jagatjit Nagar.	1-2-80	1. Power using factories employing 10-19 persons; 2. Non-power using factories employing 20 or more persons; 3. Hotels, Restaurants, Shops, Road Motor Transport Establishments, Cinemas including preview theatres and Newspaper establishments employing 20 or more persons.	565	1-2-80
Rajasthan	Chittorgarh.	27-10-79	—do—	1,750	27-10-79
Tamilnadu	The areas within the limits of revenue villages of Vanapadi Narasingapuram, Maniambattu, Lalapet and Mugundarayapuram in Wallajah Taluk, North Arkot District.	30-9-79	1. Power using factories employing 10-19 persons; 2. Non-power using factories employing 20 or more persons; 3. Shops, Hotels, Restaurants, Cinemas including preview theatres and Newspaper establishments employing 20 or more persons.	360	30-9-79

APPENDIX-II

ESI Hospitals and Annexes

Hospitals

Sl. No.	State	Place	No. of beds		Remarks
			Genl.	T.B.	
1	2	3	4(i)	4(ii)	5
(i)	Andhra Pradesh	Hyderabad	310	—	
(ii)	-do-	Sirpur-Kagaznagar	110	—	
(iii)	-do-	Visakhapatnam	110	—	
(iv)	-do-	Adoni	50	—	
(v)	-do-	Warrangal	50	—	
(vi)	-do-	Vijaywada	100	10	

1	2	3	4(i)	4(ii)	5
(vii)	Bihar	Maithon	110	—	
(viii)	-do-	Monghyr	30	—	
(ix)	-do-	Dalmianagar	72	—	
(x)	Delhi	Delhi	400	—	
(xi)	Gujarat	Naroda, Ahmedabad	—	200	
(xii)	-do-	Bapunagar, Ahmedabad	500	—	
(xiii)	Haryana	Faridabad	188	—	
(xiv)	-do-	Yamunanagar	60	—	
(xv)	-do-	Panipat	15	35	
(xvi)	Kerala	Mulakunathakavu	—	110	
(xvii)	-do-	Asramam	115	—	
(xviii)	-do-	Alleppey	55	—	
(xix)	-do-	Peroorkada	75	—	
(xx)	-do-	Trichur	90	—	
(xxi)	-do-	Udyogmandal	150	—	
(xxii)	-do-	Ernakulam	65	—	
(xxiii)	-do-	Vadavathur	65	—	
(xxiv)	-do-	Paripally	100	—	
(xxv)	-do-	Ezhukone	150	—	
(xxvi)	Karnataka	Rajajinagar, Bangalore	380	40	
(xxvii)	-do-	Dandeli	50	—	
(xxviii)	-do-	Mangalore	60	—	Commissioned on 29-11-79 and facilities for 40 more beds are under construction.
(xxix)	Madhya Pradesh	Indore	150	—	
(xxx)	-do-	Indore	—	75	
(xxxi)	-do-	Ujjain	85	15	
(xxxii)	-do-	Gwalior	75	—	
(xxxiii)	Maharashtra	MGM Bombay	700	—	
(xxxiv)	-do-	Worli	550	—	
(xxxv)	-do-	Nagpur	200	—	
(xxxvi)	-do-	Mulund	110	540	
(xxxvii)	-do-	Aundh	410	—	
(xxxviii)	-do-	Ulhasnagar	200	—	
(xxxix)	-do-	Andheri	650	—	
(xl)	-do-	Washi	650	—	
(xli)	Orissa	Choudwar	50	—	
(xlii)	-do-	Kansabahal	50	—	
(xliii)	-do-	Brajrajnagar	50*	—	
(xliv)	-do-	J.K. Pur	25	—	Commissioned on 1-8-79.
(xlv)	Pondicherry	Pondicherry	50	—	
(xlvi)	Punjab	Amritsar	125	—	
(xlvii)	-do-	Ludhiana	80	—	
(xlviii)	-do-	Jullundur	100	—	
(xlix)	Rajasthan	Jaipur	139@	—	
(l)	Tamilnadu	Madras	625	—	
(li)	-do-	Coimbatore	500	—	
(lii)	-do-	Madurai	177	25	
(liii)	-do-	South Madras	500£	—	
(liv)	Uttar Pradesh	Kanpur (Genl.)	212	—	
(lv)	-do-	Kanpur (Chest)	—	180	
(lvi)	-do-	Kanpur (Women & Children)	144	—	
(lvii)	-do-	Modinagar	100	—	

1	2	3	4(i)	4(ii)	5
(lviii)	West Bengal	Kamarthatti	175	—	
(lix)	-do-	Belur Bally	—	150	
(lx)	-do-	Serampore	216	—	
(lxi)	-do-	Uluberia	216	—	
(lxii)	-do-	Baltikuri-Bankra	416	—	
(lxiii)	-do-	Kalyani	266	—	
(lxiv)	-do-	Sealdah	250	—	
(lxv)	-do-	Gourhati	216	—	
(lxvi)	-do-	Budge-Budge	300	—	
(lxvii)	-do-	Manicktolla	500	—	
		Total :	12,722 +	1,380 =	14,102

*Includes 25 beds under construction.
@ Includes 26 beds under construction.
£ Includes 294 beds under construction.

ANNEXES

1	2	3	4(i)	4(ii)	5
(i)	Andhra Pradesh	Errumnuma	—	24	
(ii)	Bihar	Itki	—	20	
(iii)	Haryana	Faridabad	—	12	
(iv)	do	Hissar	12	—	
(v)	do	Sonepat	12	—	Commissioned on 24-1-79
(vi)	Himachal Pradesh	Dharampur	—	12	
(vii)	Karnataka	Bangalore	—	32	
(viii)	Kerala	Pulayanarkota	—	24	
(ix)	Maharashtra	Nagpur	—	25	
(x)	Orissa	Choudwar	—	12	
(xi)	Punjab	Amritsar	—	12	
(xii)	Chandigarh	Chandigarh	40	—	
(xiii)	Rajasthan	Jaipur	—	15	
(xiv)	do	Bari-Udaipur	—	16	
(xv)	do	Pali	12	—	
(xvi)	do	Bhilwara	24	—	(12 under Constn.)
(xvii)	do	Jodhpur	20	—	
(xviii)	do	Sriganganagar	12	—	
(xix)	do	Kota	24	—	
(xx)	do	Udaipur	12	—	
(xxi)	do	Bharatpur	24	—	(12 under Constn.)
(xxii)	Tamilnadu	Sivakasi	12	—	
(xxiii)	do	Tambaram	—	52	
(xxiv)	do	Koilpatti	32	—	
(xxv)	do	Lalgudi	10	—	
(xxvi)	do	Nagarcoil	—	26	
(xxvii)	do	Cauverynagar	10	—	
(xxviii)	Uttar Pradesh	Modinagar	—	24	
(xxix)	do	Rampur	24	—	Commissioned on 15-6-79
(xxx)	do	Meerut	12	—	Commissioned on 2-10-78
(xxxi)	do	Moradabad	24	—	Commissioned on 2-10-79
(xxxii)	do	Mirzapur	24	—	Commissioned on 20-6-79
(xxxiii)	do	Shikohabad	24	—	Commissioned on 3-8-79
		Total :	364 +	306 =	670

APPENDIX-III

Type of Medical Care to Employees' Family Units as on 31-3-1979 and 31-3-1980

Sl. No.	Name of the State	Restricted Care		Expanded Care		Full Care	
		31-3-79	31-3-80	31-3-79	31-3-80	31-3-79	31-3-80
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Andhra Pradesh	—	—	700	700	2,34,300	2,39,300
2.	Assam	—	—	—	—	29,000	32,000
3.	Bihar	—	—	85,700	1,02,200	39,300	37,800
4.	Chandigarh	—	—	14,000	14,300	—	—
5.	Delhi	—	—	—	—	2,45,000	2,65,000
6.	Gujarat	—	—	1,45,000	1,55,100	3,90,000	3,94,900
7.	Haryana	—	—	—	—	1,76,000	1,94,000
8.	Himachal Pradesh	—	—	900	1,200	—	—
9.	Karnataka	—	—	69,000	73,500	2,17,000	2,26,300
10.	Kerala & Mahe	—	—	—	—	3,07,000	3,08,000
11.	Madhya Pradesh	—	—	2,100	—	1,67,900	1,60,000
12.	**Maharashtra :**						
	(a) Bombay Area	—	—	—	—	11,46,000	11,46,000
	(b) Goa Area	—	—	—	—	19,000	19,500
	(c) Nagpur Area	—	—	35,000	31,100	39,000	43,900
	(d) Poona Area	—	—	54,000	52,500	1,81,000	1,92,500
13.	Orissa	—	—	—	—	92,000	1,09,000
14.	Pondicherry	—	—	—	—	15,000	15,000
15.	Punjab	—	—	—	—	1,56,000	1,65,000
16.	Rajasthan	—	—	—	—	1,15,000	1,24,000
17.	Tamil Nadu	—	—	1,25,300	—	3,19,700	4,50,000
18.	Uttar Pradesh	2,40,000	23,800	—	—	1,95,000	4,21,200
19.	West Bengal	—	—	5,95,000	6,31,600	3,70,000	3,53,400
	Total :	2,40,000	23,800	11,26,700	10,62,200	44,49,200	48,97,000

APPENDIX IV

Important decisions taken by the Employees' State Insurance Corporation during the year 1979-80

22 December, 1979 :

(1) The Corporation adopted the following resolution:

"Resolved that the sickness benefit payable to insured persons under the ESI Act for undergoing vasectomy/tubectomy operations in pursuance of the resolution adopted by the Corporation at its meeting held on 16th July, 1976, shall continue to be granted on permanent basis on the same scale and subject to the same conditions as specified in the above mentioned resolution with the change that the number of days for which sickness benefit will be paid for undergoing vasectomy/tubectomy operations will be in addition to 91 days of ordinary sickness benefit admissible to an insured person w.e.f. 1-5-1977."

(2) The Corporation finally approved the addition of following diseases to the list of occupational diseases in the Third Schedule of the ESI Act, 1948, for the purposes of grant of employment injury benefits under the ESI Act:—

PART A

Occupational diseases	Employment
(i) Poisoning by tricresyl phosphate.	Any employment involving the use or handling of, or exposure to the fumes of, or vapours containing tricresyl phosphate.
(ii) Poisoning by diethlene dioxide (dioxan).	Any employment involving the use or handling of, or exposure to the fumes of, or vapours containing diethlene dioxide (dioxan).
(iii) Poisoning by nickel carbonyl.	Any employment involving the exposure to nickle carbonyl gas.

PART B

Occupational diseases	Employment
(i) Non-infective dermatitis of external origin (including chrome ulceration of the skin but excluding dermatitis due to ionising particles of electromagnetic radiation other than radiant heat).	Any employment involving exposure to dust, liquid, or vapour or any other external agent capable of irritating the skin (including friction or heat but excluding ionising particles or electromagnetic radiation other than radiant heat).
(ii) Noise induced hearing loss.	Any employment involving exposure to high noise level over a prolonged period.
(iii) Poisoning by Dinitrophenol or a homologue or by substituted dinitrophenol or by the salts of such substances.	Any employment involving the use or handling of, or exposure to the fumes of, or vapour containing, dinitrophenol or a

	homologue or substituted dinitrophenols or the salts of such substances.
(iv) Poisoning by beryllium or a compound of beryllium.	Any employment involving the use of handling of, or exposure to the fumes dust or vapour of, beryllium or a compound of beryllium, or a substance containing beryllium.
(v) Poisoning by cadmium.	Any employment involving exposure to cadmium fumes.
(vi) Primary neoplasm of the epithelial lining of the urinary bladder (Popilloma of the bladder) or of the epithelial lining of the renal pelvis or of the epithelical lining of the ureter.	(a) Any employment involving the use or handling of, or exposure to any of the following substances: (i) Beta-napthylamine and its salts. (ii) Benzidine and its salts. (iii) 4-amino diphenyl and its salts. (iv) 4-nitro diphenyl and its salts. (v) Alpha napthylamine and its salts. (vi) Ortho tolidine and its salts. (vii) Dianisidine and its salts. (viii) Dichlorobenzidine and its salts. (ix) Auramine. (x) Magneta. (b) Maintenance or cleaning of any part of machinery used for the production, handling or processing of any substances mentioned in (a) above. (c) Cleaning of any clothing used by workers working with any substances mentioned in (a) above in a laundry which forms a part of the place of employment.

PART C

Occupational diseases	Employment
(i) Byssinosis.	Any employment in any room where any process upto and including the cording process is performed in factories in which the spinning or manipulation of raw or waste cotton or of flax is carried on.
(ii) Farmer's lung-Pulmonary disease due to the inhalation of the dust of mouldy hay or of other mouldy vegetable produce and characterised by signs and symptoms attributable to a reaction in the peripheral part of the broncho pulmonary system and giving rise to a defect in gas exchange.	Any occupation involving exposure to the dust of mouldy hay or other vegetable produce by reason of employment :— (a) in agriculture, horticulture or forestry; or b) loading or unloading or handling in storage of hay or other vegetable produce; or (c) handling bagasse.
(iii) Pneumochoniosis.	Any employment, provided that the condition is diagnosed and confirmed by the competent medical authority.

3. The Corporation finally approved the addition of "Monoplegia" in the list of diseases for extended sickness benefit in sub-clause (iii) of Regulation 98 and sub-regulation (3) of Regulation 103-A of ESI (General) Regulations, 1950.

4. The Corporation approved amendment of Forms 8, 9, 10 and 11 in the ESI (General) Regulations, 1950 so as to incorporate the following caution note on the top of each of the forms:—

"Deposit this certificate within 3 days with Local Office to avoid possible loss of benefit under Regulation 64."

5. The Corporation approved amendment of Form 2 in the ESI (General) Regulations, 1950 substituting the Column "Date of appointment" for the existing Column "Shift if any."

6. The Corporation approved amendment of Schedule III Commutation values for Permanent Disablement Benefit under Regulation 76-B of the ESI (General) Regulations, 1950, so as to substitute the existing Schedule III by the following:—

SCHEDULE III

Commutation Values for Permanent Disablement Benefit Regulation 76-B

Age last birthday of insured person on the date on which the application for commutation is received in the appropriate office	The factor with which the daily rate of benefit is to be multiplied
17 years and below	5690
18 years	5670
19 years	5660
20 years	5640
21 years	5620
22 years	5600
23 years	5580
24 years	5560
25 years	5540
26 years	5520
27 years	5480
28 years	5460
29 years	5420
30 years	5390
31 years	5360
32 years	5320
33 years	5280
34 years	5240

35 years	5200
36 years	5160
37 years	5110
38 years	5070
39 years	5020
40 years	4970
41 years	4910
42 years	4860
43 years	4800
44 years	4740
45 years	4670
46 years	4610
47 years	4540
48 years	4470
49 years	4400
50 years	4330
51 years	4250
52 years	4180
53 years	4100
54 years	4020
55 years	3930
56 years	3850
57 years	3760
58 years	3670
59 years	3590
60 years	3500
61 years	3400
62 years	3310
63 years	3220
64 years	3130
65 years	3030
66 years	2940
67 years	2850
68 years	2750
69 years	2660
70 years	2570
71 years	2470
72 years	2380
73 years	2290
74 years	2200
75 years	2120
76 years	2030
77 years	1950
78 years	1860
79 years	1780
80 years	1700

7. The Corporation approved the proposal for grant of rehabilitation allowance to the disabled persons who go to the Artificial Limb Centre for fixation or repair or replacement of artificial limb(s) and resolved as under :—

"Resolved in terms of Rule 23-A of ESI (Central) Rules, 1950 read with clause (xl) of Section 28 of the ESI Act that the Corporation may grant rehabilitation allowance subject to such proof as the Corporation may require in writing to the Insured Person for each day on which he remains admitted in the Artificial Limb Centre for fixation or repair or replacement of limb. The rehabilitation allowance will be granted at the following rate :—

(i) Where the Insured person is eligible to sickness benefit during the period of stay at Artificial Limb Centre, this allowance may be paid at sickness benefit rate.
(This period shall not be adjusted against the period for which sickness benefit is admissible under Section 47 of the ESI Act.) ;

(ii) Where the Insured Person is not eligible to the sickness benefit during the period of stay at Artificial Limb Centre the allowance may be paid at sickness benefit rate, last payable or applicable as per records of local office/Regional office ; and

(iii) Where the period of stay in the Artificial Limb Centre is before the start of the first benefit period of the Insured Person the allowance may be paid at the standard benefit rate corresponding to the daily average wages on the basis of which the contribution rate for the first contribution period is determined.

8. (i) The Corporation decided that with effect from 1-1-79, the limit of expenditure on provision of initial equipments in the ESI Hospitals, laid down in 1973 should be raised as under :

1. Upto 150 beds	from Rs. 5,000 to Rs. 8,000 per bed
2. From 151 to 300 beds	from Rs. 4,000 to Rs. 6,500 per bed
3. From 301 and above	from Rs. 3,500 to Rs. 5,500 per bed

(ii) The Corporation also decided that the initial equipment in annexes/detention wards/oridinary wards attached to the ESI Dispensaries may be provided upto Rs. 3,500 per bed.

(iii) The Corporation approved that the limit of expenditure on provision of additional equipment (replacement of costly equipment like X-Ray machine, addition of new department in the hospital etc.) in commissioned hospital which was laid down in 1973, may be raised from Rs. 2 lacs to 4 lacs.

(iv) The Corporation revised the ESI Ayurvedic formulary for use in the ESI Medical Institutions where Ayurvedic System of medicines is in vogue.

(v) The Corporation also approved the provision of P.B.X. Telephone facility for hospitals having 200 or more beds and inter-cum-telephone facility for smaller hospitals.

9. The Corporation decided to enhance the power of the the State Governments to re-imburse the expenditure incurred by the I.Ps. on medical care from Rs. 500 to Rs. 1,000 per case.

10. The Corporation accepted the recommendations of the Standing Committee and adopted the operative parts of the Fifth Quinquennial Valuation Report as on 31st March, 1974. The Corporation, however, decided that general recommendations of the Valuer contained in Part IV (Section I) of his report would be looked into by a Sub-Committee. The Sub-Committee shall submit its recommendations to the Corporation.

APPENDIX V

Important decisions taken by the Standing Committee of the Employees State Insurance Corporation during the year 1979-80

A—28 May, 1979

(1) The Standing Committee authorised the Director General to decide about the need for setting up of a Sub Regional Office in any area with reference to the size of insured population, geographical distance and other relevant factors.

B—21 December, 1979

(1) The Standing Committee authorised the Director General to relax the provisions of Rule 217(1) of Central Treasury Rules to allow disbursement of pay and allowances earlier than the prescribed date for disbursement of pay and salaries in exceptional cases subject to report to Standing Committee at its meeting held after the month in which relaxation is allowed.

(2) The Standing Committee approved certain measures of economy like reduction in the use of petrol and paper, curtailment in the expenditure on contingencies etc. as a part of an over all climate of austerity in the organisation.

(3) The Standing Committee accepted the proposal to delegate full powers to Director General subject to adherence to hiring procedure to pay advance for hiring accommodation for the offices of the Corporation and to settle terms for its adjustment/refund.

C—17 February, 1980:

(1) The Standing Committee approved the payment of Funeral Benefit by Money Order at the cost of the Corporation if opted by the claiment. Instructions in this regard have come into effect from 17-4-1980.

(2) The Standing Committee decided to appoint a Tripartite Committee comprising the Additional Secretary Shri R.K.A. Subramanya, Shri N. S. Rao, Employers' Representative and Shri G.V. Chitnis Employees' Representative to appraise the Staff Training Scheme of the Corporation.

APPENDIX VI

Important decisions of the Medical Benefit Council during the year 1979-80

17th March, 1980

1. The Medical Benefit Council approved the revised Pharmacopoeia as recommended by its Sub-Committee and recommended its circulation to E.S.I. Institutions and adoption by the Corporation.

2. The Medical Benefit Council recommended that the existing decision of the E.S.I. Corporation to provide facilities for treatment to the beneficiaries in systems other than Allopathy in the following cases should continue:

(i) Where there is a demand from a substantial no. of workers for that system ; and

(ii) Where the State Government has recognised the qualifications in such system.

The Council further recommended that in no case Intermixing of two systems should be allowed.

3. The Council recommended the following measures to bring about improvement in services:—

(a) Priority be given to improve the basic specialities of Medicine, Surgery, Paediatrics, Orthopaedics and Obstetrics and Gynaecology. Next priority should be to improve the specialities of Opthalmology and E.N.T.

The Medical Benefit Council further recommended that the super specialities existing in the Teaching hospitals may be used for the E.S.I. beneficiaries.

(b) The Council also recommended that the Yardstick for provision of Ambulance vans under the E.S.I. Scheme should be revised as under:

(i) For Centres having less than 10,000 but more than 7,000 employees.	Smaller type of vehicle like Matadore etc. which can be used as an ambulance.
(ii) For Centres having 10,000 or more employees.	One ambulance
(iii) For Centres having 30,000 or more employees.	Two ambulances
(iv) For Centres having 60,000 or more employees.	Three ambulances
(v) For Centres having 1,00,000 employees.	Four ambulances
(vi) For Centres having more than 1 lac employees.	One extra ambulance for every 50,000 employees.

The maximum staff permissible for one ambulance van should be three drivers and six cleaners-cum-stretcher bearers per vehicle to ensure round the clock utilisation.

(c) Improvement in Specialist Services:

(i) One specialist each in orthopaedics and Pediatrics should be provided even in a smaller ESI Hospital including 50 bedded hospitals.

(ii) For centres having less than 20,000 family units and for every 20,000 family units or part thereof the no. of sessions in respect of part-time specialists in medicine and paediatrics may be increased from 2 sessions per week to 3 sessions per week.

(iii) Services in the Specialists centres for the speciality of skin and sexually transmitted diseases may be increased from one session per week to two sessions per week for less than 20,000 family units and for every 20,000 family units and part thereof.

(iv) The remuneration of part-time specialists may be revised from Rs. 125/- per month for one session in a week to Rs. 200/- per month and Rs. 100/- may be paid for every additional session upto a maximum of Rs. 1,000/- per month.

(d) Provision of staff for ESI Annexes:

One Medical Officer and minimal para-medical staff be provided in each E.S.I. Annexe. A small medical store should be attached to each annexe.

(e) Radiology, Laboratory Services etc. during the night.

In the E.S.I. Hospitals where services of Laboratory, X-ray department, Sterilisation department, ECG room etc., are being provided throughout the night, minimal no. of para-medical staff (the technicians/assistants) may be provided over and above the norms for night duty.

(f) Establishment of Part-time ESI Dispensaries should be discouraged. A Mini-ESI Dispensary may be set up for about 500 Insured Persons family unit.

(g) The State Governments may be requested to:

(i) implement the norms and standards laid down by the Corporation.

(ii) to fill up the existing vacant posts of Medical Officers and specialists in ESI Hospitals and Dispensaries.

(iii) to provide diet in ESI Hospital as per approved standards.

(iv) to provide drugs and medicines to ESI Institutions as per approved pharmacopoea.

(v) to carry out periodic inspection of dispensaries specialist centres and ESI hospitals to ensure that standards are maintained, complaints taken note of and remedial steps taken expeditiously.

4. The Medical Benefit Council recommended that the reservation charges in Government/State Government/Private hospitals for the use of the E.S.I. Beneficiaries may be allowed up to Rs. 25/- per day per occupied bed.

5. The Council also recommended that payment for the supply of special medicines by the Employers' Utilisation dispensaries may be increased from Rs. 6/- to Rs. 15/- per Insured Person Family unit per annum.

APPENDIX

PART

ESI Staff Authoried

Sl. No.	Designation of posts	Hqrs.	Andhra Pradesh		Assam		Bihar		Delhi		Gujarat		Tamil Nadu	
			RO	LO	RO	LO	RO	LO	RO	LO	RO	LO	RO	LO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Director General	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Insurance Commissioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Financial Adviser & Chief Accounts Officer	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Medical Commissioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	Actuary	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Director (Administration)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Regional Dy. Medical Commr.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Jt. Insurance Commissioner/Regional Director Gr. I	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9.	Director (O & M)/Regional Director Gr. II/ Director (P&D)/Director Vigilance	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10.	Administrative Officer/DIC/RD Gr. III/Dy. CAO/JRD/Vigilance Officer/Asstt. Actuary	11	—	—	—	—	1	—	1*	—	—	—	1	—
11.	Dy. Medical Commissioner/Medical Referee	4	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	4	—
12.	RD Gr. IV/Dy. Admn. Officer/Accounts Officer/Dy. RD/Asstt. Director (P&D)	10	4	—	1	—	2	—	5	—	8	—	7	—
13.	Asstt. RD/Mgr. Gr. I/Dy. ACO/Section Officer	23	2	7	1	—	3	2	3	—	5	10	4	17
14.	Asstt. Engineer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	Section Officer (Hindi)	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
16.	Insurance Inspector/Audit Inspector/Mgr. Gr. II/Dy. Mgr./Inspector (O&M) S.G.H.T.	8	24	10	4	3	13	6	32	7	35	21	43	35
17.	P.S. to Director General	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Mgr. Gr. III/Head Clerk/Asstt./Head clerk Cashier/Hindi Translator	86	23	13	3	5	16	15	27	7	49	19	34	37
19.	Junior Engineer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	P.A.	14	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
21.	Technical Asstt.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	Artist	1	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—
23.	Librarian	1	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—
24.	Receptionist	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	UDC Incharge/UDC Cashier/UDC/UDC Caretaker	85	70	54	9	5	45	23	78	25	146	107	136	156
26.	Stenographers	21	3	—	1	—	3	—	—	—	6	—	7	—
27.	Computer	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	LDC/Adrema Operator/Telex Operator/ Telephone Operator	86	70	81	11	7	37	29	73	29	139	114	117	188
29.	Gestetner Operator	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
30.	Staff Car Driver/Driver Delivery Van	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
31.	Junior Library Attendant	1	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	Jamadar	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	Record sorter/Daftry /(Selection Gr. Daftries including)	30	19	20	2	8	11	18	19	8	37	31	36	66
34.	Peon	58	12	28	4	2	10	8	17	17	25	42	20	54
35.	Chowkidar	3	2	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—
36.	Farash	7	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—
37.	Mali	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	Liftman	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
39.	Sweeper	9	2	—	—	—	1	—	2	—	4	—	3	—
	Total	485	237	213	38	30	149	101	265	93	470	344	422	553

* V.O. of Delhi Region diverted to Hqrs.

@ Diverted to other regions.

£ includes one driver cum peon.

VII

—I

as on 31-3-1980

Kerala		Madhya Pradesh		Maharashtra Poona			Maharashtra Nagpur		Orissa		Punjab		Rajasthan		Karnataka		Uttar Pradesh		West Bengal		Total
RO	LO	RO	LO	RO	SRO	SRO	LO	RO	LO	RO	LO	RO	LO	RO	LO	RO	LO	RO	LO	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	24
2	—	—	—	6+2@	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	3	—	9	—	44
4	—	3	—	15	3	1	—	1	—	6	—	1	—	5	—	6	—	14	—	96
4	6	2	5	10	2	1	36	2	—	5	—	3	—	3	5	6	3	9	22	201
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	9
32	25	13	12	99	16	6	50	5	3	40	14	12	8	20	22	31	19	86	42	796
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
30	15	16	12	84	18	8	55	11	11	33	13	14	9	26	19	36	21	72	36	873
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
93	85	53	58	298	57	22	273	29	12	104	28	40	19	87	94	110	61	261	184	2907
4	—	2	—	15	3	1	—	2	—	5	—	2	—	5	—	6	—	16	—	102
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
90	110	54	48	308	43	23	333	28	11	93	32	36	23	89	91	116	77	294	253	3133
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	7
1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	32	15	22	91	12	4	87	7	14	27	27	7	17	23	30	36	33	80	78	970
17	35	10	20	60	8	5	140	8	4	22	15	7	6	16	39	24	33	49	112	927
2	—	2	—	6	1	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	4	—	42
2	—	1	—	9	1	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	2	—	6		42
—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	1	—	—	—	1	—	1		6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3
2	—	1	—	9	1	1	—	1		4	—	1	—	2	—	2	—	8	—	53
311	308	176	177	1023	168	75	974	98	55	354	129	132	82	288	300	388	247	924	727	10335

APPENDIX VII

Part - II

Statement Showing the Position of Staff Authorised and in Position in respect of Directorate (Medical) Delhi E.S.I. Dispensaries and E.S.I. Hospital as on 31-3-1980

S. No.	Designation of Post	Directorate (Medical) Delhi		ESI Dispensaries		E.S.I. Hospital		Total		Remarks
		Autho-rised	In position	Autho-rised	In position	Autho-rised	In position	Autho-rised	In position	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Director (Medical) Delhi	1	1	—	—	—	—	1	1	—
2.	Medical Superintendent	—	—	—	—	1	1	1	1	—
3.	Administrative Medical Officer	1	1	—	—	—	—	1	1	—
4.	Dy. Chief Accounts Officer (M)	1	1	—	—	—	—	1	1	—
5.	Dy. Administrative Officer (M)/H	1	1	—	—	1	1	2	2	—
6.	Accounts Officer (Medical)	1	1	—	—	—	—	1	1	—
7.	Dy. Accounts Officer	—	—	—	—	1	1	1	1	—
8.	Hindi Officer	1	1	—	—	—	—	1	1	—
9.	Full time specialists in Surg. Med. Ortho. Gyne. Radio. Eye and ENT	—	—	—	—	14	10	14	10	—
10.	G.D.O. Gr. I/II	—	—	217 (Authorised to fill up 200 posts)	165	30	30	247 (17)	195	—
11.	Registrars	—	—	—	—	8	6	8	6	—
12.	House Surgeons	—	—	—	—	14	14	14	14	—
13.	*Part-time Specialists	—	—	As per sessions	11+8 (at LNJP/ RBTB Hosp)	7+3	5+2*	11+8 7+3 (As per session sanctioned)	11+7 5+2	Two part-time specialists are working against full time specialist.
14.	Audit Inspector/Insurance Inspector	4	4	—	—	—	—	4	4	—
15.	Office Superintendent	1	1	—	—	—	—	1	1	—
16.	Nursing Superintendent	—	—	—	—	1	—	1	—	—
17.	Ayurvedic Physicians	—	—	2	2	—	—	2	2	—
18.	P.A. to D(M)D/Med. Supdt.	1	1	—	—	1	1	2	2	—
19	Head Clerks	8	8	—	—	5	5	13	13	—
20.	Assistant	4	4	—	—	—	—	4	4	—
21.	Stenographer	6	6	—	—	2	1	8	7	—
22.	U.D C. Cashier	1	1	—	—	1	1	2	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	U.D.Cs.	35	35	26	26	12	12	73	73	—
24.	Care taker	—	—	—	—	1	1	1	1	—
25.	LDCs/Hindi Typist	44	44	107	107	16	15	167	166	—
26.	Ambulance/Staff Car/Delivery Van Driver	7	6	1	1	5	5	13	12	—
27.	Gest. Operator	1	1	—	—	—	—	1	1	—
28.	Daftries/S. Gr. Daftries	7	7	5	5	2	2	14	14	—
29.	Peons	20	16	100	94	8	7	128	117	—
30.	Ambulance Attendent	2	2	—	—	3	—	5	2	—
31.	Social Guide	2	1	—	—	—	—	2	1	—
32.	LHV/ANM/NRN/Midwife/Dai	—	—	139	115	—	—	139	115	—
33.	Pharmacist-cum-Clerk/Store Keeper/Pharmacist/Ayu. Phar.	11	11	132	120	—	—	143	131	—
34.	Chief Pharmacist	—	—	—	—	1	—	1	—	—
35.	Laboratory Assistant	—	—	11	10	6	4	17	14	—
36.	Laboratory Technician	—	—	—	—	6	6	6	6	—
37.	Farash	3	3	—	—	—	—	3	3	—
38.	Dressers	—	—	79	78	6	6	85	84	—
39.	Assistant Matron	—	—	—	—	2	2	2	2	—
40.	Nursing Sister	—	—	—	—	22	22	22	22	—
41.	Staff Nurses	—	—	—	—	113	103	113	103	—
42.	Dietician	—	—	—	—	1	1	1	1	—
43.	Radiographer (2 in lower scale)	—	—	—	—	7	5	7	5	—
44.	Dark Room Assistant	—	—	—	—	2	2	2	2	—
45.	E.C.G. Technician	—	—	—	—	8	8	8	8	—
46.	O.T. Assistant	—	—	—	—	6	6	6	6	—
47.	O.T. Technician	—	—	—	—	4	4	4	4	—
48.	C.S.R. Assistant	—	—	—	—	4	4	4	4	—
49.	C.S.R. Technician	—	—	—	—	1	1	1	1	—
50.	Physiotherapist	—	—	—	—	1	1	1	1	—
51.	Occupational Therapist	—	—	—	—	1	1	1	1	—
52.	Optometrist	—	—	—	—	1	1	1	1	—
53.	Medical Social Worker	—	—	—	—	1	—	1	—	—
54.	Sr. Blood Bank Technician	—	—	—	—	1	—	1	—	—
55.	Linen Mistress	—	—	—	—	2	—	2	—	—
56.	Boiler Attendant	—	—	—	—	1	1	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Laundry Supervisor	—	—	—	—	1	1	1	1	—
58.	Metal-Worker-cum-Mistry	—	—	—	—	1	—	1	—	—
59.	Medical Record Technician	—	—	—	—	1	1	1	1	—
60.	Medical Record Junior Technician.	—	—	—	—	1	1	1	1	—
61.	Telephone Operator	—	—	—	—	2	—	2	—	—
62.	Librarian	—	—	—	—	1	—	1	—	—
63.	Assistant Librarian	—	—	—	—	1	1	1	1	—
64.	Havaldar	—	—	—	—	1	—	1	—	—
65.	Laundry Operator	—	—	—	—	10	10	10	10	—
66.	Head Cook	—	—	—	—	3	3	3	3	—
67.	Cook-cum-Masalchi & Cook Mates	—	—	—	—	26	24	26	24	—
68.	Stretcher Bearer	—	—	—	—	9	8	9	8	—
69.	Nursing Orderly	—	—	—	—	98	93	98	93	—
70.	Aya	—	—	34	24	4	4	38	28	—
71.	Chowkidar	—	—	34	32	23	23	57	55	—
72.	Tailor	—	—	—	—	2	1	2	1	—
73.	Sweeper	3	3	94	94	63	63	160	160	—
74.	Bearer	—	—	—	—	6	4	6	4	—
75.	Hindi Assistant	2	1	—	—	—	—	2	1	—

Note: Staff sanctioned for Mangolpuri dispensary has not been included in the statement.

APPENDIX VIII

PART I

Ministry/Department/Office of E.S.I. Corporation, New Delhi

Statement showing the total number of Corporation Employees and the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them as on 1-1-1980

Class	Permanent/ Temporary	Total Number of employees	Scheduled Castes	Percentage to total employees	Scheduled Tribes	Percentage to total employees	Remarks
Class I	Permanent	62	4	6.45	Nil	Nil	Nil
	Temporary	64	12	18.75	—	—	—
Class II	Permanent	32	—	—	4	12.50	—
	Temporary	103	9	8.74	4	3.88	—
Class III	Permanent	4579	463	10.11	12	0.26	—
	Temporary	2672	247	9.24	23	0.86	—
Class IV	Permanent	1419	362	25.51	17	1.19	—
(excluding sweepers)	Temporary	977	211	21.49	39	3.99	—
Class IV	Permanent	95	95	100.00	—	—	—
(Sweeper)	Temporary	124	123*	99.19	3	2.41	—

*One post vacant.

APPENDIX VIII

PART II

Statement Showing the Number of Reserved Vacancies Filled by Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Direct Recruitment in the Ministry/Department—Office of E.S.I. Corporation, New Delhi as on 1-1-1980

Class of Post	Total No. of vacancies		Scheduled Castes					Scheduled Tribes					
	Notified	Filled	No. of vacancies reserved		No. of S. Cs. candidates appointed	No. of S. Ts. candidates appointed against vacancies reserved for S.Cs. in the 3rd year of carry forward	No. of reservation lapsed after carrying forward for three years	No. of vacancies reserved		No. of S. Ts. candidates appointed	No. of S. Cs. candidates appointed against vacancies reserved for S. Ts. in the 3rd year of carry forward	No. of reservation lapsed after carrying forward for three years	Remarks
			Out of col. 2	Out of col. 3				Out of col. 2	Out of col. 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Class I	6	6	1	1	4	—	1	1	4	—	—	—	—
Class II	29	29	4	2	1	—	—	2	2	—	—	—	—
Class III	463	456	70	65	52	1	8	48	51	4	2	6	—
Class IV (Excluding sweepers)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Class IV (Sweepers)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

APPENDIX VIII

PART III

Statement Showing the Number of Reserved Vacancies Filled by Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes other than by Direct Recruitment in the Ministry/Department/Office of E.S.I. Corporation, New Delhi as on 1-1-1980

Class of post	Total No. of vacancies		Scheduled Castes					Scheduled Tribes					
	Notified	Filled	No. of vacancies reserved		No. of S. Cs. candidates appointed	No. of S. Ts. candidates appointed against vacancies reserved for S. Cs. in the 3rd year of carry forward	No. of reservation lapsed after carrying forward for three years	No. of vacancies reserved		No. of S. Ts. candidates appointed	No. of S. Cs. candidates appointed against vacancies reserved for S. Ts. in the 3rd year of carry forward	No. of reservation lapsed after carrying forward for three years	Remarks
			Out of col. 2	Out of col. 3				Out of col. 2	Out of col. 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Class I	12	12	3	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—
Class II	27	27	6	6	—	—	—	3	3	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Class III	680	678	90	83	91*	2	4	56	56	9	10	6	—
Class IV (Excluding Sweepers)	117	117	9	14	34	1	—	7	8	10	2	—	—
Class IV (Sweepers)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*Offer of appointment has been issued but yet to join one S.T. candidate is still to join.

APPENDIX-IX

Number of Employers and Employees covered under the E.S.I. Act as on 31-3-1980

REGION-WISE

State	Implemented Area*		Non-Implemented Area		All Areas	
	No. of employers	No. of employees as on 31-3-80	No. of employers	No. of employees as on 31-3-80	No. of employers	No. of employees as on 31-3-80
1	2	3	4	5	6	7
Andhra Pradesh	3,760	2,40,000	83	16,200	3,843	2,56,200
Assam	578	32,000	108	10,500	686	42,500
Bihar	1,682	1,40,000	235	*2,00,000	1,917	3,40,000
Chandigarh	296	14,300	—	—	296	14,300
Delhi	6,025	2,65,000	—	—	6,025	2,65,000
Gujarat	4,037	5,50,000	638	1,00,000	4,675	6,50,000
Haryana	2,491	1,94,000	168	15,000	2,659	2,09,000
Himachal Pradesh	11	1,200	68	4,100	79	5,300
Jammu & Kashmir	—	—	N.A.	11,600	N.A.	11,600
Karnataka	2,336	3,00,000	207	28,000	2,543	3,28,000
Kerala and Mahe	3,520	3,08,000	12	2,600	3,532	3,10,600
Madhya Pradesh	1,686	1,60,000	62	75,000	1,748	2,35,000
Maharashtra						
Bombay Area	11,078	11,46,000	135	14,000	11,213	11,60,000
Goa	271	19,500	—	—	271	19,500
Nagpur Area	847	75,000	153	23,000	1,000	98,000
Poona Area	2,155	2,45,000	127	37,500	2,282	2,82,500
Orissa	454	1,09,000	68	82,000	522	1,91,000
Pondicherry	124	15,000	—	—	124	15,000
Punjab	3,696	1,65,000	315	13,000	4,011	1,78,000
Rajasthan	1,732	1,24,000	67	11,500	1,799	1,35,500
Tamil Nadu	5,802	4,50,000	215	32,000	6,017	4,82,000
Uttar Pradesh	3,002	4,45,000	370	34,000	3,372	4,79,000
West Bengal	9,017	9,85,000	176	1,48,000	9,193	11,33,000
ALL INDIA (1980)	64,600	59,83,000	3,207	8,58,000	67,807	68,41,000
ALL INDIA (1979)	59,054	58,15,900	2,672	8,79,700	61,726	66,95,600

*Also includes the coverage under Section 1 (5) of the Act.

APPENDIX-X

Number of Centres, Employees, Insured Persons, Family (Insured Person) Units and Beneficiaries covered as on 31-3-1980

REGION-WISE

[including Coverage Under section 1 (5) of the Act]

State	No. of Centres	No. of employees	No. of Insured Persons	No. of family (Insured Person) Units	No. of Beneficiaries
1	2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	44	2,40,000	2,74,000	2,74,000	10,63,100
Assam	13	32,000	36,000	30,000	1,39,700
Bihar	29	1,40,000	1,71,000	1,71,000	6,63,500
Chandigarh	1	14,300	17,500	17,500	67,900
Delhi	1	2,65,000	3,30,000	3,30,000	12,80,400
Gujarat	15	5,50,000	5,92,000	5,92,000	22,97,000
Haryana	18	1,94,000	2,42,500	2,42,500	9,40,900
Himachal Pradesh	1	1,200	1,300	1,300	5,000
Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—
Karnataka	18	3,00,000	3,28,000	3,28,000	12,72,600
Kerala & Mahe	33	3,08,000	3,35,000	3,35,000	12,99,800
Madhya Pradesh	22	1,60,000	2,00,000	2,00,000	7,76,000
Maharashtra					
Bombay area	1	11,46,000	12,20,000	12,20,000	47,33,600
Goa	7	19,500	20,700	20,700	80,300
Nagpur area	10	75,000	82,000	82,000	3,18,100
Poona area	15	2,45,000	2,60,000	2,60,000	10,08,800
Orissa	22	1,09,000	1,16,000	1,16,000	4,50,100
Pondicherry	1	15,000	16,000	16,000	62,100
Punjab	27	1,65,000	2,06,000	2,06,000	7,99,300
Rajasthan	19	1,24,000	1,55,000	1,55,000	6,01,400
Tamil Nadu	44	4,50,000	5,27,000	5,27,000	20,44,800
Uttar Pradesh	47	4,45,000	4,90,000	4,90,000	19,01,200
West Bengal	7	9,85,000	12,30,000	12,30,000	47,72,400
ALL INDIA (1980)	195	59,83,000	68,50,000	68,50,000	2,65,78,000
ALL INDIA (1979)	375	58,15,900	65,89,500	65,89,500	2,55,67,300

APPENDIX

Number of Beds, Specialists, Dispensaries, Pupil

Sl. No.	Name of the State	Total No. of beds provided under the ESI Scheme				Specialists	
		General	Maternity	T.B.	Total	Full-time	Part-time
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Andhra Pradesh	582	58	92	732	39	68
2.	Assam	90	—	10	100	—	1
3.	Bihar	206	—	30	236	6	—
4.	Chandigarh Admn.	40	—	—	40	—	4
5.	Delhi	374	76	105	555	10	25
6.	Goa	33	—	—	33	—	16
7.	Gujarat	1067	59	312	1438	17	263
8.	Haryana	456	–	100	556	16	22
9.	Himachal Pradesh	—	—	—	—	—	—
10.	Karnataka	998	69	137	1204	15	77
11.	Kerala	810	110	175	1095	28	76
12.	Madhya Pradesh	433	22	117	572	4	110
13.	Maharashtra						
	(a) Gr. Bombay	2455	432	865	3752	48	116
	(b) Nagpur Area	219	31	47	297	3	66
	(c) West Maharashtra	352	25	191	568	—	125
14.	Orissa	133	17	12	162	3	3
15.	Pondicherry	68	4	10	82	—	12
16.	Punjab	532	65	34	631	26	21
17.	Rajasthan	238	30	31	299	8	82
18.	Tamil Nadu	1343	335	410	2088	40	71
19.	Uttar Pradesh	761	157	224	1142	32	58
20.	West Bengal	2158	78	694	2930	—	410
	Total	13348	1568	3596	18512	295	1626

APPENDIX

Attendance, Medical Certificates issued, Admissions to Home Visit during 1978-79

(In respect of

State		Period	No. of Insured Persons deemed exposed to risk	Attendances		
				New cases	Old cases	Total cases
1		2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	(S.S.)	1978-79	2,58,000	9,47,590	27,74,335	37,21,925
		1979-80	2,67,500	7,79,908	21,40,963	29,20,871
Assam	(S.S.)	1978-79	31,500	96,101	88,190	1,85,291
		1979-80	34,500	1,15,987	1,13,662	2,29,649
Bihar	(S.S.)	1978-79	1,39,000	1,81,699	2,29,517	4,11,216
		1979-80	1,57,500	1,83,314	2,23,931	4,07,245
Chandigarh	(S.S.)	1978-79	14,750	39,830	97,602	1,37,432
		1979-80	17,500	44,917	1,18,431	1,63,348
Delhi	(S.S.)	1978-79	2,82,000	3,45,681	16,46,458	19,92,139
		1979-80	3,17,000	3,63,671	13,81,668	17,45,339
Goa	(S.S.)	1978-79	18,100	39,605	12,392	51,997
		1979-80	20,500	43,664	13,257	56,921
Gujarat	(S.S.)	1978-79	5,47,800	6,50,271	69,15,049	75,65,320
		1979-80	5,26,400	6,23,124	33,36,844	39,59,968
Gujarat	(P.S.)	1978-79	51,700	2,11,340	2,01,440	4,12,780
		1979-80	56,500	2,25,530	2,05,317	4,30,847
Haryana	(S.S.)	1978-79	2,04,000	4,43,517	6,30,812	10,74,329
		1979-80	2,29,250	3,85,863	5,48,819	9,34,682

XI

Doctors and Ambulances as on 31-3-1980

Total No. of Dispensaries	No. of I.M. Os.		No. of IMPs	No. of Doctors in employers utilisation dispensaries	Ambulances	Remarks
	Sanctioned	Present				
9	10	11	12	13	14	15
87	201	186	2	1	13	Includes
19	22	2	—	—	2	one
47	145	120	—	—	21	Tempo
2	8	8	—	—	—	
29	217	165	—	—	5	
—	—	—	59	—	—	
91	449	434	259	1	18	
54	126	119	—	—	4	
1	1	1	—	—	—	
113	250	226	—	60	12	
121	242	220	—	—	9	
54	152	127	5	1	8	
18	14	8	2326	11	22	
26	85	80	—	—	4	
27	60	48	390	—	6	
24	67	63	—	—	7	
7	19	18	—	—	1	
39	115	108	83	—	4	
41	126	108	—	1	4	
121	390	360	—	14	23	
106	315	302	—	—	14	
3	97	—	1610	14	21	
1030	3101	2723	4734	103	198	

XII

Hospitals, Reference to Specialists and number of

and 1979-80 STATE -WISE

Insured Persons)

No. of attendances per 1000 Insured Persons per annum		No. of medical certificates issued	No. of cases admitted in Hospitals	No. of cases referred to Specialists for investigation	No. of Home visits
New cases	Old cases				
7	8	9	10	11	12
3,673	10,753	6,82,472	1,16,627	1,72,388	N.A.
2,916	8,004	5,52,764	23,978	1,14,043	N.A.
3,051	2,800	59,439	377	3,721	2,326
3,362	3,295	75,749	425	4,693	1,811
1,307	1,651	1,63,150	364	12,317	4,817
1,164	1,422	1,72,421	259	17,931	8,823
2,700	6,617	11,213	251	5,420	N.A.
2,567	6,767	11,840	1,309	8,510	N.A.
1,226	5,839	2,75,990	3,323	54,954	54,588
1,147	4,359	2,37,730	3,107	51,040	51,704
2,188	685	24,615	N.A.	1,083	413
2,130	647	26,799	N.A.	1,094	500
1,187	12,623	6,47,126	16,002	1,54,111	3,698
1,184	6,339	6,40,494	15,774	1,79,745	4,409
4,088	3,896	1,74,378	707	13,519	1,673
3,992	3,634	1,84,742	590	14,335	1,692
2,174	3,092	71,655	7,699	36,239	13,363
1,683	2,394	54,348	9,077	37,682	4,825

1		2	3	4	5	6
Karnataka	(S.S.)	1978-79	2,99,000	15,88,912	29,09,573	44,98,485
		1979-80	3,16,000	14,70,441	27,48,300	42,18,741
Kerala	(S.S.)	1978-79	3,23,900	9,26,762	23,72,596	32,99,358
		1979-80	3,28,900	13,10,935	30,33,948	43,44,883
Kerala	(P.S.)	1978-79				
		1979-80				
Madhya Pradesh	(S.S.)	1978-79	1,84,850	4,16,049	20,49,810	24,65,859
		1979-80	1,93,100	4,69,501	20,89,625	25,59,126
Madhya Pradesh	(P.S.)	1978-79	2,900	6,719	16,618	23,337
		1979-80	2,400	6,116	14,878	20,994
Maharashtra						
(i) Bombay Area	(S.S.)	1978-79	6,050	19,097	42,294	61,391
		1979-80	4,750	20,365	40,909	61,274
(ii) Bombay Area	(P.S.)	1978-79	1,72,200	9,21,631	7,43,148	16,64,779
		1979-80	1,68,500	9,23,616	7,15,749	16,39,365
(iii) Nagpur Area	(S.S.)	1978-79	79,000	2,42,314	9,06,705	11,49,019
		1979-80	81,500	2,62,336	9,81,471	12,43,807
(iv) Poona Area	(S.S.)	1978-79	32,950	1,36,540	3,79,528	5,16,068
		1979-80	48,250	1,82,772	4,17,718	6,00,490
(v) Poona Area	(P.S.)	1978-79	40,850	3,14,080	2,69,331	5,83,411
		1979-80	35,350	2,36,189	2,02,711	4,38,900
Orissa	(S.S.)	1978-79	93,500	2,62,038	3,20,492	5,82,530
		1979-80	1,07,000	2,17,373	3,05,322	5,22,695
Pondicherry & Mahe	(S.S.)	1978-79	17,600	44,964	1,95,701	2,40,665
		1979-80	17,100	63,646	1,98,381	2,62,027
Punjab	(S.S.)	1978-79@	15,350	1,06,221	1,43,883	2,50,104
		1979-80@	15,550	1,67,875	1,21,152	2,89,027
Punjab	(P.S.)	1978-79@	37,500	1,65,516	88,626	2,54,142
		1979-80@	17,350	93,207	59,441	1,52,648
Rajasthan	(S.S.)	1978-79	1,35,500	3,71,230	7,58,001	11,29,231
		1979-80	1,48,500	4,13,188	8,06,822	12,20,010
Tamil Nadu	(S.S.)	1978-79	4,75,400	13,16,394	44,94,667	58,11,061
		1979-80	5,05,350	13,00,393	50,41,457	63,41,850
Tamil Nadu	(P.S.)	1978-79	5,600	22,358	64,474	86,832
		1979-80	5,650	20,996	69,098	90,094
Uttar Pradesh	(S.S.)	1978-79	4,75,500	13,56,297	17,13,116	30,69,413
		1979-80	4,85,000	12,46,948	15,83,391	28,30,339
West Bengal	(P.S.)	1978-79	7,14,850	26,67,376	18,82,131	45,49,507
		1979-80	7,14,350	26,52,798	19,00,352	45,53,150
ALL INDIA		1978-79	46,59,350	1,38,40,132	3,19,46,489	4,57,86,621
		1979-80	48,21,250	1,38,24,673	2,84,13,617	4,22,38,290

(S.S.) Service System (P.S.) Panel System

@Figures for certain months not received; Weighted average taken.

APPENDIX

Attendance and Home visits during 1978-79 and 1979-80 State-wise

State	Period	No. of family (Insured Person) units deemed exposed to risk	Attendances	
			New Cases	Old Cases
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh (S.S.)	1978-79	2,58,000	11,30,192	29,54,296
	1979-80	2,67,500	9,81,315	26,55,075
Assam (S.S.)	1978-79	31,500	81,613	45,663
	1979-80	34,500	1 04,779	68,722
Bihar (S.S.)	1978-79	1,39,000	2,37,465	2,52,563
	1979-80	1,57,500	2,69,160	2,70,645
Chandigarh (S.S.)	1978-79	14,750	45,081	46,484
	1979-80	17,500	52,781	58,204
Delhi (S.S.)	1978-79	2,82,000	8,92,928	14,68,219
	1979-80	3,17,000	8,29,444	11,34,341

7	8	9	10	11	12
5,314	9,731	8,56,988	27,887	2,12,134	41,245
4,653	8,697	8,70,551	50,143	2,04,106	23,314
2,861	7,325	4,15,687	34,594	30,667	742
3,986	9,225	6,36,527	63,645	42,500	578
Penal System closed					
2,251	11,089	6,49,726	9,132	1,12,363	11,629
2,431	10,821	7,42,465	8,993	1,49,749	11,115
2,317	5,730	5,048	18	1,056	105
2,548	6,199	4,708	23	937	60
3,157	6,991	16,827	65,790	2,670	N.A.
4,287	8,612	11,486	73,174	2,313	1
5,352	4,316	6,24,251	2,961	48,165	4,857
5,481	4,248	5,99,252	2,064	44,658	5,431
3,067	11,477	3,06,351	12,173	32,424	7,415
3,219	12,043	3,15,428	14,321	33,084	6,724
4,144	11,518	1,28,304	372	13,550	96
3,788	8,657	1,50,513	503	18,634	357
7,689	6,593	2,50,143	N A	20,015	1,232
6,681	5,734	1,90,695	N A	8,704	545
2,803	3,428	1,25,003	3,962	28,245	14,076
2,032	2,853	1,37,731	4,497	34,524	14,392
2,555	11,119	49,008	2,316	12,415	1,983
3,722	11,601	56,557	3,186	11,346	2,191
6,920	9,373	26,490	621	3,198	5,454
10,796	7,791	28,509	N A	7,169	4,349
4,414	2,363	39,576	675	17,445	6,129
5,372	3,426	17,715	N A	11,059	2,861
2,740	5,594	1,99,398	11,198	63,309	4,034
2,782	5,433	2,03,733	11,595	73,690	4,221
2,769	9,454	17,55,697	15,315	1,79,044	16,585
2,573	9,976	25,42,546	11,077	1,52,760	12,446
3,993	11,513	20,342	1,700	2,766	2
3,716	12,230	19,701	1,163	3,194	N A.
2,852	3,603	6,35,638	15,049	71,645	8,317
2,571	3,265	6,83,775	19,636	76,231	5,682
3,731	2,633	10,94,403	N A.	1,22,754	50,524
3,714	2,660	12,12,484	N A.	1,24,650	50,914
2,970	6,856	93,08,918	3,49,023	14,27,617	2,55,303
2,867	5,893	1,03,81,263	3,14,539	14,28,381	2,18,940

XIII

(In respect of Family Members of Insured persons)

	No of attendances per 1,000 family (Insured Person) units per annum		No. of Home visits
Total Cases	New Cases	Old Cases	
6	7	8	9
40,84,488	4,381	11,451	22,466
36,36,350	3,668	9,925	20,392
1,27,276	2,591	1,450	112
1,73,501	3,037	1,992	216
4,90,028	1,708	1,817	2,733
5,39,805	1,709	1,718	6,025
91,565	3,056	3,151	1,668
1,10,985	3,016	3,326	2,311
23,61,147	3,166	5,206	10,843
19,63,785	2,617	3,578	10,168

1		2	3	4	5
Goa	(S. S.)	1978-79	18,100	38,769	9,138
		1979-80	20,500	41,511	16,135
Gujarat	(S.S.)	1978-79	5,47,800	9,77,120	41,12,014
		1979-80	5,26,400	9,20,127	37,34,294
Gujarat	(P. S.)	1978-79	51,700	2,42,899	2,13,628
		1979-80	56,450	2,56,597	2,18,425
Haryana	(S. S.)	1978-79	2,04,000	5,09,520	6,72,877
		1979-80	2,29250	4,43,948	5,13,127
Karnataka	(S. S.)	1978-79	2,99,000	21,45,273	38,58,454
		1979-80	3,16,000	19,88,867	36,65,878
Kerala	(S. S.)	1978-79	3,23,900	10,30,703	26,60,360
		1979-80	3,28,900	14,01,158	34,27,158
Kerala	(P. S.)	1978-79			
		1979-80			
Madhya Pradesh	(S.S.)	1978-79	1,84,600	6,41,688	17,87,534
		1979-80	1,93,100	6,41,889	17,57,055
Madhya Pradesh	(P. S.)	1978-79	2,900	10,126	13,401
		1979-80	2,400	9,445	11,801
Maharashtra :					
(i) Bombay Area	(S. S.)	1978-79	6,050	18,983	34,065
		1979-80	4,750	20,300	35,600
(ii) Bombay Area	(P. S)	1978-79	1,61,450	4,98,225	3,62,358
		1979-80	1,66,700	4,94,776	3,45,993
(iii) Nagpur Area	(S. S.)	1978-79	79,000	2,87,697	12,30,985
		1979-80	81 500	3,02,770	13,38,699
(iv) Poona Area	(S. S.)	1978-79	32,950	1,46,992	3,75,862
		1979-80	48,300	2,00,856	4,24,342
(v) Poona Area	(P. S.)	1978-79	40 850	3,00,195	2,17,436
		1979-80	35,850	2,16,755	1,66,045
Orissa	(S. S.)	1978-79	93,500	3,17,241	4,40,719
		1979-80	1,07,000	2,81,788	3,93,179
Pondicherry & Mahe	(S. S.)	1978-79	17,600	49,282	2,74,644
		1979-80	17,100	74,898	2,83,329
Punjab	(S. S.)	1978-79@	7,450	1,06,620	1,00,269
		1979-80@	10,250	1,81,095	65,556
Punjab	(P. S.)	1978-79@	31,000	1,60,233	92,736
		1979-80@	16,150	1,00,200	58,169
Rajasthan	(S. S.)	1978-79	1,35,500	5,98,159	10,67,014
		1979-80	1,48,500	6,31,510	10,70,102
Tamil Nadu	(S. S.)	1978-79	4,75,400	15,50,741	54,68,546
		1979-80	5,05,350	13,39,994	51,03,446
Tamil Nadu	(P. S.)	1978-79	5,600	28,598	98,209
		1979-80	5,650	22,875	91,437
Uttar Pradesh	(S. S.)	1978-79	4,75,500	13,51,222	17,75,324
		1979-80	4,85,000	11,73,033	14,39,683
West Bengal	(P. S)	1978-79	6,04,300	23,24,722	12,08,193
		1979-80	6,03,500	22,79,441	12,12,976
ALL INDIA		1978-79	45,23,400	1,57,22,287	3,08,40,391
		1979-80	47,02,600	1,52,61,312	2,95,58,376

(S. S.)—Service System

(P. S.)—Panel System :

@—Figures for certain months not received ; Weighted average taken.

	6	7	8	
	47,907	2,142	505	259
	51,646	2,025	494	276
	50,89,134	1,784	7,506	2,740
	46,54,421	1,748	7,094	2,951
	4,56,527	4,698	4,132	379
	4,75,022	4,546	3,869	391
	11,82,397	2,498	3,298	3,847
	9,57,075	1,937	2,238	3,835
	60,03,727	7,175	12,905	9,667
	56,54,745	6,294	11,601	12,559
	36,91,063	3,182	8,214	246
	48,28,316	4,260	10,420	143
Panel System Closed				
	24,29,222	3,476	9,683	718
	23,98,944	3,324	9,099	597
	23,527	3,492	4,621	44
	21,246	3,935	4,917	N.A.
	53,048	3,138	5,631	28
	55,900	4,274	7,495	4
	8,60,583	3,086	2,244	2,367
	8,40,769	2,968	2,076	2,145
	15,18,682	3,642	15,582	3,645
	16,41,469	3,715	16,426	4,158
	5,22,854	4,461	11,407	8
	6,25,198	4,159	8,786	9
	5,17,631	7,349	5,323	927
	3,82,800	6,046	4,632	521
	7,57,360	3,393	4,707	7,506
	6,79,967	2,634	3,721	5,795
	3,23,926	2,800	15,605	2,783
	3,58,227	4,380	16,569	2,353
	2,06,889	14,311	13,459	1,920
	2,46,651	17,668	6,396	2,638
	2,52,969	5,162	2,991	2,832
	1,58,369	6,204	3,602	2,561
	16,65,173	4,414	7,875	893
	17,01,612	4,253	7,206	934
	70,19,287	3,262	11,503	22,058
	64,43,440	2,652	10,099	18,795
	1,26,807	5,107	17,537	1,305
	1,14,312	4,049	16,184	1,558
	31,26,546	2,842	3,734	36,112
	26,12,716	2,419	2,968	25,158
	35,32,915	3,847	1,999	23,427
	34,92,417	3,777	2,010	22,350
	4,65,62,678	3,476	6,818	1,61,533
	4,48,19,688	3,245	6,286	1,48,843

APPENDIX XIV

Incidence of Morbidity, i.e., number of new cases per 1,000 Insured Persons and 1,000 Family (I.P.) Units 1978-79 and 1979-80

ALL INDIA

Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		1978-79	1979-80	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6
1.	T.B. of respiratory system	11.8	9.9	10.2	8.9
2.	T.B. other forms	4.3	3.8	4.7	4.1
3.	Syphilis and its sequelae	1.9	1.7	1.1	1.3
4.	Gonococcal infection	4.3	3.1	2.9	2.6
5.	Dysentery, all forms	215.7	200.5	215.7	205.7
6.	Cholera,, Enteric Fever, other infective diseases arising in intestinal tract	20.5	19.9	24.4	22.7
7.	Scarlet fever, Diptheria, Whooping Cough, Measles, Mumps, chickenpox	5.9	6.5	22.4	22.9
8.	Typhus and other rickettsial diseases	0.3	0.3	0.4	0.3
9.	Malaria	35.3	32.0	41.5	39.4
10.	Filariasis, ankylostomiasis and other Helminths	58.7	58.6	98.3	91 9
11.	All other diseases classified as infective and parasitic	51.9	49.5	60.1	57
12.	Malignant neoplasms all sites	0.3	0.3	0.2	0.2
13.	Benign neoplasms all sites	0.8	2.1	0.5	0.2
14.	Allergic disorders	95.9	97.3	122.5	119.1
15.	Diseases of Thyroid gland	1.0	1.3	1.4	1.4
16.	Diabetes Mellitus	5.9	4.4	6.9	4.2
17.	Avitaminosis and other deficiency states	118 3	109.4	135.5	129.7
18.	Anaemias	84.8	83.2	199.7	111.6
19.	Psychoneuroses and Psychoses	1.9	1.7	2.0	2.0
20.	Vascular lesions C. N. S.	2.7	0.7	1.7	0.6
21.	Disease of eye	88.5	91.2	117.5	114.9
22.	Diseases of ear and Mostoid Process	54.7	54.2	79.2	73.8
23.	Rheumatic fever	5.6	5.4	4.9	4.7
24.	Chronic Rheumatic heart diseases	0.8	0.6	1.6	0.8
25.	Arteriosclerotic and degenerative heart diseases	0.6	0.5	0.7	0.5
26.	Hypertensive diseases	8.9	8.3	13.3	9.9
27.	Diseases of Veins	7.1	6.1	7.9	5.5
28.	Acute nasopharyngitis (common cold)	269.4	268.2	309.9	301.4
29.	Acute Pharyngitis and tensillitis	74.5	74.0	97.3	94.8
30.	Influenza	220.5	116.8	125.6	119.1
31.	Pneumonia	2.8	2.8	6.6	5.8
32.	Bronchitis	219.4	214.8	238.6	226.7
33.	Silicosis and Occupational Pulmonary fibrosis	0.1	0.3	0.1	0.2
34.	Other respiratory diseases	70.7	67.0	82.3	77.4
35.	Diseases of stomach and duodenum	126.0	119.4	134.8	127.2
36.	Appendicitis	1.9	2.0	1.3	1.0
37.	Hernia of abdominal cavity	1.7	1.3	1.2	0.8
38.	Diarrhoea and enteritis	169.5	163.6	216.7	200.8
39.	Diseases of gallbladdar and bile ducts	1.7	1.3	3.5	1.3
40.	Other diseases of digestive system	138.9	133.3	158.2	139.3
41.	Nephritis and nephrosis	2.1	1.5	2.0	2.0
42.	Diseases of genital organs	15.5	17.1	34.3	31.6

1	2	3	4	5	6
43.	Deliveries, complication of pregnancy, Child birth and the Puerperium	27.4*	24 0*	11.2	10.4
44.	Boil, abscess, cellulitis and other skin infections	182.1	169.7	215.2	187.2
45.	Other diseases of skin	100.3	95.2	124.1	110.8
46.	Arthritis and rheumatism	128.3	124.9	112.2	108.7
47.	Diseases of bones and other organs of movement	9.5	9.9	8.0	7.7
48.	Congenital Malformations and diseases peculiar to early infancy	0.7	0.6	0.8	0.3
49.	Other specific and ill-defined diseases	258.9	246.1	314.3	290.9
50.	Accidents, poisoning and Violence	188.4	181.0	178.2	161.6
51.	Other Miscellaneous Groups	1.9	2.0	2.2	2.1
	Total No. of New Cases	2,970.4	2,867.4	3,475.8	3,245.3

*Per 1,000 insured women employees.

APPENDIX XV

Estimated expenditure incurred on provision of Medical Benefit during the year 1979-80

S .No.	Name of the State	No. of employees deemed exposed the risk	Total estimated expenditure on medical benefit as intimated by the State Govt.	Per Capita Cost
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	2,37,500	3,34,47,901.37	140.83
2.	Assam	30,500	23,50,000.00*	77.04
3.	Bihar	1,32,500	1,25,32,848.35	94.58
4.	Chandigarah Administration	14,150	17,44,731.95	123.30
5.	Delhi	2,55,000	3,26,34,581.69	127.97
6.	Goa	19,250	12,82,185.51	66.60
7.	Gujarat	5,42,500	7,23,88,000.00	133.43
8.	Haryana	1,85,000	1,71,11,533.46	92.49
9.	Himachal Pradesh	1,050	N.A.	—
10.	Karnataka	2,93,000	3,96,34,626.37	135.27
11.	Kerala	3,07,000	3,86,05,048.40	125.74
12.	Mdhya Pradesh	1,65,000	1,74,06,145.00	105.49
13.	Maharashtra	14,58,500	19,66,91,554.00	134.85
14.	Orissa	1,00,500	98,19,000.00	97.70
15.	Pondichery	15,000	24,39,000.00	162.60
16.	Punjab	1,60,500	2,05,25,950.75	127.88
17.	Rajasthan	1,19,500	1,66,97,000.00*	139.72
18.	Tamil Nadu	4,47,500	6,89,64,600.00*	154.11
19.	Uttar Pradesh	4,40,000	3,90,60,965.85	88.77
20.	West Bengal	9,75,000	12,33,45,500.00	126.50
	Total	58,99,450	74,66,81,172.70	126.56

*Estimated

APPENDIX

Incidence of Sickness and Maternity Benefit

State	Period	No. of employees deemed exposed to risk for Sickness/ Ext. Sickness Benefit	Total No. of cash Benefit Payments	Average No. of cas Benefit Payments per employee per annum
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	1978-79	2,31,350	4,10,354	1.8
	1979-80	2,35,150	3,66,622	1.6
Assam	1978-79	26,100	42,864	1.6
	1979-80	28,250	42,991	1.5
Bihar	1978-79	1,19,300	1,72,197	1.4
	1979-80	1,24,050	1,92,680	1.6
Chandigarh	1978-79	10,150	4,209	0.4
	1979-80	12,900	5,144	0.4
Delhi	1978-79	2,22,800	1,43,911	0.6
	1979-80	2,40,000	1,36,284	0.6
Gujarat	1978-79	5,01,900	6,55,335	1.3
	1979-80	5,24,200	6,61,132	1.3
Haryana	1978-79	1,68,800	78,993	0.5
	1979-80	1,74,300	76,742	0.4
Himachal Pradesh	1978-79	700	462	0.7
	1979-80	850	442	0.5
Karnataka	1978-79	2,73,900	5,47,290	2.0
	1979-80	2,83,900	6,28,715	2.2
Kerala & Mahe	1978-79	2,91,700	5,43,651	1.9
	1979-70	3,06,750	5,95,963	1.9
Madhya Pradesh	1978-79	1,65,800	3,42,774	2.1
	1979-80	1,69,700	3,68,929	2.2
Maharashtra	1978-79	13,20,400	19,39,621	1.5
	1979-80	14,27,200	19,35,939	1.4
Orissa	1978-79	81,850	74,993	0.9
	1979-80	90,300	83,282	0.9
Pondicherry	1978-79	15,000	22,303	1.5
	1979-80	15,000	24,731	1.6
Punjab	1978-79	1,54,400	66,163	0.4
	1979-80	1,54,600	66,425	0.4
Rajasthan	1978-79	1,10,150	1,27,069	1.2
	1979-80	1,13,900	1,43,445	1.3
Tamil Nadu	1978-79	4,42,950	10,99,634	2.5
	1979-80	4,43,750	15,46,239	3.5
Uttar Pradesh	1978-79	4,37,200	4,06,510	0.9
	1979-80	4,33,900	4,24,654	1 0
West Bengal	1978-79	9,65,000	12,68,801	1.3
	1979-80	9,65,600	12,46,908	1.3
TOTAL	1978-79	55,39,450	79,47,134	1.4
	1979-80	57,44,300	85,47,267	1.5

XVI

Claims in 1978-79 and 1979-80 —State wise

Sickness Benefit			Extended Sickness Benefit		Maternity Benefit	
Rate of fresh spells per employee per annum	Average No. of S.B. Days per employee per annum	Average daily rate (Rs.)	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees exposed	Average Amount per confinement (Rs.)
6	7	8	9	10	11	12
1.13	7.7	7.19	4.0	235.1	90.4*	774
0.97	8.0	7.59	1.9	243.3	44.3	1,116
1.00	7.0	6.16	2.4	250.8	76.4	688
1.02	7.9	6.60	2.2	245.5	74.2	764
0.83	10.3	7.79	3.7*	313.0	14.6	760
1.18	11.9	8.16	3.9	323.1	12.2	839
0.25	2.8	9.36	0.6	—	58.8	1,347
0.29	2.3	9.30	1.1	—	126 2	982
0 27	3.5	8.70	3.0	229.2	33.6	998
0.27	3.4	9.25	3 1	266.0	35.6	1,076
0.60	5.5	9.15	6.0	222.8	54.1	583
0.58	5.7	9.68	5.5	260.9	49.6	769
0.23	2.7	7.44	1.2	198.6	11.8	1,420
0.23	2.4	8.08	2.3	183.1	18.3	1,121
0.36	2.9	10.50	1.4	—	—	—
0.27	2.4	10.00	1.2	100.0	—	—
1.39	7.9	9.17	2.3	225.1	67.5	1,284
1.62	9.4	9.77	2.3	254.5	101.5	866
1.17	6.6	6.76	2.8*	245.6	55.3	702
1.26	8.6	7.20	2.6	250.1	62.0	638
0.80	12.2	8.42	3.4	260.1	31.0	728
1.64	14.4	8.76	4.8	260.7	28.0	756
0.95	6.8	9.06	5.2	189.3	41.3	1,365
0.90	6.6	10.40	4.9	182.3	44.3	1,479
0.53	4.7	7.75	1.9	291.3	27.6	752
0.59	5.1	8.00	1.6	273.3	22.0	686
0.88	5.5	9.67	2.4	216.7*	46.7	789
1.43	6.9	9.57	3.9	189.5	20.0	1,005
0.24	2.1	6.36	1.4	198.9	21.5	611
0.22	2.3	6.97	2.0	202.2	20.5	735
0.66	4.9	8.41	7.0	197.3	24.7	755
0.77	5.8	9.48	4.9	291.1	33.1	614
2.04	9.5	10.01	3.1	197.4	46.6	722
2.83	18.3	10.64	2.0	262.8	64.7	490
0.80	7.5	7.90	2.4	290.3	24.6	926
0.57	8.6	9.37	2.5	227.3	39.0	752
0.80	6.7	8.88	6.6	246.9	29.6	884
0.94	6.9	9.44	5.8	228.0	22.8	1,011
0.90	6.8	8.92	4.4*	220.9	45.9	907
1.00	7 8	9.54	4.0	225.6	49.4	860

*Figures revised.

APPENDIX

Incidence of Disablement and Dependants'

State	Period	No. of employees deemed exposed to risk	Temporary Disablement	
			Rate of fresh spells per employee per annum	No. of T. D. B. days per employee per annum
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	1978-79	2,35,000	0.06	0.75
	1979-80	2,37,500	0.05	0.75
Assam	1978-79	27,500	0.05	0.92
	1979-80	35,000	0.04	0.78
Bihar	1978-79	1,22,500	0.03	0.65
	1979-80	1,32,500	0.03	0.60
Chandigarh	1978-79	12,000	0.02	0.77
	1979-80	14,150	0.05	0.71
Delhi	1978-79	2,35,000	0.05	0.92
	1979-80	2,55,000	0.04	0.84
Gujarat	1978-79	5,15,000	0.14	1.91
	1979-80	5,42,500	0.13	1.76
Haryana	1978-79	1,72,000	0.04	0.79
	1979-80	1,85,000	0.04	0.71
Himachal Pradesh	1978-79	800	0.11	1.00
	1979-80	1,050	0.12	1.08
Karnataka	1978-79	2,81,500	0.08	0.86
	1979-80	2,93,000	0.09	0.96
Kerala & Mahe	1978-79	3,06,500	0.07	0.89
	1979-80	3,07,500	0.07	1.03
Madhya Pradesh	1978-79	1,70,000	0.17	3.34
	1979-80	1,65,000	0.19	3.33
Maharashtra	1978-79	13,93,000	0.06	0.77
	1979-80	14,77,750	0.06	0.79
Orissa	1978-79	88,000	0.03	0.53
	1979-80	1,00,500	0.03	0.55
Pondicherry	1978-79	15,000	0.12	0.98
	1979-80	15,000	0.10	0.99
Punjab	1978-79	1,53,000	0.03	0.68
	1979-80	1,60,500	0.03	0.66
Rajasthan	1978-79	1,12,500	0.08	1.00
	1979-80	1,19,500	0.09	1.00
Tamil Nadu	1978-79	4,42,500	0.09	0.78
	1979-80	4,47,500	0.08	0.69
Uttar Pradesh	1978-79	4,32,500	0.05	1.23
	1979-80	4,40,000	0.04	1.21
West Bengal	1978-79	9,65,000	0.10	1.51
	1979-80	9,75,000	0.10	1.46
TOTAL	1978-79	56,79,300	0.08	1.13
	1979-80	58,99,450	0.07	1.10

XVII

Claims admitted in 1978-79 and 1979-80

Benefit	Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
Average daily rate of T.D.B. (Rs.)	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh cases per 1,000 employees per annum	No. of cases commuted for lumpsum	No. of Beneficiaries at the end of the year	No. of Death cases admitted	No. of Beneficiaries at the end of the year
6	7	8	9	10	11	12
7.57	636 14 S	2.77	469	776	8	686
8.28	572 7 S	2.44	476	771	—	686
6.75	52	1.39	73	126	2	101
6.73	95	3.11	82	159	2	105
8.20	104	0.85	63	451	13	344
6.68	145	1.09	113	420	9	375
6.64	63	5.25	25	28	5	30
7.77	41	2.90	35	28	2	35
11.09	1,843 24 S	7.94	1,605	1,022	21	598
11.46	2,382 33 S	9.47	1,540	1,186	30	666
10.89	2,410 95 S	4.86	2,657	1,962	39	1,539
11.56	2,129 326 S	4.53	1,592	2,337	53	1,658
7.88	828	4.79@	570	871	42	570
8.59	722	3.88	606	932	34	619
12.55	—	—	—	—	—	—
9.67	—	—	—	—	—	—
8.71	395	1.40	443	710	52	823
9.04	559	1.91	429	811	49	947
9.23	832	2.71	679	794	25	690
10.27	949	3.09	678	984	31	771
10.87	376	2.21	189	680	16	584
10.87	327	1.98	170	745	18	622
11.39	4,169 197 S	3.13	2,563	12,075	53	3,895
11.63	3,584 248 S	2.59	2,326	12,258	120	4,259
6.90	105	1.19	78	215	2	181
7.23	156	1.55	86	278	12	2
11.69	6	0.40	7	22	2	17
11.63	7	0.47	5	28	1	18
6.71	516	3.37	433	699	41	585
7.19	723	4.50	454	950	35	642
9.30	259	2.30	235	360	15	490
10.21	235	1.97	209	385	18	521
10.20	796 14 S	1.83	582	1,271	27	951
10.78	645 5 S	1.54	652	1,283	17	982
9.21	468 1 S	1.08	242	1,754@	21	1,334
11.12	454	1.03	318	1,852	34	1,432
9.97	2,329	2.41	838	16,280	54	2,379
10.66	1,278	1.31	706	16,329	60	2,556
10.10	16,187 345 S	2.91	11,751	40,096@	438	15,797
10.72	15,003 619 S	2.65	10,477	41,736	525	17,102

@ Figures revised.

APPENDIX XVIII

Incidence of Permanent Disablement Benefit Claims admitted In 1978-79 and 1979-80—Industry-Wise

Industry	Period	Estimated No. of employees exposed to risk	No. of accident cases admitted	Rate of P.D.B. cases per 1000 employees per annum
1	2	3	4	5
Food, Beverages and Tobacco	1978-79	3,90,650	305	0.78
	1979-80	4,33,800	187	0.43
Textiles	1978-79	19,10,950	10,746	5.62
	1979-80	19,96,750	11,947	5.98
Leather and Rubber	1978-79	1,52,000	212	1.39
	1979-80	1,55,500	167	1.07
Chemicals and Chemical—	1978-79	3,60,900	436	1.21
Products	1979-80	3,67,250	334	0.91
Non-Metallic Minerals	1978-79	2,50,350	467	1.87
	1979-80	2,58,500	327	1.26
Metallic Minerals	1978-79	4,60,400	1,209	2.63
	1979-80	4,88,950	714	1.46
Engineering	1978-79	9,05,300	1,652	1.82
	1979-80	9,22,050	970	1.05
Transport	1978-79	3,94,050	569	1.44
	1979-80	4,02,500	351	0.87
Paper and Printing	1978-79	2,42,550	342	1.41
	1979-80	2,59,100	238	0.92
Miscellaneous	1978-79	3,92,450	594	1.51
	1979-80	3,83,850	387	1.01
Commercial Establishments	1978-79	1,16,150	—	—
	1979-80	1,24,200	—	—
Hotels and Restaurants	1978-79	73,950	—	—
	1979-80	79,400	—	—
Cinemas and Theatres	1978-79	29,600	—	—
	1979-80	27,600	—	—
Total	1978-79	56,79,300	16,532	2.91
	1979-80	58,99,450	15,622	2.65

APPENDIX

The number of Legal cases filed

S. No.	Name of the Region/ Sub Region	Number of cases filed under					
		Section 66		Section 67		Section 73-D	
		Cases	Amount Rs.	Cases	Amount Rs.	Cases	Amount Rs.
1.	Andhra Pradesh	—	—	—	—	7	10,19
2.	Assam	—	—	—	—	—	—
3.	Bihar	—	—	—	—	2	428
4.	Delhi	—	—	—	—	—	—
5.	Gujarat	—	—	—	—	—	—
6.	Karnataka	—	—	—	—	—	—
7.	Kerala and Mahe	—	—	—	—	3	63,889
8.	Madhya Pradesh	—	—	—	—	—	—
9.	Bombay (including Goa)	—	—	—	—	16	28,222
10.	Nagpur	—	—	—	—	1	3,342
11.	Poona	—	—	—	—	11	14,609
12.	Orissa	—	—	—	—	—	—
13.	Punjab (including Haryana, Chandigarh & H.P.)	—	—	—	—	—	—
14.	Rajasthan	—	—	—	—	—	—
15.	Tamil Nadu (including Pondicherry)	—	—	—	—	109	9,13,054
16.	Uttar Pradesh	—	—	—	—	—	—
17.	West Bengal	—	—	—	—	84	3,29,805
	TOTAL	—	—	—		233	13,63,541

XIX

during the year 1979-80

Section 75(2) 45B		Amount recovered by action under				No. of cases in which Prosecution filed under section 85
		Section 66	Section 67	Section 73-D	Section 75(2) 45-B	
Cases	Amount Rs	Rs	Rs	Rs.	Rs	
999	45,48,010	—	—	633	2,95,136	48
26	2,64,278	—	—	—	13,286	—
230	35,40,458	—	—	—	1,88,651	35
—	50,75,363	—	—	—	5,39,468	138
220	11,54,995		—	737	10,38,190	83
734	30,10,140	—	—	—	8,24,275	17
974	34,61,527	—	—	10,015	14,66,948	4
76	3,02,078	8,358	—	26,980	3,76,601	26
308	43,54,644	10,823	—	24,842	3,38,552	99
49	6,07,168		—	3,342	47,744	22
-	—	—	—	4,494	—	81
11	53,792	—	—	—	6,75,320	4
699	82,85,631	—	—	43,536	17,66,135	66
225	13,20,749	—	—	—	11,67,972	67
332	33,89,484	—	—	1,57,820	6 42,749	30
91	20,79,687	—	—	—	8,48,546	12
320	93,05,197	—	—	9,00,755	2,47,047	119
5,294	5,16,43,201	19,181	—	11,73,154	1,04,76,570	851

APPENDIX XX

Region wise Position of ESI Arrears

Sl. No.	Region	March 1978	Arrears as at the end of March 1979 (Rs. in lakhs)	March 1980
1.	Andhra Pradesh	82.32	86.03	137.73
2.	Assam	5.42	12.13	12.86
3.	Bihar	89.08	125.49	144.23
4.	Delhi	120.91	151.21	184.78
5.	Gujarat	67.45	64.64	54.83
6.	Karnataka	112.43	137.36	86.39
7.	Kerala & Mahe	104.04	150.89	129.82
8.	Madhya Pradesh	141.51	170.34	182.92
9.	Bombay (including Goa)	256.56	304.08	317.66
10.	Nagpur (S.R.O.)	36.69	41.71	31.27
11.	Pune (S.R.O.)	85.98	61.23	71.61
12.	Orissa	24.40	31.97	74.06
13.	Punjab & Haryana (including Chandigarh & Himachal Pradesh)	110.31	168.26	266.35
14.	Rajasthan	37.39	42.93	45.42
15.	Tamil Nadu (including Pondicherry)	112.76	135.93	184.98
16.	Uttar Pradesh	216.94	241.58	286.74
17.	West Bengal	490.59	535.66	598.13
	TOTAL	2,094.78	2,461.44	2,809.78

APPENDIX XXI

Statement showing the details of Factories/Establishments which are in default of E.S.I. Dues of Rs. One Lakh and above as on 31-3-1980

Sl. No.	Name of the Factory/Establishment	E.S.I. Dues (Rs. in lakhs)
1	2	3
	(1) ANDHRA PRADESH	
1.	M/s. Anam Electrical Manufacturing Company, Kadiyam.	1.37
2.	M/s. National Seeds Corporation, Vijayawada.	2.84
3.	M/s. Hindustan Ship yards, Visakhapatnam.	2.04
4.	M/s. Tirupati Cotton Mills, Renigunta.	2.75
5.	M/s. Sri Venkatachalapathi Mills, Tirupathi.	2.19
6.	M/s. Abdus Rahim (Karim Beddi Factory) Narasampet Road, Warangal.	1.47
7.	M/s. Andhra Cotton Mills, Proddatur.	1.72
8.	M/s. Veterinary Biological Research Institute, Hyderabad.	2.94
9.	M/s. A.P. Khadi Industry Board, Kachiguda, Hyderabad.	1.59
10.	M/s. Kuga Beedi Factory, Warangal.	4.38
11.	M/s. Bandage & Gauga Cloth Mfg. Unit, Hyderabad.	1.17
12.	M/s. Adoni Cotton Mills, Adoni.	1.49
13.	M/s. APSEB, Rajahmundry.	1.57
14.	M/s. Allwyn Metals Ltd., Hyderabad.	1.12
15.	M/s. APSEB Board, Hyderabad.	2.03
16.	M/s. Azamjahi Mills, Warangal.	5.36
17.	M/s. A.P. Text Book Press, Hyderabad.	15.55
18.	M/s. Karimnagar Co-operative Spinning Mills, Karimnagar.	1.81
19.	M/s. Anthergaon Textile Co-operative Production & Sales Society, Karimnagar.	1.71
20.	M/s. Andhra Scientific Co., Machilipatnam.	4.98
21.	M/s. Drainage Stores Workshop, Hyderabad.	1.60

1	2	3
	(2) ASSAM	
	M/s. Assam Govt. Press, Gauhati.	1.95
	(3) BIHAR	
1.	M/s. TELCO, Jamshedpur.	8.13
2.	M/s. Tisco. Jamshedpur.	2.38
3.	M/s. Pradip Lamp Works, Patna City, Patna	3.28
4.	M/s. The News Paper Publication Pvt. Ltd., Patna.	1.18
5.	M/s. India Machinery Stores, Kankerbagh, Patna.	1.14
6.	M/s. R.B.H.M. Jute Mills, Katihar.	22.44
7.	M/s. Katihar Jute Mills, Katihar.	18.21
8.	M/s. Reliance Fire Bricks, Chanch, Dhanbad.	11.28
9.	M/s. Baraee Coke & Bye Product Works, P.O. Kusunda, Dhanbad.	7.16
10.	M/s. K.E.W. (P) Ltd., P.O. Kumardubi, Dhanbad.	10.36
11.	M/s. Monghyr Gun Manufacturing Co-operative Society, District Monghyr.	1.35
12.	M/s. Electric Supply Subdivision, Dehrionson, Rohtas.	1.72
13.	M/s. Eagle Rolling Mills Ltd., Kumardubi.	1.48
	(4) DELHI	
1.	M/s. A.T. Mills	1.38
2.	M/s. D.E.S.U.	149.45
3.	M/s. Caxton Press (P) Ltd.	1.21
4.	M/s. Tax Craft Exports.	1.42
5.	M/s. Fashion Export of India.	1.19
6.	M/s. India Coffee Workers Co-operative Society Ltd.	1.55
	(5) GUJARAT	
1.	M/s. Rajnagar Textile	6.58
2.	M/s. New Manekchowk Mills.	1.21
3.	M/s. Ahmedabad New Textile.	4.48
4.	M/s. Keshav Mills.	1 13
5.	M/s. P.G. Textiles.	4.66
6.	M/s. Manekchowk Ahmedabad Pvt. Mfg. Co.	8.79
7.	M/s. Anant Mills.	1.54
8.	M/s. Bodi Fort Works.	1.18
9.	M/s. Priyalaxmi Mills.	5.15
10.	M/s. Navjivan Mills.	2.08
	(6) KARNATAKA	
1.	M/s. Mysore Machinery Manufacturing Ltd.	2.52
2.	M/s. Matro Malleables Mfg. Corporation, Bangalore.	1.43
3.	M/s. National Aeronautics Ltd., Bangalore.	6.16
4.	M/s. Karnataka Agro Industries Ltd., Bangalore.	1.21
5.	M/s. Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore.	5.12
6.	M/s. Vanivilas Water Works, Mysore.	3.31
7.	M/s. K.R. Mills, Mysore.	1.57
8.	M/s. Govt. Text Book Press, Mysore.	1.46
9.	M/s. Ballary Spinning & Weaving Mills, Ballary.	4.26
10.	M/s. Karnataka Agro Industries, Corporation.	1.06
11.	M/s. Shankar Textiles, Davangera.	1.09
12.	M/s. Mahadev Textiles, Hubli.	8.07
13.	M/s. Khoday Distillery Division, Bangalore.	1.12
	(7) KERALA	
1.	M/s. Standard Tile & Clay Works, Feroke.	5.25
2.	M/s. Star Tile Works, Calicut.	1.84
3.	M/s. Malabar Spg. Wvg. Mills, Calicut.	2.55
4.	M/s. Modern Wood Crafts, Tellicherry.	1.14
5.	M/s. Kerala Ceramics, Feroke.	1 61
6.	M/s. Malabar Motor Transport Co-operative Society, Calicut.	1.28
7	M/s. Kerala Ceramics, Feroke.	1.37
8.	M/s. Parvathy Mills, Quilon.	2.63
9.	M/s. Alagappa Textiles Govt. (P) Ltd., Trichur.	5 79
10.	M/s. Janayugom Publications Pvt. Ltd., Quilon.	1.85
11.	M/s. Thomson Cashew Factory, Mughathala, Quilon.	1.64

1	2	3
12.	M/s. Younus Kunju Cashew Factory, Quilon.	1.[illegible]
13.	M/s. Palghat Co-operative Milk Supply Union Ltd., Palaghat.	1.32
14.	M/s. Azhikode Beedi Workers Industries, Cannanore.	2.31
15.	M/s. Payyannur Beedi Workers Industrial Co-operative Society, Cannanore.	2.08
16.	M/s. Shanmughavilas Cashew Industries, Quilon.	1.72
17.	M/s. India Sea Foods, Cochin.	1.13
18.	M/s. Shanmughavilas Cashew Industries, Quilon.	1.10
19.	M/s. Shanmughavilas Cashew Industries, Kottanakkara.	1.42
20.	M/s. General Indl. Corporation, Quilon.	1.90
	(8) MADHYA PRADESH	
1.	M/s. Burhanpur Tapti Mills, Burhanpur.	2.41
2.	M/s. New Bhopal Textiles Mills, Bhopal.	6.32
3.	M/s. J.C. Mills, Gwalior.	1.50
4.	M/s. Hira Mills, Ujjain.	7.32
5.	M/s. Malwa United Mills, Indore.	40.27
6.	M/s. Kalyanmal Mills, Indore.	11.10
7.	M/s. Swadeshi Cotton and Flour Mills, Indore.	13.31
8.	M/s. Hope Textile Mills, Indore.	33.09
9.	M/s. Sound Zawarod Union, Gwalior	2.09
10.	M/s. Central India Machinery Mfg. Co., Gwalior.	1.49
11.	M/s. J.B. Mangharam & Co., Gwalior.	3.33
12.	M/s. D.N.C. Mills, Rajnandgaon.	6.65
13.	M/s. Agricultural Engg. Workshop, Gwalior.	1.13
14.	M/s. M.P.S.R.T.C., Raipur.	1.26
15.	M/s. Binod Steel Ind., Indore.	1.36
16.	M/s. Hitwad Press, Bhopal.	1.04
	(9) MAHARASHTRA (BOMBAY INCLUDING GOA)	
1.	M/s. Alcock Ashdown Co. Ltd.	4.07
2.	M/s. New Hind Textile Mills.	1.01
3.	M/s. Apollo Text Mills.	2.28
4.	M/s. Bradbury Mills Ltd.	41.15
5.	M/s. Shree Shakti Mills Ltd.	3.14
6.	M/s. Sitaram Ltd.	8.10
7.	M/s. Digvijay Spg. & Wvg. Co. Ltd.	8.76
8.	M/s. India United Mills.	7.28
9.	M/s. India United Mills.	6.53
10.	M/s. India United Mills.	7.33
11.	M/s. India United Mills.	13.36
12.	M/s. Lakhmiratan Engg. Works.	1.92
13.	M/s. Edward Text. Mills.	5.77
14.	M/s. Dhanraj Mills.	2.04
15.	M/s. Bombay Textile Mills.	1.39
16.	M/s. Phoenix Mills Ltd.	18.52
17	M/s. New India Rayon Mills.	7.79
18.	M/s. Mackenxies Ltd.	2.93
19.	M/s. Western India Mfg. Co.	11.08
20.	M/s. Premier Rubber & Cable.	1.31
21.	M/s. Bombay Fine Art.	1.34
22.	M/s. India United Mills.	4.60
23.	M/s. India United Mills.	4.41
24.	M/s. Eupharma Lab.	1.05
25.	M/s. Bombay Alloys & Casting.	1.45
26.	M/s. Allvin Caredrills (P) Ltd.	1.84
27.	M/s. Krishna Glass.	2.80
28.	M/s. Eldee Wire & Ropes.	1.56
29.	M/s. India Shoddy Mills.	1.17
30.	M/s. Radha Dyeing & Printing Mills.	1.47
31.	M/s. Krishna Weaving Mills.	2.66
32.	M/s. Sun-n-Sand Hotel.	2 70
33.	M/s. Government Gargage.	1.31
34.	M/s. Pioneer Rubber Mills.	2.13
35.	M/s. Century Rayon.	1 30
36.	M/s. K.T. Steel.	1.11

1	2	3
37.	M/s. Shri Krishna Woollen Mills, Pvt., Ltd.	1.48
38.	M/s. Deoner Abbattoir.	4.54
39.	M/s. Ellora Silk Mills.	3.10
40.	M/s. Structural Engg.	1.50
	NAGPUR (S.R.O.)	
1.	M/s. R.S.R.G. Mohta Mills, Akola.	1.55
2.	M/s. Osmanshahi Mills, Nanded.	8.56
3.	M/s. Maharashtra State Electricity Board, Akola.	1.29
4.	M/s. Mechanical Division, Nanded.	1.72
	PUNE (S.R.O.)	
1.	M/s. Agricultural Engg. Workshop, Pune.	2.18
2.	M/s. Beamwireless Station, Pune.	1.35
3.	M/s. Indian Meteorological Workshop, Pune.	2.31
4.	M/s. Solapur Municipal Workshop, Solapur.	1.90
5.	M/s. Solapur Spg. Wvg., Solapur.	3.01
6.	M/s. Jayashankar Mills, Barsi, Solapur.	1.33
7.	M/s. Sangli Municipal Works, Sangli.	1.05
8.	M/s. M.S.E.B., Satara.	2.42
9.	M/s. New Pratap Spg. & Wvg. Mills, Dhule.	4.13
	(10) ORISSA	
1.	M/s. Saraswat Press, Cuttack.	1.00
2.	M/s. Satyavadi Press, Cuttack.	3.16
3.	M/s. Durga Glass Works, Barang.	1.65
4.	M/s. Berhampur Electricity Supply Corporation Ltd., Berhampur.	1.07
5.	M/s. Prajatantra Prachar Samity, Cuttack.	1.77
6.	M/s. Orissa Textile Mills, Choudwar.	21.47
7.	M/s. Orissa Cement Ltd., Rajgangpur.	2.35
8.	M/s. Kalinga Tubes Ltd., Choudwar.	2.28
9.	M/s. Hirakud Industrial Works, Sambalpur.	1.05
10.	M/s. P.W.D. Workshop, Bhubaneswar.	2.22
11.	M/s. Orissa State Co-operative Marketing Society, Bhubaneswar.	1.23
12.	M/s. O.R.T. Company, Berhampur.	1.33
13.	M/s. Text Book Press, Bhubaneswar.	4.57
14.	M/s. O.R.T. Company, Cuttack.	1.32
15.	M/s. Orissa State Road, Transport Corporation, Cuttack.	2.80
16.	M/s. O.R.T. Co., Berhampur.	1.67
	(11) PUNJAB (INCLUDING CHANDIGARH)	
1.	M/s. Punjab Roadways Workshop, Amritsar.	1.30
2.	M/s. Municipal Power House, Amritsar.	20.83
3.	M/s. Haryana Govt. Printing Press, Chandigarh.	2.70

1	2	3
4.	M/s. Pepsu Roadways Transport Corporation, Patiala.	4.18
5.	M/s. Chandigarh Transport Undertaking, Chandigarh.	1.28
6.	M/s. Oswal Spg., & Wvg. Mills, Ludhiana.	1.05
7.	M/s. New Suraj Transport Co. (P) Ltd., Amritsar.	2.70
	(12) HARYANA	
1.	M/s. Laxmi Rattan Engg. Works, Faridabad.	1.48
2.	M/s. Haryana Roadways Workshop, Karnal.	1.18
3.	M/s. Electrical Construction Co., Sonepat.	3.10
4.	M/s. Dalima Dadri Cement Ltd., Dadri.	3.32
	(13) RAJASTHAN	
1.	M/s. Man Industrial Corporation, Jaipur.	3.13
2.	M/s. Jaipur Udyog, Swaimadhopur.	2.37
3.	M/s. S. Zorestor & Co., Jaipur.	1.03
4.	M/s. Dholpur Glass & Work, Dholpur.	1.01
5.	M/s. Jaipur Glass Potteries Works, Jaipur.	1.09
6.	M/s. Mahalaxmi Mills, Beawar.	2.53
7.	M/s. Water Works, Bikaner.	2.02
8.	M/s. Water Works, Jodhpur.	1.95
9.	M/s. Water Works, Kota.	1.87
10.	M/s. Water Works, Udaipur.	2.28
11.	M/s. Chambal Project (Workshop), Kota.	1.08
12.	M/s. Akalgarh Head Water Works, Kota.	2.87
13.	M/s. Rajasthan Canal Board, Bikaner.	1.05
14.	P.W.D., Jaipur.	1.62
	(14) TAMIL NADU	
1.	M/s. Somasundaram Mills.	5.83
2.	M/s. Kaleeswara Mills.	6.03
3.	M/s. Pankeja Mills.	1.20
4.	M/s. Prakash Mills.	1.16
5.	M/s. Enfield India Ltd.	1.26
6.	M/s. Pilot Pen. Co.	2.05
7.	M/s. Bharathi Mills.	4.36
8.	M/s. Swadeshi Cotton Mills.	10.18
9.	M/s. Anglo French Textiles.	16.42
10.	M/s. Ramalinga Chodambika Mills.	1.98
11.	M/s. Bhavani Mills.	1.56
12.	M/s. Measurall Engg.	1 82
13.	M/s. Indian Refrigeration.	2.17
14.	M/s. Madras Machine Tools.	3.31
15.	M/s. Kamadhenu Drinks.	1.40
16.	M/s. Mahalakshmi Textile.	7.65

1	2	3
17.	M/s. Palaniappa Match Industries.	1.02
18.	M/s. South India Glass & Enamel Works.	2.44
19.	M/s. Dinamani Press.	1.88
20.	M/s. Chemfab Welders.	2.07
21.	M/s. Sudarsan Finance Corporation.	2.91
22.	M/s. Southern Petro Chemical Inds., Corporation	1.13
23.	M/s. Coromondal Steels.	1.11
	(15) UTTAR PRADESH	
1.	M/s. Muir Mills, Kanpur	21.18
2.	M/s. New Victoria Mills, Kanpur.	11.62
3.	M/s. Swadeshi Cotton Mills, Kanpur.	25.78
4.	M/s. Alberton West & Co., Kanpur.	29.95
5.	M/s. Laxmi Ratan Cotton Mills, Kanpur.	16.67
6.	M/s. Kanpur Sahkari Mills Board, Kanpur.	17.79
7	M/s. Kanpur Jute Udyog, Kanpur.	4.76
8	M/s. R.S. Steel Works	1.99
9.	M/s Amausi Textile.	3.36
10.	M/s. Moradabad Spg. & Wvg. Mills	8.62
11.	M/s. Water Works, Lucknow.	3.57
12.	M/s. Tigar Products Aligarh.	3.39
13.	M/s. Allahabad Works, Naini.	1.82
14.	M/s. Water Works, Allahabad.	2.31
15.	M/s. Water Works, Allahabad	3.36
16.	M/s. Lord Krishna Textile, Saharanpur.	4.09
17.	M/s. Amitabh Textile.	3.32
18.	M/s. Durga Enterprises, Ghaziabad.	1.50
19.	M/s. R.R. Engg. Bldy.	1.46
20.	M/s. Punjab Oil Mills	1.36
21	M/s. Meerut Estraw Board	2.07
22.	M/s Sadilal Distillary.	1.05
23.	M/s. Water Works Depot.	1.37
24.	M/s. Associated Journal.	6.41
25.	M/s. Water Works, Lucknow	2.63
26.	M/s. Bijli Cotton Mills	8.35
27.	M/s. Bharat Heavy Electricals	55.21
	(16) WEST BENGAL	
1	M/s National Company Limited.	21.27
2	M/s. Sree Ambika Jute Mills Ltd.	8.66
3	M/s. Naskarpara Jute Mills Co., Ltd	1.29
4	M/s. Premchand Jute Mills Co., Ltd	22.00
5.	M/s Bharat Jute Mills Limited.	4.92
6.	M/s. India Rubber Mfg., Ltd	1.33
7.	M/s Govindadeo Glass Wks Ltd.	1.11
8	M/s. National Iron & Steel Co., Ltd.	2.12

1	2	3
9.	M/s. Markendeoprasad Radhakrishna Private, Limited.	1 00
10.	M/s. Bharat Iron & Steel Co., Private, Limited.	1 98
11.	M/s. National Screw Wire (P) Ltd.	1.09
12.	M/s. Howrah Iron & Steel Wks. (P) Limited.	1.55
13.	M/s. Indian Machinery Company, Ltd.	2.56
14.	M/s. Hooghly Docking & Engg. Co., Limited.	1.61
15.	M/s. Salimar Works.	5.89
16.	M/s. Central Cotton Mills Ltd.,	1.12
17.	M/s. Belur Glass Works (P) Ltd.,	1.41
18.	M/s. Agarwal Hardware Industries,	1 37
19.	M/s. Fort Gloster Industries Ltd. (Cable Division)	2.08
20.	M/s. Basumati Private Limited.	1.34
21.	M/s. Lynx Machinery Company.	1.44
22.	M/s. Basumati Corporation Ltd.	1.36
23.	M/s. Lily Biscuit Co.(P) Ltd.	1.56
24.	M/s. Sree Mahaluxmi Cotton Mills.	4.79
25.	M/s. Bamgasshree Cotton Mills.	1.26
26.	M/s. Mohini Mills Ltd. No. 2	5.34
27.	M/s. Union Jute Co. Ltd. (North Mill)	3.83
28.	M/s. Khardah Jute Mills.	7.38
29.	M/s. Kelvin Jute Mills.	11.45
30.	M/s. Budge Budge Amalgamated Mills Ltd.	1.45
31.	M/s. Meghna Mills Co. Ltd.	1.31
32.	M/s. Alexander Jute Mills Ltd.	7.47
33.	M/s. Victory Jute Mills.	1.36
34.	M/s. Kinison Jute Mills No. 2	21.47
35.	M/s. Eastern Mfg. Co. Ltd.	10.32
36.	M/s. Canton Carpentory Works Pvt. Ltd.	2.22
37.	M/s. Alak Udyog Vanaspati & Plywood (1971)	5.07
38.	M/s. Titagarh Paper Mills Co. Ltd.	1.71
39.	M/s. India Paper & Pulp Co.	3.26
40.	M/s. Union Paper & Board Mills Ltd.	1.53
41.	M/s. International Rubber Manufacturing Company.	1.50
42.	M/s. Bata (India) Ltd.	4.92
43.	M/s. National Rubber Manufacturing Ltd.	5.76
44.	M/s. Associated Rubber & Mfg. Works	1.35
45.	M/s. Hindustan Lever Ltd.	1.30
46.	M/s. Bird & Company (Process Engineering Division)	1.22
47.	M/s. Calcutta Glass & Silicate Works (1936) Pvt. Ltd.	1.38
48.	M/s. Krishna Silicate & Glass Works.	2.56
49.	M/s. Bengal Potteries Ltd.	16.40
50.	M/s. Sodepur Potteries (P) Ltd.	1.25
51.	M/s. Hindustan Iron & Steel Company.	1.61
52.	M/s. Soor & Company.	1.82
53.	M/s. India Malleable Casting Ltd.	3.80
54.	M/s. Aluminium Mfg. Co. (I) Ltd.	1.00

		3
55.	M/s. Bengal Enamel Works Ltd.	2.92
56.	M/s. Annapurna Metal Works.	2.64
57.	M/s. N.G.T. Engineering (P) Ltd	1.55
58.	M/s. Associated Aesbey Industries Ltd.	1.99
59.	M/s. Britannia Engg. Co. (I) Ltd	2.49
60	M/s. Maya Engg. Works (P) Ltd.	1.11
61.	M/s. Bery Machinery Mfg. (P) Ltd.	1.09
62	M/s. Motor Machinery Mfg Co	3.51
63.	M/s. National Carbon Company (Division of UCI Ltd.)	4.48
64.	M/s. East Bengal Engg. Works	4.00
65.	M/s. C.T.C. Ltd. (Monapukur Workshop)	17.11
66.	M/s. Gupta's Pencil Industries Pvt. Ltd.	1.00
67.	M/s. Indian Oxygen Ltd.	2.84
68.	M/s. Bengal Steam Laundry	1.56
69.	M/s. Indian Airlines Corporation.	1.26
70.	M/s. Carter Pooller & Co. Ltd.	3.10
71.	M/s. Poddar Sanitary Works.	1.38
72.	M/s. C.T.C. Ltd. (Belgachia Depot)	2.96
73.	M/s. C.T.C. Ltd. (Kidderpore Depot)	1.89
74.	M/s. C.T.C. Ltd. (P/Circus Depot)	1.64
75.	M/s. C.T.C. Ltd. (Rajabazar Depot)	2.83
76.	M/s. C.T.C. Ltd. (Tollygunge Depot)	1.58
77.	M/s. C.T.C. Ltd. (Garlahat Depot)	1.79
78.	M/s. Stadmed Pvt. Ltd.	2.11
79.	M/s. Directorate of Transportation (Belghoria Depot)	1.04
80.	M/s. Directorate of Transportation (Lake Depot)	1.14
81.	M/s. The Metal Box Co. of India Ltd.	3.30
82.	M/s Bengal Potteries Ltd	10.39
83.	M/s. Modern India Construction Company Ltd.	2.35
84.	M/s Shrikrishna Rubber Works Ltd.	1.15
85.	M/s. Original Machinery & Civil Construction Ltd.	1.16
86.	M/s. Kolay Iron & Steel Company	4.59
87.	M/s. Kiran Gas Co. (Cal) Pvt. Ltd.	1.45
88.	M/s. Andaman Timber (I) Ltd.	2.01
89.	M/s Kelvin Jute Co Ltd (Bread Loom Sec.)	2.70
90.	M/s Bengal Luxmi Cotton Mills.	8.46
91.	M/s Shree Durga Cotton Spg. & Wvg Mills Ltd	2.45
92.	M/s. Rampuria Cotton Mills.	5.93
93.	M/s. Keymer Bagshaw Mfg. Co. (P) Ltd	1.38
94.	M/s. Luxminarayan Cotton Mills.	6.63
95.	M/s. Bengal Fine Spng. & Wvg. Mills Ltd.	3.38
96.	M/s. Shree Engg. Products Ltd.	1.10
97.	M/s. Durgapur Chemical Ltd.	1.05
98.	M/s. Atlas Works (P) Ltd.	1.04
99.	M/s Krishna Silicate & Glass Works Ltd	1.20
100.	M/s Kalyani Spg. Mills Ltd. (No. 2)	6.72

APPENDIX

EMPLOYEES' STATE

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

EXPENDITURE

Previous year (1978-79)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs
	1. Benefits to Insured Persons & their families.		
	A. Medical Benefits.		
	(i) Payments to State Govts. as Corporation's Share of the expenses on providing medical treatment and maternity facilities etc.	60,23,42,106 A	
49,90,29,859			
	(ii) Medical care and maternity facilities (expenses incurred direct by the Corporation).	3,35,85,407	
2,97,00,515			
52,87,30,374	Total A—Medical Benefits.		63,59,27,513
	B. Cash Benefits.		
33,50,40,594	1. Sickness Benefit.	42,96,75,462 B	
3,14,41,961	2. Extended Sickness Benefit	3,25,97,884	
6,08,336	3. Enhanced Sickness Benefit for Family Planning	6,51,570	
1,73,89,593	4. Maternity Benefit.	1,94,90,537	
	5 Disablement Benefit.		
6,45,53,267	(a) Temporary	6,93,67,776	
6,38,60,000	(b) Permanent (Capitalised Value).	6,50,83,000	
	6. Dependants' Benefit.		
1,44,68,000	(Capitalised Value)	1,76,48,000	
9,70,530	7. Funeral Benefit.	10,08,398	
52,83,32,281	Total B—Cash Benefits.		63,55,22,627
	C. Other Benefits.		
	(a) Expenditure on the Rehabilitation of Disabled Insured		
28,424	Persons.	7,523	
3,74,438	(b) Medical Boards & Appeal Tribunals.	4,48,754	
	(c) Payments to Insured Persons.		
3,42,560	(i) Conveyance charges and/or loss of wages.	3,57,660	
50	(ii) Incidental charges under Family Planning.	—	
6,42,799	(d) Miscellaneous.	9,18,182 I	
13,88,271	Total C—Other Benefits.		17,32,119
1,05,84,50,926	Total Benefits to Insured Persons & their families.		1,27,31,82,259
	2 Administration Expenses		
	A. Superintendence.		
54,960	1. Corporation, Standing Committee, Regional Boards etc.	69,013	
2,04,345	2. Principal Officers	1,98,232	
58,29,336	3. Other Officers.	61,73,200	
3,00,47,548	4. Ministerial Establishment.	3,36,26,149	
50,26,425	5. Group D Staff.	54,26,092	
1,03,09,418	6. Contingencies.	1,21,06,975	
5,14,72,032	Total A—Superintendence.		5,75,99,661
	B—Field Work		
14,64,847	1. Officers.	19,00,798	
2,97,84,952	2. Ministerial Establishment.	3,33,56,058	
45,52,562	3. Group D Staff	50,71,313	
39,10,651	4. Contingencies.	39,49,877	
3,97,13,012	Total B—Field Work.		4,42,78,046
1,14,96,35,970	Total Carried over.		1,37,50,59,966

Note :— A. See paragraph 1.1 of the explanatory notes in Annexure I.
B. See paragraph 1.2 of the explanatory notes in Annexure I.
I. See paragraph 1.9 of the explanatory notes in Annexure I.

XXII

INSURANCE CORPORATION

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1980

INCOME

Previous year (1978-79)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	1. Contributions.		
1,45,78,73,675	Employers' and Employees' Shares.	1,58,68,28,298 C	
17,57,264	Employers' Share only.	15,72,055 D	
71,05,946	Employees' Share only.	77,46,520 D	
8,57,102	Interest on Contributions.	14,57,288	
1,46,75,93,987	Total Contributions.		1,59,76,04,161
1,10,49,500	State Government/Union Territories share towards medical benefits initially incurred by the Corporation.	28,21,875	
1,10,49,500			28,21,875
	Other Heads of Revenue.		
5,28,26,924	Interest & Dividends.	4,88,70,143 E	
42,33,772	Compensations.	48,42,590 F	
	Rents, Rates and Taxes.		
7,26,478	(i) Offices of the Corporation (including Staff Quarters).	7,92,757	
3,55,53,611	(ii) Hospitals, Dispensaries and Staff Quarters).	3,85,18,880	
30,07,792	Fees, Fines & Forfeitures,	32,52,980 G	
15,56,277	Miscellaneous.	17,00,879 H	
9,79,04,854	Total of other Heads of Revenue.		9,74,76,229
1,57,65,48,341	Total Carried Over.		1,69,79,04,265

C. See paragraph 1.3 of the explanatory notes in Annexure I.

D. See paragraph 1.4 of the explanatory notes in Annexure I.

E. See paragraph 1.5 of the explanatory notes in Annexure I.

F. See paragraph 1.6 of the explanatory notes in Annexure I

G. See paragraph 1.7 of the explanatory notes in Annexure I

H. See paragraph 1.8 of the explanatory notes in Annexure I.

Previous Year (1978-79)	Heads of Account	Amount		Total
1,14,96,35,970	Total Brought Forward.			1,37,50,59,966
	C. Other Charges.			
5,13,116	1. Legal Charges.	4,85,068		
67,752	2. Insurance Courts.	53,445		
1,05,851	3. Publicity & Advertisement Charges.	1,37,783		
8,45,465	4. Charges for maintaining Banking Accounts.	99,226	J	
2,55,430	5. Audit Fees.	2,16,298		
1,38,869	6. Leave Salary & Pension Contributions.	1,07,964		
3,54,834	7. Depreciation of Office Building/Staff Cars.	3,70,872		
9,66,332	8. Repairs and Maintenance of Office Buildings.	9,93,727		
	9. Retirement Benefits.			
12,44,042	(a) Pension Reserve Fund for the employees of the Corporation.	53,42,509	K	
2,58,737	(b) Corporation's Contribution towards Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.	39,401	K	
34,24,462	(c) Interest paid to ESIC Provident Fund.	37,01,309		
24,261	(d) Incentive Bonus.	1,57,579		
35,000	10. Compassionate Reserve Fund.	35,000		
80,000	11. Provident Fund Deposit-Linked Insurance Fund.	90,000		
12	12. Losses.	9,000		
4,227	13. Miscellaneous.	39,532	L	
83,18,390	Total C—Other Charges.			1,18,78,713
9,95,03,434	Total Head 2—Administration Expenses.			11,37,56,420
	3. Hospitals and Dispensaries.			
36,44,523	1. Provision for depreciation of Hospital Buildings transferred to Fund.	47,88,913		
1,05,69,117	2. Provision for Repair & Maintenance of Hospitals/Dispensaries transferred to fund.	1,38,87,848		
1,42,13,640	Total Head 3—Hospitals & Dispensaries.			1,86,76,761
	4. Capital Construction/Emergency Reserve Fund.			
14, 67,59,400	1. Capital Construction.	15,97,60,416	M	
5,15,24,188	2. Emergency Reserve Fund.	2,65,03,682	N	
19,82,83,588	Total Head 4—Capital Construction/Emergency Reserve Fund.			18,62,64,098
1,37,04,51,588	Total Expenditure on Revenue Account.			1,59,18,79,538
20,60,96,753	To excess of Income over Expenditure carried over to Balance Sheet.	10,60,24,727		10,60,24,727
1,57,65,48,341	GRAND TOTAL			1,69,79,04,265

New Delhi,
Dated 31st May, 1980.

J See paragraph 1.10 of the explanatory notes in Annexure-I.

K. See paragraph 1.11 of the explanatory notes in Annexure-I.

L See paragraph 1 12 of the explanatory notes in Annexure-I

M. See paragraph 1.13 of the explanatory notes in Annexure-I

N. See paragraph 1.14 of the explanatory notes in Annexure-I.

Previous year (1978-79)	Heads of Account	Amount	Total
1,57,65,48,341	Total Brought Forward.		1,69,79,04,265
1,57,65,48,341	GRAND TOTAL		1,69,79,04,265

M. L. SOBTI, Financial Advisor &
Chief Accounts Officer
Employees' State Insurance Corporation

APPENDIX

EMPLOYEES' STATE

Balance Sheet as at

Previous year (1978-79)	*Liabilities*	*Amount*	*Total*
Rs.		Rs.	Rs.
	Balance of excess of Income over Expenditure.		
1,36,35,52,434	As per last Balance Sheet.	1,56,96,49,187	
20,60,96,753	Addition during the year.	10,60,24,727	
1,56,96,49,187	RESERVE FUNDS		1,67,56,73,914
	1. Capital Construction Reserve Fund.		
58,65,21,536	As per last Balance Sheet.	74,89,66,131	
14,67,59,400	ADD provision made during the year.	15,97,60,416	
1,56,85,195	Interest received from Investments.	1,38,19,243	
74,89,66,131			A 92,25,45,790
	2. Permanent (Partial & Total) Disablement Benefit Reserve Fund.		
17,43,15,231	As per last Balance Sheet.	18,62,85,906	
6,38,60,000	Provision made during the year.	6,50,83,000	
89,54,711	Interest received from Investments.	70,66,776	
24,71,29,942	Total carried over of this Head.	25,84,35,682	
(—)6,08,44,036	LESS payments made during the year.	(—)5,78,70,146	
18,62,85,906			20,05,65,536
	3. Dependants' Benefit Reserve Fund.		
9,57,86,859	As per last Balance Sheet.	10,51,06,740	
1,44,68,000	Provision made during the year.	1,76,48,000	
49,20,649	Interest received from Investments.	39,87,292	
(—)1,00,68,768	LESS payments made during the year.	(—)1,18,59,142	
10,51,06,740			11,48,82, 890
	4. Employees' State Insurance B. B. Corporation Provident Fund.		
4,12,24,332	As per last Balance Sheet.	4,88,54,926	
	ADD amount credited during the year.		
1,23,56,746	(i) Employees' Subscription.	1,38,09,901	
2,65,372	(ii) Corporation's Contribution.	39,401	
34,24,462	(iii) Interest on (Employee's & Corporation's shares).	37,01,309	
24,261	(iv) Incentive Bonus.	1,57,579	
5,72,95,173	Total carried over of this Head.	6,65,63,116	

2,61,00,07,964	Total Carried Over	2,91,36,68,130

A. See Receipt and Payment Account in Statement 'A'.

B. B. See Statement 'D'.

XXIII

INSURANCE CORPORATION

31st March, 1980

Previous year (1978-79)	*Assets*	*Amount*	*Total*
Rs.		Rs.	Rs.
	Lands and Buildings (wholly owned by the Corporation).		
	(a) Buildings for Offices of the Corporation.		
2,00,22,893	As per last Balance Sheet.	3,09,71,171	
1,09,48,278	Additions during the year.	64,89,351	
3,09,71,171	Total (a)	3,74,60,522	
	(b) Hospitals & Dispensaries.		
32,32,08,822	As per last Balance Sheet.	43,05,68,012	
10,73,59,190	Additions during the year.	7,98,66,232	
43,05,68,012	Total (b)	51,04,34,244	
46,15,39,183			54,78,94,766 B
	Lands and Buildings (Jointly owned by the Corporation and State Governments)—Corporation's share. Hospitals and Dispensaries.		
9,26,807	As per last Balance Sheet.	9,26,807	
—	Additions during the year.	2,58,278	
9,26,807			11,85,085
	Amount advanced for capital expenditure.		
	(a) Amount advanced from General Cash Balance.		
4,54,36,075	As per last Balance Sheet.	4,03,95,046	
54,469	ADD payments made during the year.	—	
(—)50,95,498	LESS adjustments and recoveries	(—)41,51,368	
4,03,95,046	Total (a)	3,62,43,678	
19,18,99,835	(b) Amount advanced from Capital Construction Reserve Fund. As per last Balance Sheet.	15,87,69,716	
8,05,49,148	ADD Payments made during the year.	6,63,80,460	
(—)11,36,79,267	LESS adjustments and recoveries	(—)8,37,13,516	
15,87,69,716	Total (b)	14,14,36,660	
19,91,64,762	Staff Cars.		17,76,80,338
5,65,196	As per last Balance Sheet.	5,65,196	
—	Additions during the year.	—	
5,65,196			5,65,196
66,21,95,948	Total Carried Over		72,73,25,38

B. See paragraph 2.1 of the explanatory notes in Annexure-II.

Previous year (1978-79)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,61,00,07,964	Total Brought Forward.		2,91,36,68, 13
5,72,95,173	Total Brought Forward of the Sub-Head	6,65,63,116	
(—)84,26,704	Less Payments made during the year.	(—)1,06,61,268	
	LESS amount transferred to :		
(—)6,635	(i) Pension Reserve Fund	(—)37,41,674	
(—)6,908	(ii) Unclaimed Deposit	(—) 35,108	
4,88,54,926			5,21,25,066
	5. Provident Fund Deposit—Linked Insurance Fund.		
75,063	As per last Balance sheet.	1,08,482	
80,000	Provision made during the year.	90,000	
3,853	Interest and Gain recived from Investments.	4,055	
(—)50,434			
1,08,482	LESS payments made during the year.	(—)36,614	
	6. Employees' state Insurance Corporation—Group Insurance Fund.		1,65,923
—	As per last Balance Sheet.	75,880	
3,15,880	Constribution received during the year.	4,93,928	
—	Interest and Gain received from Investments.	2,857	
—	Amount received from Life Insurace Corporation	65,000	
(—)2,40,000	LESS 'Premium paid to Life Insurance Corporation.	(—)1,88,858	
—	Assured sums paid to beneficiaries.	(—)10,000	
—	Endowment benefit paid on Retirement.	(—)120	
75,880			4,38,687
	7. Depreciation Reserve Fund of buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
30,73,809	As per last Balance Sheet.	35,64,911	
3,33,218	Provision made during the year.	3,42,670	
1,57,884	Interest and Gain received from Investments.	1,35,309	
35,64,911			
			40,42,890
	8. Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings.		
3,44,63,168	As per last Balance Sheet.	3,98,78,158	
36,44,523	Provision made during the year.	47,88,913	
17,70,467	Interest received from Investments.	15,12,736	
3,98,78,158			4,61,79,807
	9. Depreciation Reserve Fund of Staff Cars.		
5,95,318	As per last Balace Sheet.	6,12,202	
21,616	Provision made during the year.	28,202	
28,848	Interest received from Investments.	23,136	
(—)33,580	LESS payments made during the year.	(—)41,826	
6,12,202			6,21,714
	10. Repairs and Maintenance Reserve Fund of buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
49,41,497	As per last Balance Sheet.	56,12,696	
9,66,332	Provision made during the year.	9,93,727	
1,43,929	Interest received from Investments.	1,06,735	
(—)4,39,062	LESS amount adjusted on receipt of certified statements of expenditure.	(—)7,33,477	
56,12,696	11. Repairs and Maintenance Reserve Fund of Hospital buildings.		59,79,681 C
7,13,44,246	As per last Balance Sheet.	8,19,81,321	
1,05,69,117	Provision made during the year.	1,38,87,848	
24,76,467	Interest recieved from Investments.	20,47,060	
	LESS amount adjusted on receipt of certified statements of expenditure.		
(—)24,08,509		(—)60,52,312	
8,19,8,321			9,18,63,917 D
2,79,06,96,540	Total Carried Over		3,11,50,85,815

C. See Receipt and Payment Account in Statement-B.
D. See Receipt and Payment Account in Statement-C.

Previous year (1978-79)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
66,21,95,948	Total Brought Forward.		72,73,25,385
	Permanent Advance to the Heads of Offices of the Corporation.		
78,766	As per last Balance Sheet.	86,911	
8,385	ADD payments made during the years.	5,120	
(—)240	LESS recoveries made during the year.	(—)1,000	
86,911	Advance of pay on transfer to the Employees of the corporation.		91,031
20,358	As per last Balance sheet.	28,547	
1,16,471	ADD payments made during the year.	1,51,396	
(—)1,08,282	LESS recoveries made during the year.	(—)1,05,930	
28,547	Advance of T.A. on transfer to the Employees of the Corporation.		74,013
79,236	ADD payments made during the year.	95,064	
1,78,346		1,54,562	
(—)1,62,518	LESS recoveries made during the year.	(—)1,37,772	
95,064			1,11,854
	Advance for the purchase of Conveyance to the Employees of the Corporation.		
10,40,944	As per las Balace Sheet.	13,54,727	
9,86,490	ADD paymemts made during the year.	9,78,021	
(—)6,72,607	LESS recoveries made during the year.	(—)7,66,157	
13,54,727	Miscellaneous Advances to the Employees of the Corporation (Festival Advances, Flood Advances and Fan Advances).		15,66,591
6,60,672	Axs per last Balance Sheet.	28,98,729	
32,94,188	ADD payments made during the year.	18,73,966	
(—)10,65,131	LESS recoveries made during the year.	(—)25,73,823	
28,98,729	House Building Advance.		21,98,872
83,81,477	As per last Balance Sheet.	99,57,060	
27,57,935	ADD payment made during the year.	26,39,100	
(—)11,82,352	LESS recoveries made during the year.	(—)6,45,252	
99,57,060	Advance payments on behalf of State Governments.		1,09,50,908
1,463	As per last Balance Sheet.	1,327	
2,358	ADD Payments made during the year.	1,860	
(—)2,494	LESS recoveries made during the year.	(—)948	
1,327			2,239
	Amount advanced to State Govt./ State P.W.D. etc. towards Repairs and Maintenance of Hospitals/Dispensaries/Offices of the Corporation and Staff Quarters.		
	(a) Offices of the Corporation.		
21,37,929	As per last Balance Sheet.	28,00,546	
10,48,311	ADD payments made during the year.	11,17,049	
(—)3,85,694	LESS Cash refunds.	(—)5,91,250	
28,00,546			33,76,345
	(b) Hospitals/Dispensaries/Annexes.		
2,31,36,821	As per last Balance Sheet.	2,80,17,996	
64,54,893	ADD payments made during the year.	1,11,27,409	
(—)15,73,718	LESS cash refunds.	(—)35'85,218	
2,80,17,996			3,55,60,187
	Miscelaneous Advances. E.		
20,82,545	As per last Balance Sheet.	5,49,008	
15,04,776	ADD payments made during the year.	30,43,537	
(—)20,38,313	LESS receipts during the year.	(—)23,87,155	
15,49,008			22,05,390
70,89,85,863	Total Carried Over.		78,34,62,815

E. See paragraph 2.2 of the explanatory notes it Annexure-II.

Previous year (1978-79)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,79,06,96,540	Total Brought Forward.		3,11,50,85,815
	12. Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
7,85,80,959	As per last Balance Sheet.	8,29,87,739	
51,71,765	Provision made during the year	60,22,295	
40,36,770	Interest received from Investments.	31,48,153	
(—)33,66,688	Adjustment as per 5th quinquennial Report on Valuation	—	
(—)14,41,702	LESS payments made during the year.	(—)19,80,077	
6,635	ADD amount trasnferred from ESIC Provi-		
8,29,87,739	dent Fund	37,41,674	9,39,19,784
	13. Emergency Reserve Fund.		
28,33,47,207	As per last Balance Sheet.	34,94,27,240	
5,15,24,188	Provision made during the year.	2,65,03,682	
1,45,55,845	Interest realsed on Investments.	1,32,55,332	
34,94,27,2400			38,91,86,254
	14. Compassionate Reserve Fund for the Employess of the Corporation.		
10,000	As per last Balance Sheet.	27,768	
35,000	Provision made during the year.	35,000	
521	Interest received from Investments.	1,013	
(—)17,753	LESS payments made during the year.	(—)37,479	
27,768			26,302
	Deposits.		
	Deposits of Securities.		
3,85,964	As per last Balance Sheet.	5,94,014	
5,33,608	ADD deposits during the year.	6,90,720	
(—)3,25,558	LESS deposits repaid during the year.	(—)3,86,937	
5,94,014			8,97,797
	Deduction from bills payable to other parties.		
31,755	As per last Balance Sheet.	57,378	
14,08,355	ADD amount credited during the year.	15,98,313	
(—)13,82,732	LESS payments made during the year.	(—)15,74,917	
57,378	Unclaimed Deposits in the ESIC		80,774
	Provident Fund.		
50,706	As per last Balance Sheet.	25,253	
6,908	ADD amount credited during the year.	35,108	
(—)32,361	LESS payments made during the year.	(—)9,246	
25,253			51,115
3,22,38,15,932	Total Carried Over.		3,59,92,47,841

Previous year (1978-79)	*Assets*	*Amount*	*Total*
Rs		Rs.	Rs.
70,89,85,863	Total Brought Forward.		78,34,62,815
	Loans to State Governments. F		
2,73,23,100	As per last Balance Sheet.	2,48,05,967	
—	ADD payments made during the year.	—	
(—)25,17,133	LESS amount refunded by State Governments	(—)25,17,133	
2,48,05,967			2,22,88,834
	Remittances.		
	Cash Remittances. G		
6,00,419	As per last Balance Sheet.	(—)22,45,890	
2,97,53,81,683	ADD debits during the year	3,40,53,52,264	
(—)2,97,82,27,992	LESS credits during the year	(—)3,45,21,93,838	
(—)22,45,890			(—)5,08,87,464
	Other Remittances.		
	Exchange Account. H		
36,745	As per last Balance Sheet.	(—) 60,401	
8,92,65,278	ADD debits during the year.	14,96,99,900	
(—)8,93,62,424	LESS credits during the year.	(—)13,74,20,844	
(—)60,401			1,22,18,655
	INVESTMENTS AT COST.		
	1. Capital Construction Reserve Fund.		
30,53,29,804	As per last Balance Sheet.	36,42 88,655	
5,89,58,851	ADD Investments made during the year.	10,83,35,805	
—	Deduct—realisation on maturity or sale of Investments.	—	
36,42,88,655			47,26,24,460
	2. Permanent (Partial and Total) Disablement Reserve Fund.		
17,43,15,230	As per last Balance Sheet.	18,62,85,906	
1,19,70,676	ADD Investments made during the year.	1,42,79,630	
—	LESS realisation on maturity or sale of Investments.	—	
18,62,85,906			20,05,65,536
	3. Dependants' Benefit Reserve Fund.		
9,57,86,859	As per last Balance Sheet.	10,51,06,740	
93,19,881	ADD Investments made during the year.	97,76,150	
—	LESS realisation on maturity or sale of Investments.	—	
10,51,06,740			11,48,28,890
1,38,71,66,840	Total Carried Over.		1,55,51,55 726

F. See paragraph 2.3 of the explanatory notes in Annexure-II.

G. See paragraph 2.4 of the explanatory notes in Annexure-II.

H See paragraph 2.5 of the explanatory notes in Annexure-II.

Previous year (1978-79)	*Liabilities*	*Amount*	*Total*
Rs.		Rs.	Rs.
3,22,38,15,932	Total Brought Forward.		3,59,92,47,841
	Deposits from I.L.O. for Family Planning Project.		
—	As per last Balance Sheet.	—	
7,00,000	ADD deposits during the year.	4,25,000	
	LESS payments to the Family Planing Project.		
(—)7,00,000		(—)4,25,000	
	Miscellaneous Deposits.*		
28,12,557	As per last Balance Sheet.	5,85,608	
	ADD deposits received during the		
29,95,780	year.	30,95,265	
	LESS deposits repaid/adjusted during the		
(—)52,22,729	year.	(—)18,80,531	
5,85,608			17,97,342
3,22,44,01,540	Total Carried Over.		3,60,10,45,183

*This constitutes net effect of the totals in respect of the following Heads : (i) Unclassified Receipts (Suspense Account) (ii) Unclassified Payments (Suspense Account) (iii) D.A. Deposits (iv) Miscellaneous.

Previous year (1978-79)	*Assets*	*Amount*	*Total*
Rs.		Rs.	Rs.
1,38,71,66,840	Total Brought Forward.		1,55,51,55,726
	4. Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.		
4,12,24,332	As per last Balance Sheet.	4,88,54,926	
76,30,594	ADD investments made during the year.	37,70,140	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
4,88,54,926			5,21,25,066
	5. Provident Fund Deposit-Linked Insurance Reserve Fund.		
75,063	As per last Balance Sheet.	1,08,482	
33,419	ADD investments made during the year.	57,441	
—	Deduct realisation on maturity or sale of investments.	—	
1,08,482			1,65,923
	6. Group Insurance Fund.		
—	As per last Balance Sheet.	75,880	
75,880	ADD investments made during the year.	3,62,807	
		3,62,807	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
75,880			4,38,687
	7. Depreciation Reserve Fund of buildings for the Officers of the Corporation (including Staff Quarters).		
30,73,808	As per last Balance Sheet.	35,64,911	
4,91,103	ADD investments made during the year.	4,77,979	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
35,64,911			40,42,890
	8. Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings.		
3,44,63,168	As per last Balance Sheet.	3,98,78,158	
54,14,990	ADD investments made during the year.	63,01,649	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
3,98,78,158			4,61,79,807
	9. Depreciation Reserve Fund of Staff Cars.		
5,61,738	As per last Balance Sheet.	6,12,202	
50,464	ADD investments made during the year.	9,512	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
6,12,202			6,21,714
	10. Repairs and Maintenance Reserve Fund of buildings for the offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
28,03,568	As per last Balance Sheet.	28,12,150	
8,582	ADD investments made during the year.	—	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	(—)2,08,814	
28,12,150			26,03,336
	11. Repair and Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings.		
4,82,07,426	As per last Balance Sheet.	5,39,63,325	
57,55,899	ADD investments made during the year.	23,40,405	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
5,39,63,325			5,63,03,730
1,53,70,36,874	Total Carried Over.		1,71,76,36,879

Previous year (1978-79)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs	Rs
3,22,44,01,540	Total Brought Forward		3,60,10,45,183
3,22,44,01,540	GRAND TOTAL		3,60,10,45,183

NEW DELHI,
Dated 31st May, 1980.

Previous year (1978-79)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,53,70,36,874	Total Brought Forward.		1,71,76,36,879
	12. Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
7,85,80,959	As per last Balance Sheet.	8,29,87,739	
44,06,780	ADD investments made during the year.	1,09,32,045	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
8,29,87,739			9,39,19,784
	13. Emergency Reserve Fund.		
28,33,47,207	As per last Balance Sheet.	34,94,27,240	
6,60,80,033	ADD investments made during the year.	3,97,59,014	
—	Deduct—Realisation on maturity or sale of Investments.	—	
34,94,27,240			38,91,86,254
	14. Compassionate Reserve Fund.		
9,999	As per last Balance Sheet.	27,768	
17,769	ADD investments made during the year.	(—)1,466	
—	LESS realisation on maturity or sale of investments.	—	
27,768			26,302
	General Cash Balance.		
96,95,31,370	Investment as per last Balance Sheet.	1,19,17,73,449	
50,45,98,079	ADD investments made during the year.	76,95,16,003	
(—)27,23,56,000	LESS realisation on maturity or sale of investments	—)63,64,79,700	
1,19,17,73,449			1,32,48,09,752
32,90,768	Cash in hand[1]	48,82,242	
5,98,57,702	Cash with Bankers. [1]	7,05,83,970	
6,31,48,470			7,54,66,212
1,25,49,21,919	Total Cash Balance.		1,40,02,75,964
3,22,44,01,540	GRAND TOTAL		3,60,10,45,183

Sd-
(M.L. Sobti)
Financial Adviser &
Chief Accounts Officer,
Employees' Insurance Corporation

1. See paragraph 2.6 of the explanatory notes in Annexure-II.

ANNEXURE I

Explanatory notes on Income and Expenditure Accounts

1.1 **"A" on page ii**

The amount includes Corporation's share of expenditure on the inital equipments purchased for the hospitals.

The total expenditure on the purchase of equipment from 1967-68 to 1971-72 and from 1973-74 to 1979-80 (information for the year 1972-73 is being collected) is Rs. 1,50,67,801.80. The same had not been exhibited in the Balance Sheet as assets. Capitalisation of this expenditure is still under consideration of the Corporation.

1.2 **"B" on page ii**

The increase in expenditure is mainly on account of additional coverage and increase in the amount of average daily rate of benifit consequent on revision of wages.

1.3 **"C" on page iii**

Prior to 1-7-73, the Employers' Special Contribution and Employees' Contribution were booked separately under the sub-head "Employers' share and Employees' share only". Consequent on the repeal of Chapter V-A of the Employees' State Insurance Act, 1948, the combined contributions are now being shown under the sub-head "Employers' and Employees' share" The increase in contribution income is mainly on account of additional coverage and increase in the amount of average rate of contribution consequent on revision of wages.

As per information available, there were arrears of unrealised contribution amounting to Rs. 28,09 78 lakhs for the period upto 31-3-79 as on 31-3-1980. There were also unrealised decretal amounts towards peyment of contributions aggregating Rs. 32.46 lakhs as on 31-3-1980.

1.4 **"D" on page iii**

Represents recoveries of arrears for the period prior to 1-7-73.

1.5 **"E" on page iii**

The decrease in receipts under 'Interest and Dividends' is due to investments being made since 1st October, 1976 in time deposits under 'Re-investment Plan' of the State Bank of India under which interest falling due will be credited to the Corporation's account on maturity of an investment.

Excludes the amount of Rs. 9,71.90 lakhs as interest accrued during the year 1979-80 on investments in re-investment plans as the amount will be payable to Corporation on maturity of the investments.

1.6 **"F" on page iii**

The receipts under 'Compensations' represent the amount recovered from the State Government under the provision of Section 58 (2) of the Employees' State Insurance Act, in case where the incidence of sickness payments to insured persons in any State is found to exceed the All India average.

1.7 **"G" on page iii**

This includes receipts on account of licence fee from the employers for use of franking machines by them and also damages levied on the employers for failure to pay dues of the Corporation and non-submission on contribution cards in time.

An amount of Rs. 347.89 lakhs was outstanding for recovery as on 31-3-1979 towards 'damages' payable on account of delay in payment of contributions.

1.8 **"H" on page iii**

This includes receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of over payments and disallowances in audit, recoveries of leave salary and pension contributions employees' contribution towards Central Government Health Scheme and other receipts.

1.9 **"I" on page iv**

This includes miscellaneous expenses including fee paid for postmortem examination of insured persons and charges payable to police authorities for obtaining police reports and other statements for deciding cases of employment injuries etc.

1.10 **"J" on page vi**

This includes telegraphic charges on bank tansfers and commission charges by the Associate Banks of the State Bank of India for the sale of contribution stamps. The decrease in expenditure is partly due to reduction in the rate of telegraphic transfer of fund from Rs. 7 to Rs. 3 per telegraphic transfer w.e.f. 1-9-1979 and waiver of commission on realisation of contribution in cash.

1.11 **"K" on page vi**

This excludes Rs. 6,79,786 pertaining to pensionary liability of the employees of Directorate (Medical), Delhi, which is included under 1-A(ii) Medical Benefits being sharable expenditure with the Delhi Administration.

An amount of Rs. 33.66 lakhs representing excess provision of 2% together with interest accrued thereon w.e.f. 1-4-1974 to 31-3-1978, was adjusted in the accounts for the year 1978-79 as per recommendation in the report on the 5th quinquennial valuation of the Corporation. The valuer recommended that the annual provision for Pension Reserve Fund should be made @12% of the emoluments of the employees instead of 14%.

454 persons of the Contributory Provident Fund optees exercised their option for coming over to the Pension Scheme of the Corporation in terms of Headquarters Office Estt. Branch IV letter No. F.22/11/1/78-E. IV dated 10-10-1979. The accumulated pensionary liability in respect of such employees has also been provided or in the Pension Reserve Fund during the year 1979-80.

1.12 **"L" on page vi**

This expenditure represents payments on account of refunds of lapsed deposits and payment of ESIC Provident Fund transferred to Miscellaneous receipts.

1.13 **"M" on page viii**

As per decision dated 1-2-1974 of the Standing Committee of the Corporation, 10% of the total revenue derived from Employers' and employees contribution is credited to the Capital Construction Reserve Fund for construction of Hospitals/Dispensaries/ other medical institutions and office buildings/Staff Quarters.

1.14 **"N" on page viii**

This represents transfer to Emergency Reserve Fund as per decision of the Corporation in its meeting held on 17th March, 1973. The Corporation has laid down that 20% of the excess of income over expenditure (whole of the amount when excess is less than rupees one crore) should be credited to the Emergency Reserve Fund.

ANNEXURE II

Explanatory notes on Balance Sheet

2.1 **"B" on page xi**

Includes assets worth Rs. 23,94,10,096 created out of General Cash Balance

2.2 **"E" on page xix**

Include (i) Advances to Controller of Stationery, Calcutta.
(ii) Advances to Public Works Departments.
(iii) Advances to Printing & Stationery Departments of the State Governments.
(iv) Advances to Regional Offices and other offices of the Corporation.
(v) Advances to Municipal Committees, Local Bodies etc.
(vi) Advances for legal charges.
(vii) Advances to Corporation's Departmental Canteens
(viii) Other advances which are not classified elsewhere.
(ix) Special Advances.

2.3 **"F" on page xxi**

Represents loans granted to the Government of Maharashtra prior to 1977-78 for construction and expansion of Employees' State Insurance Projects in the State.

2.4 **"G" on page xxi**

The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one Account circle to another and vice versa. The revenue of the Corporation is collected by sale of stamps/cash realisation through the State Bank of India and its Associate Banks. The contributions received are transferred to the accounts of the respective Regional Office Account No. I (Collection Account) and finally transferred to Account No. I (Central) of the Headquarters' Office. Funds for administrative expenditure and benefit payments to insured persons are provided to Regional Office/Local Office from Central Account No. I (Headquarters Office) by making transfers. All such transactions in transferring funds from one office to another are known as 'Cash Remittances'.

The minus balance of Rs. 5,08,87,464 under the head 'Cash Remittances' represents adjustments of certain credits in the accounts of the Corporation for which per contra debits could not be afforded for want of debit advices from the Bank. However, the amount under this head has since been adjusted in the month of April, 1980.

2.5 **"H" on page xxi**

The term 'Other Remittances—Exchange Account' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other and vice versa. Transactions originating in one office of the Corporation adjustable in the books of another office of the Corporation are transferred through Exchange Account.

The balance of Rs. 1,22,18,655 under the head 'Other Remittances—Exchange Account' represents Adjustment of certain debits in the accounts of the Corporation for which per contra credits (Responding items) should not be effected before the close of the accounts for 1979-80.

2.6 **"I" on page xxxiii**

(Rupees in lakhs)

Cash with bankers comprises the following .

(i) Balance in Regional Office Account No. I (Collection Account). 67.38

Cash available in Account No. I of the Regional Office (Collection Account) represents contributions received on 30th & 31st March, 1980.

(ii) Balance in Regional Office/Directorate (Medical), Delhi Account No. II for meeting Administration expenses & expenditure on medical care in Delhi. 218.46

The amount in Regional Office Account No. II was required for disbursing salary on 1-4-80 and to meet other expenditure.

(iii) Balance in Account No. II of the Local Offices 420 00

Weekly average payment of cash benefits to insured persons is approximately Rs. 123.00 lakhs The balance of Rs. 420.00 lakhs in Account No. II of Local Office could meet their requirements for about 3 weeks.

.e difference between the Accounts-figure and the figures as per Review of Balance as under, are being reconciled:

Head of Accounts	*Accounts figures*	*Broad Sheet figures*	*Difference*
1. Deposit of Securities e.g. Contractors etc.	8,97,797.00	8,97,975.00	178.00
2. Miscellaneous Deposits, Unclassified Receipts (Suspense Account)	17,97,342.00	17,91,072.22	6,269.78
3. Advance of T.A. on transfer to employees	1,11,854.00	1,11,514.00	340.00
4. Advance to the Corporation employees for the purchase of conveyance.	15,66,591.00	15,66,699.58	108.58
5. Miscellaneous-Advances to the employees of the Corporation.	21,98,872.00	21,99,089.00	217.00
6. Advances to P.W.D. etc. for Repair & Maintenance of			
(a) Offices of the ESI Corporation.	33,76,345.00	33,98,533.00	22,188.00
(b) Hospital/Dispensaries Buildings	3,55,60,187.00	3,57,23,332.00	1,63,145.00
7. Miscellaneous Advances	22,05,390.00	21,80,594.00	24,796.00

STATEMENT-A

Receipt and Payment Account of Capital Construction Reserve Fund for the year 1979-80 as at 31st March, 1980

	Rs.		Rs.		Rs.	Rs.
Opening Balance	74,89,66,131	X		Assets created out of Capital Construction Reserve Fund	30,84,84,670	
Provision made during the year	15,97,60,416	Y		Advances paid to Construction Agencies	14,14,36,660	
Interest on investments	1,38,19,243	Z		Amount available in the Fund.	47,26,24,460	
			92,25,45,790			92,25,45,790
			Hospitals & Dispensaries.	*Other Buildings*		
Opening Balance		X	59,91,72,905	14,97,93,226		
Provision made during the year.		Y	12,78,08,333	3,19,52,083		
Interest on Investment.		Z	1,10,55,395	27,63,848		

STATEMENT-B

Receipt and Payment Account of the Repair & Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (Including Staff Quarters)

	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Opening Balance	56,12,696		Amount advanced to State Governments/State Public Works Departments towards repair and maintenance of Offices of the Corporation.		
Provision made during the year	9,93,727			'A' 46,51,072	
Interest on Investments	1,06,735		Amount available in the Fund.	26,03,336	
Cash refunds of unutilised advances made by the State Governments/State Public Works Departments.	5,41,250				
		72,54,408			72,54,408
			'A' Amount advanced to State Govts.		46,51,072
			Less Cash refunds to unutilised advances.	5,41,250	
			Less Amount adjusted on receipt of certified statement of expenditure.	7,33,477	
					12,74,727
			Balance as per balance sheet (page xix).		33,76,345

STATEMEN

Receipt and Payment Account of the Repair & Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings/ Dispensaries/Annexes etc.

	Rs.	Rs		Rs	Rs.
Opening Balances.	8,19,81,421		Amount advanced to State Governments/State Public Works Departments towards repairs and maintenance of Hospitals/ Dispensaries/Annexes.	4,51,97,717 'A'	
Provision made during the year.	1,38,87,848		Amount available in the Fund	5,63,03,730	
Interest on investments.	20,47,060				
Cash refunds of unutilised Advances made by the State Governments/State Public Works Departments	35,85,218				
		10,15,01,447			10,15,01,447
			'A' Amount advanced to State Govts.		4,51,97,717
			Less Cash refunds of unutilised advances.	35,85,218	
			Less Amount adjusted on receipt of certified statements of expenditure.	60,52,312	
					96,37,530
			Balance as per balance sheet (page xix)		3,55,60,187

STATEMENT-D

Statement showing details as at 31st March 1980 of Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund and Contributory Provident Fund

		General Provident Fund (Rs.)	Contributory Provident Fund (Rs.)	Total (Rs.)
1.	Opening Balance	3,88,41,621	1,00,13,305	4,88,54,926
2.	Employees' subscription	1,26,02,508	12,07,393	1,38,09,901
3.	Corporation's Contribution	—	39,401	39,401
4.	Interest on employees' and Corporations' share	31,91,270	5,10,039	37,01,309
5.	Incentive Bonus	1,27,129	30,450	1,57,579
6.	TOTAL	5,47,62,528	1,18,00,588	6,65,63,116
	(a) Less payments made during the year	98,48,190	8,13,078	1,06,61,268
	(b) Less amount transferred to			
	(i) Pension Reserve Fund	—	37,41,674	37,41,674
	(ii) Unclaimed Deposits	21,103	14,005	35,108
	CLOSING BALANCE	4,48,93,235	72,31,831	5,21,25,066

APPENDIX XXIV

Administrative cost compared with Benefits paid etc.

	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
	(In Rupees)					
I. Total Administrative cost	6,60,68,976	7,77,62,505	8,77,45,918	9,55,40,440	9,95,03,434	11,37,56,420
II. Contributions						
(i) Employers' & Employees' Shares	60,34,74,995	73,16,86,339	123,61,94,824	1,31,11,81,105	1,45,78,73,675	1,58,68,28,2
(ii) Employer's Share only	2,16,80,542	1,78,07,427	93,97,151	25,97,022	17,57,264	15,72,055

	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
			(In Rupees)			
(iii) Employees' Share only	1,00,74,058	1,00,09,537	1,07,22,754	48,90,539	71,05,946	77,46,520
(iv) Interest	—	—	1,78,865	5,97,322	8,57,102	14,57,288
Total :	63,52,29,595	75,94,03,303	1,25,64,93,594	1,31,92,65,988	1,46,75,93,987	1,59,76,04,161
III. Total Expenditure on Revenue Account	62,49,05,056	75,58,05,845	1,01,91,84,702	1,17,71,52,092	1,37,04,51,588	1,59,18,79,538
IV. Total Benefits	46,45,26,360	57,23,86,508	70,85,36,816	87,03,56,722	1,05,84,50,926	1,27,31,82,259
percentage relationship of Administrative cost to :						
Contributions	10.40%	10.24%	6.98%	7.24%	6.78%	7.12%
Expenditure on Revenue Account	10.57%	10.29%	8.61%	8.12%	7.26%	7.15%
Benefits	14.22%	13.59%	12.38%	10.98%	9.40%	8.93%

NOTE: IV does not include share of Medical Benefit expenditure borne by the State Governments.

[No. Z-16016/3/80-HI]
N. B. CHAWLA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982